



# भारत में शिक्षा



लेखक

डॉ. श्रीधरनाथ मुकजी

अध्यक्ष

शिक्षा एवं मनोविज्ञान सहाय

श्री महाराजा सदाजीराव विश्वविद्यालय

बड़ौदा



प्रकाशक

आचार्य चुक द्विपो

बड़ौदा

१९६०



भारतीय शिक्षा को नवीन ज्योति दिखानेवाले

पूज्य राष्ट्र-पिता के

श्रीचरणों में विनम्र श्रद्धाञ्जलि



## प्राक्कथन

अंग्रेजी भाषा में मेरी 'Education in India—Today and Tomorrow' नामक पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। उसका चतुर्थ अंश भी प्रकाशित हुआ है। शिक्षा-जगत् में उस पुस्तक का इस प्रकार व्यापक एवं प्रचार उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्रस्तुत पुस्तक मेरी उसी पुस्तक पर आधारित है। इसमें कहीं-कहीं तो उस मूल ग्रन्थ का अनुवाद है, उसको आधार मान लिया गया है। आशा है कि मेरी उक्त अंग्रेजी पुस्तक हिन्दी रूप भी पाठकों को रुचिकर होगा।

शिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम की ओर दृष्टि रखकर मैंने यह पुस्तक आरम्भ किया था; किन्तु जिस समय मैं घण्टे विषय के विभिन्न अङ्गों पर ध्यान देने लगा, उस समय मैंने अनुभव किया कि व्यापकता का ध्यान ए इस पुस्तक को केवल बी० एट० या एम० एट० के पाठ्यक्रम तक ही सीमित जावे, वरन् इसे इस प्रकार लिखा जावे, जिससे यह माध्यामिक शिक्षित भारतीय भी ध्यान आकृष्ट करे। चूंकि शिक्षा-विषयक जानकारी प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है, अतएव इस पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करने का फैसला किया गया है कि जिससे बटिनाइयों के बिना सर्वसाधारण पाठक इसका लाभ ले सके।

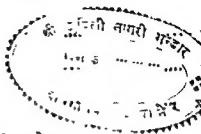
इस पुस्तक को लिखने का मेरा दूसरा उद्देश्य हिन्दी-भाषा की यथा-संवि सेवा थी है। हिन्दी भाषा में शिक्षा-विषयक पुस्तकों की माँग है, और ऐसी शिक्षा साहित्य की भी अभाव भी है। इसीसे इस पुस्तक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। मैंने इस ग्रन्थ में भाषा को भरसक सरल रखने का प्रयत्न किया है। विषयक परिभाषिक शब्दों के रूप की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी शब्दों का भी सामना करना पड़ा, पर साधारणतया मैंने हिन्दी में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया है।

अन्त में उन अनेक विद्वानों तथा ग्रन्थकारों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ, जिनके विचारों तथा ग्रन्थों से मुझे इस कार्य में सहायता प्राप्त हुई है। इनके ग्रन्थ सूची में दिये गये हैं।

मैं भी सत्यमोहन अद्वितीय, 'स्वर्ण-सहोदर' एडम्स आदर्शपूर्ण प० राजप्रधान सिन्धु, ए०, (मूलपूर्व अधीक्षक, आन्धीस विभाग महाविद्यालय, ब्रह्मपुर) का अत्यन्त

[illegible]

## विषय-सूची



प्राक्कथन	..		
तालिका-सूची	...		
चित्र-सूची	...		
<b>१. भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूपरेखा</b>			
भूमिका	...		...
वैदिक युग	...	...	
बौद्ध युग	...		...
मुस्लिम युग	...	...	...
ब्रिटिश युग	...	..	...
स्वातन्त्र्योत्तर काल	..	...	...
<b>२. शिक्षा व्यवस्था</b>			
भारत के राज्य	...	...	...
शिक्षा-प्रशासन	...	...	...
शिक्षा-नास्थाओं का वर्गीकरण	...	...	...
शिक्षा की सीढ़ी	..	...	..
शिक्षा-व्यय	...	...	...
<b>३. पुनियादी शिक्षा</b>			
प्रस्तावना	...	...	...
प्रारम्भिक कार्य	...	...	...
नदी तालिम के प्रक्रम	...	...	...
नदी तालिम और भूदान	...	...	...
नदी तालिम और सरकार	...	...	...
समाप्ति	...	...	...



## ४. प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका	...	...	६२
अनिवार्य शिक्षा-आन्दोलन...	...	...	६६
वर्तमान स्थिति	...	...	७२
प्राथमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ	..	...	७९
सुधार की ओर	...	...	८३
उपसंहार	...	...	९६

## ५. माध्यमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका	..	...	९७
वर्तमान स्थिति	...	...	१०६
माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ	...	...	११५
उपसंहार	...	..	१३५

## ६. विश्वविद्यालयीय शिक्षा

प्रस्तावना	..	...	१३६
आधुनिक काल में उच्च शिक्षा	...	...	१३६
वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ	...	...	१४३
कतिपय समस्याएँ	...	...	१४८
स्वाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय	...	...	१६१
उपसंहार	...	...	१७७

## ७. - स्त्री-शिक्षा

प्राथमिक	...	...	१७८
शिक्षा का विस्तार	...	...	१७८
स्थिति	...	...	१८१
	...	...	१८७
	...	...	१९२

## वैधिक शिक्षा

सावना	...	...	१९४
देश शासन-काल में प्राविधिक शिक्षा	...	...	१९५
चीन भारत में प्राविधिक शिक्षा	...	...	१९८
वैषय समस्याएँ	...	.	२०५
संसार	...	...	२१३

## शैक्षक प्रशिक्षण

शैक्षक-पृष्ठिका	...	..	२१५
मान्य परिस्थिति	...	...	२२०
अनुसन्धान एवं उत्तर-स्नातक कार्य	...	...	२२७
अध्ययन-अध्यापन प्रशिक्षण	...	...	२२९
शैक्षक-प्रशिक्षण समस्याएँ	...	...	२३१
शैक्षकों की कतिपय समस्याएँ	...	...	२३९
संसार	...	...	२४३

## विध विषय

वै-प्राथमिक शिक्षा	...	...	२४५
उच्च (ममात्र) शिक्षा	...	...	२५०
अध्यापन की शिक्षा	...	...	२६२
अध्ययन एवं अनुसन्धान	...	...	२७१

## विषय राष्ट्रीय संस्थान

सावना	...	...	२७९
इन्दु, बौद्ध	...	...	२७९
स० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय	...	...	२८०
विश्व-भारती	...	...	२८१
राधापीठ	...	...	२८४
मिथिला मिलिया, दिल्ली	...	...	२८५
इन्दुस्थानी तार्कीमी संघ, सेवाग्राम	...	...	२८७

## सांख्यिक शिक्षा

पुर्बे पृ. १०३	...	६०
वर्तमान स्थिति	...	६१
वर्तमान स्थिति	...	६२
वर्तमान स्थिति	...	६३
वर्तमान स्थिति	...	६४
वर्तमान स्थिति	...	६५
वर्तमान स्थिति	...	६६

## सांख्यिक शिक्षा

पुर्बे पृ. १०३	...	६०
वर्तमान स्थिति	...	६१
वर्तमान स्थिति	...	६२
वर्तमान स्थिति	...	६३
वर्तमान स्थिति	...	६४

## विश्वविद्यालयीय शिक्षा

प्रस्तावना	...	११६
आधुनिक काल में तथा शिक्षा	...	११७
वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ	...	११८
वर्तमान स्थिति	...	११९
वर्तमान स्थिति	...	१२०
वर्तमान स्थिति	...	१२१
वर्तमान स्थिति	...	१२२

## स्त्री-शिक्षा

प्रस्तावना	...	१२३
स्त्री-शिक्षा का विस्तार	...	१२४
वर्तमान स्थिति	...	१२५
आलोचना	...	१२६
उपसंहार	...	१२७

## ८. प्राविधिक शिक्षा

प्रस्तावना	...	...	...
ब्रिटिश शासन-काल में प्राविधिक शिक्षा	...	...	...
स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा	...	...	...
कतिपय समस्याएँ	...	...	...
उपसंहार	...	...	...

## ९. शिक्षक प्रशिक्षण

पूर्व-पृष्ठिका	...	...	...
वर्तमान परिस्थिति	...	...	...
अनुसन्धान एवं उत्तर-स्नातक कार्य	...	...	...
मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण	...	...	...
शिक्षक-प्रशिक्षण समस्याएँ	...	...	...
शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ	...	...	...
उपसंहार	...	...	...

## १०. विविध विषय

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	...	...	...
मौढ़ (समाज) शिक्षा	...	...	...
मजदूरों की शिक्षा	...	...	...
स्वाम्य एवं अनुशासन	...	...	...

## ११. कतिपय राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्तावना	...	...	...
गुरुकुल, काँगड़ी	...	...	...
एन० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय	...	...	...
विश्व-भारती	...	...	...
रियासीट	...	...	...
बामिना मिलिया, दिल्ली	...	...	...
हिन्दुस्थानी तालीमी संघ, सेवामान	...	...	...

૧૩. ચાલિતી	..	...	૩૨૭
દરેકનું			
૧. દિવસ દરમિયાન સર્વ કાર્યોનું, ૧૯૪૬ (૧૯૪૬-૪૭)		...	૩૨૭
૨. ૧૯૪૬ ને ૧૯૪૭ વચ્ચે, ૧૯૪૮		..	૩૨૭
૩. ૧૯૪૭-૪૮ વચ્ચે, ૧૯૪૮		...	૩૨૭
સામાન્ય	..	...	૩૨૭
અનુદાનનિધિ (અનુદાનનિધિ) ...	..	..	૩૨૭
અનુદાનનિધિ (અનુદાનનિધિ),		..	૩૨૭

## तालिका सूची

१. प्रथम तथा द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय का आवण्टन ( करोड़ रुपये )	२
२. प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य	२
३. भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या	२
४. अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा, १९२१-३७	७
५. प्राथमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६	७
६. प्राथमिक शिक्षा पर खोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६	७
७. प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा, १९५१-५२ से १९५६-५७	७
८. एक-शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूल	७
९. शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय, १९०१-०२ से १९४७-४८	८
१०. कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति	८
११. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ से १९५६-५७	१०
१२. माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६	१०
१३. माध्यमिक शिक्षा पर खोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६	११
१४. मैट्रिक तथा अन्य शालान्त परीक्षाओं का फल	११
१५. कालिजों की संख्या, सन् १८५७	११
१६. अंग्रेजी भारत में कालिज शिक्षा, १९२१-४७	१४
१७. प्रश्नानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९५५-५६	१४
१८. उच्च शिक्षा की भाव का खोतवार बँटवारा, १९५५-५६	१६
१९. विद्वत्विशालय अनुदान-आयोग द्वारा अनुदान-आवण्टन	१६
२०. विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं का परिणाम, १९५५-५६	१६
२१. स्कूल तथा कालिजों में लड़कियों की संख्या, १९२१-२२ से १९४६-४७	१८
२२. कालिज माध्यमिक शिक्षा में प्रगति	१८
२३. विभिन्न विद्वत्विशालयीय परीक्षाओं में उच्चिर्ण छात्रा-संख्या	१८
२४. कतिपय क्षेत्रों में नारी	१८
२५. भारत में शिक्षकों की संख्या, १९५६-५७	२४
२६. गमाव शिक्षा का विस्तार, १९५१-५२ से १९५५-५६	२५
२७. मध्यमों की शिक्षा सन्धान, १९५५-५६	२६
२८. राष्ट्रीय उच्च शिक्षार्थी दल की प्रगति	२७
२९. राष्ट्रीय अनुशासन योजना की व्यवस्था, १९५९-६०	२७

## विषय-सूची

१. विप्लव-प्रति उपनिषद् के एक भाष्य	...	...	८
२. रीति विचारविचार में निरूपण	...	..	१०
३. वैयर्थीय विचार-मन्त्र	..	...	१०
४. विचार-मन्त्र	...	...	१३
५. धर्मिक विचार में समान	...	...	५५
६. धर्म में सामाजिक विचार	..		७८
७. सामाजिक विचारों की धर्मिक तथा विचारों का धर्म	...	...	८६
८. सामाजिक विचार का विचार			१०६
९. धर्मिक विचार में धर्मिक धर्मों की दृष्टि में विचारों का धर्म	...		१०६
१०. धर्मिक विचारों के विचारों का धर्म	..	...	१२९
११. धर्मिक विचारों की धर्मिक, १९५७-१९५७	...	..	१४९
१२. धर्मिक विचारों का धर्म, १९५७-५८ में १९५७-५८	..	..	१५९
१३. धर्मिक विचार, १९५७-५८			१८९
१४. सामाजिक विचारों की धर्मिक, १९५७-५८	..	...	२०९
१५. सामाजिक धर्म	..	...	२२९
१६. धर्मिक विचारों की धर्मिक, १९५७-५८	..	...	२३९
१७. धर्मिक विचारों की धर्मिक, १९५७-५८	..	...	२४९
१८. धर्मिक विचारों की धर्मिक, १९५७-५८	..	...	२५९
१९. धर्मिक विचारों की धर्मिक, १९५७-५८	..	...	२६९
२०. धर्मिक विचारों की धर्मिक, १९५७-५८	..	...	२७९

## पहला अध्याय

### भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा

[ एक शिक्षाचलोकन ]

सब हमारा देश शिक्षा गिना जाता है। यदि अधोभाष पिछड़ेपन का लक्षण है कुछ कहना नहीं है। यदि निम्नता के कारण हम पिछड़े गिने जाते हैं, तो भी यह जाना पड़ता है। किन्तु यदि गव्यता की दृष्टि में देखा जाय तो कुछ देखा ही हमारी समझी कर सकते हैं। अब हमारा देश समग्र का निम्नतर जाना था, जब पाश्चात्य देश बड़े गिने जाते थे। यद्यपि आज ८१ प्रतिशत जनता निम्नतर है, तथापि ये गरीब नहीं बड़े जा सकते हैं। बावजूद भी इनमें मुँहों में बड़ी, गुत्थी प्रभृति की उपदेश-भरी पत्तियाँ निकल पड़ती हैं। वे ऊँच की दीर्घम-पूर्ण दीर्घभाषा बोलाने लगते हैं, और नरसी मोहना तथा के. भक्ति मय गीतों को गुत्थर विमोह हो गते हैं।

हमारा मुख्य कारण है हमारी साक्षरता। ऐहिक कार्य से लेकर धर्मनिरपेक्ष तक साक्षरता की धारा बहुत बनी आ रही है। निधर ही मने अनेक नौ नौ मुक्तों मग बरग पड़ा, तो भी हमारी साक्षरता का दम अटुल रहा। आज भी हमारी बाल तथा साक्षरता की उन्नति को समग्र स्वीकार करना है। अनेक समय देह में वे लोग भी समा गये, पर अनेक आज भी फिर उँचा खड़े खड़ा है। हमारा भी मुँह नीचे पर अधोभित्त हमारी समग्र आज भी उँचे खड़े खड़ा है।

हमारा भी अनेक कारण है हमारा साक्षरता है। इस अवधि अर्थात् १९०० से १९६० तक १९६० ई० तक ७ करोड़ के विद्यार्थी इस विद्यार्थी के १९६०, इन विद्यार्थी के १९६० से १९६० तक है :



१. वैदिक युग	५,५०० ई. पू. से ५०० ई. पू. तक
२. ऐतरेय युग	५०० ई. पू. से १,२०० ई. पू. तक
३. मुनि युग	१,२०० ई. पू. से १,५०० ई. पू. तक
४. वृद्धि युग	१,५०० ई. पू. से १,९०० ई. पू. तक
५. महाभारत युग	१,९०० ई. पू. से ४०० ई. पू. तक

मनुष्य युग में वर्तमान स्थिति की विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। शिक्षा के अतिरिक्त मानव की प्रगति का भी वर्णन है। यह हमें वर्तमान की समझना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि वर्तमान में क्या चीजें हुईं, परन्तु अभी भी नीचे का बड़ा होगा है। इसी कारण हम अपने में भागीरथ शिक्षा के इतिहास की रूपरेखा दी जाती है तथा वर्तमान शिक्षा के प्रत्येक शिक्षा प्रभ की पूर्ण-वृद्धि गद्यों में दी जाती है। हमने मनुष्य युग में वर्तमान शिक्षा के इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों तथा परम्पराओं का ही वर्णन किया है। ये इस प्रकार चुनी गयी हैं, जिनमें वर्तमान स्थिति पर महत्व प्रकाश पड़े।

वैदिक युग में आर्यों में यह मिथ्यात्व कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म पर लगे रहकर पैदा होता है—देव-तप, विदु-तप और शक्ति-तप। अप्रति का दान देना तथा यज्ञ कर के यह देव-तप में मग्न होता है, विचार कर और पुत्र उत्पन्न कर के विदु-तप में मग्न होता है, तथा अत्यन्त और अत्यन्त कर यह शक्ति-तप में मग्न होता है।

## वैदिक युग

वैदिक युग में मानव-समाज के स्थिति के अनुसार चार वर्गों में बाँट दिया गया था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का कर्तव्य था प्रजा तथा आभितों का रक्षण और पालन करना, वैश्य का काम था व्यापार और खेती करना, तथा शूद्र का काम था सेवा करना और सब वर्गों के काम में बंधुएँ बनाना। समाज को पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए, इस वर्ण-व्यवस्था की सृष्टि की गयी थी, जिससे प्रत्येक मनुष्य वही काम करे, जिसके लिए वह उपयुक्त समझा जावे। जाति-भेद की व्यवस्था उस समय किसीने सोची भी नहीं थी।

अध्ययन के प्रक्रम ठीक-ठीक बाँट दिये गये—जन्म से सात वर्ष तक घर में, और उसके बाद गुरुकुल में। आठवें वर्ष उपनयन के पश्चात्, बालक गुरुकुल में विद्याध्ययन



भी को पढ़ना पड़ता था। अपने-अपने वर्ग के अनुसार विद्यार्थीगण वेद तथा ग्राह्य का अध्ययन करते थे। नैतिक शिक्षा कुछ तो उपदेश से और कुछ आश्रम के आचरण से मिलती थी। शारीरिक शिक्षा के लिए प्राणायाम और व्यायाम का विधान था। यों तो दैनिक नियमित कार्यों के सम्पादन में ही पर्याप्त व्यायाम हो जाता था, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को लकड़ी काटना, पानी भरकर ढोना तथा आश्रम की स्वच्छता करना आवश्यक होता था।

व्यावसायिक शिक्षा वर्गों के अनुकूल दी जाती थी। ब्राह्मण पौरोहित्य, दर्शन, मंत्राण्ड आदि विषय का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय दण्ड-नीति, राज-नीति, सैन्यशास्त्र, रथशास्त्र, धनुर्वेद आदि सीखते थे तथा वैश्य को पशु-पालन एवं कृषि-विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त करना पड़ती थी। इन विषयों के सिवा आयुर्वेदादि विषय अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी छात्र सीख सकते थे। एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अनेक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा रहते हुए भी, प्रत्येक छात्र को किसी एक विषय में पारङ्गत होना पड़ता था। साधारणतः पच्चीस वर्ष की आयु में तीनों वर्गों की शिक्षाएँ पूरी हो जाती थीं; पर ब्राह्मण को यह विशेषाधिकार था कि वह आजीवन स्वेच्छापूर्वक विद्यार्जन करे—‘श्रावज्जीवमधीते विप्रः’। शिक्षा समाप्त होने पर तथा गुरु-दक्षिणा देकर प्रत्येक विद्यार्थी विवाहोपरान्त गृहस्थाश्रम में विष्ट होता था।

आचार्य या गुरु सभ से ऊपर के वर्गों के छात्रों को पढ़ाते थे। ये विद्यार्थी अपने-से निम्न वर्ग के छात्रों को सिखाते थे, और वे अपने-से नीचे वालों को। इस प्रकार सभ से नीचे वर्ग के छात्रों के सिवा, गुरुकुल में सभ गुरु-ही-गुरु रहते थे। अध्यापन के समय, प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। अरण्य, वैदिक काल में गुरु किसी विद्यालय या वर्ग के शिक्षक न थे। गुरु का कर्तव्य बाल पढ़ाना ही न था। उसका धर्म था कि वह प्रत्येक छात्र को सदाचारी बनावे, उसके आचरण की रक्षा करे, उसका चरित्र-गठन करे, उसके भोजन वस्त्र का प्रबन्ध करे तथा उसके प्रति अपने पुत्र के समान वात्सल्यभाव दिखावे। विद्यार्थी भी गुरु को पिता और देवता समझता था। उसे ‘आचार्यदेवो भव’ की शिक्षा दी जाती थी। यह सब कुछ सम्भव था, क्योंकि शिक्षा सांवाग-प्रणाली के अनुसार दी जाती थी और साप-साय रहते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का शिष्य गुरु का ही नहीं होता था, वरन् वह गुरु-परिवार का एक सदस्य भी होता था।  
में गरीब और अमीर साथ साथ रहते और विद्याध्ययन करते थे। वहाँ

ऊँच-नीच का भेद-भाव न था। इस प्रकार गुरुकुलों का सामाजिक जीवन भ्रातृभाव में परिपूर्ण था। इसी कारण आर्थिक मद्दे के समर मुद्रामाजी महाशय अपने पूर्व सहपाठी श्रीकृष्ण भगवान् के निम्न टीढ़े गये थे, और एक नृपति होकर भी उन्होंने अपने एक भूतपूर्व दोन सहपाठी का समुचित सम्मान किया था।

वैदिक कालीन शिक्षण-पद्धतिमें तीन क्रियाओं का समावेश था — श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। अध्ययन के समर विद्यार्थी गुरु के वचन को ध्यान-पूर्वक सुनते थे। पाठ समाप्त होने पर विद्यार्थी प्रश्न करते थे और गुरु उनके उत्तर देते थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर-प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थियों के उत्तर की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। अपने अवकाश के समर वे पठित पाठ का मनन और निदिध्यासन (चिन्तन) करते थे।

गुरुकुलों में आजकल के समान परीक्षा प्रणाली न थी। गुरुजी प्रति दिन दो कुछ पढ़ाते थे, उसे उसके अगले दिन प्रत्येक विद्यार्थी में सुनते थे। उहाँ कभी रद्द जानी थी, उसे वहाँ विद्यार्थी पूरा कर लिया था। पूर्णतः मन्दृष्ट होने पर ही गुरुजी अगला पाठ पढ़ाते थे। इस प्रकार प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत योग्यता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। बीच-बीच में गुरुजी आभय के विद्यार्थियों को दो दण्डों में डीट देते थे, जिनमें परस्पर शास्त्रार्थ चलता था। कभी कभी दो गुरुकुल के छात्रों में भी परस्पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। प्रत्येक विद्वान् को भी मदैव शास्त्रार्थ के लिए प्रयत्न रहना पड़ता था। उसे कोई भी शास्त्रार्थ के लिए आह्वान कर सकता था, और उसे स्वागित विद्या का परिचय देना पड़ता था। आजकल के विद्यार्थी तो अपनी विद्वत्ता की साक्षी के रूप में विश्वविद्यालय का एक दम्भावेज घेन कर सकते हैं, पर वैदिक काल में प्रत्येक विद्वान् की विद्वत्ता उसकी जीभ पर नाचती थी। यह नहीं कह सकता कि देने दो कुछ सीखा था उसे भूल गया हूँ। उसे मदैव विद्या की कला कर्मा पड़ती थी।

इस काल में कलाओं का वर्णवर्दीन तो अस्पर होता था, पर कलाओं के समान उनके लिए गुरुकुल न थे। ऋषदे के काल में कलाविद्या पूर्णतः प्रचलित थी। महाशय दर्शित न हो, पर धीरे धीरे यह प्रथा उठ खड़ी। दशरथवर ने कलाविद्या का उद्भवन धेनादरक समान तथा उनका "विद्वत् कलु प्रारम्भ के पूर्व होने लगने" अवस्था कलाओं के लिए यह विधान था कि वे अपने माता-पिता, देवता-भगवत, राम तथा धर्म में विद्या प्राप्त करें। आजकल की कलाएँ धर अनेक दिनों के बाद रक्षा विद्याभजन करती थी, जैसे: गुरु, देवदत्त, मीरेई आदि। इनके धर्म-कलाओं में



काष्ठ-शिल्प, चिकित्सा तथा मलय-शास्त्र, धनुर्विद्या तथा युद्ध विद्या, ज्योतिष (गणित और फलित), भविष्य-कथन, ज्ञादू, गारुड़ी विद्या, गुप्त द्रव्योत्पादन, संगीत, नृत्य, चित्रकला और ग्राह्यत्व । †

## बौद्ध युग

**भूमिका.**—प्रसिद्ध दार्शनिक श्रीगणेशधर्म का कहना है : “बौद्ध धर्म नरा धर्म नहीं, अपितु हिन्दू धर्म का ही परिवर्तित रूप है ।” ‡ जिस समय भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था (५६३ ई० पू०), उस समय धार्मिक मुद्दों की विरोध आवश्यकता थी । वैदिक धर्म में ज्ञान-एव कर्म के समन्वय का सम्पूर्ण हास हो गया था । इसके बदले यह का आटमर आ गया था, जिसमें मान की आहुति देना आवश्यक था । ब्राह्मणों की प्रधानता छूट गयी थी और उनके सिवा अन्य जातियों से उत्पन्न संस्कार उठ गया था । ब्राह्मणों ने तो अपने फन्दे में शक्ति, वैश्य और शूद्र—सभी—को फँस रखा था । उनका उनके बनाये हुए नियमों तथा धार्मिक अन्ध-विश्वासों से तह आ गयी थी, और वहीं भी स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाना नहीं पड़ता था । ब्राह्मण पुकार-पुकार कर कह रहे थे कि नीच जातियों मोक्ष नहीं पा सकती, अतः एव उनकी आशालता पूर्ण रूप से मुग्ध गयी थी और उनकी आन्तरिक भावनाओं में उत्पत्ति की ज्योति प्रज्वलित नहीं रही थी ।

उत्पत्ति की यह ज्योति दिखायी एक क्षत्रिय राजकुमार—सौतम बुद्ध ने । जाति पौति का भेद-भाव उठाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार जन-भारतों द्वारा सभी अदस्ता, धर्म, जाति तथा स्त्री पुरुष में किया । जीवन का लक्ष्य दर्शाना गया निरांग या मोक्ष । इसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय दर्शाया गया—अहिंसा तथा परिश्रम । भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को दो भागों में विभाजित किया—भििक्षु अर्थात् पुरुष और भिक्षुणी अर्थात् स्त्री ।

**परवर्तन तथा उपसम्पदा.**—वैदिक शिक्षा की भाँति बौद्ध शिक्षा का प्रारम्भ सम्भारों से ही होता है । इनमें दो मुख्य थे—सम्पत्ति (सम्पत्ति) और उपसम्पत्ति । वैदिक धर्म में जो स्थान उत्पन्न संस्कार का है, बौद्ध धर्म में वही स्थान

† D. G. Apte, *Universities in Ancient India*, Baroda, Faculty of Education & Psychology, n. d., pp. 13-14

‡ S. R. Sankar, *Indian Education*, Vol. I, p. 30.



प्रवेश (एन्ट्रन्स) का है। इस सम्कार का शाब्दिक अर्थ 'बाहर आना' है। इस सम्कार के द्वारा एक अध्ययनीय बालक या छात्रिका अपने गृह से सदा के लिए अलग होकर एक सभ में प्रवेश करता था। एन्ट्रन्स का द्वार सभी वर्गों के लिए खुला था। अपनी गिर मुद्राकर तथा पीत वस्त्र पहन कर, विद्यार्थी नत मस्तक होकर मिश्र को प्रणाम करता था तथा प्रार्थना करता था कि ये उसे शिष्यरूप में स्वीकार करें। इसके स्वीकार होने पर, उसे अपने उपाध्याय के सम्मुख 'सग्राग्र्य' के तीन प्रश्नों की तीन बार उच्चारण कर कहना पड़ता था :

बुद्धं सग्राग्र्यं गच्छामि, धम्मं सग्राग्र्यं गच्छामि, सधं सग्राग्र्यं गच्छामि।

एन्ट्रन्स प्रविष्ट छात्र समस्त अध्ययन भूमि पर कहलाता था। श्रान्तार श्रामण साहस एवं शिक्षाध्ययन करने के परवाना, धीम वर्ग की आयु में अग्रत उपाध्याय सम्कार प्रदत्त करता था। इस सम्कार के परवाना यह मिश्र कहलाता था। उसे चार व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी : (१) वृक्ष के नीचे राग करना, (२) मित्रा वास में भिक्षात्त एकाग्रता करके भोजन करना, (३) मौन रह कर रात्रि से शरीर टैकना और (४) औपधि रूप में शौच संवर्धन करना। उपाध्याय से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक विद्यार्थी एन्ट्रन्स वर्ग की आयु में भानक होकर साहस्य जीवन धारण करते थे, पर बौद्ध विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर रात्र के स्थायी सदस्य बन जाने थे, और ऐसे जीवन नियन्त्रण में विधाने थे।

**वैदिक जीवन.**—वैदिक ब्रह्मचारियों की गार्ह अग्रत तथा मिश्रों का जीवन गृह एवं शांति, गरम तथा आहारा-सन्ध होता था। उनका भोजन अति सादा होता था, गरम रस हुआ करता था और शरीर पर अति धारण करने थे। उनका जीवन निर्धन रहता था, वे दिनरात एक अनुशासित होने थे तथा उनके अध्ययन, शिक्षा और भोजन से श्रान्त समाप्त निर्धारित रहता था। उन्हें अपने अध्ययन की विभिन्न संकल्प लेनी पड़ती थी, और रात्र को साध सुषमा में रहना पड़ता था।

**विहार.**—मिश्र तथा मिश्रों द्वारा रात्र एवं सन्ध्या में अलग-अलग विहार किया जाता था। विहार करती अग्रतों से दूर स्थित होता था। बौद्ध-सन्ध्या-विहार रात्रि-विहार करती के बड़े हुए रहने थे। वैदिक युद्धों के लिये इनकी शक्ति होती थी। वे प्रमाण होते थे, तथा प्रमाणों के लिये वे ५००-१,००० विहारों के लिये का प्रमाण रहता था। इनके विहार श्रान्त व रात्र एवं सन्ध्या रूप में होते थे।



बौद्ध शिक्षा-पद्धति का एक और विशेषता थी। वह थी संघीय प्रणाली। इसके अनुसार छोटे-मोटे वैयक्तिक विद्यालय एक बड़े समुदाय से सम्बन्धित रहते थे। इनके छात्रगण अपने उपाध्याय से वैयक्तिक शिक्षा अवश्य ग्रहण करते थे, तिस पर भी वे केन्द्रीय सभा के मदस्व होते थे तथा उसके समस्त सामूहिक व्यापारों में भाग ले सकते थे। इस प्रकार यह संघीय प्रणाली वर्तमान संबंधीय विश्वविद्यालयों से मिलती-जुलती है।

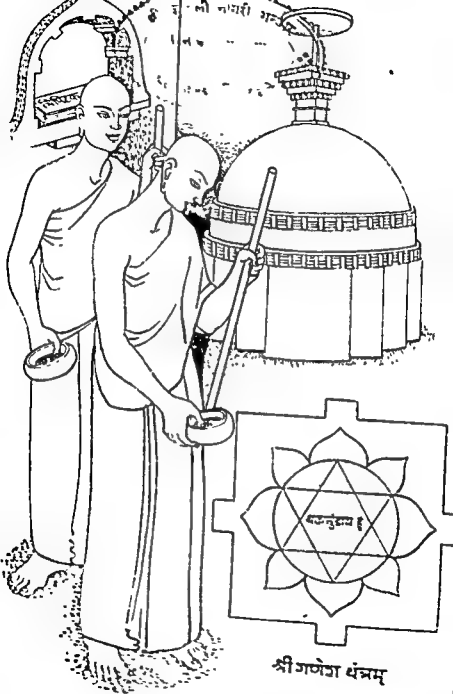
**पाठ्यक्रम.**—बौद्ध शिक्षा में दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था : (१) लौकिक और (२) धार्मिक। प्रथम पाठ्यक्रम का उद्देश्य था साधारण स्त्री-पुरुषों को उचित नागरिक बनाना तथा उन्हें अपने भावी जीवन के लिए तैयार करना। इस पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के कला-कौशल, शास्त्रार्थ, सारथीविद्या, धनुर्विद्या, मन्त्रविद्या, चित्रकारी, शरीरान, चिकित्साशास्त्र प्रभृति होते थे।

धार्मिक पाठ्यक्रम मिश्र तथा मिश्रणियों के लिए होता था। इसमें इन पाठ्य-विषयों का समावेश था : (१) बौद्ध धार्मिक साहित्य, जो नौ भागों में विभक्त था, (२) मठों तथा विहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान और (३) विहारों को दिखे गये दान की सम्पत्ति का शिक्षा-क्रिया तथा प्रबंध।

इसके अनिश्चित बौद्ध धर्म ने जन शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। बौद्ध उपाध्यायों का यह कर्तव्य था कि वे अपने परिश्रम में प्रयत्न करें। इसके द्वारा वे पुरुषों को धर्म की शिक्षा देते थे तथा उनकी शब्दाओं का समाधान करते थे। उपाध्याय के पीछे पीछे उनके शिष्यगण प्रयत्न सुनने श्रवते थे।

**अध्यापन-विधि.**—बौद्ध विहारों में साधारणतः प्रयत्न या व्याख्यान-शाला शिक्षा दी जाती थी। उपाध्याय एक मंच पर बैठते थे, और शिष्यगण उनके तीन ओर बैठकर मौनपूर्वक प्रयत्न सुनते थे। जहाँ कुछ शब्द होती थी, वहाँ शिष्याधीन उपाध्याय की आज्ञा लेकर प्रयत्न पूरते थे। प्रयत्न प्रणाली के अनिश्चित बौद्ध शिक्षाक्रम में व्याख्यान प्रणाली, प्रश्नोत्तर विधि तथा वाद-विवाद की रीति का प्रमुख स्थान था। इस बात में शिष्य का प्रयत्न हो गया था। सम्भवतः पुनराध्यास अध्यापन विधि भी कायम थी। इसके अनिश्चित, शिष्यगण आरम्भ में पाठ्य-पत्रों या दान-विनिर्माण भी शिक्षा करते थे। व्याख्यान तथा प्रश्न-निर्माण को भी मान्यता दी जाती थी।

**बौद्ध विश्वविद्यालय.**—बौद्ध शिक्षा में सबसे अधिक उल्लेखनीय बौद्ध विश्वविद्यालय : मगध (वैशाली), कपिली (गुप्तगढ़), अलेन्द्रिया (बंगाल), इत्यादि शिक्षा (पटना), विजयविहार, अलेन्द्रिया तथा प्रमद (बंगाल), इत्यादि। यहाँ शिक्षा के



होने से विद्यापीठों में विद्याभ्यास के लिये आने में और उन्हें यहाँ प्रविष्ट होने के लिये ठहरना पड़ता था। प्रवेश पाने के लिये परीक्षा का विधान बढा था। विद्यालयों के अन्तर्गत पुस्तकालय, छात्रावास तथा अनिवार्य शाला के लिये अनेक भवन थे। विद्यालय के दृश्य की मनमोहक गङ्गा-महागंगाओं ने अनेक गौरीजी (सिर पोपण) में देकर मुग्धता दी थी। नागपुर में प्राप्त यत्तोंकर्मा के लेखन में लिखा है :

अपने शुभ ऊँचे चैत्यों के दिग्ग-गमूहों में नागपुर नगरी बड़े-बड़े राजाओं की नगरियों की मानों हूँगी उड़ती है और इनके जिन ऊँचे प्रासादों एवं विहारों की पत्तियों में प्रसिद्ध धुन्धर विद्यालय नाम करते हैं, वे उस मुमेरु पर्वत-सी शोभावाली लगती हैं, जिनमें विद्याधर नाम करते हैं।

इन विश्वविद्यालयों का पाठ्य-क्रम सर्वाङ्गपूर्ण था तथा उसमें बौद्ध या ग्रीक महायान तथा हीनयान विषयों का समावेश था। कुछ विषय तो अनिवार्य थे, कुछ ऐच्छिक। प्रत्येक भिक्षु को महायान तथा अठारह सम्प्रदायों के ग्रन्थ का ज्ञान करना पड़ता था। व्यायाम तथा दैनिक चक्रक्रम अर्थात् टहलना भी उसके अनिवार्य था। इनके अतिरिक्त दर्शन, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, तात्त्विक दर्शन, वेद वेदाङ्ग, आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र, ध्याकरण, विधि (कानून), भाषा शास्त्र, इत्यादि भी पाठ्यक्रम में रखे गये थे। बौद्ध संस्थाएँ होते हुए भी, इन विश्वविद्यालयों में प्रजायिकता की घूँ न थी।

अन्तः—मुसलमानों के आक्रमण के कारण भारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ। से भिक्षु तो तलवार के घाट उतार दिये गये, और अनेक भारत के बाहर भाग गये। यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है। सन् १२३० ई० में बख्तियार खिलजी, दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचा। उसने उसे भूल से एक गद्द समझ लिया, और भिक्षुओं को सिपाही। कारण, विश्वविद्यालय के भवन के चारों ओर एक दीवार थी, और सब भिक्षुओं के शरीर पर पीत वस्त्र थे। वस्त्र, क्या था, भवन ध्वस्त हो गया और सिरमुँड़े भिक्षुओं का कल्लेआम हुआ। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय छः महीने निरन्तर जलता रहा।

उत्तम युग

भूमिका.—भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन प्रथम द्विजरी शताब्दी के में अर्थात् आठवीं शताब्दी ईस्वी के आरम्भ में हुआ था। पर वे इस देश में

महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद ने चलने लगे। जहाँ जहाँ यवन मेलाएँ पहुँचीं, वहाँ वहाँ उलेमा तथा इस्लाम के धर्म-प्रचारक पहुँच गये। जहाँ वे धर्म गये, वहाँ इस्लामी धर्म-शास्त्रों की शिक्षा देने लगे।

ईसा की तेरहवीं शताब्दी में, मङ्गोलों ने मध्य एशिया में लूट-मार मचा दी। इस कारण अनेक उलेमा वहाँ से भाग कर दिल्ली में आये। तथा उन्होंने बख्श के दरबार में शरण ली। ये विद्वान् बल्ख, बुखारा, समरकन्द, ग्यारीज़म में आये थे, जो मुस्लिम संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे। उस समय दिल्ली में इतने विद्वान् इकट्ठे हो गये थे कि इस्लामी धर्म-शास्त्रों का बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा किया गया था। इस प्रकार भारत में जो दिल्ली इस्लामी राज्य की राजधानी थी, वह मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा का केन्द्र बन गयी।

भारत में यवन-आधिपत्य प्रायः साढ़े पाँच सौ वर्षों तक रहा, अर्थात् बुध्दुहीन ऐबक के शासनोत्थान से तामी के युद्ध तक (१२०६-१७५७ ई०)। इस दीर्घकालीन आधिपत्य के फल-स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता विनाश रूप से प्रभावित हुई। साहित्य तथा ललित कलाओं का विकास हुआ, भारतीय भाषाओं की नया रूप निया तथा नवीन 'भक्ति-मार्ग' का जन्म हुआ। मुस्लिम शासन का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। प्रथमतः, एक नयी शिक्षा-प्रणाली की नींव इस देश में पड़ी। इस देश मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली बह सकती है। यह उन भारतीयों का शिष्य निर्मित हुई थी, जिन्होंने इस्लाम धर्म की दीक्षा ली थी। द्वितीयतः, यवन राजा का प्रभाव पूर्ववर्ती शिक्षा-प्रणाली पर पड़ा। इन दोनों विषयों की खोज अनेक दीर्घकों में की जायेगी।

**मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली.**—भारत में मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली का यही स्वरूप था, जो अन्य इस्लामी देशों में प्रचलित था। प्राथमिक शिक्षा मक़तबों में दी जाती थी। मक़तबों में मक़तब प्रदेह मस्जिद के साथ जुड़े रहते थे। वहीं-वहीं मक़तब और मस्जिद के पर अथवा अन्य स्थानों में लगते थे। मक़तबों का प्रारम्भिक बुरान पर ही केन्द्रित होता था। बुरान के साथ साथ बालकों को कुछ बग़ा, मक़तब पढ़ना, अरब के अक्षर पढ़ी जानेवाली हुआएँ हासिल भी मिलानी जाती थी। उन्हीं मक़तब में ही मक़तब रूप में मक़तब पढ़ने का अध्ययन करना जाता था।

मक़तब में बुरान "ताज़िन्" शीर्ष से पढ़ाना जाता था। इसके अन्तर्गत है कि बालों को मक़तब का नाम होने के पक्षार्थ दिखाने अथवा बालों को दिखाने के बुरान का पक्षार्थ है। बालों को मक़तबों को पढ़ने का अध्ययन करने के बुरान का पक्षार्थ है।

जाते थे। जब बाबरक वर्गमाला के सभी अक्षरों में परिचित हो जाते, तब उन्हें मुस्ताशरी वा ज्ञान कराया जाता था। अक्षर-ज्ञान का सम्पूर्ण अभ्यास हो जाने के बाद कुरान का तीसरा पाठ पढ़ाया जाता था, जिसमें छोटी-छोटी गूँथें हैं। कुरान को पढ़ाकर पढ़ लेने के बाद, विद्यार्थियों को फारसी का माध्याम ज्ञान करा दिया जाता था। किसी-किसी मद्रस में इरीम, कविता तथा नीनिगास भी पढ़ाया जाता था।

उच्च शिक्षा मद्रसों में दी जाती थी। भाग के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में मद्रसे थे। इनकी स्थापना बादशाहों, नवाबों तथा धनी अमीरों ने की थी। बड़े बड़े मद्रसों के माथ पुस्तकालय सलम रहते थे। कई एक संस्थान तो खास सादा विध्व-वेद्यालय थे, जहाँ कि छात्रगण दूर-दूर से विद्याध्ययन के लिए आते थे। मद्रसों का शिक्षा-काल १० से १२ वर्ष का रहता था। शिक्षा का माध्यम अरबी थी। वर्तमान वेद्यालयों के समान मद्रसों में कक्षा-प्रणाली नहीं होती थी। कक्षाओं का विभाजन पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होता था। पाठ्यपुस्तकें तीन प्रकार की होती थीं। पहली उद्दिष्ट पाठ्य पुस्तकें “मुख्तमरात” (ए० व० मुख्तमर) कहलाती थीं। दूसरी पाठ्य पुस्तकें मध्यम विस्तार वाली होती थीं। उन्हें “मुतवस्सतात” (ए० व० मुतवस्सत-मध्यम) कहते थे। तीसरी पाठ्यपुस्तकें “मुतव्वलात” (ए० व० मुतव्वल) नामक विस्तृत होती थीं। इस प्रकार सारा पाठ्यक्रम सेंकेन्द्रीय होता था।

पाठ्य-क्रम दो प्रकार के थे : (१) धार्मिक—इस्लामी धर्मग्रन्थ, इस्लामी इतिहास तथा कानून, और (२) सासारिक—अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, गणित, वेदान्त, भूगोल, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, यूनानी-चिकित्सा, कृषि, कानून, हिसाब, इत्यादि। यह आवश्यक न था कि प्रत्येक मद्रसा सब विषय पढ़ावे। कुछ मद्रसे किसी विशेष विषय या विषयों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ केन्द्रों की ख्याति देश भर में थी, जैसे : लाहोर और सियालकोट (गणित तथा ज्योतिष), रामपूर (तर्क एवं ज्योतिष), दिल्ली (कविता और संगीत) तथा लखनऊ (शिया-शिक्षा)। किसी-किसी मद्रसे में हिन्दू विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबंध रहता था, जहाँ कुरान के बदले वेदान्त तथा पातञ्जलि के योग-प्राप्य का अध्ययन कराया जाता था। कई एक मद्रसे तो केवल उत्तर-स्नातक शिक्षा ही देते थे। उदाहरण के लिए बादशाह अकबर की धाय माँ—माइम अंगा द्वारा स्थापित मद्रसा (१५६१ ई०) है। इस संस्था में केवल संगीत, चित्रकला, दर्शन तथा गणित की शिक्षा उत्तर-स्नातक स्तर पर दी जाती थी।

**पूर्ववर्ती शिक्षा-प्रणालियों का नया रूप.**—मुस्लिम शासन काल का प्रभाव बौद्ध तथा वैदिक शिक्षा-प्रणालियों पर भी पड़ा। चूँकि बौद्ध शिक्षा संस्था केन्द्रित

थी, इस कारण शिक्षा-केन्द्रों के मत्सनाश के साथ-साथ इस देश से बौद्ध शिक्षा-प्रणाली का भी लोप हो गया। इसके विपरीत वैदिक शिक्षा इस कारण अमिट रही कि यह शिक्षा सुद-केन्द्रित थी। इसके विद्यालय छोटे-मोटे थे, जिनकी छात्रसंख्या ३०-४० से अधिक नहीं और ये समूचे देश में फैले हुए थे। ये दो प्रकार के थे : (१) संस्कृत विद्यालय — इन्हें बङ्गाल में 'टोल' तथा पश्चिम भाग में 'पाठशाला' कहते थे। इनकी पढ़ाई बहुत ही ऊँचे ढँगे की थी। इन विद्यालयों में पाँच विषयों का अध्यापन होता था — तर्क, बानून्, मादित्य, ज्योतिष तथा व्याकरण। प्रत्येक विद्यालय अपना एक ही विषय पढ़ाना था। (२) प्राथमिक स्कूल — जो गाँव-गाँव में फैले हुए थे। ये दोनों प्रकार के विद्यालय उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मौजूद थे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह प्रणाली 'देशी शिक्षा' के नाम से प्रसिद्ध है।<sup>१</sup>

**शिक्षा और राज्य.**—वैदिक तथा बौद्ध युग में, शिक्षा का राज्य ने कोई सम्बन्ध न था, तथापि हिन्दू वृत्तपिण्ड शिक्षा-केन्द्रों तथा विद्वानों को पर्याप्त दान देते थे। मुसलमान-मुल्तानों तथा बादशाहों ने अनेक मकतब, मस्जिदें तथा पुस्तकालय खुलवाये, तथा उन्हेमा और मोर्धाहिमों को सरकारी खजाने में वजीफे दिये। पर पटानों के काल में शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था न थी। समुत्तः शिक्षा शासक की दृष्टि पर निर्भर रहती थी। इल्तुतमिश, इब्कि, बल्बन तथा फ़ीरोज़शाह शिक्षा में अमिदरि रखते थे। पर अलाउद्दीन, इल्हादीम खोदी आदि बादशाहों का विद्या में कोई प्रेम न था। आश्चर्य नहीं कि इसी कारण राज्य ने अपनी आत्म-स्था में लिखा है कि 'भारतीय शिक्षा गिरती हुई अवस्था में है।'<sup>२</sup>

मुग़लशा के सभी बादशाह विद्या प्रेमी थे। बादशाह अक्सर ने मुस्लिम शिक्षा को एक नयी दिशा देने की कोशिश की। सरकारी नौकरी के लिए मकतब परखी के ज्ञान की जरूरत थी, पर अनेक हिन्दू मकतब तथा मस्जिदों में अध्यापन करने में हिचकते थे। अक्सर ने पाठ्य क्रम में मुस्लिम विद्या तथा मकतबों और मस्जिदों में हिन्दुओं के पढ़ने दिखने की उचित व्यवस्था की, ताकि पढ़ने की हिचकिचाहट दूर हो और उन्हें अपनी सभ्यता का ज्ञान मिले।

इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों में एकता का सुवर्ण हुआ। इसी समय एक नवीन भाषा — उर्दू — भी पैदा हुई। हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों के अनुवाद होने से नवीन विचारों के बीजों का उद्भव हुआ, तथा पूर्वी मन का उद्भव हुआ। इस प्रकार हमें दोनो भारतीय तथा सार्वभौम सभ्यताओं के एक प्रभाव के का सम्मन्ध हो चला।

१. देविक चोखा अध्याय।

## ब्रिटिश युग

**भूमिका.**—इस युग के इतिहास को हम निम्नलिखित कालों में बाँट सकते हैं :  
 (१) प्रथम काल (सन् १७५७-१८१३ ई०)—इस अवधि में ईस्ट इंडिया कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही। उसने तटस्थता की नीति अपनायी। (२) द्वितीय काल (सन् १८१३-१८५७ ई०)—इस समय कम्पनी शिक्षा-समस्या पर विचार करती रही। उसने प्रयोगात्मक नीति अपनायी। (३) तृतीय काल (सन् १८५७-१९१९ ई०)—इस अवधि में केन्द्रीय सरकार पूरे देश की शिक्षा-नीति निर्धारित करती रही। (४) चतुर्थ काल (सन् १९१९-१९४७ ई०)—इस काल में प्रादेशिक स्वशासन शुरू हुआ। कारण, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों के हाथ में आ गयी।

**प्रथम काल (तटस्थ नीति).**—प्यासी के युद्ध ने अंग्रेजों के गले में विषम माला पहना दी, जिससे वे धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे। देश विजय करने पर भी गौगण प्रभुओं ने आरम्भ में विद्या के लिए कुछ न किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास न पैसा था और न अधिकार। भारत में अपना पाना मजबूत करने के लिए उसे दिन-रात युद्ध करना पड़ा। इस अवधि में कम्पनी ने शिक्षा के प्रति तटस्थ नीति अपनायी, और वह शिक्षा के प्रति उदासीन रही। कम्पनी के डाइरेक्टरों का कहना था कि शिक्षा-वित्तार के लिए शासक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसे किसी देश की प्रचलित शिक्षा विधि में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। इस नीति के लिए हम उन डाइरेक्टरों को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनके देश की यही राजनीति थी।

जिस समय गौगण महाप्रभुओं ने इस देश पर अपना अधिकार बनाया, उस समय हमारी देशी शिक्षा-पद्धति बहुत कुछ अस्तित्व में थी। यह अवश्य है कि अठारवीं सदी में सम्पूर्ण भारत में गड़बड़ी रहने के कारण देशी शिक्षा-पद्धति को गंवा घका पहुँचा था। इस शिक्षा की जौंच भारत के विभिन्न प्रदेशों में सन् १८२० से सन् १८३८ के बीच हुई थी।<sup>†</sup> तद्दीक्षाओं से पता चला कि भारत के गाँव-गाँव में प्राथमिक स्कूल तथा मस्जिदों से संलग्न मक़तब अवस्थित थे। उच्च शिक्षा के लिए बड़े-बड़े नगरों में 'कॉलेज' या 'पाठशालाएँ' (हिंदुओं के लिए) और मदरसे (मुसलमानों के लिए) मौजूद थे।

यद्यपि कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही, तथापि उसे अपने व्यावसायिक केन्द्रों के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कई स्कूल खोलने ही पड़े। कम्पनी के

† देखिए पीया अध्याय।

कई अफसरों ने शिक्षा के प्रति दिलचस्पी दिलवायी, और उन्होंने अपने व्यय से दो-एक विद्यालय स्थापित भी किये, जिन्हें बाद में कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया। पहली संस्था 'कलकत्ता मद्रास' सन् १७८१ में स्थापित हुई थी। उसके ग्यापक भारत के सर्व प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य कम्पनी की नौकरी के लिए सुमेलमान नवयुवकों को उचित शिक्षा देना था। दूसरा विद्यालय था ब्रानरम सम्मूह कालेज (सन् १७९१ ई०)। इसके प्रतिष्ठाता थे ब्रानरम के तत्कालीन रेसीडेन्ट जनोथान डन्कन। यह संस्था हिन्दुओं के लिए खोली गयी थी। कम्पनी के राज्य का विस्तार हो रहा था, पर अंग्रेज अफसर इस देश के कालूत बायरी से नितान्त अपरिचित थे। उनकी सहायता के लिए भारतीय नायकों की विशेष आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से ऐसे विद्यालय खोले गये।

यद्यपि कम्पनी व्यय घुस रही, तथापि उनमें भारत में ईसाई मण्डलों तथा धर्म-प्रचारकों को स्कूल तथा कालेज खोलने दिये। यद्यपि उन शिक्षा-संस्था सेनाओं का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार ही प्रधान था, तो भी उन लोगों ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और शिक्षा-चक्र में एक जान फूँक दी। उन्होंने इस देश में छापाखाने भी खोले, जिसमें छपी हुई पुस्तकों का प्रचार बढ़ा।

अन्ततः कम्पनी तटस्थता की नीति अतिरिक्त समय तक स्थिर न रख सकी। इंग्लैंड में पार्लियामेंट के कई महत्त्व प्रयत्न कर रहे थे कि कम्पनी भारत में शिक्षा-विस्तार के लिए कुछ न-कुछ करे। उनकी प्रयत्नों के फल-स्वरूप सन् १८१३ ई० का नवीन भारत अधिनियम में एक धारा बढ़ा दी गयी थी कि "ईश्ट इण्डिया कम्पनी को इंग्लैंडसरों का यह भी वर्तव्य होगा कि वे भारत में कम-से-कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करें।" पाठक समझ सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए शिक्षा व्यय की यह अल्प राशि 'ऊँट के मूँद में खींग' की भाँति थी। कुछ भी हो, सत्य की दृष्टि में भ्रष्ट ही यह राशि महसूस होनी थी, तथापि इस कार्यकारी का मुख्यकर्म बही और ही है। सन् १८१३ ई० के आदेश ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह मानने के लिए बाध्य किया कि "शिक्षा का सरकारी राज्य पर अधिकार है"। यह बात बार्नर अभी तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किन्तु उसे इस आदेश से हार माननी पड़ी और उसे चुबना ही पड़ा।

द्वितीय काल (प्रदेश-नव दशक)।—इस भाग में कम्पनी ने प्रदेश-नव दशक की अन्तर्गत। ऐसे ही बारी के कार्य पर यह स्थिर न कर सकी कि शिक्षा के लिए क्या किया जावे। उसके सामने दो समस्याएँ थी : (१) भारत के अन्तर्गत शिक्षा



फैलायी जावे या उच्च शिक्षा का प्रचार उच्च श्रेणी में किया जावे। (२) प्राच्य या पाश्चात्य विद्या का प्रचार किया जावे। (३) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होवे या संस्कृत और फारसी। (४) शिक्षा का प्रचार देशी विद्यालयों या नये स्कूलों और कालेजों द्वारा किया जावे।

इन समस्याओं के रहते हुए भी सन् १८१३ ई० के आदेशान्तर्गत धारा को क्रियान्वित करने के लिए कम्पनी इस कार्य में मग्न रही। उसे इस समय इस दिशा में सक्रियता दिखाने के लिए अवकाश भी तो नहीं था। सन् १८१३ से १८२३ ई० तक कम्पनी को गुरुओं, पिण्डारियों तथा मराठों का सामना करना पड़ा। लड़ाई से पुरमत मिलने पर कम्पनी ने सन् १८२३ में शिक्षा के लिए प्रधान शिक्षा-समिति (जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) मुकर्रर की। इस समिति को इस देश के अनुकूल शिक्षा-प्रबंध निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया, और खर्च के लिए तयकपित आदेशानुसार एक लाख रुपये वार्षिक दिया जाने लगा।

प्रधान समिति में दस सदस्य थे। शुरू-शुरू में सब-के-सब अंग्रेज थे, जो प्राच्यवादी थे। इस कारण पहिले पहल इस समिति ने प्राच्य विद्या फैलाने का किया, लेकिन धीरे-धीरे पौसा पलट गया। शिक्षा-समिति के कुछ सदस्य बदल। सन् १८३१ ई० में इसके आधे सेवर प्राच्यवादी थे और आधे आगलवा दोनों दलों में झगड़ा लड़ा हुआ। मतभेद इतना बढ़ा कि कुछ भी कामकाज कठिन हो गया। दोनों दलों ने स्वीकार किया कि अर्थाभाव के कारण जन-शिक्षा की ध्यान देना असम्भव है। इसलिए दोनों दल सहमत हुए कि इस थोड़ीसी रकम के पहले उन्नत समाज में उच्च शिक्षा का प्रचार किया जावे। उन्होंने सोचा कि ये धीरे-धीरे अपनी मातृभाषा में उपयोगी पुस्तकें लिखेंगे और जनता में शिक्षा का फैलेंगे। इस प्रकार शिक्षा छनते हुए विशिष्ट समाज से आरम्भ होकर जनता की फैलेगी। यह सिद्धान्त भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा छनने के सिद्ध (फिल्ट्रेशन थ्योरी) के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में दोनों दलों में यह विवाद खड़ा कि यह उच्च शिक्षा किस देश की विद्या हो (भारत या युरोप की), तथा शिक्षा माध्यम क्या हो—अंग्रेजी या संस्कृत और फारसी? प्राच्यवादियों का मत था कि विद्या इस देश की हो तथा शिक्षा का माध्यम इस देश की सांस्कृतिक भाषा हो; अंग्लवादियों का कथन था कि प्राच्यविद्या सड गयी है, अतएव इस देश में पाश्चात्य का प्रचार अंग्रेजी के द्वारा किया जाय।

इस विवाद ने उग्र रूप धारण किया, और सन् १८३४ ई० में दोनों दलों ने सरकार के सम्मुख अपना अपना अभिमत व्यक्त करते हुए वक्तव्य भेजे। इसी साल प्रोफेड्र अँग्रेजी विद्वान् लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होकर यहाँ आये। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक ने उन्हें शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और उन्हें अधिकार दिया कि आप इस विषय की जाँच करके अपना मत व्यक्त करें। फलतः २ फरवरी, सन् १८३५ को एक लेख-पत्र द्वारा मैकाले ने अपना मत दिया।

इस लेख-पत्र-द्वारा मैकाले ने यह प्रतिपादित किया था कि सरकार बिना रोक टोक चाहे जिस प्रकार शिक्षा की रकम खर्च कर सकती है, पर हमें इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह सब कैसे हो सकता है? इस छोटी-सी रकम के द्वारा जन-शिक्षा असम्भव है; इसलिए हमें कुछ इने-गिने मनुष्यों में उच्च विद्या का प्रचार करना पड़ेगा, जो भारतीय लोक-भाषा, संस्कृत या फारसी से समर्थ नहीं हैं। कारण, इन भाषाओं में कोई दम नहीं है और न इनका साहित्य-भण्डार यूरोपीय चुनी हुई पुस्तकों की एक आलमारी के मुकाबिले ठहर ही सकता है। हम कारण हमें पाश्चात्य विद्या का प्रचार अँग्रेजी भाषा द्वारा करना पड़ेगा। यह भाषा सारे मसार में प्रचलित है, इसके ज्ञान का स्वज्ञाना असीम है और भारतवासी इसे सीखने के लिए उत्सुक हैं। मैकाले ने पुनः घोषित किया कि “हमें निर्माण करना है हम देश में ऐसे वर्ग का, जो रङ्ग और रक्त में भेद ही भारतीय हो, परन्तु खान-पान, गहन मदन, आचार-विचार तथा बुद्धि में पूरे अँग्रेज हों।”†

यह प्रसिद्ध लेख-पत्र बेंटिंक के सामने पेश किया गया। वे तो इसी की ताक में बैठे थे। उनकी इच्छा इस देश में अँग्रेजी भाषा के प्रचार की थी ही, क्योंकि राज्ज कार्प के लिए उन्हें अल्प-वैतनभोगी अँग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय नौकरों की जरूरत थी। इस, मैकाले के लेख-पत्र के मिलने ही, उन्होंने झट उम पर लिख दिया, “मे सम्पूर्ण रूप से सहमत हूँ।”

७ मार्च, सन् १८३५ ई० को एक सरकारी सूचना निकली, जिसका मार अर्थ यह था कि भारत में पाश्चात्य विद्या का प्रचार अँग्रेजी भाषा-द्वारा किया जावे। प्रधान शिक्षा-समिति का हुक्म दिया गया, “प्राप्य शिक्षा के लिए जो कुछ किया जा चुका है, वह जैसा-सा तैयार करना रहेगा; परन्तु भविष्य में सम्पूर्ण अनुदान अँग्रेजी भाषा-द्वारा ही ज्ञानेशाली अँग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय किया जायगा।”

इस ऐलान का असर आज भी हमारी शिक्षा पर है। अंग्रेजी शिक्षा फैली, और स्कूल फैली। पर शिक्षा उच्च श्रेणी में ही सीमित रही, जनता में न फैली। फल-स्वरूप आज ८० प्रति शत भारतवासी अपढ़ हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति और सांस्कृतिक भाषाएँ भूल बैठे। हम अंग्रेजी के रङ्ग में रँग गये। हमें पाश्चात्य कला और विज्ञान का लाभ अवश्य मिला और यहाँ पाश्चात्य ढङ्ग के स्कूल तथा कॉलेज भी खोले गये, पर पर्याप्त रूप में नहीं। हमारे देश की परम्परागत शिक्षा-पद्धति नष्ट-भष्ट हो गयी। हमारे देशी स्कूल, टोल, पाठशालाएँ, मकतब तथा मदरसे कुचल दिये गये। माना कि वे पुराने ढाँचे में ढले हुए थे, तथापि उनमें सशोधन या सुधार किया जा सकता था।

आज मैकाले साहब के लेख-पत्र की नुकताचीनी करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी एक ऐसा युग था, जिसके लिए हम मैकाले साहब को विशेष दोषी नहीं ठहरा सकते। अठारहवीं शताब्दी की स्वावसायिक क्रान्ति और साम्राज्यवृद्धि ने प्रत्येक अंग्रेज का सिर फेर दिया था। यह यही सोचता था कि न अंग्रेजी भाषा के समान कोई दूसरी भाषा है और न किसी राष्ट्र की उन्नति अंग्रेजी के बिना हो ही सकती है। मैकाले इस युग का एक चिन्तनशील मानव था। पर हमें यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान से हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। आधुनिक काल में, ज्ञान का विनाश सांस्कृतिक भाषाओं-द्वारा असम्भव है।

सन् १८३५ ई० के बाद दूसरी मजिस्ट्रि आती है सन् १८५४ ई० में। इस वर्ष कम्पनी के बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स बुड ने भारतीय शिक्षा पर एक सरकारी पत्र प्रकाशित किया था। इसका नाम 'बुड का घोषणापत्र' (बुड्स डिमण्ड) पड़ गया है। प्रथमतः इस विद्वां ने शिक्षा के ये सिद्धान्त इस देश के लिए घोषित किये:

यह गम्य है कि भारत की जनता अपनी सांस्कृतिक भाषाओं के बिना काम नहीं चला सकती है, तिस पर भी इस देश में शिक्षाप्रमाण के बिना सुयोग के समुन्नत कला-मौशल, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य—संशोधन में सुयोग्य ज्ञान—हो ॥

इस घोषणा ने जन-शिक्षा पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के माध्यम पर, हम दस्तावेज ने जोर दिया, "भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी और मातृ भाषा—दोनों का विशेष स्थान है; अंग्रेजी, उच्च शिक्षा के लिए और मातृभाषा, जन-शिक्षा के लिए।"।

† *Macaula Despatch*, para 7

‡ *I. I. I.*, para 11

इस घोषणा-पत्र के फल-स्वरूप प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा-विभाग संगठित हुए। लन्डन विश्वविद्यालय के आदर्श पर चम्पई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, राजकीय प्रशासन-विभाग तथा प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये, प्राथमिक एवं स्त्रीशिक्षा पर जोर दिया गया तथा अन्तः-दाग चलाये हुए विद्यालयों की महायन्ता के लिए आर्थिक अनुदान-पद्धति (ग्राण्ट-इन-एड सिस्टम) का प्रावधान प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार वर्तमान शिक्षाप्रणाली को इस आशा-पत्र ने ही संचालित किया। इसी कारण यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा का महा विधान (मेम्ब्रा-कार्या) गिना जाता है।

**तृतीय काल (केन्द्रीय निर्धारित नीति).—**सन् १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य-युद्ध के फल स्वरूप, भारत के शासन की जागहोर ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से निकलकर अंग्रेज नरेशों के हाथ में आ गयी। इस दीर्घ काल में, अर्थात् सन् १९१९ तक, भारत सरकार सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति नियन्त्रित करती रही। केन्द्रीय सरकार ने तीन महत्व-पूर्ण आयोग या समीक्षण (ईटर, १९०२ की विश्वविद्यालय समिति तथा मैडलर) नियुक्त किये। दो शिक्षा-नीति (१९०४ और १९१३) घोषित की, प्रांतीय सरकारों को अनेक प्रसिद्धि-पत्र भेजे, तथा शिक्षा-सम्बन्धी कई सम्मेलन बुलाये। इन सबका जिक्र अगले अध्यायों में क्या स्थान दिया जावेगा। इस प्रकार भारत सरकार देश की शिक्षा नीति संचालित करती रही।

इस समय का विनोद उल्लेखयोग्य विषय है राष्ट्रीय जागरण। इसी काल में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और बंग-भंग का आन्दोलन बढ़ा हुआ। इन सब घटनाओं की ध्वनि शिक्षा पर भी लगी। लार्ड कर्जन की विश्वविद्यालय नीति का तीव्र प्रतिवाद हुआ, बंग-भंग आन्दोलन ने विद्यार्थियों को राजनैतिक क्षेत्र में खींचा तथा प्राविधिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।

श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य करने की चेष्टा की। इस प्रयत्न में वे असफल हुए, किन्तु उनकी चेष्टा व्यर्थ न हुई। देश में स्वाधीनता का आन्दोलन बढ़ा और इसीके फल-स्वरूप भारत सरकार का सन् १९१९ का नियम निम्नलिखित।

**चतुर्थ काल (प्रांतीय स्वशासन).—**प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के समय, अगस्त १९१७ ई० में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तत्कालीन भारत-सचिव माण्टेग्मू ने घोषणा की, “शासन के हर एक क्षेत्र में भारतवासियों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय।” इस घोषणा के पश्चात् माण्टेग्मू मार्व इस देश में आये। उन्होंने और तत्कालीन वाइसरॉय चेम्सफोर्ट ने मिलकर भारत में लागू करने के लिए राजनीतिक सुधारों की एक योजना तैयार की। इस योजना के आधार पर सन् १९१९ में इंग्लैंड



लिए समितियाँ गठित हुई, जैसे : प्राविधिक शिक्षा, समाज शिक्षा, उच्च ग्राम-शिक्षा, भाषा, इत्यादि। इन आयोगों एवं समितियों के अभिप्रायों के अनुसार बहुत कुछ काम भी हुआ।

पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति स्वाधीन भारत का सर्वाधिक उल्लेखनीय कदम है। इनका प्रधान उद्देश्य देश में विकास कार्य आरम्भ करना है, जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए नये अवसर प्रदान किये जा सकें। इन योजनाओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-५६ ई०) में १६९ करोड़ रुपये खर्च हुए, और द्वितीय योजना (१९५६-६१ ई०) में ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित हैं। दोनों योजनाओं के विभिन्न अंशों पर होनेवाले व्यय का आवण्टन नीचे दिया गया है :

### तालिका १

प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में  
शिक्षा-व्यय का आवण्टन (करोड़ रुपये)

विषय	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
प्राथमिक शिक्षा ... ..	९३	८९
माध्यमिक शिक्षा ... ..	२२	५१
विश्वविद्यालयीय शिक्षा ... ..	१५	५७
प्राविधिक शिक्षा ... ..	२३	४८
समाज शिक्षा ... ..	५	५
प्रशासन तथा विविध ... ..	११	५७
योग.....	१६९	३०७

सन् १९५५ ई० में द्वितीय योजना की प्राथमिक रूपरेखा की आलोचना के समय, शिक्षा के निम्न १०८ अरब रुपये की माँग थी। संशोधित रकम घटने-घटने ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित हुई। इस व्यय में से ९५ करोड़ रुपये केन्द्र तथा २१२ करोड़ रुपये राज्य सरकारें करेंगी। अगले पन्ने की तालिका में प्रथम योजना की सरकारों तथा द्वितीय योजना के राज्य दिखाये गये हैं।

## तालिका २ +

प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य

कार्य	१९५५-५६	१९६०-६१
६-११ बयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस बयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती ... ..	५१.०	६२.७
११-१४ बयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस बयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती ... ..	१८.२	२२.५
१४-१७ बयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस बयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती ... ..	८.४	११.७
प्रारम्भिक तथा अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	२,७८,७६८	३,२६,८००
अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	४२,९४१	६४,९१०
मिडिल तथा प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	२१,७३०	२२,७२५
प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	४,८४२	४,५७१
हाई तथा उच्च हाईस्कूलों की संख्या ..	१०,७३८	१२,१२५
हाईस्कूल से परिवर्तित उच्च हाईस्कूलों की संख्या... ..	४७	१,१९७
बहुदेवीय स्कूलों की संख्या ..	३६७	१,१८७
विश्वविद्यालयों की संख्या ... ..	३२	३८
इंजीनियरिंग डिप्लोमा-संस्थानों की संख्या ..	४७	५४
“ डिप्लोमा “ “ “ ..	८८	१०४
“ डिप्लोमा छात्रों की संख्या ..	३,३९५	५,४८०
“ डिप्लोमा प्रशिक्षण “ “ “ ..	३,८११	८,०००
टेक्नोलॉजी डिप्लोमा संस्थानों की संख्या ..	२५	२८
“ डिप्लोमा “ “ “ ..	३६	१७
“ डिप्लोमा छात्रों की संख्या ..	७००	८००
“ डिप्लोमा प्रशिक्षण “ “ “ ..	४३०	५८०

मूल्य पर आधारित योजना (१९६१-६६) की प्राथमिक परीक्षण की आवश्यकता है। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य यह है कि मूल्य पर आधारित योजना के

अन्त तक ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे अनिवार्य शिक्षा-योजना के अन्तर्गत आ जावें तथा लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जावे। इस रूप-रेखा में यह भी सिफारिश की गयी है कि कम-से-कम ५० प्रति शत वर्तमान हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलने की व्यवस्था की जाय तथा गवर्न-मन्त्रालय द्वारा वार्षिक स्कूलों की स्थापना का अलग कार्यक्रम शामिल किया जाय।

भारत को म्याचीन हुए बारह वर्ष हुए। इस अरसे में शिक्षा काफी बढ़ी। आज (१९५७) हमारे देश में २,८७,३१८ प्राथमिक शालाएँ, ३५,८३८ माध्यमिक स्कूल, ७७१ आर्ट्स तथा साइन्स कॉलेज, ४०४ व्यावसाय-सम्बन्धी कॉलेज तथा ३,२८३ व्यावसायिक स्कूल हैं।<sup>†</sup> सन् १९४८ के वर्ष में इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः १,४०,७९४ (प्राथमिक), १२,८९९ (माध्यमिक), २९५ (आर्ट्स तथा साइन्स कॉलेज), १३१ (व्यावसायिक कॉलेज) और १,३९१ (व्यावसायिक स्कूल) थी।<sup>‡</sup> इसी अरसे में छात्र-संख्या भी प्रायः तिगुनी हो गयी।

यह शिक्षा-विस्तार कुछ कम नहीं है, पर यदि हम सब कदमों से कच्चा लगाकर काम करते तो सम्भवतः प्रगति और भी अधिक होती। हाल ही में चीन देश से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है 'China's Big Leap Forward'। इससे पता चलता है कि चीन में ८ वर्ष के अरसे में शिक्षा-संस्थाओं की छात्र-संख्या कितनी बढ़ी। प्राथमिक शालाएँ २,४०,००० से ६,४०,०००, माध्यमिक शालाएँ १० लाख से ६० लाख, व्यावसाय-सम्बन्धी स्कूल साठे तीन लाख से ७,८०,००० तथा विश्वविद्यालय और कॉलेज १,५५,००० से ४,४५,००० की संख्या में बढ़े। इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की संख्या तो पचगुनी होकर १,६३,००० तक जा पहुँची। सरकार तथा जनता के पारस्परिक सहयोग के कारण ही यह विस्तार वहाँ हो सका।

आज भारत खचेत हो उठा है। चागे ओर से शिक्षा-मुफार की पुकार मची हुई है। लोग अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा के अह्न प्रत्यह्न में एक नवीन जीवन के प्रादुर्भाव की आवश्यकता है। प्रशासन-व्यवस्था, शैक्षणिक रूप-रेखा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा स्त्री शिक्षा पर नये नये विचार हो रहे हैं। भारत तथा शिक्षा के माध्यम की नयी समझदार देश के सामने उपस्थित है। इसीके फलस्वरूप हमारे शिक्षा क्षेत्र में नयी नयी विचार धाराएँ बहने लगी हैं, जैसे : बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय प्रयोग शालाएँ तथा दिशान-मन्दिर, राष्ट्रीय तथा महानगर क्षेत्र शिक्षार्थी हल, इत्यादि। इन महान प्रयत्नों पर हम पुस्तक के अगले अध्यायों में विचार किया जाएगा।

† भारत, १९५७, पृष्ठ ७९।

‡ *Seven Years of Freedom* pp 34-47.



## दूसरा अध्याय

### शिक्षा-व्यवस्था

#### भारत के राज्य

जब १५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वाधीन हुआ तब भारत में नौ अतिरिक्त ५४८ रियासतें थीं। भारत के उपप्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया, जिससे ये बहुमूल्य भारत के आन्तरिक भाग बन गये, जिस तरह कि अन्य राज्य इसके अङ्ग हैं। सारे भारत में प्रजातन्त्र राज्य प्रस्थापित हुआ। १ नवम्बर, १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें देशी राज्यों का घटक राज्यों के रूप में नवनिर्मित राज्यों में विलय हुआ। आज भारत इन चौदह नवीन राज्यों का संघटित रूप — राष्ट्र-संघ — है। राज्यों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अधोलिखित तालिका में प्रदर्शित है।

#### तालिका ३

#### भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जन-संख्या†

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन-संख्या
असम	८५,०६२	९०,४३,०००
आन्ध्रप्रदेश	१,०५,६७७	३,१२,६०,०००
उड़ीसा	६०,२५०	१,४६,४५,०००
उत्तरप्रदेश	१,१३,४२२	६,३२,१५,०००
केरल	१५,००६	१,३५,४९,०००
जम्मू और कश्मीर	८५,८६१	४०,१०,०००
पंजाब	४७,०६२	१,६१,३४,०००
पश्चिम बङ्गाल	३३,९२७	२,६३,०२,०००
बिहार	९०,६६८	४,८२,६५,०००
छत्तीसगढ़	६७,०७१	३,८७,८३,०००
मद्रास	५०,१३८	२,९९,७४,०००
मध्यप्रदेश	१,७१,२५०	२,६०,७३,०००
मैसूर	७४,८६१	१,९०,०१,०००
राजस्थान	१,३२,१४८	१,५९,७०,०००

इन राज्यों के सिवा भारत में छः संघीय क्षेत्र हैं, अर्थात् (१) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, (२) दिल्ली, (३) हिमाचल प्रदेश, (४) लका द्वीप, मिनिक्वा तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह, (५) मणिपूर और (६) त्रिपुरा।

भारत पृथ्वी का एक छोटा-सा स्वरूप है, जिसका क्षेत्रफल १२,५९,७६५ वर्ग मील है। ससार के सबसे अधिक जन-संख्यावाले देशों में इस देश का स्थान दूसरा है। १९५१ की जन-गणना के अनुसार, इस देश की कुल जन-संख्या ३६,६८,७९,३४९ थी, जिसमें १८,३३,०८,७३३ पुरुष तथा १७,३५,२२,८३१ स्त्रियाँ हैं। औसतन १,००० पुरुष पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि देश की एकत्रित जन-संख्या में से १७-३ प्रतिशत लोग शहरों में तथा शेष गाँवों में रहते हैं। इस जन-गणना के अनुसार भारत में ५,९१,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४९,८१७ महिलाएँ थी; अर्थात् सम्पूर्ण देश की साक्षरता थी : १६-६१ प्रतिशत — २४-८७ (पुरुष) तथा ७-८७ (स्त्रियाँ)।

भारत में विभिन्न रूप-रङ्गोंवाले तथा अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं। १९५१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें ७०२ भारतीय भाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक के मापियों की संख्या एक लाख से कम है, तथा ६३ गैर भारतीय भाषाएँ हैं। ९१ प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी-न-किसी एक भाषा को बोलती है।

## शिक्षा-प्रशासन

### पूर्व-शिक्षा

सन् १८५५ ई० तक इस देश में शिक्षा-प्रशासन मुख्यस्थित न था। कुछ के घोषणा-पत्र की विप्लवियों के कारण, प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग कायम हुए। इनके साथ-साथ समूचे देश की शिक्षा-नीति भारत सरकार निरूपित करने लगी। पर केन्द्र में शिक्षा शासन के लिए कोई राजकीय विभाग स्थापित न हुआ। कुछ काल तक शिक्षा की व्यवस्था यह-विभाग की शिक्षा-शाखा करती रही, पर भारत सरकार अनुभव कर रही थी कि पूरे देश की शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक अफसर की आवश्यकता है। इस अभाव की पूर्ति लार्ड कर्जन ने की। सन् १९०१ ई० में उन्होंने पूरे देश के लिए प्रधान शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर जनरल ऑफ़ एजुकेशन) पद की सृष्टि यह-विभाग के मातहत की।

↑ देखिए चौथा अध्याय।

नौ वर्षों तक इसी प्रकार ही काम चलता रहा। सन् १९१० ई० में वाइसरॉय की कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों की संख्या एक और बढ़ा दी गयी। इस सदस्य की शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गयी, पर प्रधान शिक्षा-संचालक का पद उठा दिया गया। पाँच वर्ष बाद 'एज्यूकेशन कमिश्नर' नामक एक नये अफसर की नियुक्ति हुई। उसका काम वही रहा जो प्रधान शिक्षा-संचालक का था। इसी साल शिक्षा-सूचना-कार्यालय (ब्यूरो ऑफ एज्यूकेशन) भी खोला गया। भारत सरकार की वार्षिक तथा पंचवार्षिक रिपोर्टों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त, यह दफ्तर शिक्षा-सम्बन्धी अनेक साहित्य निकालता रहता था। सन् १९०२-१८ की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा प्रान्तीय सरकारों को काफी रुपये अनुदान में दिये।

भारत सरकार के सन् १९१९ के कायदे के अनुसार, शिक्षा की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार के हाथ से निकल कर प्रान्तीय सरकार के हाथ आ गयी। पर इस प्रान्तीय स्वशासन के कारण प्रान्तीय सरकारों का भारत सरकार से एकलन होने के सिवा, आपसी पृथकरण भी हुआ। इस पृथक्वादी नीति के फल-स्वरूप पैसा तथा परिश्रम बहुत कुछ व्यर्थ जाने लगा। कारण, न प्रान्तीय सरकारें आपस के कार्य-कलापों का लाभ उठा सकती थीं और न केन्द्रीय सरकार पूरे देश के लिये कोई शिक्षा-नीति निर्धारित कर सकती थी। इस प्रकार सभी अनुभव करने लगे कि संपूर्ण देश की शिक्षा-नीति में एकसूत्रता लाने के लिए, एक प्रतिष्ठान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान बन्द हो गया। फलस्वरूप, शिक्षा की नवीन योजनाएँ विधिल पड़ने लगीं।

इस कारण सन् १९२१ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार मण्डल (सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन) की स्थापना हुई। पर केवल दो वर्ष बाद, इस मण्डल का गायन हुआ। कारण, सलाह के नाम पैसा न था। इस मिनवपना के फलस्वरूप शिक्षा-सूचना-कार्यालय भी उठा दिया गया, तथा शिक्षा विभाग अन्य सरकारी मुरकमों अर्थात् स्वास्थ्य, गन्ध-कर और कृषि के साथ जोड़ दिया गया। आर्थिक स्थिति सुधरने पर तथा हार्टग मनिनि की सिफारिशों के कारण, सन् १९३५ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मण्डल तथा इसके दो साल बाद शिक्षा-सूचना-कार्यालय पुनः स्थापित हुए।

सन् १९४५ ई० में, भारत सरकार ने अपना एक स्वतंत्र शिक्षा-विभाग गीया। दो वर्ष बाद यह विभाग मन्त्रालय में बढ़ा दिया गया। सन् १९५७ में इस मन्त्रालय को

वैज्ञानिक शोध का कार्य सँपा गया और इसका नाम पड़ा 'शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय'। लेकिन एक बड़े बाद, यह मन्त्रालय दो भागों में विभक्त हुआ : (१) शिक्षा और (२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति।

यह हमारे देश के शिक्षा-शासन के विकास की रूप-रेखा हुई। इस शासन की जागहोर तीन स्वतन्त्र अधिकारियों के अधीन है : (१) केन्द्रीय सरकार, (२) राज्य सरकार और (३) स्वायत्त शासन। इनके कार्यक्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

### केन्द्रीय सरकार

**शिक्षा-मन्त्रालय.**—शिक्षा-मन्त्रालय, शिक्षा-मन्त्री की अधीनता में है। सन् १९५८ तक शिक्षा-मन्त्री मन्त्री-मण्डल के सदस्य रहे, पर अब वे केवल राज्य-मन्त्री ही हैं। मन्त्रालय के मुख्य दो कर्तव्य हैं : (१) देश की शिक्षा-नीति संयोजित करना और (२) यथा सम्भव-मित्र मित्र राज्यों की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता रखना।

मन्त्रालय के सब से प्रधान कर्मचारी शिक्षा-परामर्श-दाता (एज्युकेशन एडवाइजर) होते हैं। ये भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के सचिव का काम करते हैं, तथापि इनकी सबसे बड़ी जवाबदारी यह है कि ये शिक्षा-मन्त्री को पूरे देश की शिक्षा-नीति-तथा-शासन-के विषय में उचित परामर्श दें। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय निम्नलिखित आठ संविभागों में विभक्त है :

- (१) प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा,
- (२) माध्यमिक शिक्षा,
- (३) उच्च शिक्षा तथा यूनेस्को,
- (४) हिन्दी,
- (५) सामाजिक शिक्षा तथा समाज-कल्याण,
- (६) व्यायाम तथा मनोरंजन,
- (७) छात्र-वृत्ति तथा
- (८) प्रशासन।†

# केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय



विभाग

आधिकार क्षेत्र

शिक्षामन्त्री

शिक्षा  
परामर्शदाना

सलाहकारी परिषद

केन्द्रीय शिक्षा  
सलाहकार मण्डल

विश्वविद्यालय  
अनुदान आयोग

अखिल भारतीय  
माध्यमिक  
शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय  
प्रारम्भिक  
शिक्षा परिषद

ग्रामीण उच्चतर  
शिक्षा समिति

राष्ट्रीय  
स्त्री-शिक्षा  
परिषद

अन्तर्राष्ट्रीय  
सम्पर्क

संघीय क्षेत्र

शिक्षा-सूचना  
कार्यालय

विदेशी दफ्तरे

केन्द्रीय  
विश्वविद्यालय

पब्लिक स्कूल

अखिल भारतीय  
शिक्षा-संस्थाएँ

प्रारम्भिक तथा  
बुनियादी शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

उच्च शिक्षा  
तथा युनेस्को

हिन्दी

सामाजिक शिक्षा  
तथा समाज-कल्याण

व्यायाम तथा  
मनोरंजन

छात्र-वृत्ति

प्रशासन

शिक्षा-मन्त्रालय को कई सलाहकारी या परिनियत परिषद् सहायता पहुँचाती है। मुख्य परिषद् ये हैं : (१) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (केडिसम), (२) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन), (३) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् (आल इंडिया प्राइमरी एज्युकेशन), (४) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (आल इंडिया प्राइमरी एज्युकेशन), (५) ग्रामीण उन्नतर शिक्षा समिति (नेशनल काउन्सिल ऑफ़ रूर एज्युकेशन), (६) राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् (नेशनल काउन्सिल ऑफ़ वुमेन्स एज्युकेशन), (७) केन्द्रीय समाज-सेवा-मण्डल (सेन्ट्रल सोशियल वेल्फेयर बोर्ड), इत्यादि। इस अध्याय में केवल 'केडिसम' की आलोचना की जायेगी। अन्य परिषदों के विवर में अगले अध्यायों के यथायोग्य अंशों में लिखा जायगा।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यों का प्रधान साधन 'केडिसम' है। इसकी स्थापना एन० १९२१ ई० में हुई थी। इसका संविधान इस प्रकार है :

- (१) भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्री (सभापति),
- (२) भारत-सरकार के शिक्षा-परामर्श-दाता (सदस्य),
- (३) भारत सरकार द्वारा मनोनीत पंद्रह सदस्य, जिनमें से पाँच सदस्य महिला हों,
- (४) संसद द्वारा निर्वाचित पाँच सदस्य — दो राज्य-सभा-द्वारा तथा तीन लोक-सभा-द्वारा,
- (५) अन्तर्विद्यालय-मण्डल (इण्टर युनिवर्सिटी बोर्ड) द्वारा निर्वाचित दो सदस्य,
- (६) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् (आल इंडिया प्राइमरी एज्युकेशन) द्वारा मनोनीत दो सदस्य,
- (७) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, जो कि शिक्षा-मन्त्री हो। उसकी अनुपस्थिति में, उसका मनोनीत व्यक्ति किसी भी बैठक में भाग ले सकता है और
- (८) मण्डल का सचिव — (जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है)।

भारत-सरकारी सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष रहता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है, जिसमें सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार

किया जाता है। मण्डल की कई स्थायी समितियाँ भी हैं, और समय-समय पर मण्डल शिक्षा के विशिष्ट विषयों पर रिपोर्टें प्रकाशित करता रहता है। हमें की बात है कि आरम्भ से ही मण्डल का कार्य प्रगतिमान रहा है। मण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। कारण, शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय है। राज्य सरकारें मण्डल की सिफारिशों को ठुकरा सकती हैं, बदल सकती हैं या अपना सकती हैं। इस कारण, मण्डल की चेष्टाएँ कभी-कभी व्यर्थ भी जाती हैं।

मण्डल से सलग शिक्षा-सूचना कार्यालय तथा एक सर्वाङ्गपूर्ण पुस्तकालय है। शिक्षा-सूचना-कार्यालय का काम है देश-विदेश के शिक्षा-विषयक समाचारों का संग्रह करना तथा शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित करना। पुस्तकालय तो देश-विदेश के शिक्षा-साहित्य का भण्डार ही है।

यद्यपि शिक्षा के सम्बन्ध में भारत-सरकार राज्यों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तथापि उसका स्थान शिक्षा-क्षेत्र में महत्व-पूर्ण है। प्रथमतः, पूरे देश की शिक्षा-नीति में समानता लाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है। 'केशिसम' तथा राज्य के शिक्षा-मन्त्रियों की बैठकों में, पूरे देश के शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ करता है। शिक्षा के पंचादे प्रश्नों को मुलझाने के लिए भारत-सरकार समितियाँ तथा आयोग नियुक्त करती है, रिपोर्टें प्रकाशित करती है तथा विचीय मामलों पर सोच-विचार करती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञ तथा प्रकाशक का कार्य करती है। द्वितीयतः, यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा समुक्त राष्ट्र सघीय शिक्षा, 'विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन' (यूनेस्को) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करती है। इसके सिवा, केन्द्रीय सरकार का काम है इस देश के छात्रों को विदेश की शिक्षा-संस्थाओं में प्रविष्ट कराना तथा उनकी देख-भाल करना। इस कार्य के लिए भारत-सरकार के लंदन, वाशिंगटन, ब्रान तथा नैरोबी में दफ्तर हैं। तृतीयतः, सघीय क्षेत्र की शिक्षा की जिम्मेवारी भारतीय सरकार पर है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (दिल्ली, अलीगढ़, बनारस और विश्व-भारती) की देख-रेख इसे ही करनी पड़ती है। चतुर्थतः, भारत के अठारह पब्लिक स्कूल शिक्षा-मन्त्रालय के प्रशासन में हैं। पञ्चमतः, अनेक आखिल भारतीय शिक्षा-संस्थाएँ स्वयं भारत-सरकार-द्वारा सञ्चालित हैं, जैसे : दिल्ली सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एज्युकेशन, देहरादून सेन्ट्रल ग्रेजुएट मेस, दिल्ली नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ बेसिक एज्युकेशन, इत्यादि। षष्ठतः, केन्द्रीय सरकार अनेक शिक्षा-योजनाओं के लिए राज्यों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है, बशर्ते कि ये योजनाएँ केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त हों।

**वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय.**—इस मन्त्रालय के सबसे प्रमुख व्यक्ति एक राज्य-मन्त्री है, जिसकी सहायता एक उप-मन्त्री करते हैं। इस मन्त्रालय की स्थापना हाल ही में हुई है। इस मन्त्रालय के मुख्य कार्य ये हैं : (१) वैज्ञानिक शोध तथा भूमीक्षण, (२) सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा (३) प्राविधिक शिक्षा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर में इस मन्त्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, ज्यूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, धोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेओलोटिक सर्वे ऑफ इंडिया—इसीके प्रशासन में हैं। यह मन्त्रालय अनेक शिक्षा-मस्थाएँ भी चलाता है, जैसे : दिल्ली पोलिटैकनिक, खड़गपुर-स्थित प्रौद्योगिकी संस्था, धानबाद-स्थित इंडियन स्कूल ऑफ मार्निंग एण्ड एप्लाइड ज्योलोजी, इत्यादि। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक गवेषणा के प्रोत्साहन के लिए, मन्त्रालय अनेक मस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता भी देता है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद मन्त्रालय को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देता है।<sup>†</sup>

**राज्य सरकार**

यह पहले ही बताया जा चुका है कि, शिक्षा एक राज्यीय विषय है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केवल दो विषयों की धारत, केन्द्रीय सरकार की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है। ये हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विभिन्न उच्च शिक्षा निकायों के बीच सम्बन्ध स्थापित करना और उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना। ये उच्चतर तथा व्यवसायिक विषय पूरे देश से सम्बन्धित हैं, इसलिए हमारे विधान ने इनकी जिम्मेवारी राज्यों पर स्थापना हितकारी नहीं समझा। और यह ठीक भी है। इनके सिवा, राज्य-सरकारों पर एक और प्रतिबन्ध है। दिन-दिन योजनाओं के लिए, राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं, उन योजनाओं को चलाने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करना पड़ता है। इन रणनीतियों के सिवा, राज्यों की शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण स्वायत्तता है।

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति-द्वारा पौंच वरों के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने की दृष्टि से मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि परिषद की व्यवस्था की गयी है। मन्त्रियों को अत्या-अत्या शासन-विभाग सौंप दिये जाते हैं, जिनकी जिम्मेवारी पूरे मन्त्रि-परिषद पर होती है। वरं सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा मन्त्री के

<sup>†</sup> देखिए आठवीं अध्याय।



मातहत शिक्षा-विभाग रहता है। पूरे राज्य की शिक्षा-नीति का निर्देशन वे ही करते हैं। उनकी सहायता के लिए दो प्रधान अफसर रहते हैं : शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन)। सचिव शिक्षा-विभाग के सारे कामजात शिक्षा-मन्त्री के सामने पेश करते हैं तथा सरकार की ओर से हुकम निकालते हैं। बहुधा सचिव शासकीय अफसर ही होता है, और उसे शिक्षा-विभाग का अधिक अनुभव नहीं रहता है।

शिक्षा-विभाग का असली काम डाइरेक्टर चलाते हैं, जो सदा इस विभाग के एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी पेचीदे प्रश्नों पर वे ही शिक्षा-मन्त्री को सलाह देते हैं। डाइरेक्टर की सहायता के लिए, सटर दफ्तर में कई उपसंचालक (डिप्टी या असिस्टेण्ट डाइरेक्टर) रहते हैं। राज्य विभागों में बाँट दिया जाता है, और विभाग जिलों में। प्रत्येक विभाग एक क्षेत्रीय डिप्टी डाइरेक्टर या सुपरिण्टेण्डेण्ट अथवा इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के प्रशासन में रहता है। यह प्रबंध प्रत्येक राज्य की शासन-पद्धति पर निर्भर होता है। कई राज्यों में मध्यवर्ती शासक रखने की प्रथा उठा दी गयी है। इन राज्यों में डाइरेक्टर से पञ्चवर्ती अफसर जिला शाला निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट एज्यूकेशन इन्स्पेक्टर) होता है। प्रत्येक राज्य तालुका या तहसीलों में बाँट दिया जाता है जो कि एक डिप्टी इन्स्पेक्टर के मातहत रहता है। इन सब अफसरों के काम की निगरानी शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर करते हैं।

यों तो पूरे राज्य की शिक्षा की जिम्मेवारी शिक्षा-मन्त्री पर रहती है, पर कुछ विशेष शिक्षा-संस्थाएँ अन्य मंत्रियों के प्रशासन में रहती हैं, जैसे : कृषि-विशालय, टेक्नीसी स्कूल तथा कालेज, समाज शिक्षा-केन्द्र, आदि। हमें यह न सोचना चाहिए कि शिक्षा-विभाग अपना पूरा कार्य स्वयं चलाता है। उसे अन्य ध्येयस्थापनों की सहकारिता की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे : उच्च शिक्षा-विश्वविद्यालयों के जरिये, प्राथमिक शिक्षा-स्थानीय बोर्डों में मिलजुल कर, माध्यमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-मण्डलों के सहयोग से। इस पृथकीकरण नीति के कारण, कभी कभी शिक्षा को धर्ती पहुँचती है। शिक्षा प्रशासन का समग्र यह एक मुख्य-पूर्ण प्रश्न है।

#### स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन की नीति सन् १८६१ ई० में पड़ी। इस वर्ष कएरणा, मद्रास और बम्बई शहरों का स्वशासन करने के लिए प्रशासनिक निर्माण तथा भौतिक विकास हुआ। इसके बाद सन् १८८२ ई० में मॉरे रिज ने एक नियम बनारा, विमर्श-प्रणाली प्रस्ताव के द्वारा, कर्मों और जिलों का प्रत्यक्ष करने के लिए नगरपालिका।

सरकार के हैं : शहरी तथा ग्रामीण । बड़े बड़े नगरों के निकायों को 'निगम' और मध्यम तथा छोटे नगरों के निकायों को 'नगरपालिका समिति' कहा जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों की देख-भाल जिला-मण्डल अथवा तालुका-मण्डल (जनपद सभा) तथा ग्राम-पंचायतें करती हैं ।

सरकार ने कई कायदे-कानूनों तथा प्रस्तावों द्वारा स्थानीय निकायों को शिक्षा-विवरक अनेक अधिकार दिये हैं । माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने स्पष्ट घोषणा की कि "ग्रामन की ओर से जिले, शहरों एवं कस्बों का शासन उनके निवासियों को मिल जाय और वे उनका प्रबन्ध-सम्भाल बनाकर इच्छानुसृत कार्य करें ।" इस विषय में बाहरी हस्तक्षेप धान्यछनीय नहीं है । इस घोषणा का फल यह हुआ कि प्रान्तीय विधान सभाओं ने धीरे-धीरे स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ा दी । आज सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का शासन स्थानीय निकाय ही करते हैं । वे स्वतः स्कूल खोलते हैं, गैरसरकारी स्कूलों को मजूर करते हैं तथा उन्हें ग्राण्ट देते हैं । शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए वे अपने स्कूल-बोर्ड स्थापित करते हैं तथा स्कूलों की देखरेख के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं । प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, वे अपनी योजनाएँ भी बना सकते हैं ।

### शिक्षा-संस्थाओं का वर्गीकरण

भारत की शिक्षा-संस्थाएँ दो भेदों में विभाजित की जा सकती हैं : (१) स्वीकृत तथा (२) अस्वीकृत । पहले वर्ग की संस्थाएँ किसी शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय या हाईस्कूल बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृत होती हैं । इनके द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को पाठ्य क्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों का चयन करना पड़ता है, और उन्हें अपने विद्यार्थियों को सरकारी या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बिटाने का हक रहता है । समय-समय पर इन संस्थाओं का निरीक्षण भी होता है । इस कारण, इन्हें सदैव चौकसा रहना पड़ता है । ऐसे स्कूल और कॉलेजों को छोड़कर दोय संस्थाएँ अस्वीकृत होती हैं । कृपया ये देखी विद्यालय होते हैं, जिनमें मजदूर, पोरों, कुलग, आयुर्वेद या दूनानी चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता है । इनारे देश में कुछ ऐसे स्कूल भी खुल गये हैं, जो परीक्षाओं में अस्वीकृत छात्रों को फिर से परीक्षाओं में प्रवेश दियाने के लिए तैयार करने हैं । परमेश्वर देश को ऐसी अनधिकारी संस्थाओं से बचावे ।

स्वीकृत संस्थाएँ भी दो प्रकार की हैं—सरकारी तथा स्वयं-चालित । पहले वर्ग की संस्थाएँ राष्ट्रीय या स्थानीय निकायों द्वारा परिचालित होती हैं । स्वयं-चालित संस्थाओं को तो कोई स्थाविर अवेण्ड ही चलना है या कोई शिक्षा-मण्डल चलाना है । इन

संस्थाओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं : (१) महाविद्यालय अर्थात् किन्हीं सरकार या और स्थानीय निकायों में ग्राण्ट मिलती है, और (२) स्वाभिन, किन्हीं अनुदान प्राप्त नहीं होता। ऐसी संस्थाओं को अविहार प्रोग्राम, नन्दा या दान पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

१९५५-५६ में स्वीडन संस्थाओं की संख्या ३,६६,६४१ थी : राष्ट्रीय ८७,६०१, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १,४२,९८०, म्युनिसिपल बोर्ड १०,४९७, स्वसहायित १,१४,२०४ (महाविद्यालय-प्राप्त) और ११,३५९ (स्वाभिन)। इसी वर्ष सम्पूर्ण देश में ४,८०६ अस्वीडन संस्थाएँ थीं।†

## शिक्षा की सीढ़ी

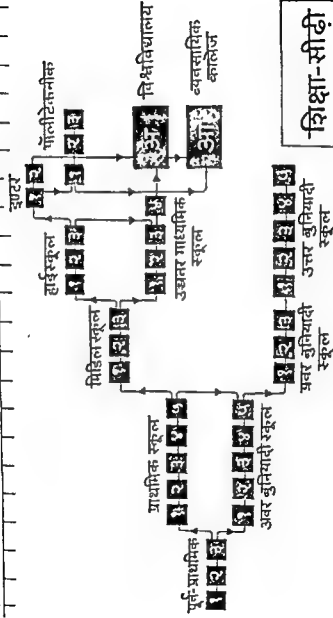
शिक्षा की पहली सीढ़ी पर पूर्व-प्राथमिक स्कूल हैं, जहाँ ३ से ६ वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या देश में बहुत ही कम है। इनके बाद प्राथमिक स्कूलों और अवर बुनियादी स्कूलों का नम्बर आता है, जहाँ ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बाद के माध्यमिक स्कूल दो प्रकार के होते हैं— (१) मिडिल—अवर हाई स्कूल या अवर बुनियादी स्कूल, जिनमें ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चे विद्याध्ययन करते हैं और (२) हाईस्कूल, जिनमें ११ से १६ वर्ष की आयु के बच्चे शिक्षा पाते हैं। परन्तु कई राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी हैं, जहाँ ११ से १७ या १८ वर्ष की आयु के बालक शिक्षा पाते हैं।

हाईस्कूल के बाद इण्टरमीडिएट कालेजों या डिग्री कालेजों की इण्टरमीडिएट कक्षाओं का नम्बर आता है। यहाँ दो वर्ष शिक्षा मिलती है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में सफलभूत होने के बाद विद्यार्थी को दो वर्ष का समय प्रथम डिग्री पाने के लिए लगता है। जो विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्कूल से उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट नहीं पढ़नी पड़ती है। वे सीधे तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्य क्रम में भरती होते हैं।

स्नातक होने के बाद, विद्यार्थी को उत्तर-स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए दो वर्ष लगते हैं। आजकल विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-संस्थाओं तथा कई कालेजों में का विशेष बन्दोबस्त है। यहाँ विद्यार्थी उच्च-स्नातक स्तर के अनुसन्धान कार्यों को दिलचस्पी ले सकते हैं।

उमर

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४



शिक्षा-सीढ़ी

व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा नाना प्रकार की होती है, जैसे : अर्थ-व्यापार, कृषि, शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विधि (कानून), चिकित्सा, वन-विद्या, नृत्य, चित्रकला, आदि। कालेजों में तो विद्यार्थी इण्टरमीडिएट या पूर्व-व्यावसायिक (प्री-प्रफेशनल) परीक्षा उत्तीर्ण होकर ही प्रविष्ट होते हैं, पर स्कूल तथा पालीटेक्नीक में प्रवेश पाने के लिए मैट्रिक सर्टीफिकेट सफेद होता है। अशक्त एवं अन्य विकलाङ्ग बच्चों के लिए विशेष स्कूल हैं। इसी प्रकार प्रौढ़ों के लिए भी अलग स्कूल हैं।

यह तो हुआ हमारे देश की शिक्षा-पद्धति का साधारण विवरण। आजकल पद्धति में बहुत कुछ फेरफार हो रहे हैं। इनके सिवा प्रत्येक राज्य की कुछ-न-कुछ अपनी शैक्षणिक विशिष्टताएँ हैं, जिसे समूचे देश की शिक्षा-पद्धति एक समान नहीं है।

### शिक्षा-व्यय

शिक्षा-व्यय दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) और परोक्ष (इन्-डाइरेक्ट)। प्रत्यक्ष व्यय में जो व्यय शामिल है, वे ये हैं : अध्यापकों, कर्मचारियों आदि के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंश-दान, मात्र-सामान और उपयोग में आनेवाली वस्तुएँ, लेखन सामग्री, इमारतों की मरम्मत, क्रिया, परीक्षाओं आदि का आरम्भ प्रसार। परोक्ष व्यय में वे व्यय शामिल हैं : छात्रावास और छात्र-नृत्तियों का व्यय, इमारतों और मात्र-सामान का व्यय, निर्देशन एवं निरीक्षण का व्यय और इस प्रकार के विविध व्यय जो किसी एक संस्था या एक प्रकार की संस्थाओं में नहीं बाँटे जा सकते।

गिठने कुछ वर्षों में शिक्षा-व्यय बढ़ गया है, और उतनेतर बढ़ता ही जा रहा है। ११ मार्च, १९४८ को पूरे देश का कुल शिक्षा-व्यय केवल ५५.१ करोड़ रुपये था। पर वर्ष १९५६ ई० में १८९.८ करोड़ रुपये हुआ। अर्थात् शिक्षा व्यय तीन गुने में अधिक बढ़ गया है। इसका होने हुए भी इस व्यय में पूरे देश की शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती है। एक सरकारी रिपोर्ट का कहना है :

शिक्षा-व्यय में यह वृद्धि अत्यन्त सगर्हीत है; पर पूरे देश की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ४०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस व्यय में यह भी धना व्यय है कि हमें अपनी शिक्षा बनाना है।\*

## तीसरा अध्याय

### युनियादी शिक्षा

#### प्रस्तावना

आधुनिक भारतीय शिक्षा के विज्ञान में सबसे उल्लेखनीय घटना है 'युनियादी शिक्षा'। इसने हम देश के शिक्षा-क्षेत्र में एक नवीन धारा प्रवाहित कर दी। भारत को भ्रष्ट राष्ट्र की यह अन्तिम, किन्तु सबसे बहुमूल्य देन है। उन्होंने अनुभव किया कि देश में एक नूतन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की सृष्टि की आवश्यकता है और यह उपयुक्त शिक्षा-पद्धति के द्वारा ही सम्भव है। गान्धीजी ने तो देश का कोना-कोना छान टाना था, और उन्हें जन-समुदाय की स्थिति का रस्ती-रस्ती पता था। उन्होंने अनुभव किया था कि भारतीय जनता को न तो भरपेट भोजन ही नसीब होता और न तन भर कपड़ा ही प्राप्त होता है।

इस आर्थिक दरिद्रता से भी हीनतर थी आत्मिक दरिद्रता। देश में सदियों परंपरा का श्रेष्ठवाला था। यहाँ के अधिवासी तन, मन, विचार, आचार, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि के दासत्व के कुचक्र में इस घुरी तरह फँस रहे थे कि उसमें उन्हें मुक्ति पाना दुष्कर-सा हो रहा था। अधिक क्या, लोग इस मायामय गुलामी पर मोहित-से हुए उसे अविकाशिक आत्ममार्ग करते जा रहे थे। पूज्य गान्धीजी के ध्यान में यह बात विशेष रूप से खटकी। देश के शिक्षित वर्ग की आकांक्षा तथा गति-विधि को देखते हुए उनके हृदय में वर्तमान शिक्षा के प्रति एक विवृण्णा उत्पन्न हुई। जिस जमीन पर अन्न-पानी हम वर्ग के शरीर में भिदा था उस वातावरण में अनुकूल उसे शिक्षा नहीं मिली थी, जिसमें उसे अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम था। उसके हाव-भाव से पाश्चात्य धू आ गयी थी, वह परिश्रम से दूर भागता था और जनता से अपने को कोशों दूर रखना चाहता था। इस कारण समाज के दो टुकड़े हो गये थे। एक ओर इन्ते-गिने बुद्धिजीवी थे और दूसरी ओर करोड़ों धमजीवी। दोनों के बीच भेद की गहरी खाई खुद गयी थी। बुद्धिजीवी धर्म से प्यारते थे, अ

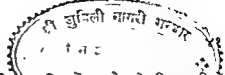
यह ध्यान देते थे। इन तीन, तीस वृद्धा, महिला और दृढ़-मन के विचार में मन्त्री हम पूरी तरह पछाड़ गया था कि युद्धों का कोई मन्त्र ही नहीं हो रहा था।

नयी शिक्षा का जन्म भवे गंगाधर और नवीन शिक्षा की रचना के विचार में हुआ था। इस शिक्षा में गान्धीजी ने शिक्षा के अनेक आदर्शों का समावेश करना चाहा था। वे हम शिक्षा के द्वारा अपनी मानु-भूमि में सामाजिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे; ऐसी शिक्षा, जो पुनर्जीव न हो, बल्कि प्रतिष्ठा तथा सुव्यवस्था का जो प्रभाव हो, जो भारतीय मनुष्य के पाँव पर गड़ी हो, जिसमें दार्शनिक परिधन के लिए संघट्ट स्थान हो, जो अमीर गरीब का भेद मिटावे और जो पूरे देश को एक मूर में बिलो देवे। गान्धीजी के सामने एक और प्रश्न था — अर्थ। वास्तव, शिक्षा-विचार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होना है। पर हमारी गरीब एवं पराधीन मानुभूमि के लिए हम मन्त्र कां के निमित्त इतना अधिक धन माग्न करना सम्भव न था। इसलिए गान्धीजी एक ऐसी शिक्षा की कल्पना में थे जो अगम्य अवश्य हो, पर स्वयंसेवी न हो।

गान्धीजी अपनी नवीन शिक्षा विवरण कल्पना में पन्तु दिनों से निमग्न थे। उनकी शिक्षा का आरम्भ दक्षिण आफ्रिका के किम्वरु कापोली में अपने परिवार में ही और टाटम्यार फार्म में हुआ। दक्षिण आफ्रिका में मानव की आत्मा एवं मानसता का जो निम्न अवमान हो रहा था, और आज भी हो रहा है, उसके विरुद्ध गान्धीजी ने जो अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया, यही उनकी शिक्षा के कार्यक्रम का माध्यम रहा। इस माध्यम का प्रथम विकास दक्षिण आफ्रिका में करके गांधीजी भारत में आये, और यहाँ सागरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सन् १९१७ ई० के चम्पारण सत्याग्रह से लेकर उनकी जन-शिक्षा का कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। यह भारत जैसे एक विराट राष्ट्र की समग्र जनता के लिए अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन की तैयारी थी। आगे जाकर उन्होंने अपनी इस नयी शिक्षा का नाम 'बुनियादी शिक्षा' या 'नयी तालीम' दिया। जुलाई, १९३७ के 'हविजन' के अंशों में गान्धीजी ने राष्ट्र के सामने बुनियादी तालीम की मूल कल्पना रखी। †

प्रारम्भिक कार्य

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन, वर्षा.—२२ और २३ अक्टूबर, १९३७ को वर्षा के मारवाडी हाईस्कूल (वर्तमान नवभारत विद्यालय) की



रजत-जयन्ती के अवसर पर, गान्धीजी के सम्पादित्व में इस देश के शिक्षा-शास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें गान्धीजी ने अपनी नवीन शिक्षा-योजना उपस्थित करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा न तो किसी प्रकार की जीवन-वृत्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित करती है और न उसमें किसी प्रकार के उत्पादनशील कार्य की क्षमता ही है। उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए :

१. इस सम्मेलन की राय में, देश के सब बच्चों के लिए सात वर्ष की मुफ्त और लाजिमी तालीम होना चाहिए।

२. तालीम का जरिया मातृ-भाषा होना चाहिए।

३. यह सम्मेलन महात्मा गान्धी की इस तत्त्वजीव की ताईद करता है कि तमाम मुद्दों में शिक्षा का मध्य बिन्दु किसी किसम की दस्तकारी होना चाहिए, जिनसे कुछ मुनाफा हो सके और बच्चों में जो कुछ अच्छे गुण पैदा करने हैं और उनको जो शिक्षा-दीक्षा देनी है वह जहाँ तक हो सके किसी केन्द्रीय दस्तकारी से सम्बन्ध रखती हो और जिस दस्तकारी का चुनाव बच्चों के माहोल का लिहाज रखकर किया जाय।

४. सम्मेलन आशा करता है कि इस तरीके से धीरे-धीरे अध्यापकों की तनख्वाह का खर्च निकल आवेगा।†

**नयी तालीम की आर्हिस्सक योजना.**—सम्मेलन ने फिर दिल्ली के जमिया मिलिया के प्राचार्य डाक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमिटी मुक़रर की। उन समिति की रिपोर्ट २ दिसम्बर, १९३७ में निकली। १९३८ की हरिपुरा कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को मंज़ूर किया और बर्धा के पास सेवामाम में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ स्थापित किया। इस संघ का उद्घाटन करते हुए गान्धीजी ने कहा :

यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है। इसके आदर्श का जन्म संगीत में हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गाँवों में बसता है, जो संगीत से भी बहुत हीन दशा में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन गाँवों में निरक्षरता दूर भगा दें, तथा मूल्य और अहिंसा के द्वारा स्वयंसेवा प्राप्त करने का सन्देश गाँवों में पहुँचावें। यह जिम्मेवारी आपके





धुनाई और कनाई का साधारण ज्ञान । (३) मातृ-भाषा । (४) गणित । (५) समाज-शास्त्र (इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का समन्वय) । (६) साधारण विज्ञान । (७) संगीत और चित्रकला । (८) हिन्दुस्तानी ( ऊर्दू और देवनागरी लिपि-ज्ञात) ।

**योजना की प्रगति.**—झाकि हुसैन रिपोर्ट के निकलते ही कांग्रेस प्रदेशों अधोन् अस्म, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का प्रचार जोग में आरम्भ हुआ । स्कूल स्थापित हुए, शिक्षकों तथा शासकीय अफसरों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्तजीवन केन्द्र खोले गये तथा बुनियादी शिक्षा की समितियाँ स्थापित हुईं । शक्ति राज्यों में कश्मीर ने अच्छा काम किया । कुछ शिक्षा-प्रतिष्ठानों ने अपनी निजी बुनियादी शालाएँ चलायीं । इनमें उद्दिष्टयोग्य हैं - दिल्ली जामिया मिलिया, मुबरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, आन्ध्र ज्ञातीय कलाशाला, इत्यादि । पर द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होते ही, योजना में दिथिलता आ गयी । तो भी देश की आजादी के साथ-साथ बुनियादी शिक्षा में फिर से तेजी आ गयी ।

**नयी तालीम पर नये विचार.**—हम अर्थात् में गान्धीजी ने नयी तालीम को एक नया रूप दिया । १९४२ में जेल से मुक्त होने के बाद, उन्होंने घोषणा की :

बन्दी अवस्था में नयी तालीम की शक्यता पर सोचने-सोचते में आइल अस्थिर हो पड़ा । योजना की कामगारी देखकर हमें चुन नहीं रहना चाहिए । हमें आगे बढ़ना है । हमें बच्चों के घर मुधारने पड़ेंगे, हमें उनके मौ-श्राप को शिक्षा देनी होगी । बुनियादी शिक्षा का ध्येय होना चाहिए—आजीवन शिक्षा ।

हम घोषणा के साथ आरम्भ हुई नयी तालीम की दूसरी मंजिल । बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध अब बच्चों की तालीम में मर्यादित न रहा । हत शिक्षा का तत्त्व बढ़ाना पड़ा, ताकि हम तत्त्व में हर उम्र का हर व्यक्ति शामिल हो सके । जनवरी १९४५ को, कोलाम में राष्ट्रीय कार्य-कर्त्ताओं की एक बैठक हुई । अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा का निहादलोकन तथा मरिध के लिए एक प्रोग्राम स्वीकृत । अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन हुए गान्धीजी ने कहा :

हमारी शिमेवारी साथ से बीरुद बर्द के बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ समाप्त नहीं होगी । नयी तालीम के कार्य क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि आवश्यकता है । यह शिक्षा मानव जीवन में सर्वप्रधान से आरम्भ होगा है और मनुष्य जीवन बदली रहनी है ।

गान्धीजी के नवीन निर्देशानुसार बुनियादी शिक्षा को आजीवन शिक्षा बनाने की ओर सम्मेलन ने ध्यान दिया। सम्मेलन ने चार समितियाँ गठित की और प्रत्येक को जीवन के एक-एक प्रक्रम के अनुकूल सुप्रयोज्य शिक्षा-योजना निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इन शिक्षा-प्रक्रमों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं : (१) प्रौढ़ शिक्षा, (२) पूर्व बुनियादी अर्थात् सात से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा, (३) बुनियादी अर्थात् सात से चौदह वर्ष वाले बच्चों की शिक्षा और (४) उत्तर बुनियादी शिक्षा, अर्थात् उन विद्यार्थियों की शिक्षा, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा समाप्त कर ली हो।

३० जनवरी, १९४८ को गान्धीजी हम सबको रोता हुआ छोड़ इस संसार से सदा के लिए विदा हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात् नयी तालीम के कार्यकर्त्ताओं ने यह शपथ ली कि जब तक हमारे ढग में दम है तब तक हम नयी तालीम की यात्रा को जारी रखेंगे, तथा अपने जीवन और काम में नीचे लिखे उद्देश्यों को सामने रखकर मजिल की ओर बढ़ते रहेंगे :

१. तालीम में सत्य और अहिंसा की रूढ़ फूँकना।
२. तालीम को हाथ के काम से, कुदरती वातावरण से, और समाजी ज़िन्दगी से जोड़ना।
३. तालीम के द्वारा सच्ची देश-भक्ति और इन्सानी हमदर्दी सिताना तथा साम्प्रदायिकता को मिटाना।
४. बचपन से बुढ़ापे तक की उम्र की हर सीढ़ी के लिए नयी तालीम का उचित प्रयत्न करना।
५. बच्चों और सयानों को ऐसे समाज के लिए तैयार करना, जिनमें मुसाफिरों की जगह सहयोग हो, लूट की जगह ईन्साफ हो, आज्ञाकारी हो जिम्मेवारी के साथ, और आर्थिक उन्नति हो नैतिक उन्नति के साथ।

### नयी तालीम के प्रक्रम

अब तनिक नयी तालीम के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर विचार किया जाय।

१. शिक्षा.—नयी तालीम की पूरी कामगारी के लिए आवश्यक है कि घरों में आरम्भ न की जाय, बरन् इसकी शुरूआत बच्चों के माना गिरा, एवं प्रौढ़ समाज में होनी चाहिये। इसलिये नयी तालीम का प्रयत्न

प्रक्रम है 'प्रौढ़शिक्षा'—अर्थात् समूचे समाज की तालीम और साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी शिक्षा, जिससे कि सब लोग एक मुन्नी, स्वास्थ्यकर, स्वच्छ तथा स्वावलम्बी जीवन बिता सकें।

**पूर्व-बुनियादी—**(७ से ४५ आयुवाले बच्चों की शिक्षा)—ज्योंही बच्चा स्वतः अपने घर में स्कूल पैडल जाने लगता है, त्योही शिक्षा-प्रक्रिया गृह से शान्ति की ओर प्रसारित होती है। पूर्व-बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों का पूर्णतया शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। यह तभी सम्भव है जब कि मिष्ठक, माता-पिता तथा समाज मिल-जुल कर बच्चों की शिक्षा में हाथ बँटावें तथा घर, स्कूल एवं गाँव एक एक में गुँथ जायें। †

**बुनियादी शिक्षा—**(मात में चौदह वर्ष वाले बालक-बालिकाओं के लिए)—इस शिक्षा की हमारा प्रौढ़ शिक्षा तथा पूर्व-बुनियादी शिक्षा की नींव पर गढ़ी होती है। जाकि हमें रिपोर्ट का पूर्व पाठ्यक्रम दुबारा संशोधित किया गया है। योजना निम्न लिखित कार्य-कलापों से सम्बन्ध रखती है :

१. आवश्यक ज्ञान, अभ्यास, भाव तथा कौशल — जो स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद जीवन (व्यक्तिगत तथा सामाजिक) के लिए आवश्यक हो।

२. नागरिक शिक्षा (व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक)—घर, स्कूल, ग्राम, स्वदेश तथा विश्व के ज्ञान के द्वारा। यह ज्ञान इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सरल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र-द्वारा दिया जाना।

३. स्वावलम्बी होने की क्षति—अन्न-वस्त्र तथा आभय-प्राप्ति के लिए।

४. केन्द्रीय दायित्व—इनमें से कोई भी एक हस्तक्षेप हो : कृषि और वाणजनी, कलाई और बुनाई, बटुईगिरी, घर निर्माण और सम्मान का ज्ञान, या अन्य कोई दायित्व जो शिक्षा प्रद हो और जिसके लिए स्थानिक साधन अनुबल हो।

५. साधारण विज्ञान और कला।

हम ही में बुनियादी शिक्षा की अटुमान निर्धारण समिति (एनेक्मेन्ट बन्दिटी) ने सिफारिश की है कि जो विद्यार्थी हार्दिकता या अन्य उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय की ओर छोड़ कर से ले सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी देखो की बुनियादी शिक्षाओं में हिन्दी एक अनिवार्य विषय का विषय बन।

**उत्तर बुनियादी शिक्षा (फरवरी से अगस्त वर्षगत विद्यार्थियों के लिए)।**—  
 हिन्दुस्तानी तालीमी मण्डल की उत्तर बुनियादी समिति के निर्णय के अनुसार इस शिक्षा के उद्देश्य हैं : (१) इस शिक्षा की नींव भी बुनियादी शिक्षा की जैसी किसी दस्तावेज पर आधारित या केन्द्रित होना चाहिए। (२) पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण हो। (३) पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के विषयों का समावेश रहे, ताकि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार विषयों का चयन हो सके। (४) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। (५) पूरी शिक्षा की अवधि, पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार कुछ और बढ़ा हो, पर गोल से चार वर्ष के भीतर ही हो। (६) पाठ्यक्रम होगा जो कि अन्ततः-काल में प्रदेश शिक्षाधीनता स्तर बना बना रहे।

समिति ने श्रीरंग प्रसार के साथ प्रस्तावित किये हैं, ताकि प्रत्येक शिक्षाधीनता स्तर के अनुसूचित वर्गों का चयन कर सके। ये कार्य ये हैं : कृषि, विज्ञान, इतिहास, स्वास्थ्य, कला, वाणिज्य, इत्यादि, विज्ञान, शिक्षा, परम्परा, कला, इत्यादि, परम्परा, परम्परा, परम्परा और उपयोग।



ग्राम-दान आन्दोलन आगे बढ़ता हुआ अब शान्ति-सेना के कार्य-क्रम तक आ पहुँचा है। शान्ति-सेना की कल्पना भारत के लिए बाँई नहीं पात नहीं है। आज से बीस वर्ष पूर्व गांधीजी ने शान्ति सेना की योजना राष्ट्र और विश्व के सामने उपस्थित की थी, लेकिन उक्त समय उसकी कल्पना के अनुसार काम करने का नैतिक पल इस देश में जागृत न था। अब मन्त विनोबाजी ने भूदान-यज्ञ के द्वारा सम्पूर्ण देश में एक नवीन जीवन फूँक दिया है। ग्राम-दान में मिले हुए गाँवों में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नयी तालीम का एक नया पथ है। विनोबाजी ने ग्राम-शिक्षा और ग्राम-रक्षा—इन दोनों—को जोड़कर राष्ट्र के समक्ष नयी तालीम का जो समग्र कार्यक्रम रखा है उसके विषय में शिक्षक-समाज को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए। सच्चा शिक्षक यही है जो प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-निर्भरता का और समाज की प्रवृत्तियों में अनुशासन-युक्त सहयोग की भावना का विकास करे तथा जो सबका सेवक एवं मित्र होवे।

गांधीजी के मन में शान्ति-सेना की जो कल्पना थी, विनोबाजी ने उसकी ओर राष्ट्र का ध्यान पुनः आकर्षित किया है। शान्ति-सैनिक का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है :

शान्ति सेना का सैनिक नित्य जन-सेवा करेगा, और नैतिक तौर पर शान्ति-कार्य करेगा। ऐसे निष्काम, निस्वार्थ, निष्पक्ष एवं निरपेक्ष सेवकों की सेना खड़ी होनी चाहिए।

राष्ट्र के शिक्षक ही इस शान्ति-सेना के सैनिक बन सकते हैं। नयी तालीम का ध्येय है : जब कि समाज संसार भयभीत है तब शिक्षकगण स्वेच्छा से शान्ति-सेना के स्वयंसेवक (सैनिक) बनकर विश्व में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करें।

नयी तालीम और सरकार

**खैर समितियाँ.**—जाफिर हुसैन रिपोर्ट की जॉन्-पड़ताल के लिए 'केसशिम' ने बम्बई के मुख्य तथा शिक्षा मन्त्री श्री खैर की अध्यक्षता में दो बार समितियाँ नियुक्त कीं। प्रथम समिति ने अपनी रिपोर्ट १९३८ में तथा दूसरी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४० में दी। प्रथम रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं :

१. बुनियादी शिक्षा का आरम्भ पहले गाँवों में किया जाय। ✓
२. अनिवार्य शिक्षा की आयु ६ से १४ वर्ष रखी जाय। ✓
३. विद्यार्थियों को बुनियादी स्कूलों से अन्य स्कूलों में जाने की

४. मासिक विषयों के घे अंश स्वतन्त्र रूप से मिलाये जावे, केन्द्रीय दस्तकारी द्वारा न मिलाये जा सके।
५. बुनियादी शिक्षा के अन्त में किसी बाह्य परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आन्तरिक परीक्षा के आधार पर एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाय।

द्वितीय समिति ने निम्न-लिखित रिपोर्ट दी :

१. बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम आठवर्षीय अवधि में ६ से १ वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा जावे, पर पाठ्यक्रम की एकता को बना रखने हुए इस अवधि को दो हिस्सों में बाँट दिया जाय, (१) अर्ध (प्रारम्भिक) बुनियादी, जो ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए हो और (२) प्रार (सीनियर) बुनियादी, जो ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए हो।

२. अर्ध शिक्षा के समाप्त होने पर ही, विद्यार्थी अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाने पावें।

**सारजेष्ठ योजना (मार्च १९४४)**—'केमरिस' ने शेर समितियों के अधिसूचना विचारों को स्वीकार कर लिया। इसी समय अर्थात् मार्च १९४४ में आरम्भ में 'केमरिस' ने अपनी 'युद्धोत्तर शिक्षा-पुनर्निर्माण योजना' प्रकाशित की। इस योजना का सार नाम 'सारजेष्ठ योजना' है, क्योंकि सर जॉन सारजेष्ठ ने, जो कि उस समय भारत सरकार के शिक्षा-सलाहकार थे, इस योजना के तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस योजना ने शेर समितियों की रिपोर्टों पर पूर्णतः विचार किया और घोषित किया कि इस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नयी तालीम होनी चाहिए। यह शिक्षा आठ वर्ष की अवधि की हो; पर शेर समिति की सिफारिशों के अनुसार दो भागों में हो—अर्ध और प्रार। पर नयी तालीम के 'विद्या के द्वारा ज्ञान' के सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन करने हुए रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया :

उसकी सम्मति में विद्यार्थी प्राथमिक चरण में शिक्षा करने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए और न होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के उत्साहन में, अध्यापकों के अधिक, दृष्टिकारी के सामान ही निर्भर कर सकते हैं।

**हाल की समितियाँ**—'केमरिस' के सदस्य अधिपति की निर्देशों के कारण, एक केन्द्रीय बुनियादी समिति स्थापित हुई है। इस समिति का मुख्य कार्य



केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बुनियादी शिक्षा के लिए सलाह देना । सन् १९५५ में केन्द्रीय सरकार ने अनुमान-निर्धारण समिति (एसेसमेण्ट कमिटी) मुक़रर की । इसे निर्देश दिया गया कि वह चुने हुए स्थानों में स्वतः जाकर बुनियादी शिक्षा की जाँच करे । समिति ने सिफ़ारिश की है :

१. प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत उत्तर-स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किये जावें ।

२. बुनियादी शिक्षा पर गवेषणा करने के लिए, एक केन्द्रीय अन्वेषण संस्था की आवश्यकता है ।

३. ग्राम-पुनर्गठन से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी और गैरसरकारी समितियों शिक्षा-विभाग से मिलकर बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करें ।

४. प्रत्येक राज्य-सरकार अपनी शिक्षा-नीति स्पष्ट घोषित करें कि थोड़े ही अरसे में राज्य के सब प्राथमिक स्कूल तथा प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी रूप में बदल दी जावे ।

५. उच्च विद्यालयों में भरती होने के समय बुनियादी तथा माध्यमिक स्कूलों के समान वर्गों को एक-सी मान्यता दी जावे ।

६. दस्तकारी सिखाने के लिए, बुनियादी स्कूलों में पुराने कुशल अशिक्षित कारीगर नियुक्त किये जावें, जो बुनियादी शिक्षकों से मिलकर काम करें ।

**वर्तमान स्थिति**—आज हमारे देशमें नयी तालीम का जो भी काम चल रहा है, वह अधिकतर सरकार के शिक्षा-विभाग की ओर से या सरकारी मान्यता और आर्थिक सहायता के बल पर चल रहा है । केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों ने स्वीकार कर लिया है कि पूरे देशमें ६ से १४ वर्षवाले बच्चों की शिक्षा बुनियादी होगी । देश में बुनियादी स्कूल खुलते जा रहे हैं, पुरानी प्राथमिक शाळाओं को बुनियादी रूप दिया जा रहा है, प्रशिक्षण स्कूलों के विद्यार्थी-शिक्षकगण इस नयी शिक्षा में प्रशिक्षित किये जा रहे हैं तथा नयी तालीम के साहित्य की उन्नति होती जा रही है । इतना होते-हुए भी बुनियादी शिक्षा की प्रगति आश्चर्यकूल नहीं हो रही है ।

हमारी प्रश्न के समान राष्ट्रीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न उठा है ।

प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा में नहीं। फल-स्वरूप उत्तर बुनियादी शिक्षा एक टिमटिमाते हुए दीप के समान है। पूरे देश में सिर्फ २६ उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं (१९५६-५७)।† हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने ग्यारह ग्राम-प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं, जिनका बुनियादी शिक्षा में निकटतम सम्बन्ध है। इस समय पूरे देश में ५८१ प्राथमिक स्कूल तथा ३१ प्राथमिक महाविद्यालय हैं।‡

अनुमान-निर्धारण—समिति की सिफारिश के कारण, राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान की स्थापना हाथ में ही हुई है। इस समस्या का उद्देश्य नयी तालीम में खोज या अन्वेषण, तथा बुनियादी शासकों एवं निरीक्षकों को बुनियादी दैर्घ्य में प्रशिक्षित करना है। प्रतिष्ठान अन्य बुनियादी प्राथमिक विद्यालयों से मिलकर काम करता है, वह बुनियादी शिक्षा के विविध समाचारों का लेखा रखता है तथा नयी तालीम की समस्याओं को मुद्दा करने की चेष्टा करता है।

समालोचना

कुछ आक्षेप—इस योजना के प्रस्तुत होने के साथ ही साथ, भारतीय शिक्षा-जगत् में इसकी बड़ी आलोचना हुई तथा शिक्षा-विशारदों ने इसके विरुद्ध अनेक आक्षेप प्रस्तुत किये। इनमें से कुछ आक्षेपों को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रथम आक्षेप शिक्षा की स्वाधनता है। बच्चों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा स्कूल शिक्षा-केंद्र बन जावेंगे, जिनमें बालकों का शोषण होगा। कारण, शिक्षकों का वेतन विद्यार्थियों के परिश्रम पर निर्भर रहेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के द्वारा प्रस्तुत माल सब समय भरा रहेगा। यह कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित माल के समझ न टिक सकने योग्य रहेगा। ऐसे में उसकी खपत भी न होगी। यह प्रायः देखा गया है कि इस कौशल-शिक्षा सदैव खर्चीली ही हुआ करती है। इसमें आमदनी की अपेक्षा खर्च सदैव अधिक ही रहता है।

यह आक्षेप बहुत कुछ युक्ति-संगत तथा तथ्यपूर्ण है। बुनियादी तालीम का प्रचार अनेक स्थानों में हुआ है। सक्ता अनुभव है कि वहाँ स्वाधनता नहीं बन पायी। शायद कहीं वह सघ भी सकी होगी। सारजेण्ट रिपोर्ट ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि शिक्षा — विशेषकर प्राथमिक शिक्षा — अभी भी स्वाधनयी नहीं हो सकती है।\*

† Education in The States, 1956-57, pp. 2-3.

‡ Loc. cit.

\* Sargent Report p 8

बाकिर हुसैन समिति ने भी चाट को इस प्रश्न पर विचार करते हुए कहा, “यद्यपि यह शिक्षा स्वावलम्बी नहीं हो सकती है, तथापि इसकी आवश्यकता है। कारण, ऐसी ही शिक्षा से राष्ट्रीय संगठन हो सकता है।”†

स्वावलम्बन की चर्चा करते हुए गान्धीजी ने कहा था कि पहली-दूसरी कक्षाओं में नुकसान होगा, इसलिए घाटा रहेगा। लेकिन कुल सात कक्षाएँ होंगी; अतएव कुल मिलाकर सब ठीक हो जायगा। बिहार सरकार का कहना है, “यदि आठ कक्षाओंवाले प्रत्येक बेसिक स्कूल हों — १५० विद्यार्थी प्रथम पाँच वर्गों में तथा १०० विद्यार्थी अन्तिम तीन वर्गों में — तो स्कूल का ६७ प्रतिशत खर्च, विद्यार्थी — निर्मित माल की कीमत से निकल सकता है।”‡ लेकिन आज सभी जगह आठ कक्षाएँ नहीं हैं, और सभी जगह प्रत्येक कक्षा में ३० विद्यार्थी मिलना शक्य नहीं है। उत्तर-बुनियादी भवन सेवाग्राम में देखा गया है कि विद्यार्थीगण अपने परिश्रम-द्वारा अपना ६५ प्रतिशत खर्च निराला कर लेते हैं, पूरा नहीं।\* सार अर्थ यह है कि स्वाभयता केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं स्वीकार करना चाहिए। हाल में ही अखिल भारतीय नयी तालीम के द्वादशवें सम्मेलन के उद्बोधन भाषण में डा० बाकिर हुसैन ने उत्पादक कार्य (प्रोडक्टिव वर्क) का यथार्थ रूप समझाते हुए कहा :

मेरी समझ में एज्युकेशन प्रोडक्टिव वर्क का नाम ही ‘शिक्षा’ है। यह काम अमल में मल्टिप्ल का काम है, कभी हाथ के काम के साथ, और कभी हाथ के काम से अलग। यह हाथ का काम भी हो सकता है, और मल्टिप्ल का काम भी।‡

द्वितीय आशेष यह है कि एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा पूर्ण शिक्षा देना। इस विषय में अनेक प्रश्न किये जाते हैं : क्या केन्द्रीय उद्योग-द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है ? और क्या हमने साहित्यिक शिक्षा नीति नहीं हो जानी है ? क्या हम शिक्षा के द्वारा बौद्धिक एवं व्यावहारिक माध्यम से प्रत्येक विषय का बीना-बीना पढ़ाया जा सकता है ? इत्यादि अब पदस्थ प्रश्न तीजिए और बुनियादी पाठ्यक्रम

† *Hindustani Talimi Sangh, Educational Reconstruction*, 1930 p. 56.

‡ *Education in India, 1950-51*, Vol. I, p. 77

\* Ram Kishore, *op. cit.*, p. 229.

† द्वादश बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, नवम्बर, १९५०।

पर दृष्टि-निक्षेप कीजिए। इस दृष्टिगत से ज्ञात होगा कि पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों का यथेष्ट समावेश है, और हमका उद्देश्य एक समन्वित एवं सर्वांगीण शिक्षा देना है। पुस्तकों के पढ़ने के साथ-साथ बच्चों को अपने हाथ तथा अपनी बुद्धि को उपयोगी कामों में लगाने की क्षमता प्राप्त होनी है। अपनी मातृभाषा, राष्ट्र भाषा, स्वदेश का इतिहास, साधारण विज्ञान, इत्यादि साहित्यिक विषयों के सीखने के सिवा यह इस देश का एक उपयुक्त नागरिक तैयार होता है। सागस्य यह है कि प्रचलित पाठ्यक्रम की अपेक्षा बुनियादी पाठ्यक्रम वहीं अधिक स्वाभाविक, प्रेरणादायक तथा मनोवैज्ञानिक है।

दूसरी शंका के उठने का मुख्य कारण है योजना की भ्रामक समय माहिणी, जिसके ५६ घण्टे के दैनिक कार्यक्रम में ३ घण्टे २० मिनट केन्द्रीय दम्पकारी के लिए और केवल दो घण्टे साहित्यिक विषयों के लिए निर्धारित किये गये हैं। इस भ्रम को मिटाने के लिए जाकिर हुसैन समिति की द्वितीय रिपोर्ट का निम्नांकित अंग पढ़ना आवश्यक है :

आधारभूत कौशल के लिए निर्धारित समय की त्रुटि टीका टिप्पणी हुआ करती है और कहा जाता है कि इसके कारण साहित्यिक विषयों पर अपेक्षा होती है। ... .. इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि केन्द्रीय दम्पकारी के लिए बँधा हुआ पूरा समय केवल गित-संगीत पर अभ्यास में नहीं व्यय हो जाता, बल्कि निर्धारित समय का यथेष्ट भाग दम्पकारी में सम्मिश्रित मौखिक कार्य, भाषा-अभिव्यञ्जन तथा वैयक्तिक परस्पर होना है। इसके सिवा, शिक्षार्थियों का उपयोग प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप अपनाए हुए विज्ञान का क्या और कहां का परिचय दिया जाता है। १

यहाँ तक सभी सहमत होने हैं, पर बुनियादी योजना में हस्त-कौशल के साथ पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का अवतरोपग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है। समतुल्य सहज तथा स्वाभाविक होना चाहिए। यदि हम यद्यपि में अधिक ग्रीचनान की जगह से हस्त-कौशल तथा योग्यता यह जाता है। सब विषयों का प्रत्येक भाग समतुल्य भाग सभी की नहीं सिखाया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा के दिग्गजों ने हम बच्चों को सीप ही समता दिया और ऊँहने हने हडाने की कोसिस भी की। मन् १९३९ के अक्टूबर में नयी तारीफ के समेतन ने निर्णय किया :

५. बुनियादी शिक्षण में समवाय-का-प्रयोग ज़रूरती न किया जाय । समवाय की स्थापना केवल केन्द्रस्थ दस्तकारी के साथ ही तक सीमित न रहे । यह समवाय बच्चों के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से भी सम्बद्ध किया जाय ।†

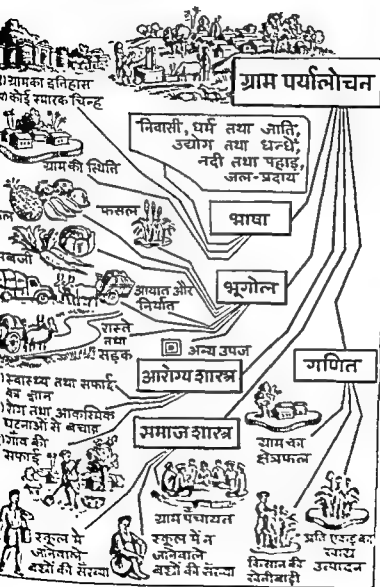
असल में इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थीगण जो उद्योग करते हैं, उस उद्योग के आसपास जो ज्ञान सहज-प्राप्य हो, वह उन्हें देना चाहिए ।

हाल में ही केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने अंग्रेजी भाषा में 'बुनियादी शिक्षकों की पुस्तिका' (The Hand-book for Teachers of Basic Schools) प्रकाशित की है । इस पुस्तिका ने बुनियादी शिक्षण-पद्धति तथा विशेषतः समवाय के यथार्थ रूप पर नवीन प्रकाश डाला है । पुस्तिका में ठीक ही समझाया गया है कि बुनियादी पाठ्य-क्रम कार्य-कलाप पर निर्भर है । इसका उद्देश्य है विविध विषयों के पृथक्त्व को दूर करना तथा उन अंशों को समन्वित करना जो सहज में ही जोड़े जा सकें । इसके सिवा बुनियादी शिक्षा जोर देती है कि समग्र तालीम जीवन के जीते-जागते नाकार तथा जहाँ तक हो सके उत्पादक अनुभवों के मार्फत ही जाय । इसी प्रकार प्रत्येक बुनियादी दस्तकारी शिक्षणीय अवश्य हो; पर इसके साथ-साथ वह स्वाभाविक वातावरण के अनुकूल हो । चित्र ५ में एक कार्य-कलाप-केन्द्रित कार्य-क्रम का रूप समझाया गया है । इस आकृति से यह भी स्पष्ट होगा कि आशय-पूर्ण कार्यों-द्वारा विद्यार्थीगण किस प्रकार अपने स्थानिक वातावरण का अपने अध्ययन में उपयोग कर सकते हैं । इससे यह भी स्पष्ट होगा कि समवाय केवल केन्द्रीय दस्तकारी तक ही मर्यादित नहीं है । इसकी सीमा और भी विस्तृत है ।

इन आक्षेपों के सिवा, बुनियादी शिक्षा की और भी बहुत कुछ तुलनाचर्चा होती रहती है, जैसे: हम शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया ग विद्यार्थी की रुचि का ध्यान किये बिना ही हम उस पर एक दस्तकारी स्टाद देते एक ही प्रकार के या कुछ इने-गिने हस्त-कौशल के साथ भाषा-पन्थी करते-करते क्रम उसमें उपगमता हो जाती है, योजना में केवल गाँवों की आवश्यकता का ध्यान र गना है, अध्यापक के व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रह गया, इत्यादि । जहाँ तक सचा है, बुनियादी शिक्षा के कार्य-कर्त्ताओं ने इन भ्रष्टियों को दूर करने की चेष्टा हाल ही की है ।

# बुनियादी शिक्षा में समवाय

## कार्यकलाप: ग्राम पर्यालोचन



**कुछ गुण.**—यह निर्विवाद है कि इस शिक्षा-योजना ने भारत के शिक्षा-क्षेत्र में एक हलचल-सी मचा दी है। इसका जन्म नये गमाज और नये मनुष्य की रचना के विचार में हुआ था। देश में सड़ियों से गुलामी की बेड़ियों पड़ी थी। अपनी दूर दृष्टि ने गान्धीजी ने यह देख लिया था कि भारत की उन्नति के लिए शिथिल नयी वृत्ति, बुद्धि, भावना और शक्तियुक्त गमाज की आवश्यकता है। पर देश की शारीरी तथा निश्चरता इस दिशा में पद-पद पर बाधा डाल रही थी।

यही कारण है कि गान्धीजी ने एक ऐसी योजना हमारे सामने रखी, जिसके द्वारा तमाम लड़के और लड़कियों को सात साल तक मुफ्त और लाजिमी तालीम मिल सके। चूंकि अनिवार्य शिक्षा-योजना बिना पैसे के नहीं चल सकती है, इस कारण उन्होंने एक स्वाध्यायी योजना की परिकल्पना की। पर स्वाध्याय तो हम शिक्षा की प्रासंगिक बात थी। इस विचार ने देश में एक लहर-सी लहरा दी और प्रत्येक भारतवासी अनुभव करने लगा कि उनकी मातृ-भूमि की उन्नति अनिवार्य शिक्षा पर निर्भर है। हम तरंग के आगे अग्रज सरकार न टिक सकी।

गान्धीजी की बनवायी हुई योजना में बहुत महत्व की दूसरी बात यह थी कि बुनियादी शिक्षा केवल शब्दों और किताबों की शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन की शिक्षा है। आदमी के जीवन के तीन बड़े-बड़े क्षेत्र (परकृज) हैं: एक, उसका प्राकृतिक वातावरण; दूसरा, उसका सामाजिक वातावरण; और तीसरा, उसका काम। इस योजना में अहिंसा के अनुसार, इन्हीं तीन को शिक्षा का परकृज भी माना गया है। जैना कि डाक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, “इसमें बच्चों के लिए एक काम होगा। ऐसा काम जिससे कुछ काम की चीज़ बने, जो उनके अपने काम आ सके या उसके साथियों और पड़ोसियों के काम आ सके।” †

पर इस योजना में खाली काम शिक्षा का परकृज नहीं है, बच्चे का प्राकृतिक वातावरण भी है। मौखिक ग्यन्त के बदले यह शिक्षा बच्चों को सृजनात्मक कार्य के लिए तैयार करती है। इसके कारण शिक्षा में एक नयी जान आ गयी है, कक्षाओं की पुरानी नीरसता समाप्त हो गयी है, ग्यन्त विद्या के बदले विविध प्रकार के रचनात्मक शारीरिक कार्य होने लगे हैं। अब कक्षाएँ मानों हँसने लगी हैं और छात्रों में परिश्रम के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। पर सबसे उल्लेखनीय परिणाम यह है कि हमें हमारे देश के प्रचलित शिक्षा के अंग-प्रत्यंग के दोष दृष्टि में आने लगे। हम अनुभव करने लगे कि देश की शिक्षा-नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

† द्वादश आबिल भारतीय नयी तालीम सम्मेलन — उद्बोधन भाषण।

इस शिक्षा का 'बुनियादी' नामकरण क्यों हुआ ? इसके मुख्य तीन कारण हैं :

१. यह शिक्षा इस राष्ट्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति, संस्कृति तथा शिक्षा मण्डन की नींव पर खड़ी है ।

२. यह शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को वह ज्ञान देती है जो उसके लिए अपने यातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने तथा प्रयोग करने के लिए आवश्यक है ।

३. यह शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य जीवन के निर्वाह की क्षमता देती है ।

नयी तालीम के कट्टर विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि इस शिक्षा में स्वाधीन भाग्य के बच्चों के मानने तथा आदर्श उपस्थित किया है । प्रत्येक योजना में कुछ-न-कुछ त्रुटियाँ हो ही सकती हैं । समय और अनुभव उन त्रुटियों को दूर करने का सामर्थ्य देता है ।

**उपसंहार.**—इतना होने हुए भी नयी तालीम की सन्तोषप्रद प्रगति नहीं हुई । सन् १९५६-५७ में, अवर बुनियादी स्कूलों और पुराने प्राथमरी स्कूलों की सख्या क्रमशः ४६,८८१ तथा २,४०,४१७ थी । इसी प्रकार उस वर्ष प्रवर बुनियादी स्कूलों तथा पुराने मिटिल स्कूलों की तादाद क्रमशः ६,८९७ तथा १७,५८९ थी;† अर्थात् पुरानी समस्याओं की सख्या प्रायः त्रैगुनी थी । यह स्थिति उस समय की है, जब सरकार ने ६ से १४ वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए नयी तालीम को अपनाना स्वीकार किया । इस मन्थर गति के अनेक कारण हैं । एक सरकारी रिपोर्ट ने स्वीकार भी किया है, "बुनियादी शिक्षा एक नवीन प्रयोग है । इसे पद-पद पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है : उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, अधोभाव तथा शिक्षा-साधनों की स्थिति ।"‡

असन्तोषप्रद प्रगति के और भी अनेक कारण हैं । नयी तालीम को चले हुए साईस वर्ष बीत गये, पर लोग इस शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सके । जैसा कि अनुमान-निर्धारण समिति ने महसूस किया है कि "बुनियादी शिक्षा के विषय में सही धारणा का अभाव है, और अभी भी अधिकतर लोगों को इस सम्बन्ध में ठीक

† *Education in the States, 1956-57*, p. 2

‡ *Ten Years of Freedom*, II 3.



ज्ञान नहीं है। जहाँ भी कहीं समिति के सदस्य गये, वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि बुनियादी शिक्षा की अलग-अलग रीति से व्याख्या की जाती है — ऊँचे पद के लोगों के द्वारा भी।”†

मुख्य प्रश्न यह है कि बुनियादी शिक्षा की स्पष्ट धारणा क्यों नहीं हो पायी है? इसका एक प्रधान कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में बुनियादी शिक्षा के भिन्न भिन्न रूप हैं। कहीं प्राथमिक चरण में चार वर्ष की पढ़ाई हो रही है, कहीं पाँच वर्ष की और कहीं छः वर्ष की। कुछ स्कूलों में एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा शिक्षा दी जा रही है और कहीं दूसरे विषयों के साथ एक उद्योग सिखाया जाता है। जब सम्पूर्ण देश के प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा ही अपनायी जायगी तब अत्यावश्यक होगा कि बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा का एक ही स्वरूप सारे देश में चालू किया जावे। राज्य सरकारों से मिलकर, केन्द्रीय सरकार इस नीति को स्पष्ट करे।

बुनियादी शिक्षा के समर्थकों में हम दो मत देखते हैं : कट्टरपन्थी और उदारपन्थी। कट्टरपन्थी गांधीजी के आदर्श पर चल्ना चाहते हैं। वे नयी तालीम के मूल रूप में विशेष परिगर्तन नहीं चाहते हैं। वे समग्र नयी तालीम पर आस्था रखते हैं तथा उसे आमतौर रूप में रखना चाहते हैं। उदारपन्थी खैर समितियों तथा सार्वजनीन योजना द्वारा निश्चित मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। वे नयी तालीम की महत्ता अवश्य स्वीकार करते हैं, पर स्याभयता का समर्थन वे नहीं करते हैं।

उदारपन्थी अनुयायियों में भी दो भेद हैं। प्रथम ढल बुनियादी शिक्षा की अवधि (६-१४ वर्ष) को दो हिस्सों (अवर और प्रवर) में बाँटने का पक्षपाती है। द्वितीय इस बात का विरोध करता है। उसका कथन है कि यह बाँट बुनियादी शिक्षा में दोर लागू। कारण, इस शिक्षा में दस्तकारी का महत्वपूर्ण स्थान है। आठ वर्ष के प्रतिष्ठित — सतत — अभ्यास के बिना, उद्योग-द्वारा शिक्षा ठीक ठीक प्रतिफलित नहीं हो सकती।

यह मत-भेदों के कारण, नयी तालीम की धारणा स्पष्ट नहीं

... शिक्षा में वैसी ही नियम-निष्ठा आ गयी है, जैसी कि वर्तमान है। नयी तालीम की भिन्न-भिन्न क्रियाओं के बिन्दु हैं। यदि किसी भी कार्य-क्रम के तालीम करने में योदीकी



हर्ष की बात है कि अनुमान निर्धारण-समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि ग्राम-पुनर्रचना तथा बुनियादी शिक्षा साथ-साथ चले। समिति ने यह सुझाव दिया है कि ग्राम-पुनर्रचना से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारीगत बुनियादी शिक्षा के विभाग में सहयोग देगे।

बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरियाँ यह हैं कि यह योजना वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। चूँकि सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा को अपना लिया है, इस कारण अवर और प्रवर बुनियादी स्कूल काफी खुल गये हैं और खुलते जा रहे हैं। पर इसके बाद के चरणों का कुछ विशेष पता नहीं चलता। ग्यारह उच्च शिक्षाग्राम-प्रतिष्ठान अवश्य खुल गये हैं, पर उत्तर-बुनियादी स्कूलों की संख्या तीस से भी कम है। इसके विपरीत पूरे देश में बारह हजार से अधिक माध्यमिक स्कूल तथा एक हजार कालेज हैं, और इनकी संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर एवं उत्तम बुनियादी शिक्षा की स्थिति शोचनीय है और पुराने दरों की शिक्षा-संस्थाओं की माँग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

बिहार के उत्तर-बुनियादी स्कूलों पर विचार करते हुए, एक सरकारी रिपोर्ट ने कहा है, “पुराने माध्यमिक स्कूल अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोगों में मैट्रिक सर्टीफिकेट की चाह अधिक है।”† अनुमान-निर्धारण समिति ने भी बुनियादी शिक्षा की कठिनाइयों को अनुभव किया। इसी कारण समिति ने सुझाव दिया है कि उत्तर-बुनियादी शालाओं की स्थापना और बुनियादी संस्थाओं का अन्य संस्थाओं के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है।‡

यह मानना ही पड़ेगा कि हम देश की शिक्षा-वृद्धि में अनेक दोष आ गये थे, और इनके सुधार की ज़रूरत थी। बुनियादी विचारधारा ने भारतीय शिक्षा-संसार में एक नवीन जीवन का सञ्चार किया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा-क्षेत्र में दो विभिन्न धाराएँ प्रवाहित होने लगे, और जिनके मन्तव्य मार्ग एक दूसरे के सर्वथा प्रतिरुद्ध हों। पर ग्रेट की बात है कि आज हमारे देश के शिक्षा-शास्त्रियों में दो दल हैं — बुनियादी और गैरबुनियादी। इन दोनों दलों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। पर होद देश के लिए हितारह एवं भेदभर नहीं है। समझे अच्छा तो यह हो कि ये

† Education in India, 1951-52, Vol. I, p. 75

‡ इतिहास, पृष्ठ ५०।

विभिन्न धाराएँ विरुद्ध दिशाओं में न जाकर एक साथ मिल जावें। इस सम्मिलित प्रवाह में हमारी शिक्षा में व्याप्त समस्त दोषों का प्रभालन हो जायगा।

बुनियादी शिक्षा 'नूतन' शिक्षा है। हमने हमारे सामने नवीन विचार उपस्थित किये हैं — सृजनात्मक शिक्षा, रचनात्मक कार्य, कलात्मक कृतिशौ, परिश्रम के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास, मातृ-भाषा के प्रति श्रद्धा, चाक्ष परीक्षाओं की परिमामानि, भागतीय सृति तथा मभ्यता का सम्मान, समाजसेवा, शिक्षा का विद्यार्थी के भावी जीवन से सम्बन्ध, देश की आवश्यकताओं का ध्यान, इत्यादि। हमें इस नवीन रस में अपनी पुरानी शिक्षा-संस्थाओं को परिप्लवित कर देना चाहिए ताकि वे इस नूतन शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण को आत्मसात कर लें। कुछ सङ्कलने हुए उत्तर-बुनियादी स्कुलो तथा अथ शिक्षा प्राम-प्रतिष्ठानों द्वारा ही इस देश का काम नहीं चल सकता है। हमारे देश में एक मुड्ड तथा विशाल शिक्षा-अट्टानिका की जरूरत है, न कि दो विभिन्न या कमशोर इमारतों की। शिक्षा की उन्नति विकासवाद द्वारा हो सकती है, न कि पं परिवर्तन के द्वारा।

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में एक नवीन प्रकार की शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। इसका प्रभाव देश की समूची प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था पर पड़ा।

**इंस्ट इंस्ट्रिया कम्पनी की नीति.**—अनेक कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कम्पनी ने अंग्रेजी बच्चों में कुछ प्राथमिक स्कूल खोले। कम्पनी ने इस देश में भी अपने ही देश की शिक्षा-नीति अमल की तथा सर्वव्यापक शिक्षा का उत्तरदायित्व पूर्णतः स्वयं न उठाना चाहा। न उनके पास पैसा था, और न अग्रहारा। कुछ के योगदान-पत्र के बाद सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की ओर कुछ ध्यान दिया। इस पत्र ने सिफारिश की कि देशी विद्यालयों को मान्यता दी जाये तथा अधिक संख्या में प्राथमिक स्कूल खोले जायें। इसके फल-स्वरूप कुछ सरकारी स्कूल खोले गये, और गैरसरकारी स्कूलों को ग्राण्ट (अनुदान) मिलने लगा। पर अर्थाभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा की दशा ज्यों की त्यों रही।

**हालेण्ड के नरेशों का शासन (१८५७-१९०२).**—सन् १८५९ ई० में स्टेनले का आशा-पत्र निराला। इस पत्र ने यह अंगीकार किया कि अर्थाभाव तथा ग्राण्ट-इन-एड की अभावता के कारण प्राथमिक शिक्षा गिरती हुई दशा में है। पत्र ने यह भी स्वीकार किया कि जन-साधारण की शिक्षा सरकार का मुख्य कर्तव्य है। उसे इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए स्थानीय कर भी लगाना चाहिए। इन सिफारिशों का परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय सरकारों अपने स्कूल खोलने लगीं तथा बङ्गाल को छोड़कर सभी प्रान्तों में स्थानीय कर के कानून पास हुए। इस्तमगरी बन्दोबस्त (स्थायी भू-व्यवस्था) होने के कारण यह कर बंगाल में नहीं लगाया गया। सन् १८७१ ई० में लाई मेयो ने प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा-विषयक अनेक अधिकार दिये और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा के व्यय के विषय में कुछ निश्चित आदेश भी दिये। इन प्रयत्नों के फल-स्वरूप १८७०-७१ से १८८१-८२ तक प्राथमिक शिक्षा का यथेष्ट विस्तार हुआ। सन् १८८३-८४ ई० में लाई रिपन ने 'लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट एक्ट' पास किया। इसके अनुसार भारत के शहरों, कस्बों और जिल्लों का प्रबन्ध करने के लिए नगरपालिका समितियाँ और जिला मण्डल स्थापित हुए। उन्हें प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्ध का विशेष अधिकार दिया गया, और सरकार इसके प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से मुक्त हो गयी। परन्तु स्थानीय बोर्डों के अर्थाभाव के कारण प्राथमिक शालाओं की प्रगति मलीमोति नहीं हो पायी। सन् १९०४ ई० की शिक्षा-नीति को कहना ही पड़ा :

## प्राथमिक शिक्षा

साधारणतः यह गणना की जाती है कि किसी भी देश की का १५ प्रतिशत स्कूल में पढ़नेवाले बच्चे होते हैं, पर दुःख यह है कि इस वर्ग के एक-पाँच बच्चों को भी भारत मिलती है। सग्नति शिक्षा की प्रगति रुकी हुई है। स्पष्ट है कि और न विशेष ध्यान दी दिया जाना है, और न विशेष हुआ है।†

**असन्तोषजनक स्थिति के कारण.**—इस प्रकार उन्नीस प्राथमिक शिक्षा की विशेष उन्नति नहीं हुई। शिक्षा-नीति में अनेक इस शिक्षा की दशा गिरती हुई रही। प्रथमतः, सरकार ने देशी शिक्षा को न दी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है हमारे सभी गाँवों में प्रायः स्कूल अवस्थित थे, पर वे धीरे धीरे टुम हो गये। यह बात अवगत थी। दोष था गये थे। इन्हें सुधारने का प्रयत्न तत्कालीन अंग्रेजी शासन के था, पर देशी स्कूल निरक्षर ठहरा दिये गये। उनकी प्रतिष्ठाविता में और जातिधर्म की स्थापना हो गयी। हमारा पुरानी समझाएँ मन्त्र इन बातों तक सामना कर सकनी थीं? फलतः, अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के विधीन हो गये। भारत में जहाँ बोलने-बोलने में देशी स्कूलों का जाल सा घरो उँगलियों पर गिने जाने वाले थे आपुनिक प्राथमरी स्कूल स्थापित होने-गिने सहरी और घरे-घरे कूटों में।

**दिनांकतः,** ई.स. १८५८ ई. में ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन शिक्षा-नीति अथ 'शिक्षा छनने का सिद्धान्त' कहते हैं। ई.स. १८५८ ई. में ब्रिटिश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। विविध समाज को उच्च शिक्षा दी जाये, और इसी शिक्षित समाज में और शिक्षा प्रसार पढ़ाया जावे। प्रसिद्ध लेखक मेल्ट कहते हैं :

सरकार सोचती थी कि राज्य में शिक्षा जनता की ओर

पर ऐसा न हुआ। सरकार ख्याली पुन्यव ही पकानी रही। उसने जो कुछ सोचा था, वह मृग-तृष्णा मात्र रहा। शिक्षित समाज ने जनता की ओर अग्रसर होने के बदले, उधर से मुँह मोड़ लिया। जो धारा नदी के रूप में विस्तृत होनेवाली थी, वह एक प्रवाह-विहीन उथली तलैया बनकर गढ़ गयी!!

तृतीयतः, अंग्रेजों ने यह कभी अङ्गीकार नहीं किया कि प्राथमिक शिक्षा दी जावे। हण्डर कमीशन की ६०० पन्नोंवाली रिपोर्ट में, अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। अंग्रेजों का हर समय यही कहना रहा कि अनिवार्य शिक्षा भारत के लिए दिया-स्वप्न है। पर सबसे अचम्भे की बात यह है कि अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन विश्व में सबसे पहले इंग्लैण्ड से ही आरम्भ हुआ था।

उपर्युक्त तीन मूल शिक्षा-नीति के सिवा, उन्नीसवीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा के अस्तन्तोपप्रद प्रसार के अन्य कारण भी हैं :

१. केन्द्रीकरण राजनीति.—जिसके कारण देहाती भारत की उपेक्षा की गयी थी। स्मरण रहे कि ८० प्रति शत भारतवासी देहात में रहते हैं।

२. भारतीय उद्योगों के प्रति उदासीनता.—जनता के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कोई भी विशेष चेष्टा नहीं की गयी।

३. शिक्षा का तिरस्कार.—सन् १९०१-०२ में समूचे देश का शिक्षा-व्यय सिर्फ १,०२,७८,६५९ रुपये था। यह रक्तम देश की आय का ०.८८ प्रतिशत भाग था।

### अनिवार्य शिक्षा-आन्दोलन

प्रारम्भिक प्रस्ताव.—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सब से प्रथम सुझाव एडम साद्वि ने सन् १८३८ में दिया था। उनका कहना था कि एक ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक गाँव कम-से-कम एक प्राथमिक स्कूल चलावे। सन् १८५२ में, बम्बई प्रान्त के लिए रेवन्यु सर्वे कमिश्नर कप्तान किन्गेट ने प्रस्ताव किया कि जमीन की आय का पौंच प्रति शत कर शिक्षा के लिए लगाया जाय और इस रकम से ii के वर्गों को अनिवार्य शिक्षा दी जावे। इसके बाद वर्ष पश्चात् गुजरात के जे. के. इन्स्पेक्टर भी टी. सी. होप ने सिफारिश की कि एक ऐसा कानून अमल में लाय, जिसके अनुसार किसी भी जगह के निवासियों को स्कूल खोलने के लिए





अपने गान के अन्तर्गत गानों में निःस्वार्थ अनित्यता के प्राथमिक शिक्षा दी गई थी। तत्पश्चात् सन् १९१६ ई० में, इसका विचार अपने पूर्व गान में कर दिया।

**स्वर्गीय गोकुल के प्रयास.**— अन्तिम गान में स्वर्गीयों ने अनुमति दिया कि स्वयं अपने पास पर गाने हुए अन्तिम भाग में शिक्षा दी उपरि अग्रगण्य है। इस आन्दोलन के कारण प्रतिष्ठित गानों में गानों की शक्ति का प्रयोग हुआ। सन् १९१० में उन्होंने इन्हीं विचारों के प्रतिष्ठित का अन्तिम में प्रयोग रखा। उन प्रयास का आगमन यह था कि भारत के उन भागों में जो वे हमारे देश के लोगों की अनित्यता तथा निःस्वार्थ शिक्षा दी जाये, वहाँ पर ११ प्रतिष्ठित गानों का अन्तिम है। किन्तु सरकार के आदेशानुसार देने पर गोकुल ने अपना यह प्रयास वापस ले लिया।

पर जो सरकार ने आशागत के कारण कुछ न किया, तब दूसरे वर्ष भी गोकुल ने अपना दूसरा विधेयक का अन्तिम में उपस्थित किया। विधेयक की शक्ति बहुत ही साधधानी से रखी गयी थी। मुख्य शक्ति ये थी : (१) यह योजना केवल उन स्थानों में प्रयुक्त की जाये, जहाँ पर ६ से १० वर्षों के बच्चों (बालक-बालिकाओं) के एक निर्धारित प्रतिष्ठित को शिक्षा मिल रही हो। (२) अनित्यता शिक्षा पहले बालकों के लिए लागू की जाये, और बाद में प्रत्यक्ष लड़कियों के लिए व्यवहृत की जाय। (३) इस योजना को अपने सम्पूर्ण अधिकार-क्षेत्र या उसके कुछ भाग विशेष में एकदम लागू न करने का अधिकार स्थानीय शासकों पर छोड़ दिया जाय। (४) अनित्यता शिक्षा का रखे चलाने के लिए प्रत्येक स्थानीय मण्डल को कर लगाने का अधिकार दिया जाये। (५) योजना को अन्तिम में रखने के लिए प्रान्तीय सरकार की अनुमति अपेक्षित है।

विधेयक पर दो दिनों तक गरमागरम बहस हुई। पर ५१ सदस्यों में से केवल ११ सदस्यों ने श्री गोकुल का समर्थन किया। सरकारी एवं अर्मीदार सदस्यों ने घोर विरोध किया, किन्तु गोकुल हतोत्साह न हुए। उन्होंने अपनी बहस को समाप्त करते हुए कहा था :

मैं जानता था कि सन्ध्या तक मेरा विधेयक उल्लाङ्घन कर दिया जायगा। इस पर मुझे न कोई शिकायत है और निराशा ही है। ... मैं सदैव सोचता हूँ और कहता हूँ कि इस पीढ़ी के भारतवासी अपनी मातृ-भूमि की सेवा अपनी असफलताओं के द्वारा ही कर सकते हैं। ... कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए असफलता अकर्मण्यता में अन्तर्भूत है।†

**उपसंहार.**—पर गोल्वले के प्रयास सर्वथा निष्फल न हुए। सन् १९१०-१९१७ के बीच, प्राथमिक शिक्षा का गैरसरकारी प्रसार हुआ। तब सरकार भी चुप न रह सकी। सन् १९११ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय अधि-सुपरी-टरी को प्राथमिक शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सन् १९११-१२ में इस देश में सम्राट् पद्मम आर्च का शुभागमन हुआ। उन्होंने दिल्ली दरबार में पंचाम लाम्प रुपये का आवर्तक वार्षिक अनुदान प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्वीकृत किया। सन् १९१३ ई० में भारत सरकार ने अपनी शिक्षा-नीति में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह आदेश प्रसारित किया :

१. प्राथमिक शिक्षा में निम्न-प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार और विस्तार किया जाय।

२. केन्द्रीय ग्रामों में उच्च-प्राथमिक स्कूल अधिक माल्या में खोले जायें।

३. साधारणतः प्राथमिक शिक्षा का प्रसार बड़े स्कूलों के द्वारा हो। जहाँ यह न हो सके, वहाँ स्वीकृत स्कूल 'ग्रान्ट इन-एड' पद्धति पर खोले जायें।

इसी अवसर पर प्रथम विश्व-युद्ध शुरू हुआ। इस कारण ऊपर के प्रसार कार्यान्वित न किये जा सके। युद्धकाल में भारत को अनेक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा। पर अन्त में सन् १९१९ ई. में इंग्लैंड की सरकार ने भारतवासियों को माण्डेयू-वेमगेरेट्टे सुधार प्रदान किये। भारत सरकार की शिक्षा नीति पर इस सुधार का अनुकूल प्रभाव पड़ा।

**मन्त्रिपरिषद् शिक्षा का प्रसार (१९१८-४०)**

**पहले मन्त्रीमण्डल-परिषद्.**—सन् १९१९ ई० में माण्डेयू वेमगेरेट्टे सुधारों पर कार्य आरम्भ हुआ। इसके अनुसार शिक्षा हस्तान्तरित होकर भारतीय मन्त्रियों के हाथ आ गयी। तत्परन्तु मन्त्रीमण्डल आर्चु हटिंघम एक्ट (१९२५) ने भारतीय सरकार में पूर्ण हस्तगत प्रविष्टि किया। इनके पक्ष में भारतीय मन्त्रियों ने बड़े परिश्रम और उत्साह से काम किया, और अन्त में शिक्षा का कार्य उत्तर दिया। इसी समय (१९१९-१९२०) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लार्डोले का उद्घरण हुआ। उन्होंने भारतीय सरकार को एक नया रूप दिया। उनकी प्रेरणा ने यह आन्दोलन देश के कोण-कोण और घर-घर में फैला। समस्त देश में एक नया जेठ खिल रहा, और मन्त्री

यह अनुभव लिया कि स्थगनना-प्राप्ति के बाद भारत का नाम शिक्षा के अन्तर्गत न रखा गया; अतएव शिक्षा परम आवश्यक है।

**अनिवार्य शिक्षा के कानून.**—अगस्त, १९१७ की गोवर्णा के बाद सभी अंग्रेजी प्रान्तों की विधायिका सभाओं के सदस्यमग नियुक्ताना दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन तो स्वर्गीय गोवर्ने से पहले ही तैयार कर रही थी। उन्होंने जो बात समूचे देश के लिए चाही थी, उसे भी विद्वत्भार पटेल ने बम्बई के लिए कर दिखाया। सन् १९१७ ई० में उन्होंने बम्बई प्रान्त के, बम्बई नगर को छोड़कर, नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा जारी करने के उद्देश्य से प्रान्तीय धारा सभा में एक विधेयक उपस्थित किया। दो छूटों को छोड़कर यह बिल गोवर्नेजी के विधेयक से निम्नता जुलता था : (१) यह बिल केवल नगरपालिका के क्षेत्रों के लिए लागू होता था, पर गोवर्नेजी के विधेयक में गाँव भी शामिल थे। (२) सरकार पर आर्थिक जवाबदेही नहीं रखी गयी थी। पर यदि सरकार चाहे तो अनिवार्य शिक्षा के कुल खर्च का एक भाग, जिसे वह स्वयं निश्चित करे, दे सकती थी। श्री गोवर्ने के विधेयक की शर्तों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के दो-तिहाई खर्च की जिम्मेवारी सरकार पर रखी गयी थी।

श्री विद्वत्भार का विधेयक पारित होकर “बम्बई प्राथमिक एजुकेशन एक्ट, १९१८” के रूप में प्रसारित हुआ। प्राथमिक शिक्षा का यह सबसे प्रथम कानून है। इस एक्ट ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की सार्वजनिक माँग को वैधानिक स्वीकृति दी। इस कानून से भारत के दूसरे प्रान्त भी प्रभावित हुए बिना न रहे। सभी प्रान्तों में थड़ाथड़ा अनिवार्य शिक्षा के फायदे बनावे गये। सामान्यतः ये कानून एक दूसरे से मिलते-जुलते-से हैं, और वे गोवर्ने-बिल या पटेल-एक्ट के आधार पर बनावे गये हैं। जो स्थानीय मण्डल अनिवार्य शिक्षा की इच्छा करते हैं, वे पहले स्थानिक आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वे अनिवार्य शिक्षा की एक योजना तैयार करते हैं। यह योजना मण्डल के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से उनकी विशिष्ट बैठक में पारित की जाती है। इसके पश्चात् प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, जो अत्यावश्यक होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि अनिवार्य शिक्षा मण्डल-क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग में लागू की जावे। यह धीरे-धीरे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में लागू की जा सकती है। शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय मण्डल शिक्षा-कर लगा सकते हैं।



इस प्रकार सन् १९५५-५६ ई० में जो कुल खर्च हुआ, सरकार ने उसके प्रा-  
 तीन-चौथाई का खर्च उठाया। समय-समय पर केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को का-  
 रकम अनुदान के रूप में देती है। लेकिन यह रकम निश्चित नहीं रहती है।  
 स्थानीय मण्डलों, दान तथा दूसरे स्रोतों का अंश-दान विशेष सराहनीय नहीं है।  
 जिन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, यहाँ शिक्षा निःशुल्क है। दूसरे क्षेत्रों  
 भी सरकार तथा स्थानीय मण्डल मुफ्त शिक्षा देते हैं। गैरसरकारी स्कूलों में फी  
 लगती है। सन् १९५५-५६ में समूचे देश के प्रत्येक प्राथमिक छात्र का औसत  
 वार्षिक खर्च २३-४ रुपये था।

**प्राण्ट-इन-एण्ड पद्धतियाँ.**—इसकी चर्चा तीन स्तरों में की जा सकती  
 है — केन्द्रीय-राज्यीय अनुदान, राज्यीय-स्थानीय अनुदान और स्वसंचालित सत्याम  
 को राज्यीय या स्थानीय अनुदान। प्रथम अनुदान सदैव अनिश्चित रहता है। यह रकम  
 केन्द्रीय योजनाओं तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहती है। द्वितीय अनुदान-नीति  
 पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। वर्तमान  
 तरीकों का सार नीचे दिया गया है :

१. खण्ड अनुदान-नीति — मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में  
ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर है  
 इस कार्य के लिए राज्य-सरकार उन्हें एक निश्चित रकम द्वारा मदद  
 करती है।

२. कुल खर्च का एक निर्दिष्ट प्रति शत अनुदान (विहार, बम्बई,  
 पंजाब) — राज्यीय सरकार स्थानीय मण्डलों को कुल खर्च का एक बंधा  
 हुआ हिस्सा अनुदान स्वरूप देती है। यह रकम जिला-मण्डल तथा  
 नगरपालिका-मण्डल के लिए भिन्न होती है।

३. स्थानीय मण्डल अपने राजस्व का एक विशिष्ट अंश प्राथमिक  
 शिक्षा पर खर्च करता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की जिम्मेवारी अति  
 सामान्य रहती है। राज्य-सरकार खर्च का अधिक भार स्वयं उठाती है।  
 बम्बई राज्य के जिला तथा अनधिकृत नगर-पालिका-मण्डलों के लिए यह  
 प्रथा लागू है।

वर्तमान समय में पहली प्रथा उठती जा रही है। सरकार अनुभव कर रही है  
 कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर पूर्णतः नहीं छोड़ी जा सकती है।  
 दूसरी प्रथा स्कुल सोल रही है, और कई स्थानीय बोर्डों के अंशदान को



## वर्तमान स्थिति

## प्रशासन

**प्रबन्ध.**—प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध तीन विभिन्न कार्य-कर्त्ताओं के हाथ में है : (१) राज्य सरकार, (२) स्थानीय बोर्ड और (३) स्वसंचालित संस्थाएँ (प्रायः सभी को ग्राण्ट मिलता है)। इस दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों का विभाजन निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

## तालिका ५

## प्राथमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६†

अनुशासन			स्कूलों की संख्या	कुल स्कूलों का प्रतिशत
राजकीय	...	..	६४,८२७	२३.३
जिला-मण्डल	..	..	१,३३,२९६	४७.९
नगर-पालिका-मण्डल	..	..	८,९२७	३.२
स्वसंचालित संस्थाएँ :				
सहायता-प्राप्त	...	..	६७,२६३	२४.२
सहायता-रहित	..	..	३,८२२	१.४
योग			२,७८,१३५	१००.००

**अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद्.**—भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए पहली जुलाई, १९५७ को एक 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद्' की स्थापना की गयी है। इस परिषद् के मुख्य उद्देश्य ये हैं : केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह देना, प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति का निरीक्षण, प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए योजना तैयार करना, शोध तथा अनुसन्धान, शिक्षणोचित साहित्य तैयार करना, प्रारम्भिक शिक्षा का आदर्श सर्वोच्च, पाठ्यक्रम पर निवार, इत्यादि। इस परिषद् के २३ सदस्य

है: चौदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, 'केतशिप' का एक प्रतिनिधि, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् का एक प्रतिनिधि, एक प्रशिक्षण विद्यालय का अध्यक्ष, बुनियादी शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों की शिक्षा के दो-दो विशेषज्ञ। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के शिक्षा-परामर्शदाता, इस परिषद् के 'अध्यक्ष' तथा उसी मन्त्रालय के बुनियादी और समाज-शिक्षा विभाग के प्रमुख 'मन्त्री' हैं। गैरसरकारी सदस्यों का कार्य-काल दो साल निर्दिष्ट है।

विषय

स्रोतपर खर्च.—प्राथमिक शिक्षा का खर्च पाँच स्रोतों से निकलता है: सरकारी (केन्द्रीय तथा राजकीय) निधि, स्थानीय मण्डल-निधि, फीम और दूसरे स्रोत (दान, फन्डा आदि)। सन् १९५५-५६ ई० में प्राथमिक शिक्षा के स्रोतगत खर्च का विवरण अधोलिखित तालिका में दिखाया गया है:

### तालिका ६

प्राथमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष व्यय, १९५५-५६\*

स्रोत	रकम (रुपयों में)	कुल व्यय का प्रतिशत
राजकीय निधि ... ..	१९,५७,१०,६७१	७१.६
मिशन मंडल निधि ... ..	६,२४,७४,२६६	११.६
नगरपालिका निधि ... ..	४,४९,८१,०७९	८.४
फीम ... ..	१,७५,२७,१२७	३.३
दान ... ..	६२,८२,१६४	१.२
दूसरे स्रोत ... ..	१,०४,९४,७५९	१.९
कुल ... ..	२९,७२,७२,०६६	१००.००





राज देकर दोर स्वयं खुद देती हैं। स्वयंचालित संस्थाओं को स्थानीय मण्डलों के द्वारा प्राण्ट दिया जाता है। सरकार कभी-कभी स्थानीय बोर्डों को राण्ड-अनुदान भी देती है। इसका उद्देश्य यह रहता है कि इस आर्थिक सहायता-द्वारा बोर्ड अत्यावश्यक सुधारों को कार्य-रूप में परिणत कर सकें।

### अन्य प्रश्न

**स्कूल तथा छात्र-संख्या**—सन् १९४७ के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई है। सन् १९४७-४८ में देश भर में १,४०,१२१ प्राथमिक स्कूल थे। इनकी छात्र-संख्या १,१०,००,९६४ थी। आठ साल बाद प्राथमरी स्कूलों की संख्या २,१५,३२० तथा उनकी छात्र-संख्या १,७९,८५,०७४ पहुँची। पिछले अध्याय में यह बतलाया गया है कि आज भारत की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली युनियादी शिक्षा है। इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें प्राथमिक स्कूलों को युनियादी स्कूलों में बदलने की चेष्टा कर रही हैं। नये युनियादी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। तिस पर भी अधिकतर प्रारम्भिक स्कूल प्राथमिक हैं। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट होगा :

### तालिका ७

प्राथमिक तथा युनियादी शिक्षा. १९५१-५२ से १९५६-५७†

वर्ष	स्कूल		छात्र-संख्या (द्वारों में)	
	प्राथमिक	युनियादी	प्राथमिक	युनियादी
१९५१-५२	२,१५,३६६	३३,७५१	१,९०,२३	२९,८५
१९५२-५३	२,२२,४१०	३४,२२३	१,९५,५१	२९,६०
१९५३-५४	२,३९,८०८	३४,९४०	२,०८,४३	३०,३१
१९५४-५५	२,६४,१३९	३७,३९५	२,२२,४३	३१,५५
१९५५-५६	२,७८,७६८	४२,९७१	२,२९,६६	३७,३०
१९५६-५७	२,८८,०९१	४६,८५५	२,३९,०७	४१,०३

**अनिवार्य शिक्षा.**—सन् १९४७-४८ ई० में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा २२४ शहरों तथा १०,०१० गाँवों में चालू थी, तथा १९५५-५६ में १,०९३ शहरों तथा ३७,२७६ गाँवों में थी । सन् १९५१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में शहरों तथा ग्रामों की संख्या क्रमशः ३,०१८ तथा २,८५,०८९ थी । अर्थात् आज ( १९५५-५६ ) भारत के एक-तिहाई शहर तथा एक-दशांश गाँव अनिवार्य शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं । यहाँ यह ध्यान रहे कि अनेक शहरों तथा गाँवों में अनिवार्य शिक्षा सम्पूर्ण क्षेत्र में नहीं, बरन् कुछ अंशों में ही जारी है ।

**शिक्षक.**—सन् १९५५-५६ में समूचे देश के प्राथमिक शिक्षकों की संख्या ६,९१,२९५ थी । औसतन प्रत्येक शिक्षक के अधीन ३३ विद्यार्थी पढ़ते थे । पर सब से खेद की बात यह है कि एक-शिक्षकवाले स्कूलों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है । इसका अन्टाज निम्नांकित तालिका से चलेगा :

**तालिका ८**  
**एक-शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूल**

वर्ष	स्कूल
१९४९-५०	६७,७६२
१९५०-५१	६८,८४१
१९५१-५२	७१,७६२
१९५२-५३	८६,०३१
१९५४-५५	१०१,३४२
१९५५-५६	१११,२२०

**पाठ्यक्रम.**—पाठ्यक्रम में अधिकतर मानवमात्र, गणित, भूगोल, मातृ भाषा इतिहास एवं सृष्टि-विज्ञान का समावेश रहता है । पर पढ़ाई का लक्ष्य विद्यार्थियों के बानाबरन की ओर नहीं रहता है । गाँव तथा शहर के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं

है। रजत विद्या का प्रचार अधिक है। माघ ही ग्वचनात्मक कार्य का अभाव है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि सरकार का ध्येय है कि प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया जाय। इसी उद्देश्य का पहला कदम है, गैरबुनियादी स्कूलों में उद्योग की शिक्षा देना।

**शाला-गृह.**—स्कूलों की इमारतें मन्तोषजनक नहीं हैं। केवल सरकार तथा स्थानीय बोर्डों ने स्वाम शाला-गृह निर्मित कराये हैं, पर कुल छात्र मख्या का ३० प्रतिशत ही ऐसी इमारतों में शिक्षा पा रहा है। अधिकतर स्कूल किंगेय के मकानों, मरायों तथा मन्दिरो में लगते हैं। ऐसी जगहों में हवा तथा प्रकाश का नामोनिशान नहीं रहता है। वहाँ बच्चे बन्द कमरों में दूँग दिये जाते हैं।

**व्यर्थता.**—आज माध्याम जनता शिक्षा में दिलचस्पी दिग्वा रही है। तिम पर भी प्राथमिक शिक्षा में व्यर्थता की मात्रा इतनी अधिक है कि शिक्षा के विस्तार से बालविक लाभ नहीं हो रहा है। १९५२-५३ में स्कूलों में पहली कक्षा में भगती हुए प्रति १०० बच्चों में से ६४ दूसरी कक्षा में (१९५३-५४), ५१ तीसरी कक्षा में (१९५४-५५) और सिर्फ ४३ चौथी कक्षा (१९५५-५६) में शिक्षा पाने रहे।† इस प्रकार ५७ बच्चे स्थायी साक्षरता के लिए न्यूनतम माने जानेवाले चार वर्षों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पहले ही पढ़ना छोड़ बैठे। व्यर्थता के अनेक कारण हैं, जैसे: (१) अनिवार्य शिक्षा-विषयक एकटों का भली भौति पालन न करना; (२) लोगों की गरीबी; (३) माता-पिता की शिक्षा के प्रति उदासीनता; (४) पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता; (५) शिक्षक की प्रभाव-हीनता; (६) एक-शिक्षकवाले स्कूलों का बाहुल्य; (७) बहुत से स्कूलों का नाम मात्र के लिए अस्तित्व, इत्यादि।

**अधरोधन.**—व्यर्थता (अपव्यय) से मलग्न दूसरा दोष अधरोधन (स्विरता) है जो प्राथमिक शिक्षा में पाया जाता है। अधरोधन का अर्थ है बालक का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक कक्षा में प्रति वर्ष २० से ३० की मयी विद्यार्थी रोक लिये जाते हैं। सर्वाधिक निगशाजनक स्थिति पहली कक्षा की रहती है। यह कक्षा एक गैदले कुण्ड के समान बनी रहती है।

इस अधरोधन का विनाश परिणाम विद्यार्थी, माता पिता तथा पूरे गृह पर पड़ता है। अधपढ़ता के पल्ल-स्वरूप ऊँची कक्षा में न जा सकने के कारण विद्यार्थी

† Education in India, 1955-56, Vol I, p 64

# भारत में प्राथमिक शिक्षा १९५५-५६

प्राथमिक स्कूलों में  
६-११ वयोवर्ग के बच्चे



५३  
स्कूल के भीतर

४७  
स्कूल के बाहर



स्कूलों का  
बन्दोबस्त

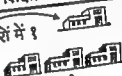


प्रति ३ गाँवों में १ स्कूल

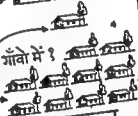


अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध

प्रति ३ शहरों में १



प्रति १४ गाँवों में १



शिक्षा-खर्च



व्यर्थता

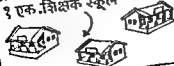
प्रत्येक पूर्ण प्रतिरूप = २०

	कक्षा १	कक्षा २	कक्षा ३	कक्षा ४
४३				१००
५१			१००	
६४	१००	१००	१००	

एक-शिक्षक स्कूल



प्रति ३ स्कूलों में  
१ एक-शिक्षक स्कूल



निरन्तर हो जाते हैं, उन्हें उनके माता-पिता स्कूल से खींच लेते हैं, देश की सम्पत्ति का अपव्यय होता है तथा राष्ट्र की भावी निधि — वाय्फो — का विकास पूर्णरूपेण होना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा की व्यर्थता की वृद्धि होती है। हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि विद्यार्थी स्कूल में विद्याध्ययन के लिए आते हैं, न कि वार्षिक परीक्षा में टोकर खाकर पदचातुर्पद होने के लिए।

### प्राथमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ

**भूमिका.**—स्वतन्त्रता अर्जन करने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की उपरति अवश्य हुई है; पर वैसी नहीं हुई, जैसी देश की कल्पना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ६-११ वर्ष के बच्चों के ६० प्रति शत बच्चों की शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करना था। पर आयोजना के अन्त में यह संख्या ५१.० प्रति शत ही पहुँची। इस निराशा-जनक स्थिति के अनेक कारण हैं। संक्षेप में कुछ कारणों पर विचार कर लेना यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

**दोष-युक्त सरकारी नीति** — पिछले पृष्ठों में अंग्रेजी शिक्षा-नीति के दोषों पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। वहाँ अंग्रेज सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर संक्षेप प्रकाश डाला जा चुका है। प्रथमतः, उसने 'शिक्षा छनने के सिद्धान्त' का प्रचार किया, और तत्पश्चात् टोन नीति का। आज उस पर दोषारोपण करने में कुछ भी लज नहीं। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक शिक्षा की उपरति के लिए कोई सुसंगठित योजना नहीं थी। दो वर्ष पूर्व लोकमन्त्रालय ने अनुमान-समिति ने स्वेड के साथ घोषित किया था कि "शिक्षा-मन्त्रालय ने अभी तक ऐसी कोई सुसंगठित योजना प्रस्तुत नहीं की, जिसके द्वारा मरिधान का ४५ वाँ अनुच्छेद कार्यरूप में परिणत हो सके।"<sup>१</sup> विभिन्न राज्य भी अनिवार्य शिक्षा को सफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर सभी 'अपनी अपनी टफली, अपना अपना राग' वाली बहाल के लक्ष्य बन रहे हैं। सारांश यह है कि सम्पूर्ण देश के लिए सुसंगठित योजना की आवश्यकता है।

हमके अतिरिक्त हमारी सरकार आदर्शवादी है। वह यथार्थवादी नहीं है। उसने स्वीकृत शिक्षा प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है, और प्राथमिक शिक्षा को इसके अनुरूप बनाना चाहती है। पर यह तभी संभव हो सकेगा, जब कि

<sup>१</sup> Estimates Committee Elementary Education, 1957-58  
New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958 p 60.

पर्याप्त द्रव्य हो और यथेष्ट शिक्षक उपलब्ध हों। आज तो हमारे देश के एक-तृतीयांश प्रारम्भिक स्कूल एक-शिक्षकवाले स्कूल हैं।

**दुर्यल शासन.**—प्राथमिक शिक्षा का भार मुख्यतः स्थानीय मण्डलों पर है, और राज्य-सरकार शिक्षा-नीति निर्धारित करती तथा शिक्षा की देखरेख करती है। इस दोहरे नियंत्रण के कारण अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। इसके सिवा, स्थानीय मण्डलों के पास न काफी पैसा है और न उन्हें सरकारी अनुदान ही इतना मिलता है कि वे अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी को उठा सकें। शिक्षा कर लगाने के लिए वे सदैव हिचकते हैं। कारण, इससे स्थानीय विरोध बढ़ता है। अनिवार्य शिक्षा के कायदे देश के पुराने दरे पर बनते चले आ रहे हैं। इनमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है।

कुछ वर्षों से, सरकार अनिवार्य कार्यों को यथाविधि अमल में लाने की चेष्टा कर रही है। सन् १९५५-५६ में ६,८७,४२१ नोटिसे बच्चों को स्कूल में दाखिल न करने के लिए और २,४०,४५० नोटिसे बच्चों की गैरहाजिरी के कारण जारी हुई। गैरहाजिरी तथा भरती न कराने के कारण क्रमशः ५७,१४६ तथा ३९,५१४ मुकदमे चलाये गये। पर पूरे देश से २३,२३९ रुपये ही जुर्माने में बसल हुए।† फिर, इस योजना की कार्यक्षमता ही कहाँ रही!

इसके साथ-साथ निरीक्षकों की अपर्याप्तता भी जुड़ी हुई है। सन् १९५५-५६ में अनिवार्य शिक्षा अमल में लाने के लिए केवल ९८१ अधिकतर थे। निरीक्षकों की संख्या भी कुछ अधिक नहीं है। औसतन एक निरीक्षक को प्रतिवर्ष सौ से अधिक स्कूलों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। ऐसी दशा में स्कूल की शिक्षा में कोई उन्नति की कैसे आशा करे!

स्कूल के विकास की भी कोई निर्धारित नीति नहीं है। सर्वेक्षण किये बिना ही स्कूल स्थापित होते हैं। स्कूल मनमाने ही खोले जाते हैं तथा स्थानिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका विपरीत परिणाम यह होता है कि कहीं तो एक भी स्कूल नहीं होता है, और कहीं इतने स्कूल खुल जाते हैं कि वे आपस में खींचातानी करते हैं।

**अर्थाभाव.**—प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खर्च का है। अर्थाभाव के कारण, शिक्षा का प्रसार ठीक नहीं हो सक रहा है। अगले पन्ने की तालिका से ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का पता चलेगा :

## तालिका ९

शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय  
१९०१-०२ से १९४७-४८ (करोड़ रुपये)

विवरण	१९०१-०२	१९२१-२२	१९३६-३७	१९४७-४८
एकत्रित शिक्षा व्यय ..	४.०१	१३.३७	७८.०५	५९.१८
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	१.२८	३.०९	८.३७	१८.९०
प्रति शान ..	२९.६	२७.३	२९.८	२९.९

इस प्रकार ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर कुल शिक्षा व्यय का ३० प्रतिशत अधिक बचो भी खर्च नहीं हुआ। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा-व्यय अत्यधिक बढ़ गया है, पर प्रति शान खर्च कहीं-कहीं बढ़ा है। उदाहरण स्वरूप सन् १९५६-५७ में शिक्षा पर हुए २०६.६ करोड़ रुपये के कुल व्यय-व्यय तथा प्राथमिक शिक्षा पर ५८.४ करोड़ रुपये का व्यय प्रत्यक्ष है, यह प्राथमिक शिक्षा-व्यय का २९ प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप में पैसा नहीं मिलता। हमारे देश के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उत्पन्न देश प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा-व्यय का दो तृतीयांश और बड़ी-बड़ी तीन-चतुर्थांश तक खर्च करते हैं।

**प्राथमिक शिक्षा का अभाव—**भारत की ८६.७ प्रतिशत जन-संख्या प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण आदि में अनेक कठिनाईएँ हैं, जैसे : गाँवों का दूर दूर बसा होना, जन-संख्या के घनत्व की कमी, बच्चों का अभाव तथा प्राथमिक कठिनाईएँ। गाँवों में शिक्षक-व्यय करना ही पड़ता है, और यदि जाने भी हैं तो वे सीधे भाग जाते हैं।

भारतीय देश का २६.११ प्रतिशत भाग, अर्थात् २,८०,१५९ वर्ग मील बहुत से भाग पड़ा है। इसके सिवा देश की सीमा परों में निवास करने वाले लोग



जगहों में स्कूल खोलना कठिन है। उदाहरणार्थ, सन् १९४७ ई० के पहले पान देश के सीमान्त क्षेत्र में तीस हजार वर्ग मील का एक ऐसा भाग था, जहाँ कि कभी भी स्कूल न था।

**सामाजिक, धार्मिक तथा भाषा-जन्य बाधाएँ।**—अनेक स्थानों में लड़कियों के लिए स्वतन्त्र स्कूलों की माँग है। कारण, कई अपढ़ माता-पिता अपनी कन्याओं को लड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते। इसी प्रकार विविध धर्मावलम्बी विभिन्न स्कूल खोलना चाहते हैं। इसके सिवा, प्रत्येक मनुष्य अपने बच्चों को मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा देना चाहता है। यह ठीक है, पर यदि किसी स्थान में किसी अन्य भाषा-भाषियों की मख्या कम हुई तो उनके लिए स्वतन्त्र स्कूल खोलना असम्भव हो जाता है।

सन् १९५६ की सशोधित सूचि के अनुसार इस देश में इस समय अनुसूचित जातियों के ५,५३,२७,०२१ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है। इन जातियों में शिक्षा की अधिकाधिक सुविधा देने के लिए उपाय प्रयुक्त किये जा रहे हैं, पर इनमें शिक्षा का प्रसार करना एक समस्या का विषय है।

**शिक्षा-सम्बन्धी तथा आर्थिक बाधाएँ।**—वर्तमान पाठ्यक्रम सतोपजनक नहीं है। पाठ्यक्रम पुस्तकीय है, तथा दैनिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस शिक्षा को पाकर, विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से घबराते हैं तथा अपने शप-द्रव्य का धन्वा छोड़ बैठते हैं। यही कारण है कि माध्याम्य जनता का विधान इस शिक्षा से उठ गया है। इस कमी के निगमन के लिए ही, बुनियादी शिक्षा का प्रचार आग हुआ है। पर इस शिक्षा के सिद्धान्तों को लोग पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं। स्कूलों में शिक्षा ठीक नहीं दी जा रही है। कारण ग्योत्रों की अधिक आवश्यकता नहीं हमारे देश के एक-तृतीयांश स्कूल एक-शिक्षकवाले हैं। शिक्षकों की पढ़ाई का विशेष ऊँचा नहीं है। चाग्रिम प्रति शन शिक्षक अप्रशिक्षित हैं तथा अनेक अन्यकालिक प्रशिक्षण-प्राप्त ही हैं। इतना होने हुए भी प्राथमिक शिक्षा के लिए, स्व में शिक्षक नहीं मिलते हैं।

अनेक माता-पिता स्वयं अपढ़ हैं। इस कारण, वे शिक्षा के प्रति उदात्त नहीं होते। वे यह सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो हमारे लिए ही होगा। इससे माप माप है।

अनेक बच्चे ऐसे हैं, जो यदि स्वयं मेहनत न करें तो उन्हें सूखी रोटी भी नसीब न हो। शरीर मजदूर तथा किसान चाहते हैं कि वे उनके कार्य में सहायता दें। तब उनके बच्चों को शिक्षा किस प्रकार मिल सकती है? इस प्रकार कितनी ही कठिनाइयाँ शिक्षा-प्रसार में बाधक हैं।

## सुधार की ओर

**भूमिका—इंग्लैण्ड का मन् १९४४ ई० का शिक्षा-कानून** निम्न-लिखित गण्टों में आरम्भ होता है :

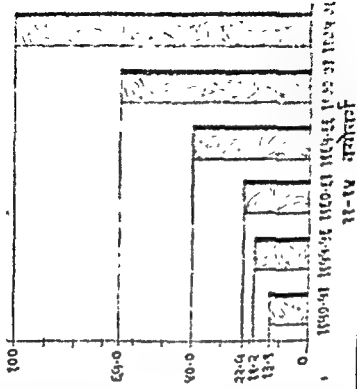
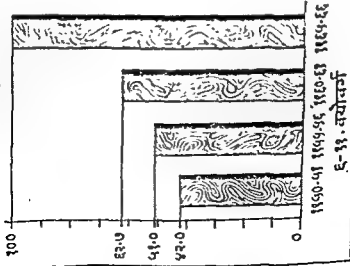
इस देश का भाग्य जनता की शिक्षा पर निर्भर है।

उपर्युक्त विचार का सम्मान सम्पूर्ण विश्व में होना चाहिए। बीसवीं शताब्दी अनिवार्य शिक्षा का युग है। इस शिक्षा का महत्व सभी देशों ने स्वीकार किया है। लोग चाहें, या न चाहें, आक्राढ़ देश में किसीको अपठ नहीं रहना चाहिए। आक्राढ़ी का मन से कट्टर दुश्मन है निरक्षरता। इसी कारण स्वाधीन भारत में यह आवश्यक हो गया है कि देश के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कम से कम अवधि में उपलब्ध करा दी जाए। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद ने गण्टों को यह निर्देश दिया है :

गण्ट इस संविधान के आरम्भ में दस वर्ष की बाल्यवधि के भीतर नव शालक-शालिकाओं को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए साधन उपलब्ध करने का प्रयास करेगा।

इस अवधि के बीतने का समय आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यह निर्देश वागन्ती आदर्श होकर ही रह गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पहले ६-११ वयोग्रुह के ४२.० प्रति शत (१,८६.८० लाख) बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधाएँ थीं। आयोजना के अंत में ५१.० प्रति शत (२,४८.१२ लाख) बच्चों को ये सुविधाएँ मिलने लगीं। वहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में ११-१४ वयोग्रुह के बच्चों की संख्या ११.९ प्रति शत (११.७० लाख) में बढ़कर १९.२ प्रति शत (५०.९५ लाख) हो गयी है, और द्वितीय आयोजना में २२.५ प्रति शत (६३.८७ लाख) बच्चों की सुविधाएँ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

# प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य



आज पूरे देश के सामने यही प्रश्न है कि मविधान के निर्देश को केसे कार्य-रूप में परिणत किया जाय। हाथ में ही योजना-आयोग ने स्वीकार किया है कि ६-१४ वयोवर्ग की अनिवार्य शिक्षा अगम्य है। इस कारण ६-११ वयोवर्ग की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जावे। अन्विष्ट भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिपट ने भी सुझाव दिया है कि तृतीय आयोगना के अन्त तक ६-११ वयोवर्ग के सभी बच्चे अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत आ जाना चाहिए। नयी दिल्ली में २८-३० जून, १९५९ को गण्डो के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी टम की जो मयुक्त बैठक हुई थी उसने भी इस सिफारिश का अनुमोदन किया है। तृतीय पञ्चवर्षीय मधीन योजना का लक्ष्य है कि योजना-काल के दौरान में ६-११ वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिले।

११-१४ वयोवर्ग के बच्चों की शिक्षा के विषय में, उपयुक्त सूच योजना ने अभिप्राय किया है कि आयोगना की अवधि में स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा पाने वालों की संख्या ३० प्रति दान पहुँचेगी। इससे अनिवार्य १० प्रति दान बच्चों की सामान्य (बटिन्वुशन) शिक्षा मिलेगी। इस प्रकार तृतीय आयोगना के अन्त तक इस वर्ग के शिक्षित बच्चों की संख्या ४० प्रति दान पहुँचेगी। आशा की जाती है कि यह संख्या चतुर्थ एवं पञ्चम योजना के अन्त तक क्रमशः ६५ तथा १०० पहुँचेगी। इस प्रकार सन् १९७५ के अन्त तक मविधान के लक्ष्य के सम्य होने की सम्भावना है।

पर हुई हमारे देश में ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की योजना की आवश्यकता। पर इसे सफलीभूत करने के लिए अनेक बटिन्वुशन की सामान्य बनना पड़ेगी। मुख्य समस्याएँ हैं (१) प्रमाणन, (२) दान, (३) अनिवार्य शिक्षा का अग्रगम तथा प्रसार, (४) स्कूलों का प्रबंध, (५) पाठ्यक्रम, (६) शिक्षक, (७) निवास-सुवस्था और (८) अनुसंगजन।

प्रमाणन — जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्कूलों के लिए एक सुनिश्चित योजना की आवश्यकता है। विशेष रूपसे हमें इस योजना की कार्यान्वयन की जाती है। स्कूलों के शिक्षकों-बच्चों में स्वीकृत किया कि प्रारम्भिक शिक्षा ६-११ वयोवर्ग के बच्चों के लिए हो, तथा १९६६ के अन्त तक इस वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा मिले। पर इसके साथ साथ अनेक प्रश्न खड़े होते हैं— (१) केन्द्रीय सरकार की नीति, (२) अनिवार्य शिक्षा प्रमाणन-प्रणाली, (३) स्कूलों के

वित्त-नीति, (४) पाठ्यक्रम, इत्यादि। ये ऐसे प्रश्न हैं, जो समूचे देश से सम्बन्ध रखते हैं। इस कारण इन मामलों में एक समान नीति की आवश्यकता है। पर इसमें अर्थ यह नहीं है कि देश के विभिन्न राज्य एक ही अनुशासन की शृंखला से जकड़े दिये जायें। स्थानीय तथा विशेष आवश्यकताओं का सदा ध्यान रखना होगा। ऐसी नीति की अनुपस्थिति में अर्थ तथा धन के अपव्यय होने की आशंका है।

सब से बड़ी आवश्यकता है केन्द्रीय सरकारों की राज्य-सरकारों से सहकारिता की। राज्य-सरकारों में आजकल यह धारणा है कि भारत-सरकार अधिकार केन्द्रीभूत करना चाहती है, तथा ऐसे क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करती है, जिनका संबंध राज्य-सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस धारणा का निर्मूलोद्धार करे। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच आर्थिक तथा अन्य बातों में अधिकाधिक सहयोग स्थापित हो। अनुदान देते समय, उन राज्यों पर विशेष ध्यान रहे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो और जिनकी शिक्षा पिछड़ी हुई हो।

प्राथमिक शिक्षा के पिछड़े रहने का विशेष कारण हमारे स्थानीय मण्डलों की अनमर्थता है। सारजेण्ट योजना ने तो स्पष्ट मुद्दाव दिया था कि प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों के हाथ से ले लें। इस प्रश्न पर तब से बहुत हो रही है, लेकिन अभी तक सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का स्थानीय निकायों से निकटतम सम्बन्ध है। कारण, वे ही अपनी जरूरतों को ठीक समझ सकते हैं। इसके सिवा अनतन्त्र की हमारा स्थानीय निकायों की बुनियाद पर पड़ी होती है। इस कारण इन्हें अपनी जिम्मेवारी खुद संभालनी चाहिए।

लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि राज्य-सरकारों पर कुछ भी उत्तरदायित्व न रहे। इस प्रश्न पर कुछ मुद्दाव नीचे दिये हैं :

१. सरकार पूरे राज्य के लिए, एक शिक्षा-नीति तथा न्यूनतम मान-दण्ड स्थिर करे।

२. क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उपर्युक्त नीति तथा मानदण्ड परिवर्तन किया जावे, क्योंकि कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ और कोई क्षेत्र उन्नत भी हो सकता है।

३. अनिवार्य शिक्षा के प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य में एक शक्तिशाली राबर्टीय विभाग होवे। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है

कि शिक्षा-विभाग स्थानीय मण्डलों के कार्यों का निर्गमन तथा नियन्त्रण करे।

४. राज्य सरकार स्थानीय निकायों को यथेष्ट आर्थिक अनुदान दे।

**वित्त.**—निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए काफी पैसों की आवश्यकता है। ७ मार्च, १९५७ को लोक-सभा में बजट पर भाषण देते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री लक्ष्मण श्रीमाली ने कहा कि देश में ६-११ वयोवर्ग के सभी बच्चों को तृतीय योजना के अन्त तक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के निमित्त ३०० करोड़ रुपये की जरूरत है। अर्थ में यह उक्ति लोक-सभा को चुनौती थी। आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अनिवार्य शिक्षा के लिए इस रकम का प्रबन्ध रहेगा। इसके साथ साथ, राज्य सरकारों को कमर बंधना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी योजनाओं में इस महत्वपूर्ण तथा जरूरी कार्य के लिए यथेष्ट अर्थ का प्रबन्ध करें। इसके बिना वे केन्द्रीय आर्थिक अनुदान का यथोचित लाभ न उठा सकेंगे।

**अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ तथा प्रसार.**—अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ मोच कर करना चाहिए तथा समस्त-बूझकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ मुद्दाय नीचे दिये गये हैं।

**प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता.**—अनिवार्य शिक्षा चालू करने के पहिले एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार ठीक समय पर करे। सर्वेक्षण में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जावे : राज्य की विदेश जरूरतें, वे केन्द्र जहाँ स्कूल खोलना चाहिए, उन बच्चों की संख्या, जिन्हें अनिवार्य शिक्षा देनी है, स्कूलों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा-साधनों, शिक्षकों तथा शाला-गृहों की आवश्यकता, और सम्पूर्ण योजना पर खर्च। अनिवार्य शिक्षा आरम्भ होने के पश्चात्, सामयिक सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है। इसके द्वारा अनुमान किया जा सकता है कि योजना कैसी चल रही है, उसमें कौनसे परिवर्तन की आवश्यकता है, मुख्य बाधाएँ क्या हैं, ये कैसे हटायी जा सकती हैं, आदि।

इस की बात है कि केन्द्रीय सरकार के मुद्दाय के कारण प्रत्येक राज्य-सरकार ने रात ही में ऐसे प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये हैं। आशा की जाती है कि इस जाँच का लाभ प्रत्येक राज्य अपनी अनिवार्य शिक्षा-परिकल्पना में उठावेगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता.—अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन इने-सिने क्षेत्रों या राज्यों में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण देश में जोर-शोर से चलना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा बूँद बूँद टपकना नहीं चाहिए, बल्कि जोर से बरसना चाहिए। शुरू-शुरू में इसकी बहुत आवश्यकता है। अनेक देशों ने इस नीति का अनुसरण किया था; और केवल दस ही वर्षों के भीतर इन देशों के प्रारम्भिक स्कूलों की छात्र-संख्या दुगुनी हो गयी। इस तालिका की छात्र-संख्या पर दृष्टि डालिए :

### तालिका १०

कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति†

देश	छात्र-संख्या (वर्ष)	छात्र-संख्या (वर्ष)
इंग्लैण्ड ...	१८,००,००० (१८७१)	४६,००,००० (१८८१)
जापान ...	१७,४६,००० (१८७३)	२३,००,००० (१८७९)
इजिप्ट ...	३,०३,००० (१९२८)	१०,००,००० (१९३८)
चीन ...	२८,००,००० (१९२१)	१,१७,००,००० (१९३१)

इस प्रकार, आरम्भ में सम्पूर्ण देश में एक आन्दोलन तथा राष्ट्रीय जागरण की ज़रूरत है; पर प्रगति मुचाक रूप से, समझ-बुझकर तथा नियमित हो। प्रत्येक क्षेत्र को अपने सामर्थ्य के अनुसार चलने देना चाहिए। उसीके अनुरूप उसका प्रोग्राम भी हो। पर यह सदा ध्यान में रहे कि पूरे देश का लक्ष्य क्या है, अर्थात् सम्पूर्ण देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कब तक हासिल करना है।

अनिवार्य शिक्षा एकड़ों का संग्रोधन.—इस देश की अनिवार्य-शिक्षा विषयक कानून लगभग चाँटीस वर्ष पुराने हैं। ये मोललेजी के विरोध या पटेल एक्ट के द्वारे पर दाले गये हैं। इनकी कमज़ोरियों पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। केन्द्रीय सरकार को उचित है कि राज्य सरकारों के विभिन्न प्राथमिक शिक्षा कानूनों पर

पर विचार करे तथा सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य शिक्षा-कानून का एक समान तथा आदर्श ढाँचा निर्मित करे। यह कार्य राज्य-सरकारों के परामर्श से किया जाना आवश्यक है। हाल में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने भी यह मुझाय दिया है।

**मानवीय वैयक्तिक सम्बन्ध.—**बहुधा देखा गया है कि उपस्थित अधिकारी-गण साधारण जनता के प्रति कटोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी व्यावहारिक रुझता का परिणाम यह होता है कि अपट्ट व्यक्तियों के हृदय में शिक्षा के प्रति वितृष्ण उत्पन्न होती है। वे उपस्थित अधिकारियों को आगधी चिन्मात्र के कर्मचारियों के तुल्य गिनते हैं। स्वाधीन भारत के उपस्थित अधिकारियों को समाज-कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। जनता के साथ उनके किये गये व्यावहारिक आचरण पर ही शिक्षा का भविष्य निर्भर है। यह जनता अनुकम्पा, भाव-माय तथा महानुभावता की ही अपेक्षा रखनी है, यह बात सर्वथा स्मरणीय है।

**स्थानीय सहयोग तथा नेतृत्व.—**यह प्रकट सत्य है कि स्थानीय सहयोग के बिना अनिवार्य शिक्षा-योजना सफल नहीं हो सकती है। स्कूल तथा स्थानीय समाज का अग्रन्त पविष्ठ सम्बन्ध है। स्कूल का कर्तव्य है कि यह सदा स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखे तथा समाज की उन्नति की चेष्टा करे। यदि समाज ने एकबार ताड़ लिया कि स्कूल उसके कल्याण के लिए है तो यह स्कूल की उन्नति के लिए भगवत् प्रयत्न करेगा। भारत के अनेक स्थानों में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, यह बात देखी गयी है कि जनता स्कूल के कार्यों में श्वेष्ट दिलचस्पी ले रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में उद्धृत निम्नादि विवरण पटिए :

उदा के अनेक भागों में, जनता ने अपने गाँव के स्कूल के लिए धर्म, भूमि तथा भ्रम का दान किया है। एक जिले में ६०० छात्र-गर्लों का स्थानीय जनता ने स्वयंसेव निर्माण किया था। इसी उन्माद के फलस्वरूप अनेक दुर्गम स्थानों में भी आज स्कूल स्वीकृत हो गये हैं। उदाहरण-स्वरूप सन् १९४७ के पहले भारत की ईशान दिशा में मियन आदिम जातीय क्षेत्रों में एक भी स्कूल न था। वहाँ सन् १९५३ में १,९०० स्कूल थे।†

इस प्रकार हम 'जहाँ चाह है, वहाँ गढ़ है' वाली श्लोकालि को प्रत्यक्ष परिचित होने देखते हैं। यदि स्थानीय जनता चाहेगी, तो वह स्वयं स्कूल स्वीकरी। उनकी इस इच्छा को प्रवृत्तिक रुकावटें भी न हो सकेंगी। सरकार का कर्तव्य है कि वह

† Seven Years of Freedom pp 2-3



जनता की इस इच्छा को पूर्णरूपेण आगत करे। इस आगुनि के माग-माग सम्पूर्ण देश में स्कूल खोलना आगान हो जायगा।

**स्कूलों का प्रबन्ध.**—इसके बाद आता है स्कूलों का प्रबन्ध। काम, समूचे भारत के कोने-कोने में प्राथमिक शालाओं की जरूरत है — शहरों में तथा गाँवों में। इसके अतिरिक्त देश में कई जगह विशेष स्कूलों की माँग है। विभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषा-भाषी पृथक् निजी स्कूल चाहते हैं, तथा आदिम जातियों के लिए भी विशेष स्कूलों की जरूरत है।

**शहरों में स्कूल.**—शहरों में स्कूल खोलने और चलाने की विशेष अनुविधाएँ नहीं हैं। यहाँ शाला-गृह शीघ्रता-पूर्णक निर्मित किये जा सकते हैं, शिक्षकगण शहरों में रहना चाहते हैं, जनता में शिक्षा की चाह है। यहाँ केवल उपयुक्त उपस्थित-अधिनारियों की आवश्यकता होती है। इन्हें थोड़ा प्रशासनिक क्षमता दी जावे। इसके सिवा, जनता के सुभीते की ओर ध्यान रखते हुए, स्कूल अनुकूल समय में लगे।

सन् १९५४ ई० में 'भारतीय उद्योग-नायना' के अनुसार, भारत में ७,०६७ पंजीकृत कारखाने थे। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या १७,१४,७७० थी।† इन व्यक्तियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का ठीक प्रबंध होना चाहिए, उनका विशेषकर, जो कि कारखाने के आसपास रहते हों। हमारे देश में एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसके अनुसार औद्योगिक संस्थाओं को अपने कर्मचारियों तथा मजदूरों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्कूल चलाना पड़े। मेक्सिको में सन् १९४२ ई० के शिक्षा-कानून के ६७-७१ अनुच्छेदों के अनुसार कल-कारखानों के स्वामियों पर कुछ प्रबन्ध रखे गये हैं। उन्हें स्कूल चलाना पड़ता है, स्वास्थ्यकर शाला-गृहों का निर्माण करना पड़ता है तथा विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त देना पड़ता है।

**गाँवों में स्कूल.**—गाँवों में सोच-विचार कर स्कूल खोलना चाहिए। सन् १९५१ ई० की जन-संख्या के अनुसार सम्पूर्ण देश में कुल ५,५८,०८८ गाँव थे। उनमें से ३,८०,०१९ गाँवों की मनुष्य-संख्या ५०० से कम थी। आर्थिक दृष्टि-कोण से ऐसे छोटे गाँवों में स्वतन्त्र स्कूल खोलना हितकर नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय गाँव में स्कूल स्थापित करना चाहिए। ऐसा गाँव विशेष विचार के साथ चुनना चाहिए, ताकि अन्य गाँव उससे दूर न हों। इस कारण स्कूल खोलने के पहले एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, ताकि स्कूल मनमाने जहाँ-तहाँ न खोले जावें।

† भारत, १९५९, पृष्ठ २२१।

गाँव में स्कूल खोलना कुछ सहर नहीं है, उसमें अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है।<sup>†</sup> वहाँ पर अनेक माता-पिता गरीब हैं तथा शिक्षा के विरुद्ध विचार रखते हैं। उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी करानी पड़ती है। मजदूरी किये बिना उनके कुटुम्ब का पालन-पोषण होना कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्हें भी अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है, तथा इसीलिए उनके बच्चों को स्कूल में रखा जाना पड़ता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन बच्चों के माता-पिताओं की ज़रूरतों की ओर बिल्कुल ध्यान न दें। हमें स्कूलों के लगने का समय बदलना पड़ेगा। यदि स्कूल सुबह तथा शाम को लगाये जावें, तो बच्चों को अपने माता-पिता की सहायता करने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलने लगेंगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत कृषि-प्रधान देश है। इस कारण किसानों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए स्कूलों के लगने का समय स्थिर करना चाहिए। हमें ऐसे समय नियम-निष्ठुर — लबीर के फबीर — नहीं रहना चाहिए। उदाहरणार्थ, चीन में ग्रामीण पाठशालाओं का खेती से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वहाँ साधारण सिद्धान्त यह है :  
 "जब तुम्हारे पास अधिक समय है, तब अधिक पढ़ो। जब अल्प अवकाश हो, तब कम पढ़ो। जब तुम बहुत ही व्यस्त हो, तब कुछ समय तक पढ़ना बन्द करो।"<sup>‡</sup>

सार अर्थ यह है कि स्कूल समाज के कल्याणार्थ है। स्कूलों के प्रति ग्रामवासियों की उदासीनता बहुत कुछ दूर हो जायगी, यदि पाठ्यक्रम में गाँवों की ज़रूरतों की ओर ध्यान रखकर विषयों का चयन किया जावे। समाज-शिक्षा भी इस उदासीनता-रूपी द्वाधि की अमोघ औषधि है। बहुतो अवद स्पष्ट ही शिक्षा के विरोधी होते हैं। इसके सिवा ग्राम्य स्कूल की जिम्मेवारी बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहती है। स्थानिक समाज की उन्नति भी उसी पर निर्भर है। उन्ने आज ग्रामवासियों को किसान नहीं बनाना है, बल्कि स्वतंत्र भारत का नागरिक निर्मित करना है। इस प्रकार प्राथमिक स्कूल ग्रामोत्थान के केन्द्र हैं। इस कार्य में स्कूल को सम्पूर्ण ग्राम के साथ हाथ बैटाना चाहिए, ताकि ग्रामवासियों को समझ हो कि स्कूल हमारा है। आज मेक्सिको में यही प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ स्कूल तथा गाँव परस्पर एक सूत्र में गुँथ गये हैं। स्कूल समाज की उन्नति के प्रयत्न करता है तथा समाज स्कूल की प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए भरसक कोशिश करता है। मेक्सिको के शिक्षा-उपमन्त्री भी मोरमोन्ते नेद्रेस का कथन है :

<sup>†</sup> देखिए पृष्ठ ८१।

<sup>‡</sup> *Peking Review*, April 15, 1958, p. 12

यह ठीक नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्कूल का काम कहाँ आरम्भ या समाप्त होता है। उसी प्रकार ग्राम्य जीवन के आरम्भ और समाप्ति के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण, गाँव और स्कूल एक ही सस्या हैं, तथा स्कूल ने ग्राम-मुधार का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लिया है।

**विशेष स्कूल.**—कभी-कभी धर्म एवं भाषा-भेद के कारण, विभिन्न स्कूलों की माँग रहती है। इसके सिवा, कन्या-शालाओं की भी चाह है। वस्तुतः मजहबी स्कूलों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत एक असांप्रदायिक राष्ट्र है। यद्यपि छात्र-संख्या के बिना न स्वतन्त्र भाषा-भाषी स्कूल चल सकते हैं और न कन्या-शालाएँ। यदि विशेष भाषा-भाषी स्वतन्त्ररूप से अपना स्कूल अलग से अपने व्यय के द्वारा चलाना चाहें तो वह दूसरी बात है। इसी प्रकार स्वतन्त्र कन्या-शालाओं की विशेष आवश्यकता नहीं है। कारण, प्राथमिक स्कूलों में बालक-बालिकाएँ बिना रोक टोक साथ-साथ पढ़ सकती हैं। इनकी सह-शिक्षा में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए।

असली समस्या आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल खोले जाने की है। ये बस्तियों से दूर जंगल पहाड़ों में रहते हैं तथा शिक्षा के महत्व को भी नहीं जानते हैं। हमें की बात है कि सम्प्रति इन लोगों में शिक्षा प्रसार के कार्य का भीगनेवा हुआ है। इन लोगों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, कई स्वेच्छिक संगठन तथा धर्म-संस्थाएँ पर्याप्त प्रयत्न-शील हैं। सरकार भी अब सजग हो उठी है। सब कुछ होते हुए भी, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति अभी भी अनुत्तमप्रग है।

**पाठ्यक्रम.**—प्रचलित पाठ्यक्रम की त्रुटियों एवं कमियों की आलोचना पूर्ण पृष्ठों में पर्याप्त कर दी गयी है। इसीके प्रतिकार-स्वरूप बुनियादी शिक्षा का आविर्भाव हुआ है। यह शिक्षा आज हमारे देश की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली है। अब इसकी सफ़लता के लिए यद्यपि कुशल शिक्षकों एवं पर्याप्त अर्थ-राशि की आवश्यकता है।

सम्प्रति, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने घोषणा की है कि आगामी दो या तीन वर्षों में देश के वर्तमान प्राथमरी स्कूल बुनियादी स्कूल में बदल दिये जावेंगे। ग्रामीण तथा शहरी स्कूलों के लिए न्यूनतम बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित किया जायगा, तथा तहसील और तालुका केन्द्रों में अल्प-कालिक प्रशिक्षण का बन्दोबस्त

लेगा। राज्य-सरकारों को केन्द्रीय सरकार से कुछ खर्च का साठ प्रति शत प्राप्त हो मिलेगा।† हम इस योजना की मफयता के लिए शुभाकांक्षाएँ रखते हैं। पर यदि बुनियादी शिक्षा बुनियादी ही रखना है, तो उसका सूत्र आकार हो ही नहीं सकता है।

हमें आदर्शवादी के बदले यथार्थवादी होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों के लिए एक कार्य-योग्य पाठ्यक्रम की जरूरत है। इसमें समाविष्ट हो : मातृ भाषा, गणित, सरल खण्ड-विज्ञान, समाज शास्त्र की रूप-रेखा तथा एक उद्योग। पर इसका उद्देश्य है एक उद्योग का साधारण ज्ञान, न कि उद्योग द्वारा शिक्षा। गाँवों में कृषि या बागवानी सिखलाई जा सकती है। विद्यार्थीगण खेतों तथा झींझों में काम कर सकते हैं। शहरों में स्थानीय कारीगर उद्योग सिखा सकते हैं। मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा रचनात्मक हो तथा स्थानीय वातावरण पर पाठ्यक्रम आधारित हो। विद्यार्थियों में नागरिकता की भावना को जगाना उचित है तथा उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना सिखाना चाहिए।

**शिक्षकगण.**—हिसाब लगाया गया है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना के लिए अष्टाईस लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। पर आज प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक-सेखना प्रायः सात लाख ही है। शिक्षा-सम्बन्धी मुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५३ ई० में शिक्षित बेकारों की सहायता-योजना शुरू की है। इसने अनुमार ३१ जनवरी १९५६ तक राज्यों के लिए कुल मिलाकर ८०,००० शिक्षक और २,००० सामाजिक कार्य-कर्ता नियुक्त कर दिये गये।‡ इसी योजना के अन्तर्गत आयोजना आयोग और भी ४०,००० शिक्षक नियुक्त करना चाहता है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की घोषणा के अनुसार आज इस देश में ६,२५,५६७ मैट्रिक पास विद्यार्थी बेकार बैठे हुए हैं।७ यदि वे स्वतः शिक्षक बन जायें, तो शिक्षक-समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

पर केवल इन्हीं चेष्टाओं से काम न चलेगा। शुरू-शुरू में आकांक्षाएँ अधिक ऊँची नहीं होनी चाहिए। हमें मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे अर्थात् वनांकयुक्त फार्मल या मिडिल पास शिक्षकों से काम चलाया पड़ेगा। हमें मंटेब सचेत रहना चाहिए कि ये शिक्षक गाँवों में टिकेंगे ना नहीं। देखिए, बेकिमको ने शिक्षक-समस्या का समाधान बंमे किया, जब कि उस देश में प्रति वर्ष एक हजार से अधिक स्थानीय स्कूल खुल

† *Times of India*, March 17, 1959

‡ भारत में शिक्षा — लेखा — चित्रों में, पृष्ठ ६।

\* *Times of India*, August 10, 1959

रहे थे। उच्च शिक्षित व्यक्ति शिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे; अतएव अध्यापन कार्य के लिए सप्परित्र, उत्साही तथा सेवा प्रेमी स्त्री-पुरुष नियुक्त हुए। युवक तथा युवतियों शिक्षात्म्य कार्य के लिए अधिक पसन्द की गयी, तथा स्थानीय उम्मेदवारों के प्रति रियायत या उदारता दिखायी गयी। उच्च-शिक्षा प्राप्त न होने हुए भी ऐसे व्यक्ति अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त हुए। बाद में मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण-द्राग उनकी माहिरिक तथा व्यावसायिक क्षमियों दूर की गयी। भारत में ऐसी योजना की विशेष आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ हमें वर्तमान शिक्षकों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना चाहिए, जैसे : शिक्षकों का उचित बँटवारा, परिवर्तन-प्रथा का अधिक उपयोग, प्रत्येक कक्षा की छात्र-संख्या-वृद्धि, इत्यादि। यह देखा गया है कि शहरी स्कूलों के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षक मिलते हैं, पर ग्रामीण स्कूल बहुधा एक-शिक्षक-वाली संस्था होते हैं। यह दूषित प्रणाली आज नहीं चल सकती। स्थानिक मण्डलों की शिक्षकों का बँटवारा इस प्रकार करना उचित है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में, चाहे वह शहर में स्थित हो या एक छोटे-से गाँव में, कम-से-कम तीन शिक्षक अवश्य हों। इसी नीति का अवलम्बन करने पर अनेक शिक्षकों का शहरों से गाँवों में त्रासदला अवश्य होगा। पर न्याय तथा दीक्षणीक दृष्टिकोण से, यह बहुत ही जरूरी है।

उपर्युक्त प्रस्ताव कार्यान्वित होने पर हम देखेंगे कि किसी भी शिक्षक को कमी भी दो से अधिक कक्षाएँ एक साथ नहीं पढ़ाना पड़ेंगी। यदि ये शिक्षकगण द्वैत-शिक्षा में यथोचित प्रशिक्षित किये जायें तो उनका अध्यापन-कार्य बहुत कुछ सुधर सकता है। इसके साथ-साथ भारत में परिवर्तन-प्रथा की अधिक जरूरत है। इसके अनुसार स्कूल की कक्षाएँ भिन्न-भिन्न समय में लग सकती हैं। शिक्षकों का काम अवश्य बढ़ जायगा, पर उन्हें एक से अधिक वर्ग एक साथ तो न पढ़ाना पड़ेंगे। यह मानना ही पड़ेगा कि यह प्रथा आदर्श नहीं है, पर शिक्षकों की कमी दूर करने की यह एक अच्छी दवा है। यह प्रथा कुछ नयी नहीं है। सभी उन्नत देशों ने अनिवार्य शिक्षा के आरंभ में इस प्रथा को अपनाया था, जैसे : जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, पोर्तुगाल। आज भी यह प्रथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, टर्की, इजिप्ट, चीन, सीलोन तथा डेनमार्क में प्रचलित है।

हम प्रत्येक कक्षा की छात्रसंख्या भी बढ़ा सकते हैं। यह प्रथा बड़े स्कूलों में अपनायी जा सकती है जहाँ एक ही कक्षा के कई वर्ग होते हैं। हम देखते हैं कि किसी-न-किसी समय सभी देशों के प्रत्येक प्राथमिक कक्षा की छात्रसंख्या अत्यधिक थी :

इंग्लैण्ड में ६० (१८९४), जर्मनी में ८० (१८९६), इटली में ६० (१९२२), इत्यादि। यहाँ तक कि सन् १९२२ ई० में इंग्लैण्ड में २८,००० और ५,००० कक्षाएँ ऐसी थीं, जिनमें प्रत्येक की छात्रसंख्या क्रमशः ५० से ६० और ६० से अधिक थी। आज हमारे शिक्षा-विभागों के अनुसार एक कक्षा में ४० से अधिक विद्यार्थी भर्ती नहीं किये जा सकते हैं। हम इस सीमा को ५० तक आसानी से बढ़ा सकते हैं।

**निद्यास-व्यवस्था.**—यह बतलाया जा चुका है कि हमारे अधिकांश शाला-गृह अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, पर इस कारण हमें इतना न होना चाहिए। लगभग पचास वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड के कुछ स्कूल रेल-पथ के मेहराबों के नीचे लगाने में तथा जर्मन शाला-गृह अँगोरे तथा गन्दे थे। यहाँ तक कि सन् १९२५ में रूस के प्रांतीय प्राथमिक शाला-गृह भेदे तथा पुराने ढङ्ग पर बने हुए थे।

कहा जाता है कि हमारे देश के अनेक स्कूल धर्मशालाओं, मगानों, मन्दिरों तथा मस्जिदों में लगा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ लगाना नहीं आनी चाहिए। यह प्रथा इस देश में परम्परा में बली आ रही है। हमारे देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत है। अथक उपयुक्त शालागृह न बने, तब तक क्या हम हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रह सकते हैं! हमें जहाँ भी कोई खाली जगह मिले, वहाँ ही स्कूल खोलना चाहिए। नीले आकाश के नीचे मुक्त वायु (ओपन-एयर) में हम स्कूल खोल सकते हैं। दौधणिक दृष्टि से ऐसी सरथाएँ आदर्श गिनी जाती हैं। भारत पर निर्भर देवी का बरद हम है। तब हमें ऐसे स्कूल खोलने में क्यों हिचकना चाहिए!

**अनुसंधान.**—हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा-समस्याएँ अति गम्भीर तथा पेचीली हैं। इन पर बहुत कुछ सोचविचार की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा विभागों तथा प्रादेशिक महाविद्यालयों को चाहिए कि वे इन प्रश्नों की जाँच तथा उपयुक्त टोच करें। कुछ समस्याओं के स्तार्पक नीचे दिये गये हैं :

१. प्राथमिक स्कूलों को दुनियावी रूप देना,
२. अनिवार्य शिक्षा-प्रतिपादन की समस्याएँ,
३. अरुढ़ भाषा दिताओं की ध्वनि बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रवृत्ति,
४. दिन शिक्षा-प्रवृत्ति,

५. परिवर्तित शिक्षा विधि,
६. व्यंगता तथा अनगोधन,
७. शास्त्र-शास्त्र,
८. भिन्न-भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणाली, इत्यादि ।

### उपसंहार

इस अध्याय में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा कुछ उद्देश्यनीय समस्याओं पर विचार विज्ञापन है । ब्रिटिश सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन रही । आज यह बात पुगनी हो गयी है । हम पर आलोचना करना स्वार्थ है । आज हमें अपने देश के भविष्य की ओर ध्यान देना है । भारत की उन्नति जनता की साक्षरता पर निर्भर है । ८० प्रति शत में अधिक भारतवासी अभी निरक्षर हैं । मले ही वे न चाहें, किन्तु हमें उन्हें शिक्षित करना है । यह हमारा पगम कर्तव्य है ।

पर जब हम अनिवार्य शिक्षा की समस्याओं पर विचार करते हैं, तब हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग ढीले पड़ जाते हैं, चेहरा मुग्ध जाता है और हमारा जोश ठण्डा पड़ जाता है । पर ऐसा करने में काम न चलेगा । निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए समुचित अर्थ एवं सर्वाङ्गपूर्ण योजना अपेक्षित होती है, पर इससे भी अधिक मन में शक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता है । — ऐसी दृढ़ता, जो हमें कठिन-से कठिन मुश्किलों का सामना करना सिलाये, जो हमें हताश न होने दे और जो हमें नीचे न गिरने दे । परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह हमें ऐसा बल प्रदान करें ।

प्रत्येक उन्नत देश की अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । वे आगे ही बढ़ते गये । पीछे नहीं हटे । चालीस साल के अरसे में अमेरिका ने फिलिपाइन द्वीप-पुञ्ज की साक्षरता २ से ५५ प्रति शत बढ़ायी । पन्चीस वर्ष की अवधि में रूस की साक्षरता ८ से ८८ पहुँची । अनेक कठिनायों का सामना करते हुए, चीन तथा टर्की ने अपनी निरक्षरता दूर की । फिर हम क्यों हताश हों ?

## पाँचवाँ अध्याय

### माध्यमिक शिक्षा

#### पूर्व-पृष्ठिका

**प्रारम्भ.**—उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से आज, हम देश के अधिकांश माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी सम्पाएँ हैं। अंग्रेजी स्कूल हम देश में जब प्रथम-प्रथम खुले, तब इनका उद्देश्य धनी भारतवासियों को राज-भाषा (अंग्रेजी) सिखाना था। सन् १८३० में ई० ई० कंपनी के डाइरेक्टर्स ने तय कर लिया था कि “भारतवासियों को अंग्रेजी-शिक्षा दी जाय, ताकि हम प्रकार का एक वर्ग तैयार किया जा सके, जो अपनी बुद्धि और नैतिकता के कारण, उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया जा सके।”†

इसी बीच लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा-नीति पर अपनी सम्मति एक प्रसिद्ध लेख-पत्र-द्वारा घोषित की, और लॉर्ड विलियम बैंटिन्क ने इस सम्मति को एक सरकारी ऐलान द्वारा स्वीकार किया (७ मार्च, १८३५)। इस ऐलान ने घोषणा करते हुए कहा, “सरकार का मुख्य उद्देश्य हम देश में अंग्रेजी भाषा-द्वारा युरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है।” इसके पश्चात् तुरन्त ही और भी कार्यदे निकले, जिनके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा। सन् १८३७ ई० में ‘अंग्रेजी’ भारत की राज-भाषा बना दी गयी और लॉर्ड हार्डिन्ग के सन् १८४८ की घोषणा के अनुसार उच्च सरकारी नौकरियों शिक्षित भारतीयों के लिए खुल गयीं। अब तो पाश्चात्य ज्ञान का आश्र और भी बढ़ा, और अंग्रेजी स्कूल बढ़ाचढ़ खुलने लगे।

• **बुड की घोषणा (१८५४) से भारतीय विध्वविद्यालय कानून (१९०) तक**—बुड के घोषणा-पत्र की सिफारिशों के कारण माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस पत्र ने जोरदार शब्दों में कहा :

† A N Basu, ed “Letters from the Court of Directors to the Governor of Fort St George, September, 29, 1830” Indian Education in Parliamentary Papers, Part I Bombay, Asia Publishing. 1932 p 195.



भारतीयों को पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं से पूर्णतः परिचित होना पड़ेगा, ताकि उन्हें युरोपीय ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक शाखा की जानकारी हो सके। इस विद्या-परिचय का प्रसार भारतीय शिक्षा-पद्धति का भविष्य में मुख्य ध्येय हो।†

इस ध्येय के फल-स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा और भी पल्लवित होने लगी। सन् १८५७ में, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसका माध्यमिक शिक्षा पर अति गहरा प्रभाव पड़ा। मैट्रिक परीक्षा-द्वारा विश्वविद्यालय माध्यमिक स्कूलों का पाठ्य-क्रम, शिक्षण का माध्यम, अध्यापन-पद्धति, इत्यादि का नियन्त्रण करने लगे। इसके फल-स्वरूप शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए विद्यार्थी तैयार करना हो गया।

बुड के घोषणा-पत्र ने स्वसंचालित स्कूलों के सहायतार्थ 'ग्राण्ट-इन-एड पद्धति' के व्यापक व्यवहार का आदेश दिया था। इस सरकारी अनुदान-नीति के फल-स्वरूप नेजी स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। सन् १८५४ तक केवल मिशन-संस्थाओं के ही स्वसंचालित स्कूल थे, पर बाद में भारतीय लोग भी माध्यमिक विद्यालय खोलने लगे। इस प्रकार माध्यमिक क्षेत्र में तीन प्रकार के हाई स्कूल प्रचलित हुए : (१) मिशन, (२) राजकीय और (३) भारतीयों द्वारा खोले हुए। सन् १८५४ में राजकीय स्कूलों की संख्या केवल १६९ थी, किन्तु सन् १८८२ में वह बढ़कर १,३६३ हो गयी। नेजी स्कूलों का विस्तार भी द्रुतगति से हुआ। सन् १८८२ में, भारतीयों-द्वारा परिचालित माध्यमिक विद्यालयों की संख्या १,३४१ हो गयी। इसी वर्ष अन्य स्वसंचालित संस्थाओं के द्वारा ७५७ स्कूल क्रियाशील थे।

इस विकास के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक दोष आ गये, जो अब तक अपना असर फैलाये हुए हैं। प्रमुख दोष ये हैं - जीवन की दृष्टि से शिक्षा अदेय-हीन हो गयी थी। मातृ-मापा के बदले अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो गयी। भारतीय मापाओं की उपेक्षा की गयी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। परीक्षा का असर बढ़ने लगा। पाठ्यक्रम सकुचित हो गया। औद्योगिक शिक्षा का अभाव रहा।

सन् १८८२ ई० में इण्टर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के क्षेत्र में एक महत्व-पूर्ण सुझाव दिया। आयोग ने कहा :

† Wood's Despatch, Para 10.

माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम रखे जायें : (१) अ-कोर्स जो साधारण रूप में साहित्यिक पाठ्यक्रम हो और जिसका उद्देश्य विश्व-विद्यालय में प्रवेश पानेवाले छात्रों को तैयार करना हो; और (२) आ-कोर्स — यद्वा व्यावहारिक तथा औद्योगिक पाठ्यक्रम हो, जिसमें व्यावहारिक, व्यावसायिक तथा साहित्यिक विषयों का समावेश हो ।<sup>१</sup>

आज हम अपने इस देश में बहुदेखीय स्कूलों की चर्चा सुनते हैं, पर इसकी परिस्थिति ८० वर्ष पूर्व इण्डियन कमीशन ने की थी । खेद की बात है कि हम मुगाव की ओर न सरकार ने ध्यान दिया और न जनता ने ही ।

सन् १८८२ से १९०२ तक माध्यमिक शिक्षा में एक शब्द भी आ नहीं । सन् १८८२ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या २,९१६ थी । इनमें २,१४,६७७ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे । सन् १९०२ में स्कूलों की संख्या ५,१२४ तथा उनकी छात्र-संख्या ६,२२,८६८ हो गयी । इसी अवधि में, मैट्रिक परीक्षा में बैठनेवाले परीक्षार्थियों की भी संख्या घटी — १८८६ में ७,४२९ में १९०२ में २२,७६७ हुई । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का विचार अवश्य हुआ, पर अधिकांश एक संगठन के अभाव में 'बमबोरे स्कूलों' की ही संख्या घटी । ये स्कूल अधिकांशतः बिना सहायता-प्राप्त स्कूल थे । ये शिक्षा विभाग के प्रशासन के बाहर थे; बाहर, उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता था । वे पीग की ओर पर चलते थे, तथा उनके सचचारों को घुट थी कि वे अपने स्कूल, जैसा भी चाहें, चलावें । वे अपने विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में भेज सकते थे । विश्वविद्यालय उन्हें माध्यमिक अवस्था देता था पर उसे उनसे निरीक्षण का अधिकार न था ।

सन् १९०४ के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, सभी स्वतन्त्र स्कूल-सहायता प्राप्त और बिना सहायतावाले-सरकारी नियंत्रण के अर्धीन आये । इस प्रस्ताव में, सरकार ने कुछ मांगें की थी निर्धारित की, दिनका पाठ्यक्रम बनाने वाले स्कूलों के लिए अनिवार्य हो गया । इन बातों के आगे बिना स्कूल स्वीकृत नहीं मिले करते थे । इस तरह बिना सहायतावाले स्कूल सरकारी नियंत्रण में लाने लगे । इसी समय, माध्यमिक शिक्षा-विभाग कायम (१९०४) बना हुआ । इसके अनुसार मैट्रिक परीक्षा में सफल होनेवाले माध्यमिक विद्यालयों को सहायता देने का अधिकार शिक्षा-विभाग को मिला गया । परिणामस्वरूप प्रदेश शिक्षा-विभाग ने कुछ दम निर्धारित की । समय-समय पर शिक्षा-विभाग द्वारा इन विद्यालयों का निरीक्षण भी होने लगा । इसके

स्कूलों की शिक्षितता निम्न ही दूर हुई; पर माध्यमिक क्षेत्र में, विश्वविद्यालय का प्रभुत्व बढ़ा तथा प्रशासन में द्वैध शासन शुरू हुआ।

**स्वदेशी आन्दोलन से सेडलर कमीशन तक (१९०५-१७).—**  
 इस अवधि की मुख्य विशेषतायें हैं : (१) राष्ट्रीय जागृति, (२) शिक्षा के माध्यम पर विचार और (३) माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन।

**राष्ट्रीय जागृति.**—बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से, भारतवासियों ने शिक्षा में दिलचस्पी लेना शुरू किया। पिछली शताब्दी में, हम देश के निवासी सरकार की शिक्षा-नीति के प्रति उदासीन रहे। पर लार्ड कर्जन के सुधारों को भारतवासी सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। देश भर में यह भावना लहरा गयी कि लार्ड कर्जन के शिक्षा-सुधारों का मुख्य उद्देश्य 'शिक्षा का विस्तार रोकना' है। हमारे नेताओं ने यह पूर्णतया समझ लिया कि देश का पुनर्जागरण शिक्षा के प्रसार से ही सम्भव है। यह जागरण केवल सरकार का मुँह ताकने से ही सम्भव न था, बल्कि उनके प्रयत्नों पर अवलम्बित था। इस प्रकार हमारे नेतागण शिक्षा-सुधार के लिए कटिबद्ध हुए।

सन् १९०५ में लार्ड कर्जन की भा विच्छेद-चेष्टा के कारण, बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन शुरू हुआ। इसका शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। फलतः, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् की स्थापना हुई। इसके कर्णधार थे सर गुरुदाम बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा खीन्द्रनाथ ठाकुर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का यही सबसे प्रथम प्रयास था। परिषद् ने पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के सुधार की एक चतुर्वर्तनी योजना तैयार की। कार्यक्रमों में एक राष्ट्रीय कालेज तथा एक इंजीनियरिंग कालेज (वर्तमान जादवपुर विश्वविद्यालय) स्थापित हुआ। राष्ट्रीय कालेज के अध्यक्ष थे श्री इन्दु। कुछ राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल भी खोले गये। इनमें साधारण विषयों के अतिरिक्त, एक उद्योग भी सिखाया जाता था।

परिषद् ने सम्पूर्ण भारत में शिक्षा-सुधार की एक लहर सी फैला दी। किन्तु सरकार ने स्वदेशी आन्दोलन के शिक्षित होने पर सभी राष्ट्रीय सभाएँ बन्द हो गयीं। जब जादवपुर विश्वविद्यालय आज भी खिल रहा है। पर परिषद् की दृष्टि के कारण, माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की माँग शुरू हुई।

**शिक्षा का माध्यम.**—इस अवधि में शिक्षा के माध्यम पर और तर्क विचार आरम्भ हुए। कारण, यह सभी अनुभव करने लगे कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम

मातृ-भाषा होना चाहिए न कि अंग्रेजी । १७ मार्च, १९१५ में श्री एस० रायानिन्गार ने केन्द्रीय विधानिका में निम्न-लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया :

यद् विधायिका गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी समिति से सिफारिश करती है कि माध्यमिक स्कूलों का शिक्षा-माध्यम भारतीय भाषाएँ हों; पर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य भाषा के रूप में रहे । इन प्रश्नों का विचार कार्य-कारिणी समिति प्रांतीय सरकारों का परामर्श लेकर करे ।

इस प्रस्ताव का घोर विरोध हुआ । विरोध के मुख्य कारण ये थे : (१) विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में अवनति की आशङ्का, (२) भारतीय भाषाओं में उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का अभाव, (३) बहुभाषा-भाषी प्रांतों की कठिनाईयें और (४) अन्तर-मार्देशिक आदान-प्रदान में अंग्रेजी की आवश्यकता । परिणाम-स्वरूप अंग्रेजी का माध्यम माध्यमिक क्षेत्र में बना रहा ।

प्रशासन.—सन् १९०४ के सरकारी प्रस्ताव की नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति हुई । पर स्कूलों की वृद्धि गीरी न जा सकी । स्कूलों की मरुता प्रमदाः पड़ती हुई सन् १९१७ में ७,६९३ हो गयी । पर इस अवधि में हाईस्कूल के प्रशासन में द्वैध शासन आरम्भ हुआ । कारण, हाईस्कूलों को दो अधिकारियों के सामने छुटना पड़ता था । एक ओर उन्हें अनुदान-सहायता के लिए सरकारी शिक्षा-विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती थी और दूसरी ओर मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थियों को भेजने के लिए विश्वविद्यालयों के समक्ष प्रार्थी होना पड़ता था । इस दोहरे नियन्त्रण के कारण, शिक्षा-विभागों तथा विश्वविद्यालयों में तनावनी खड़ी थी । शिक्षा विभाग का फयन था कि विश्वविद्यालय की स्वीकृति केवल मैट्रिक वर्ग तक ही सीमित रहे, पर विश्वविद्यालय इस-से-जम होना नहीं चाहता था ।

सैंट्रलर बर्मीशन से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक (१९१९-४०).—इस अवधि में कई विवेकान विरोधों ने माध्यमिक शिक्षा पर अनेक प्रतिबन्ध डाल दिए । इनमें से मुख्य ये : सैंट्रलर बर्मीशन-विरोध (१९१९), हाईस विरोध (१९२९), एण्ट्रुड विरोध (१९३७) तथा साट्रेण्ट विरोध (१९४४) ।

सैंट्रलर बर्मीशन विरोध—सन् १९१७ ई० में मध्य सरकार ने कच्छना विध-विचार की ओर के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति, सर मार्सेलस मैट्रग की अध्यक्षता में 'कच्छना विश्वविद्यालय बर्मीशन' की नियुक्ति की । इस आयोग ने माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के कुछ सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया । बर्मीशन की

राय थी कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के बिना विश्वविद्यालय की उन्नति असम्भव है।<sup>†</sup> इस कारण, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण विश्लेषण किया और इस क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव रखे :

१. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का विभाजन, मैट्रिक परीक्षा की अपेक्षा इण्टरमीडिएट परीक्षा द्वारा हो।

२. माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त दो परीक्षाएँ ली जायें : (१) हाईस्कूल परीक्षा, जो वर्तमान मैट्रिक परीक्षा के समान हो। इसे परीक्षार्थी सोलह वर्ष की आयु में दे सके। (२) इण्टरमीडिएट परीक्षा, जिसे विद्यार्थी १८ वर्ष की आयु में दे सकें। यह प्रचलित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समान अवश्य हो, पर इसके पाठ्य-क्रम में विविध विषयों का समावेश हो।

३. इण्टरमीडिएट शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों से इस्तान्तरित होकर एक नये प्रकार के विद्यालय अर्थात् इण्टरमीडिएट कालेजों के हाथ में आवे। इनमें कला तथा विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, प्रशिक्षण, इजिनियरिंग, कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय के शिक्षण की सुविधा हो। ये कालेज या तो स्वतन्त्र हों या हाईस्कूलों से सलग हों।

४. माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध, प्रवेश एवं परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट मण्डल की स्थापना की जाये। प्रत्येक परिषद में सरकार, विश्वविद्यालय, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रतिनिधि हों।

भारतीय शिक्षा में यह पहला ही अग्रसर था कि एक शिक्षा-आयोग ने इण्टरमीडिएट शिक्षा का इस्तान्तरण हाईस्कूलों में करने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालयों का मैट्रिक तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका प्रबन्ध एक स्वतन्त्र शिक्षा-परिषद करे।

हार्टेग रिपोर्ट.—हार्टेग कमिटी की दृष्टि में, माध्यमिक पाठ्यक्रम मैट्रिक परीक्षा की आवश्यकताओं में पूर्णतः प्रभावित था। कमिटी ने कहा कि “माध्यमिक शिक्षा की उन्नति सम्भवतः दुर्लभ है, किन्तु इसके समकाल में अनेक दोष हैं। इसका अन्तर्गत मैट्रिक परीक्षा में अत्यधिक अवकाश होने वाले छात्रों की मंजूरी में लगता है।” इस अवकाश को दूर करने के लिए कमिटी ने यह प्रस्ताव दिया कि :

१. जो शालक ग्रामीण व्यवसायों में लग सकें, उनके लिए ग्रामीण शालाएँ खोली जावें। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में विविधता लायी जाय।

२. मिडिल कक्षाओं में ही पाठ्यक्रम का विभाजन हो जाय, ताकि वही से विद्यार्थीगण औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों की ओर मुड़ सकें।

एबट-बुड रिपोर्ट.—मन् १९३६-३७ ई० में भारत सरकार ने दो अंग्रेज विरोपशों को, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सलाह देने के लिए नियुक्त किया। ये महानुभाव थे श्री एबट तथा श्री बुड। इन्होंने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया, तथा मार्च, मन् १९३७ में अपना प्रतिवेदन तैयार किया जो एबट-बुड रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख सिफारिशें ये थीं :

१. ग्रामीण मिडिल स्कूलों का पाठ्य-क्रम बालकों के वातावरण से सम्बन्धित हो।

२. इनका, कला तथा कौशल के शिक्षण को प्रोत्साहित किया जावे। प्रत्येक स्कूल के पाठ्य-क्रम में इनका समावेश हो।

३. दो प्रकार के व्यावसायिक स्कूल खोले जावें; (१) अपर (१ वर्ष की शिक्षा) — इनमें आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थीगण भरती हो, और (२) प्रवर (२ वर्ष की शिक्षा) — इनमें ग्यारहवीं कक्षा के बाद छात्र भरती किये जावें।

४. चुने हुए स्थानों में भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण कालिद्र तथा तकनीकी स्कूल स्थापित करे।†

सार्जेन्ट रिपोर्ट.—माध्यमिक शिक्षा के विषय में, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये :

१. दसैमान हण्टरमीस्ट्रिएट का प्रथम वर्ष हाईस्कूल में मिलाकर, हाई स्कूल की शिक्षा छः वर्षों की कर दी जावे। हाई स्कूल में भारती की अवस्था ११ वर्ष होनी चाहिए।

२. हाई स्कूल की शिक्षा छठी छात्रों की ही करनी चाहिए, जिसकी सम्भावना भीमन छात्रों में स्थित है। इस कारण, अगर बुनियादी पाठ्यक्रम स्थान बनने के बाद चुनाव द्वारा छोट कर केवल २० प्रतिशत

छात्र हाई स्कूलों में प्रवेश पावें। पर बुनियादी शिक्षा में जो छात्र योग्य दिखलावे, उनके प्रवेश के लिए भी हाई स्कूलों में स्थान रखे जावे।

३. हाई स्कूल दो प्रकार के हों — साहित्यिक तथा तकनीकी। दोनों का लक्ष्य विद्यार्थी को एक उत्तम टोस शिक्षा देना हो, ताकि आखिर कक्षाओं में उसे एक ऐसे उद्यम की शिक्षा मिले जो उसके स्कूल छोड़ने पर भारी जीवन में काम आवे।

४. प्रत्येक दशा में पाठ्य-क्रम विभिन्न हो। उस पर विश्वविद्यालय या सार्वजनिक परीक्षण मस्थाओं का अनावश्यक प्रभाव न हो।†

**उपसंहार.**—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति उत्तरोत्तर होती ही रही। सन् १९४८ ई० में मुख्य प्रान्तों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या १२,६९३ तक पहुँची। इनकी छात्रसंख्या भी बढ़ि हुई। इस वर्ष मिडिल स्कूलों की तथा हाई और उच्चतर हाईस्कूलों की सम्मिलित छात्रसंख्या क्रमशः ११,६७,२८१ तथा १७,८६,७१२ थी। जनता में माध्यमिक शिक्षा की चाह बढ़ी। देशांतों में अनेक माध्यमिक स्कूल खुले तथा कन्या शिक्षा बढ़ी।

सन् १९४७ ई० में, ब्रिटिश राज्य का अन्त हुआ। अंग्रेजी शिक्षा-नीति के माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव की आलोचना करते हुए, श्री हैम्पटन ने कहा है :

माध्यमिक शिक्षा का एक सिंहावलोकन करते समय, हमें मानना ही पड़ता है कि यह शिक्षा पूर्ण विकसित न हो सकी—न यह देश के राजनैतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वृद्धि के साथ कच्चे से कच्चा लगाकर बढ़ी, और न आधुनिकतम शैक्षणिक प्रगति के साथ अग्रसर हुई। स्कूलों पर मैट्रिक परीक्षा तथा शिक्षा-विभाग के आलीशानी स्वीकृत नियमों का अत्यधिक प्रभुत्व है। पाठ्यक्रम नितान्त पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, अंग्रेजी में घोटते घोटते वे अपनी प्रेरणाशक्ति खो बैठते हैं। स्कूलों की पढ़ाई शुष्क तथा नीरस है, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक विषयों का आयोजन नहीं किया गया है, दारारिक शिक्षा, खेल-कूद तथा मनोरंजन-कार्यों का अभाव है। अनेक शिक्षा आयोग तथा समितियाँ ने शिक्षा-मुद्धार पर सुझाव दिये थे,

† Sargent Report, pp 26-27.

पर उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हने-गिने विद्यालयों को छोड़कर माध्यमिक स्कूल आज उसी दशा में हैं, जैसे कि वे सन् १८८४ या १९०४ में थे।

**स्थापनापश्चात्तर काल.**—इस काल में तीन प्रसिद्ध निकायों ने माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया : ताराचन्द समिति (१९४८), विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४९) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३)।

**ताराचन्द समिति.**—इस समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का अवधि-काल १२ साल का हो : ५ वर्ष अवर-बुनियादी, ३ वर्ष प्रवर-बुनियादी तथा ४ वर्ष उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक स्कूल बहुरेखीय हों। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि साधारण स्कूल बन्द कर दिये जायें। माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए समिति ने एक कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश की।

**विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग.**—इस आयोग का सम्बन्ध विश्वविद्यालयीन शिक्षा से था, पर इसने माध्यमिक शिक्षा का भी विस्तरेय किया और उस पर कुछ सुझाव भी दिये। कमीशन ने गौर किया कि हमारी माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है और उसका सुधार अत्यावश्यक है। आयोग ने फिर मत दिया कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टरमीडिएट पास करने के बाद होना चाहिए, अर्थात् बारह वर्ष स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालिज में शिक्षा के पश्चात्।

**माध्यमिक शिक्षा-आयोग.**—ताराचन्द समिति तथा 'वेराशिम' की सिफारिशों के कारण भारत-सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को यह कमीशन नियुक्त किया। मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डॉ० लक्ष्मनस्वामी मुशलियर, इसके अध्यक्ष थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जून, १९५३ में भारत सरकार को दे दी। इसमें माध्यमिक शिक्षा के पंचादे प्रश्नों पर विचार किया गया है। मुख्य सिफारिशों की चर्चा इस अध्याय में दशोचित स्थानों पर की जावेगी।

**उपसंहार.**—स्वातन्त्र्य लाभ के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में उल्लेखयोग्य प्रगति हुई है। इसका पता अगले पन्ने के तान्त्रिका से लगेगा :

† H. V. Hampton. "Secondary Education", *The Educational System Bombay*, O. U. P. 1943 pp. 30-31.



## तालिका ११

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ से १९५६-५७

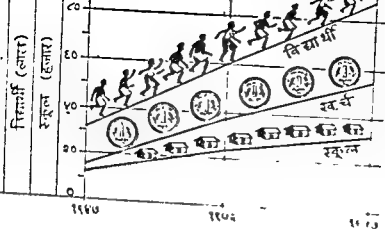
वर्ष	स्कूल-संख्या	छात्र-संख्या	खर्च (करोड़ रुपये)
१९४७-४८	१२,६९३	२९,५३,९९५	१४
१९५२-५३	२४,०५९	५९,०६,६६६	३७
१९५६-५७	३५,८३८	९३,३०,०००	५८

इस काल में माध्यमिक शिक्षा के ध्येय, पाठ्यक्रम, संगठन इत्यादि में अनेकानेक हेरफेर हुए। उल्लेखयोग्य सुधार ये हैं : (१) पाठ्यक्रम में विविधता तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश, (२) विज्ञान आदि विषयों के अभ्यास में सुधार, (३) नये प्रकार के उत्तर-प्राथमिक स्कूलों का आविर्भाव, (४) क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्र-भाषा की ओर अधिक झुकाव, (५) व्यायाम तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन, इत्यादि। इतना होते हुए भी, भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा सबसे निकम्मी ठहरायी जाती है।

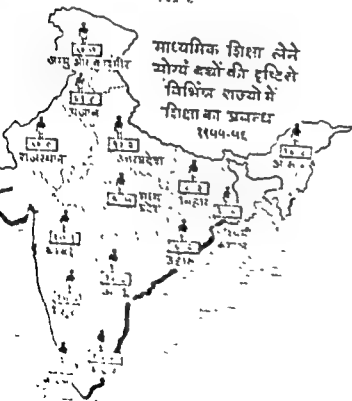
## वर्तमान स्थिति

**स्कूलों का वर्गीकरण.**—साधारणतः माध्यमिक स्कूलों की शिक्षावधि सात वर्ष होती है। इस अवधि को हम दो भागों में बाँट सकते हैं : (१) मिडिल या प्रवर बुनियादी या अवर माध्यमिक प्रकरण — यहाँ ११-१३ वयोवर्ग के विद्यार्थीगण अभ्यास करते हैं, और (२) हाईस्कूल — जहाँ १३ से १६ वयोवर्ग के छात्रगण शिक्षा पाते हैं। यह अवश्य है कि यह व्यवस्था पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विद्योपता है। बहुधा मिडिल स्कूल हाई-स्कूलों से संलग्न रहते हैं।

हाल ही में कुछ नये प्रकार के माध्यमिक स्कूल खुल गये हैं। ये ये हैं : उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा उत्तर-बुनियादी स्कूल। उच्चतर माध्यमिक स्कूल की अवधि किसी राज्य में तीन वर्ष और किसी में चार वर्ष है। इनके सिवा, अनेक स्कूलों को बहुदेशीय स्कूलों में बदल दिया गया है।



चित्र ८



**स्कूल तथा छात्र-संख्या.**—सन् १९५६-५७ में कुल स्वीकृत माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३६,२९१ थी, जिनमें से २६ उत्तर-बुनियादी, २४,४८६ मिडिल तथा ११,७७९ उच्च एवं उच्चतर स्कूल थे। इनमें से ४,३७३ कन्या-शालाएँ थीं। देहातों की कुल स्कूल-संख्या २४,९३६ थी, जिनमें १९,७१३ मिडिल तथा ५,२२३ हाई स्कूल थे।

इसी वर्ष माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या थी : ७९,७१,५९५ (५४,३५,७९६ लड़के और २५,३५,७९९ लड़कियाँ)। इन विद्यार्थियों में से ४८,२३,३४४ (३८,३०,७८४ लड़के और ९,९२,५६० लड़कियाँ) मिडिल कक्षाओं में, तथा २०,३३,२६१ (१६,५५,७५० लड़के और ३,४७,५११ लड़कियाँ) उच्च वर्गों में अध्ययन कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा लेने योग्य सम्पूर्ण देश के बच्चों का १३.५ प्रति शत स्कूलों में शिक्षा पा रहा था। इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों का शिक्षा-प्रबन्ध चित्र ९ से मिलेगा।

**प्रबन्ध.**—प्रबन्ध की दृष्टि से माध्यमिक स्कूलों का विभाजन निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

**तालिका १२**  
**माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६†**

अनुशास	स्कूल-संख्या	कुल स्कूलों का प्रतिशत
राजकीय ... ..	६,५७३	२०.२
जिला-मण्डल ... ..	९,१५४	२८.१
नगर-पालिका-मण्डल ..	१,२३६	३.८
स्वसंचालित स्कूल :		
सहायता-प्राप्त ... ..	११,६३२	३५.७
स्वाभित ... ..	३,९७३	१२.२
योग...	३२,५६८	१००.००

इस प्रकार एक-पंचमांश सस्थाएँ गवर्नीय हैं तथा लगभग आधे स्कूल गैसरकारी हैं। प्रायः एक-चतुर्थांश स्वयंचालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता तथा प्रायः एक-तृतीयांश स्कूल स्थानीय निकायों-द्वारा परिचालित हैं।

**प्रशासन.**—माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेवारी गवर्नों पर है तथा इसका प्रशासन शिक्षा-विभाग करता है। शिक्षा-विभाग शाला-स्वीकृति के निम्न बनाता है, स्कूलों के प्रशासन के लिए कायदे-कानून ठीक करता है, पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तथा स्कूलों का निरीक्षण करता है। पर स्कूल-इन्स्पेक्टरों की मर्यादा पर्याप्त न होने के कारण, स्कूल-निरीक्षण ठीक नहीं हो पाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा ही है :

प्रचलित निरीक्षण-पद्धति की अनेक साधियों ने ताम समालोचना की है। उनका कहना है कि निरीक्षण-कार्य असावधानी से किया जाता है, तथा स्कूल का निरीक्षण अग्र-जातिक होता है।।

सैद्धांतिक बर्मादान की विचारियों के कारण आब प्रायः प्रत्येक राज्य में इन्टर-मीडिएट था। और माध्यमिक शिक्षा-मण्डल स्थापित हुए हैं। सन् १९५७ ई० में इनकी संख्या पन्द्रह थी। इनके नाम तथा प्रत्येक का संस्थापन वर्ष इस प्रकार हैं :

(१) बिहार स्कूल परीक्षा-मण्डल, पटना, १९५२, (२) राज्य परीक्षा-मण्डल, त्रिवेन्द्रम १९४९, (३) उत्तर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली, १९२६, (४) आन्ध्र माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, ग्वालियर, १९५६, (५) उत्तर-प्रदेश माध्यमिक तथा इतरमीडिएट शिक्षा-मण्डल, आग्राहाबाद, १९२२, (६) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मद्रास, १९११, (७) उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बटक, १९५६, (८) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, जयपुर, १९५०, (९) पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५१, (१०) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, अजमेर, १९२९, (११) महाबोरोल माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५६, (१२) मेरु माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, बालौर, १९११, (१३) माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट मण्डल, पुना, १९४८ और (१४) बिस्नेस माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, नागपुर, १९२६। इनमें से अजमेर मण्डल को छोड़कर शेष बचने-बचने शेष या राज्य के इतरमीडिएट था। और शासन परीक्षाओं का परिचालन करते हैं। अजमेर-मण्डल की परीक्षाओं में भारत के किसी भी भाग के विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ये परीक्षाएँ उन छात्रों के लिए सुविधाजनक हैं, जिनके अभिभावकों की वसती भारत के विभिन्न भागों में बसा हुआ करती है।

† *State's Educational Commission's Report* p. 113

धित्त.—माध्यमिक शिक्षा का स्रोतवार खर्च का विवरण निम्नांकित तालिका में मिलेगा :

### तालिका १३

माध्यमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६†

स्रोत	रकम (रुपये)	कुल खर्च का प्रति शत
राजकीय निधि ... ..	२४,६८,२६,९५२	४६.६
जिला मंडल निधि ... ..	२,४९,३०,७६५	४.७
नगर पालिका मंडल निधि ... ..	१,०७,६१,५४४	२.०
फीस ... ..	२०,०४,९२,२६७	३७.८
दान ... ..	१,५०,३९,४५५	२.८
दूसरे स्रोत ... ..	२,८६,७८,७३०	६.८
योग...	५३,०१,९८,६१९	१००.००

ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा का आधा खर्च स्वतः चलाती है, पर यह रकम सब राज्यों में एक सी नहीं है। सबसे अधिक यह मध्यप्रदेश (५७.३) में थी तथा सबसे कम आन्ध्र प्रदेश (२३.९) में। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश का आवे से अधिक खर्च फीस द्वारा चला। दान और दूसरे स्रोत का भी हिसाब भिन्न-भिन्न था — कुल खर्च का १५.१ प्रति शत उद्दीर्ग में तथा ४.६ प्रति शत आन्ध्र प्रदेश में।

† Education in India, 1955-56, Vol 1. p. 144.

स्वसंचालित संस्थाओं को बहुधा राजकीय अनुदान मिलता है। पर हम प्रश्न पर प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्र नीति होती है निम्न-लिखित विषयों में से किसी भी एक मद पर अनुदान प्राप्त हो सकता है :

१. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वृत्ति;
२. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा का खर्च;
३. अनाथ बच्चों के छात्रावासों का सञ्चालन;
४. स्कूल तथा छात्रावास की इमारतों के निर्माण तथा प्रसार पर खर्च;
५. अभ्यास, शिक्षा-साधन, विज्ञान-शिक्षा तथा पुस्तकालय पर व्यय;
६. स्कूल की इमारतों, छात्रावासों तथा खेल-कूद के लिए जमीन खरीदने का खर्च;
७. हस्त-कला, कला तथा क्रीडाल के शिक्षण पर व्यय; तथा
८. निर्वाह-अनुदान।†

केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों तथा शिक्षा-संस्थाओं को कुछ अनुमोदित विषयों के लिए अनुदान देती है। प्रथम योजना-काल में केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के कारण माध्यमिक शिक्षा में अनेक सुधार किये गये। ४७० स्कूल बहुदेशीय स्कूलों में बदल दिये गये। १,०७२ स्कूलों को समाज-शास्त्र तथा २१४ स्कूलों को विज्ञान-अभ्यास की उन्नति के लिए, १,४७९ स्कूल-पुस्तकालयों तथा १,११९ मिडिल स्कूलों को हस्तकला आरम्भ करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था की गयी। १० प्रशिक्षण केन्द्रों और ११ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्राण्ट मिला तथा २१ संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के ३१ विषयों पर शोध करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मद में अनावर्ती खर्च का ६६ प्रति शत तथा आदर्शक खर्च का २५ प्रति शत स्वयं अनुदान के रूप में दिया।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् — माध्यमिक शिक्षा आयोग की विपरीतियों के कारण, भारत सरकार ने हम परिषद् की स्थापना २२ मार्च, १९५५ में की। परिषद् एक विरोध संस्था के रूप में काम करती है, तथा केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देती है। सितम्बर, १९५८ को परिषद् की कार्यवाही की बीच केन्द्रीय शिक्षा-सञ्चालन-द्वारा नियुक्त एक

† Secondary Education Commission's Report, p. 221

समिति ने की। इस समिति के परामर्श के अनुसार, परिषद पुनर्गठित हुई। इस पुनर्गठित परिषद के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है : (१) संचालक, माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण - कार्यक्रम - संचालक-मण्डल, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय, (२) नायब वित्त-परामर्शदाता, केन्द्रीय मन्त्रालय, (३) प्रत्येक संस्था से एक प्रतिनिधि — (अ) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिषद, (आ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (इ) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद, (ई) अखिल भारतीय शिक्षण-संघ और (उ) शिक्षण महाविद्यालय - आचार्य-सभा, (४) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, (५) पाँच नामजद शिक्षा-शास्त्री - केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा मनोनीत। इस तरह सभासदों की संख्या चौबीस है।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के संयुक्त शिक्षा-परामर्श-दाता माध्यमिक शिक्षा-विभाग, तथा इसी विभाग के प्रधान क्रमशः इस परिषद के अध्यक्ष एवं मन्त्री हैं। परिषद के मुख्य कार्य निम्न-लिखितानुसार हैं :

१. माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की आलोचना करना तथा एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना;

२. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये हुए प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर उपयुक्त सुझाव देना;

३. माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए, नये प्रस्तावों को उठाना; और

४. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शोधों पर विचार करना तथा गवेषणा के लिए नये तथ्य मुझाना।†

मूल परिषद के विधायक कार्य अत्र एक स्वतन्त्र 'माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण-कार्यक्रम-संचालक-मण्डल' को सौंप दिये गये हैं। यह मण्डल केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय से संलग्न है। नये परिषद का प्रथम अधिवेशन २७ जुलाई, १९५९ को हुआ, जब कि माध्यमिक शिक्षा के मुख्य पाँच प्रश्नों पर विचार करने के लिए पाँच उप-समितियाँ नियुक्त हुई : (१) उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा बहुदेशीय स्कूल, (२) पाठ्य-विषयक तथा परीक्षा-सम्बन्धी सुधार, (३) मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण, (४) शिक्षक तथा प्रयोग और (५) विज्ञान-शिक्षा।

† *Government of India Resolution No F. 13-36/58-SE 3, March 28, 1959.*

**पाठ्यक्रम.**—बहुधा माध्यमिक पाठ्यक्रम में ये विषय सम्मिलित रहते हैं :  
 (१) अंग्रेजी, (२) मातृ-भाषा, (३) इतिहास तथा भूगोल, (४) गणित, (५) विज्ञान  
 और (६) सांस्कृतिक या आधुनिक नाट्य। हाल ही में औद्योगिक विषयों का भी  
 समावेश हुआ है। पाठ्यक्रम के दोषों की आलोचना करते हुए, माध्यमिक शिक्षा  
 समिति ने कहा :

१. प्रचलित पाठ्यक्रम अति सकुचन है;
२. यह निग पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है,
३. पाठ्य-विषयों की अधिकता होती हुई मी, इसमें उन क्रियाओं  
 का अभाव है, जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो सके;
४. यह विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति  
 नहीं करता;
५. इसमें परीक्षा की प्रधानता रहती है, और
६. इसमें तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। देश  
 की आर्थिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है।

ताम्रचन्द्र रिपोर्ट के निष्कर्षों से ही देश में विविध पाठ्यक्रम की सीमा शुरू हुई  
 तथा कुछ औद्योगिक स्कूल खुले। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के फल-स्वरूप  
 हम कार्य में एक नवीनता आयी। धर्म प्रहरेदीय स्कूल खुलने लगे हैं तथा  
 पाठ्यक्रम का कुछ पैग रहा है। दारिद्र्य शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है तथा  
 राष्ट्रीय सैन्य-विद्यार्थी दल की आवश्यकता भी गयी है।

**बाल्या-वृद्ध तथा शिक्षा-साधन.**—इसमें कुछ विशेष उन्नति नहीं दिखलाई  
 दे रही है। अनेक स्कूल बंद हो रहे हैं तथा गन्दी बालियों में लगते हैं। पुस्तकालयों का  
 स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। कनता इन दोषों से पूर्णतया परिचित है, पर उन्नति का  
 आकाश नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण है माध्यमिक शिक्षा का दौरे बर्तन में  
 शिक्षा। बर्तमान में हमारे नेतागण हतोत्साह होकर बह देते हैं कि शिक्षा-समस्या  
 अभी होने दो। शिक्षा-साधनों एवं साधन वृद्धों की बिना हम अग्रिम में बरेद।

**परीक्षा.**—हमारी शिक्षा-प्रणालि में परीक्षा का प्रमुख स्थान है। परीक्षा ही  
 मूल्य की होती है: आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक परीक्षाओं के द्वारा शिक्षार्थी



तः शिक्षात्मक तथा उन्नती क्षमता भी जैसा होती है। आन्तरिक परीक्षाएँ सामाजिक, तात्त्विक, सांख्यिक तथा वार्षिक होती हैं। इन मध्ये वार्षिक परीक्षा ही अपने महत्व पूर्ण होती है। कारण, इस परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को उस की कक्षाओं में स्थाने जाने हैं, अथवा अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में गेक गिये जाने हैं।

बाह्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने पर ही जाती है। निम्न-निम्न मध्ये में जः माध्यमिक परीक्षा के विविध नाम हैं: मैट्रिक, स्कूल परीक्षा, स्कूल मरीटिकेण्ड, आदि। वेद के साथ कहना पड़ता है कि इस परीक्षा में समूचे देश के ५० प्रतिशत में भी इस परीक्षाओं सफल होते हैं। निम्नलिखित तालिका पर दृष्टि-निर्देश कीजिए :

### तालिका १४

मैट्रिक तथा अन्य शालान्त परीक्षाओं का फल

वर्ष	परीक्षार्थियों की संख्या	'पास' संख्या	उत्तीर्णता का प्रतिशत
१५१-५२	५,८३,५७०	२,६२,०५९	४४.७
१५२-५३	७,२४,७९९	३,३४,७६०	४६.२
१५३-५४	८,१८,६२०	३,९७,००५	४८.५
१५४-५५	८,३०,००१	४,००,०१४	४८.२
१५५-५६	९,२०,०२६	४,२९,४९४	४६.७

परीक्षार्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक, समाज तथा शिक्षा-पद्धति पर इस परीक्षा का विपक्ष परिणाम होता है। घोटते-घोटते विद्यार्थी निष्पाप-सा हो जाता है, और उसकी शारीरिक सम्पत्ति निस्तेज पड़ जाती है। परीक्षा में वह जो कुछ भी उगल जाता है, उसी पर उसे उसका मूल्यांकन होता है। उसके आन्तरिक परीक्षा-फल की कोई नज़र भी परवा नहीं करता है। उस मूल्यांकन में परीक्षकों की वैयक्तिक रुचियाँ एवं चारों का ही प्राधान्य रहता है। यदि परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होता है, तो वह अपना नैतिक संतुलन खो बैठता है, विलाप करने लगता है और आत्म-विश्वास गँवा देता

है। इन के साथ-साथ उसके माता-पिता के तथा देश के अर्थ का नाश या अपव्यय होना है।

पर इस परीक्षा का सबसे बुरा परिणाम हमारी शिक्षा-पद्धति पर पड़ता है। कारण, एक शिक्षक की योग्यता तथा एक स्कूल की दक्षता शालान्त परीक्षा-फल के आधार पर की जाती है। शिक्षक का घ्येय हो जाता है विद्यार्थियों को परीक्षा में पास करना। वह वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली भूल जाता है। पढ़ाने समय वह उन अंशों पर धोर देता है, जिन पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को भी ऐसे स्थल बिना समझे-पूछे कंठस्थ करने पड़ने हैं। इन परीक्षा के विकृष्ट पचास वर्षों से आवाज उठती आ रही है, पर परीक्षाओं के बोझ से भारतीय शिक्षा मुक्त नहीं हो पायी है।

### माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ

**भूमिका.**—आज विदेश रूप से माध्यमिक शिक्षा की नुस्ताखीनी हो रही है, और इस शिक्षा की आद्यानुरूप प्रगति नहीं हुई है। असन्तोष के अनेक कारण हैं। पूरे विश्व के माध्यमिक क्षेत्र में आज एक नवीन विचार-धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, नये नये विषयों का समावेश हो रहा है तथा उपयोगिता और व्यावहारिक ज्ञान की पुकार मची है। इन सब बातों की ओर हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, पर आद्यानुरूप परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। लगभग दस वर्षों से हम प्रजातान्त्रिक हैं, पर आज भी हमारी माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली प्रजातान्त्रिक नहीं है। विद्यार्थियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पाठ्यक्रम सुवर्ण है, निर्देश तथा प्रगमन का अभाव है, परीक्षा पर विरोध धोर दिया जाता है, जीवन की आवश्यकताओं से शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है, इत्यादि। माग्य यह है कि आज माध्यमिक शिक्षा के सामने अनेक समस्याएँ हैं। उनमें से मुख्य ये हैं: (१) उद्देश्य, (२) माध्यमिक शिक्षा की दूर, (३) माग्यनिक ढाँचा, (४) पाठ्यक्रम, (५) निर्देश, (६) निर्देश तथा प्रगमन, (७) प्रवासन, (८) परीक्षा तथा योग्यता निर्धारण और (९) विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण। अब इन समस्याओं पर प्रत्येक संक्षेप से विचार किया जाए।

**उद्देश्य.**—अभी तक माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को वा तो विश्वविद्यालयों के योग्य तैयार करना था, अथवा दफ्तारी के जूबों के लिये बना देना था। अगर माध्यमिक शिक्षा वा यही उद्देश्य रखे है तो हमारे माध्यमिक स्कूल आद्यानीय सफल-रूत हुए हैं। वाग्य, वाग्यिक स्वभावच भरे हुए हैं। यहाँ तक कि अनेक विद्यार्थियों को यहाँ आज उगद नहीं मिल रही है। इनके निरा, इत्यादि निर्दिष्ट

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की अवधि बच्चों की मजदूरी बढ़ाने के लिए बढ़ाई गई है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वर्ष बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ क्षमता बढ़े तथा बालिकाओं में अधिक आयु के लिए विद्यार्थी बन सकें। यह भी देखा जाता है कि हमारे स्कूल पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को आने वाले विज्ञान-आन्दोलन का प्रथम वर्ष शुरू को सम्मान में लग जाता है, और विज्ञान-आन्दोलन उन्हें इण्टरमीडिएट परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तीन वर्ष का माध्यमिक शिक्षा की आयोजना इसीलिए नहीं की गई है। अब में अच्छा तो यह होगा कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वर्तमान इण्टरमीडिएट का स्थान ले लेता, और उसके बाद विद्यार्थियों का तीन वर्ष का डिग्री कोर्स आना। राष्ट्रीय आयोग का यही सुझाव था, पर इसमें शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ जाती और माता-पिताओं पर बढ़ने बच्चों के एक वर्ष के खर्च का बोझ लग जाता। यह सब सोच-विचार कर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की अवधि नहीं बढ़ानी चाही।

**सांख्यिकीय ढाँचा.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर कई समितियों तथा परिषदों ने विचार किया। अन्त में 'कंसल्टिंग' तथा विश्वविद्यालयों के प्रमुखों की एक बैठक में (१९-१४ जनवरी, १९५५) भारत की शिक्षा के विषय के विषय में कुछ प्रस्ताव पास हुए। भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया। इनके अनुसार, भविष्य में शिक्षा का ढाँचा साधारणतया इस प्रकार का होगा :

१. आठ वर्ष की अवधि की अष्टतम बुनियादी शिक्षा — ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए;

२. तीन वर्ष की अवधि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें बहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी — १४-१७ वयोवर्ग के हेतु; और

३. उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् विश्वविद्यालयों का तीन वर्षीय डिग्री कोर्स।

इस प्रकार भारत सरकार अष्टवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना कर रही है; इस स्तर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा : (१) प्रारम्भिक ६-११ तथा (२) निम्न माध्यमिक या प्रथम बुनियादी ११-१४। इसके मुख्य दो कारण हैं : प्रथमतः, ६-१४ वयोवर्ग के विद्यार्थियों की सार्वजनिक, अनिवार्य शिक्षा अभी कुछ वर्ष प्रारम्भ है। द्वितीयतः, ११ वर्ष की आयु के पश्चात् अनेक विद्यार्थी बुनियादी स्कूल नहीं चाहेंगे। अभी भारत के सामने मुख्य प्रश्न ६-११ वयोवर्ग के बच्चों की

अनिवार्य शिक्षा का है। यह शिक्षा ठीक पाँच वर्ष की अवधि की हो, न कि चार अथवा पाँच वर्षीय — जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया था। इस अवधि को अनिवार्य न छोड़ देना चाहिए।

प्रारम्भिक स्तर के बाद आना चाहिए निम्न माध्यमिक या प्रथम बुनियादी (११-१४ वयोवर्ग के लिए), और तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक (१४-१७ वयोवर्ग के लिए)। यहाँ यह भी कहना अनुचित न होगा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रथम बुनियादी विद्यार्थीगण बे-रोकटोक दाखिल हो सकें। यह आवश्यक है कि प्रथम बुनियादी के अधिकांश विद्यार्थियों को उत्तर बुनियादी स्कूलों में अग्रगण्य करें। इस तरह माध्यमिक शिक्षा के दो मिश्र-मिश्र स्तर होंगे : (१) निम्न (वर्ग ६-८) तथा (२) उच्च (वर्ग ९-११)। इस तरह उच्च माध्यमिक का दौरान तीन वर्ष होगा, न कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग के सुझाव के अनुसार चार वर्ष। यह कहना अनावश्यक है कि उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त ढाँचे को कार्यान्वित करने में दो अड़चनें आवेंगी : (१) वर्तमान हाई स्कूलों को उच्चतर स्कूल में बदलना और (२) उच्चतर हाई स्कूल पाठ्यक्रम को और भी कम समय में समाप्त करना—अर्थात् छः वर्ष में, न कि ७ या ८ वर्ष में। चूँकि अभी हम प्रत्येक हाईस्कूल को उच्चतर रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ समय तक कालिज तथा विश्वविद्यालय पूर्व-विश्वविद्यालय कोर्स चलावेंगे। पर कम-से-कम प्रत्येक जिले में एक उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल की आवश्यकता है। द्वितीय प्रश्न का समाधान हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक (वर्ग ६-११) के समूचे पाठ्यक्रम को विचारपूर्वक एकीकरण के द्वारा। यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को एक चुनौती है। कारण, उन्हें सात या आठ वर्ष के पाठ्यक्रम को छः वर्ष के वृत्त में बमना पड़ेगा।

**पाठ्यक्रम.**—माध्यमिक पाठ्यक्रम की कमियों की चर्चा पहले ही की गयी है। अब एक-उद्देशीय पाठ्यक्रम से काम न चलेगा। कारण, ऐसे पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों की विभिन्न रुचियों, शक्तियों तथा रुझानों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा का ध्येय है, “उत्पादन-कार्य-चतुरता का विकास करना, राष्ट्र का धन बढ़ाना और उसके द्वारा जनता के जीवन-स्तर को देश में ऊँचा उठाना।”<sup>1</sup> हम यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ उनकी शारीरिक उन्नति तथा चरित्र-गठन करना भी है। अतः, इन विचारों से माध्यमिक पाठ्यक्रम को दृढ़तर बनाना अनिवार्य हो जाता है। साहित्यिक

स युवक और युवतियों नौकरों की अर्जी लिये घड़े घाते हुए फिर रही है। इस प्रकार स्तविक जीवन की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य हीन हो गयी है। हिमाचल न्यायालय का है कि केवल ५०-५५ प्रति शत मैट्रिक पास विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। इसके सिवा गत पचास वर्षों में माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या पन्द्रह गुना बढ़ गयी है। सन् १९०१-०२ में ६०२३ लख छात्र थे, जो सन् १९५६-५७ में ३०३ लाख हो गये। इसका अर्थ यह है कि अब विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक वर्ग के विद्यार्थीगण माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। इन शिक्षा-सम्बन्धी वृत्ति में अधिकतर विविधता पायी जाती है। निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा का और भी विस्तार होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की केवल पृष्ठभूमि न रहेगी, पितृ स्वतः पूर्ण भी होगी। हाँ, यह विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिभा-संग्रह छात्र प्रार करके अवश्य देवेगी; पर यह भी आवश्यक है कि इस शिक्षा के समाप्त करने पर किसी कार्य-क्षेत्र में सीधे लग सकें और जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करने में सक्षम हो सकें। चूँकि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्ग-पूर्ण विकास करना है, इस कारण माध्यमिक स्कूल का ध्येय विद्यार्थी की मानसिक उन्नति के साथ-साथ उसका शारीरिक तथा नैतिक गठन भी होगा।

आजादी मिलने के पश्चात् हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक नवीन उत्तरदायित्व पड़ा है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है कि इन स्कूलों के छात्रों को सी-शिक्षा देनी चाहिए “जिससे वे धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र के सारे उत्तरदायित्वों को वहन कर सकें, और देश का नैतिक अभ्युत्थान कर सकें।”<sup>†</sup> माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य देश के लिए मध्यवर्ती नेता तैयार करना होना चाहिए। इर्ष की बात है हमारे देश में अनेक विश्व-विख्यात उच्चश्रेणी के नेतागण हैं; पर मध्यवर्ती नेताओं की अत्यन्त अभाव है। किसी भी देश की उन्नति मध्यवर्ती नेताओं पर ही रहती है। अतः, ये ही स्थानिक समाज के कर्णधार होते हैं। ये ही सामान्य जनता को समुचित दिशा दे सकते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माध्यमिक स्कूलों ने भी तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

**माध्यमिक शिक्षा की हद्द.**—आज हमारे देश के शिक्षा-जगत् में विभिन्न रिभाषिक शब्दों का उपयोग हो रहा है : अवर तथा प्रवर बुनियादी, प्राथमिक, प्रारम्भिक, डिल, जूनियर माध्यमिक, हाई, उच्चतर माध्यमिक, विश्वविद्यालय, इत्यादि। इन्हें

हुनकर कोई भी धरारा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा के मुख्य तीन धर्म हैं : प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च। इन्हीं तीन पारिभाषिक शब्दों का हमारे देश में उपयोग किया जाय।

इन तीन धर्मों में एकता की बहुत जरूरत है। पहले, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर विचार कीजिए। दोनों शिक्षा-प्रणाली की अवधि, विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। उनमें एक समानता चाहिए। जब कि बुनियादी शिक्षा हमारे देश की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली है, तब पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा का दौरान ५ वर्ष (अथवा बुनियादी) क्यों न हो ?

इस शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए ? माध्यमिक शिक्षा अधोग ने सिफारिश की है कि चार या पाँच वर्ष की प्राथमिक अवस्था अथवा बुनियादी के बाद माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो, तथा इस शिक्षा के दो खतम हों : (१) मिडिल अवस्था अथवा माध्यमिक अवस्था अथवा बुनियादी—तीन वर्ष की शिक्षा ; और (२) उच्चतर माध्यमिक—४ वर्ष की शिक्षा।

अथवा बुनियादी की माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत लाकर आयोग ने ठीक सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा के लिये वांछित बौद्धिक आधार तथा व्यावसायिक कुशलता दोनों ही की प्राप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ाना अपेक्षित है। इस विचार को कार्यान्वित करने लिए यह सुझाव दिया गया कि :

१. माध्यमिक शिक्षा की वय-अवधि ११ से १७ वर्ष हो।
२. उच्चतर माध्यमिक के चार वर्ष के पाठ्यक्रम में इष्टतम विषय प्रथम वर्ष सम्मिलित हो।
३. द्वितीय वर्ष टिप्परी-बोर्ड में जोड़ दिया जाय। इस प्रकार टिप्परी-बोर्ड तीन वर्ष का कर दिया जावे।
४. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्, किसी भी व्यावसायिक शिक्षण में प्रवेश किया जा सके।
५. जब तक माध्यमिक हाईस्कूल का नया ढाँचा कार्यान्वित न हो तब तक पुराने हाईस्कूल जारी रखे जावें। इन स्कूलों में मध्यम-विद्यालय के लिए वांछित में एक वर्ष का पूर्व-निश्चिन्त पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाय।

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की अवधि बच्चों की मग्नद वर्ष आयु तक है। उपर्युक्त सुझाव के अनेक कारण थे। माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वर्ष जोड़ने का मुख्य ध्येय था कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ धमता बढ़े तथा कानिजों में अधिक आयु के तैयार विद्यार्थी आवें। यह भी देखा जाता है कि हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को अपने कालिज-अध्ययन का प्रथम वर्ष खुद को सँभालने में लग जाता है, और सँभलते-सँभलते उन्हें इण्टरमीडिएट परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तीन वर्ष स्नातक शिक्षा की आयोजना इसीलिए रखी गयी है। सब से अच्छा तो यह होता कि उच्चतर माध्यमिक स्तर वर्तमान इण्टरमीडिएट का स्थान ले लेता, और उसके बाद विश्वविद्यालयों का तीन वर्ष का डिग्री कोर्स आता। राधाकृष्णन आयोग का यही सुझाव था, पर इससे शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ जाती और माता-पिताओं पर अपने बच्चों के एक वर्ष के खर्च का बोझ लट जाता। यह सब सोच-विचार कर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की अवधि नहीं बढ़ानी चाही।

**सांगठनिक ढाँचा.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर कई समितियों तथा परिपदों ने विचार किया। अन्त में 'केसशिम' तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक में (१२-१४ जनवरी, १९५५) भारत की शिक्षा के ढाँचे के विषय में कुछ प्रस्ताव पास हुए। भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया। इनके अनुसार, भविष्य में शिक्षा का ढाँचा साधारणतया इस प्रकार का होगा :

१. आठ वर्ष की अवधि की अक्षत बुनियादी शिक्षा — ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए;

२. तीन वर्ष की अवधि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें बहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी — १४-१७ वयोवर्ग के हेतु; और

३. उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् विश्वविद्यालयों का तीन वर्षीय डिग्री कोर्स।

इस प्रकार भारत सरकार अष्टवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना कर रही है; पर इस स्तर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा : (१) प्रारम्भिक ६-११ तथा (२) निम्न माध्यमिक या प्रवर बुनियादी ११-१४। इसके मुख्य दो कारण हैं : प्रथमतः, ६-१४ वयोवर्ग के विद्यार्थियों की सार्वजनिक, अनिवार्य शिक्षा अभी कुछ वर्ष असम्भव है। द्वितीयतः, ११ वर्ष की आयु के पश्चात् अनेक विद्यार्थी बुनियादी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेंगे। अभी भारत के सामने मुख्य प्रश्न ६-११ वयोवर्ग के बच्चों की

अनिवार्य शिक्षा का है। यह शिक्षा ठीक पाँच वर्ष की अवधि की हो, न कि चार अथवा पाँच वर्षीय — जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया था। इस अवधि को अनिवार्य न छोड़ देना चाहिए।

प्रारम्भिक स्तर के बाद आना चाहिए निम्न माध्यमिक या प्रथम बुनियादी (११-१४ वयोवर्ग के लिए), और तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक (१४-१७ वयोवर्ग के लिए)। यहाँ यह भी करना अनुचित न होगा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रथम बुनियादी विद्यार्थीगण बे-रोकटोक दाखिल हो सकें। यह आवश्यक है कि प्रथम बुनियादी के अधिकांश विद्यार्थियों को उत्तर बुनियादी स्कूलों में अग्रगण्य करें। इस तरह माध्यमिक शिक्षा के दो भिन्न-भिन्न स्तर होंगे : (१) निम्न (वर्ग ६-८) तथा (२) उच्च (वर्ग ९-११)। इस तरह उच्च माध्यमिक का दौरान तीन वर्ष होगा, न कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग के सुझाव के अनुसार चार वर्ष। यह कहना अनावश्यक है कि उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष सम्मिलित रहेगा।

उपर्युक्त ढाँचे को कार्यान्वित करने में दो अड़चने आवेंगी : (१) वर्तमान हाई स्कूलों को उच्चतर स्कूल में बदलना और (२) उच्चतर हाई स्कूल पाठ्यक्रम को और भी कम समय में समाप्त करना—अर्थात् छः वर्ष में, न कि ७ या ८ वर्ष में। चूँकि अभी हम प्रत्येक हाईस्कूल को उच्चतर रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ समय तक कालिब तथा विश्वविद्यालय पूर्ण-विश्वविद्यालय कोर्स चलावेंगे। पर कम से-कम प्रत्येक जिले में एक उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल की आवश्यकता है। द्वितीय प्रश्न का समाधान हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक (वर्ग ६-११) के समूचे पाठ्यक्रम को विचारपूर्वक एकीकरण के द्वारा। यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियों की एक चुनौती है। कारण, उन्हें मात्र या आठ वर्ष के पाठ्यक्रम को छः वर्ष के हित में समाना पड़ेगा।

पाठ्यक्रम.—माध्यमिक पाठ्यक्रम की कमियों की खोज पहले ही की गयी है। अब एक-उद्देशीय पाठ्यक्रम से काम न चलेगा। कारण, ऐसे पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों की विभिन्न रुचियों, शक्तियों तथा इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, “उत्साहन-कार्य कुशलता का विकास करना, राष्ट्र का धन बढ़ाना और उसके द्वारा जनता के जीवन-स्तर को देश में उच्च उठाना।” हमें यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के सामाजिक विकास के साथ उनकी शारीरिक उन्नति तथा चरित्र-वर्धन करना भी है। अतः, इन दिश्यों में माध्यमिक पाठ्यक्रम को हलक कराना अनिवार्य हो जाना है। सामाजिक



विषयों के शिक्षा, इसमें औद्योगिक तथा तकनीकी विषयों का रहना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गृहनायक कायों की ओर ध्यान दिया जाय।

**निम्न माध्यमिक स्तर.**—इस स्तर के पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन से सम्बन्धित आवश्यक विषयों का परिचय कराना है। इस स्तर के पाठ्यक्रम में, मातृ-एँ, समाज शास्त्र, सामान्य विज्ञान तथा गणित का समावेश हो। इनके अतिरिक्त विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चरित्र के लिए कथा एवं संगीत और मञ्च-कला, तथा उन्हें जीविकीय रहने के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल कूद का ज़रूरत है। इन आवश्यकताओं की ओर ध्यान रखा हुआ, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया है :

१. मातृ-एँ : (१) राष्ट्र-भाषा (हिन्दी), (२) मातृ-भाषा — जिन क्षेत्रों में हिन्दी मातृ-भाषा हो, वहाँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जाये, और (३) अंग्रेज़ी अथवा उच्च मातृ-भाषा या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा;

२. समाज शास्त्र — इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का समावेश;

३. सामान्य विज्ञान;

४. गणित : अंकगणित, सरल बीजगणित, सरल रेखागणित;

५. कला या संगीत;

६. एक मज़ाफ़ (स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए; देशांतरों में कृपि); और

७. शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक और मनोरञ्जक क्रियाएँ।†

शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो। पाठ्यक्रम विभिन्न स्वतन्त्र विषयों में न बँटा हुआ हो, बल्कि विभिन्न प्रकार के "ज्ञान-क्षेत्रों में बँटा हुआ हो, जो कि जीवन से सम्बन्धित हों। इसके अतिरिक्त जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने प्रस्ताव किया है कि "मिडिल तथा प्रवर बुनियादी पाठ्यक्रम एक से हों। इनकी अध्यापन-पद्धति में ही केवल विभिन्नता की आवश्यकता है।"‡

† Ibid., p 89.

‡ Ibid., pp 86-87.

**उच्चतर माध्यमिक स्तर.**—निम्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सभी विषय अनिवार्य हैं। इस न्यूनतम ज्ञान की आवश्यकता सभी शिक्षित मनुष्य को रहती है। पर उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-विषयों का प्रबन्ध होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, निम्न माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की बुनियाद पर अब विशेषीकृत अध्ययन शुरू हो सकता है। द्वितीयतः, किशोरों की विभिन्न क्षमताओं का ठीक अनुमान १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर आधे से अधिक विद्यार्थियों के सामने दाल-रोटी का प्रश्न आ जाता है। इस कारण उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक विशेष ध्येय होना चाहिए — प्रत्येक विद्यार्थी को एक व्यवसाय या उद्योग के लिए तैयार करना। इन जरूरतों को सामने रखते हुए दो विशिष्ट निश्चयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार किया जाय, अर्थात् माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद् (अभामाशिव)।

१. माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रभाव.—इस आयोग ने सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर में निम्न-लिखित विषय सम्मिलित किये जायें :

अ. भाषाएँ.—(१) मातृ-भाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृ-भाषा तथा सांस्कृतिक भाषा सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, (२) इनमें से कोई भी एक भाषा : (अ) हिन्दी (जिनकी मद भाषा मातृ-भाषा न हो), (आ) सरल अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल स्कूल में अंग्रेजी न पढ़ी हो), (इ) उच्च अंग्रेजी (इस भाषा का जिन्होंने पहले अध्ययन किया हो), (ई) एक आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर), (उ) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी को छोड़कर), (ऊ) एक सांस्कृतिक भाषा।

आ. (१) समाज शास्त्र और (२) सामान्य विज्ञान (गणित के साथ) — प्रथम दो वर्ष।

इ. स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए, इनमें से एक अग्रदूत : (१) बतार्ई तथा कुनाई, (२) बटईगिरी, (३) धान का काम, (४) बागवानी, (५) टर्डीगिरी, (६) छारने की कला, (७) कारखाने का काम, (८) सुविधमं तथा बसीनकारी, और (९) मूर्ति कला।

ई. निम्न-लिखित वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के कोई भी तीन विषय : (१) मानवीय विषय—(अ) एक सांस्कृतिक भाषा या अन्य कोई

भाषा, जो कि अ(२) में न गयी हो, (आ) इतिहास, (इ) भूगोल, (ई) सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (उ) सरल मानव और तर्क शास्त्र, (ऊ) गणित, (ए) गीत, (ऐ) गृह विज्ञान । (२) विज्ञान — (अ) पदार्थ विज्ञान, (आ) रसायन शास्त्र, (इ) प्राणी-विज्ञान, (ई) भूगोल, (उ) गणित, (ऊ) सरल शरीर तथा आगेय विज्ञान । (३) प्राविधिक विषय. — (अ) व्यावहारिक गणित और भूमिति रेल्वे नियम, (आ) व्यावहारिक विज्ञान, (इ) सरल मैकेनिक्स इंजिनियरिंग, (ई) सरल इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग । (४) वाणिज्य विषय. — (अ) व्यापारी अभ्यास, (आ) लेखा-कार्य, (इ) व्यापारिक भूगोल या सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (ई) डॉक्ट्रेण्ड तथा ट्राईपिंग । (५) कृषि. — (अ) साधारण कृषि, (आ) पशु-पालन, (इ) उद्यान-विद्या तथा बागवानी, (ई) कृषि-सम्बन्धी रसायन तथा वनस्पति-शास्त्र । (६) कलित कलाएँ. — (अ) कला-इतिहास, (आ) नकशा तथा रेखा-चित्र, (इ) चित्र-कला, (ई) मूर्ति-कला, (उ) संगीत, (ऊ) नृत्य । (७) गृह-विज्ञान. — (अ) गृह अर्थशास्त्र, (आ) आहार तथा पाक-कला, (इ) मातृ-कला तथा शिशु-पालन, (ई) गृह-प्रबन्ध तथा सुधूषा ।†

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि आयोग ने दो प्रकार के विषयों का सुझाव दिया है : (१) अनिवार्य अर्थात् अ, आ, इ समूह और (२) बहुमुखी अर्थात् ई समूह । इसके अन्तर्गत ई समूह के ३ वर्ग आ जाते हैं । इनमें से किसी भी वर्ग के तीन विषय लिये जा सकते हैं । आवश्यकतानुसार दूसरे प्रकार के विविध विषय भी अवश्य सम्मिलित किये जा सकते हैं । आयोग ने यह सिफारिश की है कि बहुमुखी पाठ्यक्रम उच्चतर स्तर के द्वितीय वर्ष से शुरू किये जावें ।

२. अभ्यासाश्रित के प्रस्ताव. — माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावों का विचार कई निकायों ने किया । भाषा के विषय में 'अभ्यासाश्रित' की एक बैठक (११ जनवरी, १९५६) ने सुझाव दिया कि उच्चतर पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ अनिवार्य हों । 'किसशिम' ने अपनी सन् १९५७ ईस्वी की जनवरी की बैठक में इस सुझाव को मान लिया तथा राज्य-सरकारों की विवेचना के लिए निम्न-लिखित दो सूत्र प्रस्तुत किये :

प्रथम सूत्र : (१)—(अ) मातृ-भाषा या (आ) क्षेत्रीय भाषा या (इ) मातृ-भाषा तथा कोई क्षेत्रीय भाषा-सम्मिश्रित एक पाठ्यक्रम, या (ई) मातृ-भाषा और सांस्कृतिक भाषा-सम्मिश्रित एक पाठ्यक्रम, या उ) एक क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक भाषा-सम्मिश्रित एक पाठ्यक्रम; (२) हिन्दी या अंग्रेजी; (३) कोई आधुनिक भारतीय या पाश्चात्य भाषा जो कि (१) या (२) में न ली गयी हो।

द्वितीय सूत्र : (१) प्रथम सूत्र के ममान, (२) अंग्रेजी या कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा; (३) हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए) या कोई भी भारतीय भाषा (हिन्दी क्षेत्रों के लिए)।

उपर्युक्त सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषाएँ सीखना ज़रूरी हो गया है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो अनिवार्य भाषा का सुझाव दिया था। तब की बात है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या 'अभ्यासाक्षर' ने पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक भाषा को योग्य स्थान नहीं दिया है। इसे यह बात स्थाना बाधित कि किसी भी देश का सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन सांस्कृतिक भाषा के अध्ययन पर ही निर्मित है। यह सोच विचार पर भाषा-अध्ययन पर एक सुझाव नीचे दिया जाता है :

१. मातृ-भाषा या अहिन्दी क्षेत्रों के लिए अन्य कोई भारतीय भाषा;

२. कोई भी दो भाषाएँ : (१) कोई अन्य भारतीय भाषा जो ऊपर न ली गयी हो, (२) एक सांस्कृतिक भाषा, (३) अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा।

व्याधीन भाषा में मातृ भाषा का ज्ञान किसी भी भाषाभाषी के लिए अनिवार्य होता है। किसी मातृ भाषा हिन्दी हो, वे कोई भी एक भारतीय भाषा होवे। आज देश के अनेक भाषा में यह धारणा है कि हिन्दी मातृ भाषा के रूप में अहिन्दी क्षेत्रों में लगी जा रही है। यह तथ्यावली बहुत कुछ दूर हो सकती है, यदि हिन्दी भाषा अपने अपने कोई भारतीय भाषा का अध्ययन करे।

द्वितीय सूत्र के, विद्यार्थी कोई भी दो भाषा ज्ञान रखने हैं। अनेक विद्यार्थी अंग्रेजी ज्ञान बाधित। कारण, यह एक स्थान अध्यापक भाषा है तथा विद्यार्थियों का ज्ञान में इसका स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपने अपने आधुनिक भाषा एक भाषा सीख सकते हैं — एक भारतीय भाषा या एक सांस्कृतिक भाषा या अंग्रेजी होकर कोई भी एक आधुनिक भाषा।

तीन भाषाओं के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में समाज-शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान आधारभूत विषय होंगे। इन दो बुनियादी विषयों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना भविष्य में अन्य विषय पूर्णतः नहीं समझे जा सकते हैं। ये विषय, कई विषयों के समावेश से बनाये गये हैं। वर्तमान युग में ज्ञान के विस्तार के कारण, ऐसे सम्मिलित विषयों की सृष्टि हुई है। इन दोनों बुनियादी विषयों की पढ़ाई प्रथम दो वर्ष में खतम कर देनी चाहिए, तथा तृतीय वर्ष से विशिष्ट विषयों का अध्ययन आरम्भ किया जाय। विद्यार्थीगण बहुधा असमझस में पड़ जाते हैं, जब कि उन्हें बुनियादी और विशिष्ट विषय साथ-साथ सीखना पड़ता है।

३. उपसंहार.—इस प्रकार पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ और दो बुनियादी विषय आधारभूत होंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक क्राफ्ट तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाये हुए बहुमुखी पाठ्यक्रम के किसी भी समूह से तीन विषय लेने पड़ेंगे। क्राफ्ट के द्वारा विद्यार्थियों की कलात्मक तथा सृजनात्मक भावनाओं का विकास होता है। बहुमुखी पाठ्यक्रम की आयोजना के समय सदा दो प्रकार के विद्यार्थियों की जरूरतों की ओर लक्ष्य रहे : (१) वे विद्यार्थी, जो माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर, जीवन-क्षेत्र में घुसना चाहते हों, और (२) वे, जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों। ऐसी स्थिति में बहुमुखी पाठ्यक्रम दो प्रकार के होना चाहिए : (१) शालान्त और (२) प्रवेशक। पाठ्यक्रम के विषय, किशोरों की व्यक्तिगत रुचियों, विशेष क्षमताओं और योग्यताओं की ओर लक्ष्य रखते हुए, चुने जायें। इनके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हों।

अभ्यापन तथा पाठ्यक्रम में, सदा निम्न-लिखित विषयों की ओर ध्यान दिया जावे :

१. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो;
२. जहाँ तक हो सके, पाठ्य-विषयों का एकीकरण किया जाय;
३. पाठ्यक्रम का सञ्चालन सही रीतियों से हो;
४. स्थानीय आवश्यकताओं तथा विद्यार्थियों की रुचि का सदा ध्यान रहे; तथा
५. छात्रों को निर्देश तथा परामर्श देने का प्रयत्न रहे।

**विशेष स्कूल.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित के बाद, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की ओर विशेष रूप से ध्यान

दिता है। योजना के दो अङ्ग हैं : (१) हाई स्कूलों की उत्पत्ति माध्यमिक स्कूलों से बढ़ाना, तथा (२) वर्तमान स्कूलों की बहुदलीय स्कूलों में बदलकर नया कर देना। प्रथम योजना के अरधिकार में ३६७ बहुदलीय स्कूल आते हैं। द्वितीय योजना का लक्ष्य है १३७ बहुदलीय तथा १,१८७ उत्पन्न माध्यमिक स्कूल स्थापित करना। इस प्रकार द्वितीय योजना की सम्पत्ति मूल १० प्रति शत माध्यमिक स्कूल बहुदलीय रूप में बदल दिये जायेंगे। तृतीय योजना का लक्ष्य है और भी १,००० बहुदलीय स्कूल स्थापित करना।

उत्पन्न माध्यमिक स्कूल.—देखा गया है कि योजनानुसार बहुदलीय स्कूलों का रहे हैं, पर हाई स्कूलों की उत्पन्न माध्यमिक स्कूलों में बदलने का काम धीरे-धीरे हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः, राज्य सरकारों बहुदलीय स्कूल खोलने में दिलचस्पी ले रही हैं, और जनता में इन सम्स्थाओं की अधिक माँग है। द्वितीयतः, उत्पन्न माध्यमिक शिक्षा योजना के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता का कारण है केन्द्रीय सरकार की अनुदार नीति। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ ही समय तक मित्रगी। वर्तमान समय में इस कार्य का ४० प्रति शत राज्य सरकारों दे रही है, और शेष केन्द्रीय सरकार। पर द्वितीय योजना के अरधिकार के बाद, राज्य सरकारों को इस कार्य का कुल भार स्वयं उठाना पड़ेगा। तृतीयतः, राज्य सरकारों अपना अधिकांश धन बहुदलीय स्कूल योजना पर खर्च कर रही हैं। इस खर्च की मित्राने के बाद, उनके पास अधिक पैसा नहीं बचता। चतुर्थतः, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स १९५७-५८ में आरम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम के चलते बिना, उत्पन्न माध्यमिक स्कूलों का प्रसार असम्भव है। पर सब कठिन सम्भाव है उत्पन्न माध्यमिक स्कूलों के लिए उपयुक्त शिक्षकों का अभाव। आ पूरे देश में लगभग २,००० उत्पन्न माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें से ७०० स्कूल ही में खोल गये हैं। इनके लिए प्रति वर्ष २०,००० उत्तर-स्नातक डिग्री धारी शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य-सरकार का अनुभव है कि एक शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। समूचे देश में प्रति वर्ष औसतन १४,००० एम० ए निकलते हैं। यदि ये सब भी शिक्षक बनें, तो भी देश की आवश्यकता पूरी न होगी।

बहुदलीय स्कूल.—माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्देशित बहुमुखी पाठ्यक्रम में से तीन या उससे अधिक विषयों का प्रबन्ध एक बहुदलीय स्कूल में रहता है। इस स्कूल की लोक-प्रियता के कारण अगले पक्ष में दिये गये हैं :

१. इस सस्था-द्वारा सामाजिक एकता बढ़ती है। कारण, यहाँ सभी प्रकार के विद्यार्थियों पढ़ सकते हैं तथा उनमें भेद-भाव बढ़ने नहीं पाता है।

२. ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों को उनके भौतिक आचार तथा व्यावसायिक कुशलता के अनुसार छात्र उचित पाठ्य-क्रम की शिक्षा देना सज्ज होना है। तत्पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को अनुभव के आधार पर एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में बदलने के लिए कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

३. चूँकि ऐसे स्कूल में अनेक स्तर के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, इस कारण छात्रों तथा उनके अभिभावकों में कोई न्यूनता या श्रेष्ठता का भाव नहीं उपजता। यह भाव विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिल होने या न होने के कारण उत्पन्न होता है।

बहुद्देशीय योजना के कार्यान्वित होने में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं। प्रथमतः, इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा उनकी आवश्यकताओं को अनेक स्कूल-संचालकगण ठीक तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्रत्येक शिक्षा-विभाग का यह कर्तव्य है कि वह उचित मार्गदर्शन करे। इसमें विविध प्रकार की आवश्यकताओं का ध्यान रहे, यथा : शालाग्रह, प्रयोग-शाला, कर्म-शाला, शिक्षा-साधन, पुस्तकें इत्यादि। द्वितीयतः, ये स्कूल जहाँ तहाँ स्थापित न किये जायें। इनके खोलने के समय, सदा स्थानिक जरूरतों तथा साधनों का ख्याल रहे। अधिक छात्र-संख्या के बिना एक बहुद्देशीय स्कूल चल नहीं सकती है। यदि तीन ही विविध विषय एक स्कूल में रखे जायें, तो प्रत्येक कक्षा में कम-से-कम तीन वर्ग होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षा-विभाग अपने राज्य का एक सर्वेक्षण करे, और तत्पश्चात् ऐसे स्कूल ठीक जगहों में खोले तथा अनुकूल विषय स्थिर करे। तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललितकला तथा गृह-विज्ञान सरीखे विषयों के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के मिलने में विशेष कठिनाई अनुभव की जाती है। इसके सिवा, ये विषय व्यय-साध्य भी हैं; अतएव स्वसंचालित भव्याएँ इन्हें बड़ी कठिनाई से चला पाती हैं। शिक्षा-विभाग के अनुसार इन विषयों के पढ़ाने के लिए बहुमूल्य प्रयोग-शालाएँ, विशाल कर्म-शालाएँ तथा विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। इन्हें सब समय जुटाना टेढ़ी खीर है। सबसे अच्छा तो यह हो कि अधिकांश व्यावहारिक कार्य कल-कारखानों, व्यवसाय-केन्द्रों तथा विद्यार्थियों के निजी खेतों पर किया जावे। यह प्रथा अनेक पाश्चात्य देशों में आज प्रचलित है।

एक-उद्देशीय स्कूल.—यह किसीको न समझ लेना चाहिए कि एक-उद्देशीय स्कूल बहुद्देशीय संस्थाओं से कम महत्वपूर्ण है। शिक्षा-क्षेत्र में स्वतन्त्र प्राविधिक, प्रशासनिक या साहित्यिक स्कूलों का एक विशिष्ट ध्यान है। उदाहरण-स्वरूप इंग्लैण्ड में बहुद्देशीय स्कूलों का समर्थन नहीं करता है। उसके विरोध के मुख्य कारण नीचे दिये जा रहे हैं:

१. बहुद्देशीय स्कूलों का इतना अनुभव नहीं हुआ है कि वे वांछनीय गिने जा सकें।

२. एक-उद्देशीय संस्था का मान-दण्ड सदा ऊँचा कायम रखा जा सकता है।

३. बहुद्देशीय स्कूलों-द्वारा सामाजिक एकता नहीं बढ़ती है। सामाजिक एकता का अर्थ विद्यार्थियों की अधिकता नहीं है। यह भावना आध्यात्मिक होती है; और इसका विकास तभी सम्भव है, जब विद्यार्थीगण एक ही विचार में मग्न रहें।

४. एक-उद्देशीय स्कूलों का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। बहुद्देशीय स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा लक्ष्य की एक खिचड़ी-सी पक आती है।

५. बहुद्देशीय स्कूलों के उपयुक्त अनेक विषयों के विद्यार्थ प्रधानाध्यापकों का अत्यन्त अभाव है।†

इस प्रकार इंग्लैण्ड में बहुद्देशीय स्कूलों के विषय में घोर मतभेद है। इस देश में एक-उद्देशीय स्कूल फैल रहे हैं, जैसे: ग्रामर-स्कूल, माडर्न-स्कूल, इत्यादि। प्रचलने की बात है कि एक ही छिनालीस स्थानिक निवासों में से सिर्फ़ दसों ने बहुद्देशीय स्कूल खोले हैं। इस प्रकार हमारे देश में भी ये स्कूल सोच-विचार कर स्थापित किये जायें।

ग्रामीण तथा श्रमि-विद्यालय.—किसी भी शिक्षा-योजना में हमारे देशतों का ध्यान सदा सम्मुख रहना चाहिए। कागज, ८० प्रति शत भागवतवाली गाँवों में रहने हैं, तथा श्रमि में अपनी गुजर करते हैं। पर गाँवों की दशा दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है। ग्राम-वासी शहरो की ओर भाग रहे हैं। गाँवों में सुविधा का अभाव है। शिक्षा-मुधार ग्राम-मुधार का एक प्रधान अंग है।

† T. L. Reller, 'The Comprehensive Secondary School Controversy in England,' *Educational Administration and Supervision*, October, 1955



सन् १९५६-५७ ई० में देहातों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवल २४,९३६ (इनमें उच्च या उच्चतर ५,२२३ और १९,७१३ मिडिल) थी। इनके तथा शहरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कोई भी फर्क नहीं है। सबसे अच्छा तो यह हो कि देहाती मिडिल स्कूल प्रवर बुनियादी स्कूलों में बदल दिये जावें। पर इनके पाठ्यक्रम का केन्द्रीय उद्योग कृषि या बागवानी होवे। जहाँ तक हो सके हाई स्कूल की पढ़ाई का सम्बन्ध ग्रामीण वातावरण से रहे, तथा क्राफ्ट एक देहाती विषय या कुटीर शिल्प हो। इसके साथ-साथ कृषि हाई स्कूल पर्याप्त रूप में खोले जावें। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरीखे कृषि-प्रधान देश में ऐसे स्कूलों की संख्या सिर्फ ८४ (१९५६-५७) है। कृषि विद्यालयों में कृषि के साथ-साथ, बागवानी तथा पशु-पालन पढ़ाया जाय।

**निर्देश तथा परामर्श.**—बहुमुखी पाठ्यक्रम के आयोजना के कारण, शिक्षकों तथा स्कूलों पर एक नयी जिम्मेवारी आ गयी है। वह जिम्मेवारी यह है कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं रुचियों का मान हो जाय तथा उन्हें इस प्रकार निर्देश तथा परामर्श मिले कि उनके उपयुक्त कौन-कौन से विषय हैं, जिनके अध्ययन से उन्हें अधिकतम सफलता मिले। विषयों के निर्वाचन के समय प्रत्येक विद्यार्थी को आठवीं कक्षा में यह परामर्श मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर एक छात्र को एक ऐसा निर्देश दिया जाय कि अपनी माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर उसे एक उपयुक्त नौकरी मिले; या, यह एक उच्च विद्यालय में शिक्षा मिले। यह सब सोच "सभी स्कूलों को प्रशिक्षित पथ-परामर्श-दाताओं तथा व्यवसाय-निर्देशकों की सेवाएँ अधिकाधिक मात्रा में क्रमशः उपलब्ध करायी जावें।" इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप कई प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा राज्य-निर्देश-केन्द्रों ने इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त काम आरम्भ किये हैं। आज जनता भी निर्देश तथा परामर्श में दिलचस्पी लेने लगी है। १९५१-५२ के बीच बम्बई राज्य सरकारी निर्देश-केन्द्र ने ४२,००० व्यक्तियों को व्यक्तिगत परामर्श तथा २३,००० पुरुष-स्त्रियों को व्यवसायी सलाह दिया था। इसी दौरान में, केन्द्र ने ५० व्यवसाय-सम्मेलन आयोजित तथा १,००० व्यवसाय निर्देशक

# हाईस्कूल पाठ्य-विषयों के निर्वाचन के लिए निर्देश



**प्रशासन : सहयोग की आवश्यकता.**—शिक्षा-विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रशासनीय विभागों का भी शिक्षा से सम्बन्ध रहता है, जैसे: कृषि-विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग-विभाग, प्राविधिक विभाग, श्रम-विभाग, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग, इत्यादि। इनके निजी स्कूल रहते हैं, और ये अपना-अपना रहूँटा राग अलग-अलग अलापते हैं। इस कारण श्रम तथा अर्थ के नाश की सम्भावना रहती है। शिक्षा में इस द्वैध शासन को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है :

१. प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र में शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न विभागों के मन्त्रियों की एक समिति स्थापित हो। इस समिति का मुख्य उद्देश्य हो कि शिक्षा-विस्तार के निमित्त विभिन्न विभागों के अर्थ का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाय।

२. शिक्षा की उन्नति तथा प्रसार की विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के लिए, प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों की एक सहयोग-समिति की विरोध आवश्यकता है।

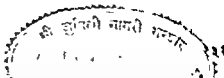
**माध्यमिक शिक्षा-मण्डल.**—शालान्त या/और माध्यमिक परीक्षा चलाने के लिए इस देश में आज पन्द्रह माध्यमिक शिक्षा-मण्डल हैं।† पर यह देखा गया है कि कई मण्डलों के सदस्यों की संख्या अत्यधिक है। कुछ सदस्य तो ऐसे रहते हैं, जिनका शिक्षा से कुछ सरोकार नहीं है। काम सुधारने के बदले वे काम बिगाड़ते हैं। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है :

माध्यमिक शिक्षा के यथोचित विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा-मण्डल की संख्या ठोस हो। इसके सदस्य शिक्षा-विद हों तथा उनका कार्य केवल शिक्षा-नीति निर्धारित करना हो।‡

अनेक राज्यों में इन मण्डलों की स्थापना के कारण, द्वैध-शासन आ गया है। कारण, शालान्त कक्षा का पाठ्यक्रम का मानदण्ड निम्न कक्षा के पाठ्यक्रम से बहुतानिष्ठ रहता है। शिक्षा में निरन्तरता की आवश्यकता है। द्वैध शासन के कारण, अनेक हानियाँ होती हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा परीक्षा-नीति स्थिर करने की जिम्मेवारी शिक्षा-मण्डल को दी जाय, पर उन सबका निरीक्षण शिक्षा-विभाग करे।

† २६ अप्रैल १९०९।

‡ Secondary Education Commission's Report. ■ 191



निरीक्षण.—हमारी स्कूल-निरीक्षण-सद्वृत्ति का आज तीव्र प्रतिवाद हो रहा है। इस प्रथा के सम्बन्ध में शिक्षा-जगत् में असंतोर्ष व्याप्त हो रहा है। यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह पद्धति दोष-पूर्ण है। इसका मुख्य कारण निरीक्षकों की कमी तथा निरीक्षकों में पर्याप्त क्षमता का अभाव ही है। हमारे देश में ऐसा कोई उपयुक्त प्रादेशिक पाठ्यक्रम नहीं है, जिसके द्वारा हमारे निरीक्षकगण शिक्षा प्रशासन-कला में प्राशिक्षित किये जा सकें। जून, १९५६ में शिक्षा-प्रशासन की एक गोष्ठी भीनमर में हुई थी। उसमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुए थे :

१. शिक्षा-शास्त्रों की प्रशासन-कला में प्रशिक्षित करने के लिए समस्त समय पर सक्षित तथा दीर्घ कोसों, गोष्ठियों एवं कर्म-शालाओं का आयोजन किया जावे। इसके सिवा, नवीन अधिकारीगण कुछ समय तक अनुभवी शास्त्रों के साथ पद-शिष्याधीन के रूप में रहें जावें।

२. निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है।

३. प्रत्येक राज्य में एक सचालक की नियुक्ति हो, जो शिक्षा-शास्त्रों के प्रशासन का उपयुक्त प्रबन्ध करे। ... .. प्रत्येक प्रादेशिक महाविद्यालय में एक शोध-विभाग की स्थापना हो, जिसका काम शिक्षा तथा शिक्षा-प्रशासन सम्बन्धी तथ्यों का शोध करना हो।

स्वाधीन भारत में निरीक्षण-सद्वृत्ति में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। आधुनिक जगत् में निरीक्षण का ध्येय अस्थापन की उन्नति है। यह कार्य शिक्षकों को ही करने-इसने से ही नहीं पूरा होगा। निरीक्षकों तथा अस्थापकों के पारस्परिक सहयोग से ही अस्थापन में उन्नति हो सकती है। इस कार्य में निरीक्षक-शिक्षकों का मित्र-परास्पर-दान तथा मार्ग-निर्देशक है। यह भी शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा सकता है। इस भाव के अभाव के कारण, निरीक्षण बहुधा व्यर्थ ही खर्च जाता है।

प्रबन्ध.—तालिका १२ में प्रबन्ध के अनुसार माध्यमिक स्कुलों का विभाजन किया गया है : गवर्नीय स्कुल (२००२), स्थानीय निवास (३१०९) तथा स्वसंचालित (४७०९)। इतना तक कम गहना है, सरकार स्वतः माध्यमिक स्कुल स्कोलना नहीं चाहती है। सरकारी नीति निजी स्कुलों को द्रष्टा देकर प्रोत्साहन देने की है। हाँ, सरकारी स्कुल-शास्त्राध्यक्ष तथा स्वायत्त-माध्यमिक स्कुल स्वतः स्थापित करती है तथा रिजर्गेड्ड स्कुल क्षेत्रों निजी माध्यमिक स्कुल स्कोलती है।

स्थानिक बोर्डों-द्वारा परिचालित माध्यमिक स्कूल प्रायः सफल नहीं होते। इन संस्थाओं की आलोचना करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मत दिया, “इन स्कूलों में अनेक सुधारों का प्रयोजन है।” देश की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय निकाय अपना सम्पूर्ण ध्यान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ओर दें।

वर्तमान काल में स्वसञ्चालित स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। ये स्कूल चाहे जहाँ, खुलते ही जा रहे हैं। कहीं-कहीं तो दो-तीन स्कूल पास-पास स्थापित हो जाते हैं, पर अनेक स्थानों में कोई भी माध्यमिक स्कूल नज़र नहीं आते हैं। यह भी देखा गया है कि अनेक अच्छे मिडिल स्कूल कमजोर हाई स्कूल में बदल दिये जाते हैं। बहुतसे निजी स्कूल अस्वास्थ्यकर स्थानों में लगते हैं। उनमें शिक्षा-साधनों, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि का अभाव रहता है। वहाँ शिक्षकों की बुरी दशा रहती है। यथार्थ में इन स्कूलों का वहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। पर किसी न-किसी रीति-द्वारा वे शिक्षा-विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। इन स्कूलों की दशा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने गौर किया है :

अभाग्यवश इस शिथिलता के फल-स्वरूप अनेक निकम्मे स्कूल सञ्चालकों के खीसे गरम करने के लिए चलते रहते हैं। ... न उनके पास उपयुक्त स्कूल-गृह रहता है, और न शिक्षा-साधन। शिक्षा-विभागों को मजबूर होकर, उन्हें स्वीकृति देनी पड़ती है। कारण, उनके भरती किये हुए विद्यार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है।†

पर इन स्वसञ्चालित स्कूलों से घटतर हैं अस्वीकृत स्कूल। हाल ही में दिल्ली सेण्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन ने एक सर्वेक्षण किया है। इससे शत होता है कि जितने विद्यार्थी दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठते हैं, उनसे दुगुने परीक्षार्थी निजी अस्वीकृत स्कूलों द्वारा पञ्जाब मेट्रिक परीक्षा के लिए तैयार किये जाते हैं। एक बड़े अस्वीकृत स्कूल के प्रिंसिपल का मासिक वेतन ₹, २००) है। इसी प्रकार एक अस्वीकृत मण्डल के अन्तर्गत १२ संस्थाएँ हैं जिनमें से छः संस्थाएँ एक मील के अर्द्ध व्यास में स्थित हैं। शिक्षा में यह व्यवहार नहीं तो क्या है !

**वित्त.**—अर्थात्कारण के कारण, अनेक माध्यमिक स्कूल कमजोर हैं। उन्हें विद्यार्थियों की फीस पर अपना निर्वाह करना पड़ता है। प्रायः २५ प्रति शत स्वयं सञ्चालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता। कुछ क्यों से माध्यमिक शिक्षा में

अनेक सुधार हुए हैं, तथा होने आ रहे हैं, जैसे: विविध विषयों का समावेश, प्राप्ट शिक्षा, शिक्षकों की वेतन-वृद्धि, क्रिश्चियन-कल्याण, इत्यादि। अतः स्कूलों का स्तर बढ़ गया है तथा निजी स्कूलों को अधिक सरकारी प्राप्ट की ज़रूरत है। प्रत्येक राज्य में प्राप्ट की रकम स्थिर रहती है, पर स्कूलों को यथेष्ट सहायता नहीं मिलती। इस कारण, एक सुवि-पूर्ण वित्त-नीति की आवश्यकता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये :

१. माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा उन्नति के कार्य में, केन्द्रीय तथा राज्य का पूर्ण सहयोग स्थापित हो।

२. यह सोचना सत्य है कि केन्द्रीय सरकार की माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दिनेशनः, प्राविधिक तथा नागरिक शिक्षा के प्रकार का उत्तरदायित्व भारत सरकार अपने ऊपर ले।

३. माध्यमिक शिक्षा पर प्राविधिक तथा स्वास्थ्य-परिक शिक्षा के विकास के लिये एक उपकर लगाया जाय, जो 'औद्योगिक शिक्षा उपकर' कहा जाय।

४. शिक्षा-दान की रकम पर कोई उपकर न लगाया जाय।†

**परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण.**—भारतीय शिक्षा पर परीक्षा का किन्ना महान प्रभाव है, यह तो सबको विदित ही है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का ध्यान मग परीक्षाओं की ओर भिँचा रहता है। हमारी परीक्षा-पद्धति में अनेक दोष हैं। फिर भी हम परीक्षा को बहिष्कृत नहीं कर सके। वास्तव, परीक्षा ज़रूरी है। इसके मुख्य तीन कार्य हैं : (१) परीक्षा, अभ्यास का एक अङ्ग है, (२) विद्यार्थियों के वर्गीकरण का यह एक माधन है, और (३) विद्यार्थियों की प्रवृत्ति तथा शिक्षकों की कार्य-पुष्टयन की ओर करने की यह एक बमोटी है।

परीक्षाएँ बन्द नहीं की जा सकती हैं। उनमें सुधार की विविध आवश्यकता है। हम निम्न पर कुछ सुझाव दिये जाने हैं : (१) विद्यार्थियों की उन्नति निरन्तर लेना हमें चाहिये, (२) वार्षिक परीक्षा एक घोरदिन करने के समय कार्याधिक तथा प्रेरणा-परिणाम एवं उन्नति निरन्तर लेना पर विचार किया जाय, (३) साप्ताहिक परीक्षा में केवल उन्नति ही अतः की परीक्षा की जाय, जो उस दिन काय में पदार्थ कर ले। वास्तव की अवधि ४० दिनों से अधिक न हो, (४) साप्ताहिक परीक्षा के लिये केवल

नवीन परीक्षा-प्रणाली के प्रश्नों का समावेश हो। त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में आधे निबन्ध प्रश्न और आधे नवीन परीक्षण-प्रणाली के प्रश्न हों, (५) सार्वजनिक परीक्षा-फल में आन्तरिक परीक्षाओं, छात्रों की उन्नति-विषयक लेखा तथा साल भर के किये गये कार्य पर विचार किया जाय।

सितम्बर, १९५९ के माध्यमिक शिक्षा-मण्डल के मंत्रियों के एक सम्मेलन ने शालान्त परीक्षा के दोषों पर विचार करते हुए स्थिर किया : (१) एक सन्तुलित पाठ्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है; इस कारण, प्रचलित पाठ्यक्रम की परीक्षा शिक्षकगण तथा राज्यीय पाठ्यक्रम समिति करे। (२) पाठ्यक्रम के ध्येय, अध्यापन विधि तथा परीक्षा-पद्धति में एक विशेष समन्वय की आवश्यकता है, ताकि परीक्षार्थी की दैहिक क्षमताओं की जाँच हो न कि स्मरणशक्ति की। (३) सार्वजनिक परीक्षा दो प्रकार की हो : (अ) शालान्त — उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे न पढ़ना चाहते हों, और (आ) प्रवेशिका — जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों।†

**विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण.**—आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना है; परन्तु खेद की बात है कि हमारे अधिकांश माध्यमिक स्कूलों का ध्येय शिक्षा-विभाग-द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समाप्त करना तथा विद्यार्थियों को सार्वजनिक परीक्षा के लिए तैयार करना ही हो गया है। ये न तो शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद की ओर ही ध्यान देते हैं और न विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा चरित्र-निर्माण के प्रति ही सचेष्ट रहते हैं। स्कूल का आखिरी घण्टा बजते ही मानो उनका दैनिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्र घोष की निम्नांकित मुक्ति सर्वथा उपयुक्त एवं आश्चर्य-विरहित है :

क्या हम अपने नवयुवकों को मनुष्य बना रहे हैं या और कुछ ?  
क्या हम उन्हें कुछ सभाष्य प्रश्नों के उत्तर कंठस्थ करने के निदा और भी कुछ सिखा रहे हैं ? क्या हम उनकी चिन्तन-शक्ति, आत्म-निर्भरता तथा आत्म-निश्चय बढ़ाने की दिशा में कुछ भी प्रयत्न कर रहे हैं ?

उत्तरुक्त बचन मते ही अत्यन्त बटु हों, पर यह अतीव मत्त है। हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक गहनतर उत्तरदायित्व है। उन्हें अपने विद्यार्थियों को एक प्रशस्ततन्त्र राज्य का मुक्तोन्मत्त नागरिक बनाना है, उनमें सांघाजिक, आर्थिक तथा गहननैतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से सोचने तथा कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करना है, जिसमें वे समाज के हितरक्षणार्थी अङ्ग बन सकें।

## उपसंहार

आज पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा-मुधार की पुकार मच रही है। नये दृष्टि के स्कूलों का प्रादुर्भाव हो रहा है। शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके अनुसार एक माध्यमिक विद्यार्थी सत्रह वर्ष की अवस्था में उच्चतर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने की आकांक्षा रखता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूरा देश एक ही रंग में रंग जाय। आरित, हममें हब ही क्या है कि एक विद्यार्थी अपनी माध्यमिक शिक्षा १६ या १७ या १८ वर्ष की आयु में समाप्त करे। विद्यार्थी का योग्यता तथा पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों की अवधि में हेरफेर होना उचित है। राष्ट्रीय आयोग ने देश को यह चेतावनी दी है, “भारतीय शिक्षा में ग़ैर एक पद्धति एकरूपता कायम रही। यह देश के लिए हितकर नहीं है।”<sup>१</sup>

इस कारण, हमें शिक्षा-मुधार सोच-मसल कर करना चाहिए। तेज़ी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रा एक-ही प्रश्न पर विचार कीजिए — “हमारे देश के ११,००० हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बदलने की समस्या।” ये स्कूल का कमर कम कर बैठे ही हैं। एक इशारा मिलन ही, ये स्वयं को उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बदलना आरम्भ कर देंगे। ये तनिक भी विचार नहीं करेंगे कि इस परिवर्तन के लिए किन-किन योजनाओं की आवश्यकता है। उच्चतर स्कूल होने पर सहा एवं संचालक की प्रतिष्ठा बढ़ जावेगी, तथा प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी। यही विचार-धारा उनके मस्तिष्क में प्रवाहित है। कोई जरा सोचता भी नहीं है कि यह सब हम उच्चतर कार्य के लिए योग्य, सक्षम अथवा उपयुक्त है या नहीं है।

इस प्रकार हमें समझ-बूझकर कदम रखना चाहिए। हमें इस देश के लिए उपयुक्त माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें हमारे विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा मिले। प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् मैथ्यू एर्नॉल्ड ने कहा था, “हमारे देश का मध्यम वर्ग बहुत ही कमजोर है।” इस कथन के पर्याय इंग्लिश की माध्यमिक शिक्षा-पद्धति को पूर्ण एवं सशक्त होने के लिए सत्रह वर्ष लगे। भारत में आज भारतीय शिक्षा की मज्दगी कमजोर बनी अब मजबूत होती !!



## छठा अध्याय

### विश्वविद्यालयीय शिक्षा

#### प्रस्तावना

पहले अध्याय में हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयीय शिक्षा की चर्चा की गयी है। यह शिक्षा इस देश के लिए कोई नयी वस्तु नहीं है। वैदिक युग में, कितने ही कुलपतियों के आश्रम खाते सावाम विश्वविद्यालय थे। बारमीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा इत्यादि आचार्यों के आश्रमों में प्रायः दस सहस्र शिष्य विद्याध्ययन करते थे। उपनिषत्काल में परिषदों की स्थापना हुई थी। उनमें आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण प्रस्तुत थे।

बौद्ध युग में 'विहार' या 'संघाराम' शिक्षा केन्द्रों में संगठित होने लगे। धीरे-धीरे वे विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गये। इन शिक्षा-केन्द्रों में नालन्द, तक्षशिला, विक्रमशिला एवं वल्लभी मुख्य थे। कई एक विश्वविद्यालयों में दूर-दूर देशों के विद्यार्थीगण विद्याध्ययन के लिए आते थे।

मुस्लिम युग में, अनेक मदरसे खुले। ये कालिजों के समकक्ष थे। कई एक मदरसों की तुलना आधुनिक विश्वविद्यालयों से की जा सकती है। दिल्ली, आगरा, रामपुर, जौनपुर, बीदर, मुर्शिदाबाद, लखनऊ, आदि स्थानों में प्रख्यात मदरसे थे। इसी समय में अनेक टोल एवं पाठशालाएँ स्थापित हुईं। इन संस्थाओं में हिन्दू-पद्धति पर उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था थी। बनारस, नव-द्वीप (वर्तमान 'नदिया'), मिथिला, पूना तथा अहमदनगर मुख्य हिन्दू-शिक्षा-केन्द्र थे। जॉन टैमास, एक वेष्टिस्ट पादरी, ने नव-द्वीप की तुलना आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ की है, (१७९१)।

आधुनिक काल में उच्च शिक्षा

**भूमिका.**—उच्च शिक्षा के अनुशीलन के लिए, हम आधुनिक काल को चार उपकालों में बाँट सकते हैं : (१) कालिज कॉल (सन् १७८१ से सन् १८५७ तक), (२) मूल विश्वविद्यालय काल (सन् १८५७ से सन् १९१७ तक), (३) आधुनिक विश्वविद्यालयों का उदय-काल (सन् १९१७ से सन् १९४७ तक) और (४) स्वातन्त्र्योत्तर काल।

**कालिज कायद.**—इस कायद का प्रारम्भ कलकत्ता मद्रास की स्थापना से होता है, तथा अन्य मूत्र विधविशालयों (कलकत्ता, बम्बई और मद्रास) के सुस्थापन के साथ होता है। इस कायद में कई अंग्रेजी और प्राच्य—सरकारी और निजी—महाविद्यालय गुप्त हैं। इन मन्थाओं का रूप वर्तमान कालिजों से विभिन्न था। आरम्भ में ये मन्थाएँ माध्यमिक स्कुल थीं, पर धीरे-धीरे ये कालिज के रूप में वर्द्धित हो गयीं। इसी कारण प्रत्येक माथा के दो अंग्रेज थे: कालिज और हाई स्कुल। इस कायद के प्रसिद्ध कालिज थे: कलकत्ता मद्रास (१७८१), बनारस मङ्गल कालिज (१७९१), लिट्टू कालिज, कलकत्ता (१८१७), श्रीगणेश कालिज (१८१८), मद्रिडा जर्न कालिज, कलकत्ता (१८३०) विजयन कालिज, बम्बई (१८३२), एल्फिन्स्टन कालिज, बम्बई (१८३५), त्रिनिटी कालिज, मद्रास (१८३७), पेंड्राना कालिज, मद्रास (१८४१), ग्रेट डायन कालिज आगरा (१८५२), इत्यादि। इस बीच में कलकत्ता (१८३५), मद्रास (१८४३) और बम्बई (१८४५) में सेंट्रिकल कालिज तथा बम्बई में इन्जिनियरिंग कालिज (१८४७) स्थापित हुए। इनके निवा, कुछ कानून की कक्षाएँ भी गुप्त हैं।

सन् १८४५ और सन् १८५७ में विधविशालय आरम्भ करने के प्रयत्न हुए पर ये प्रयत्न कार्यविध न हो सके। मद्रास के स-कार्यीय सरनेर लार्ड एल्फिन्स्टन कोर्ट आफ् हायकोर्ट के पास मद्रास में विधविशालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा (१८५९)। यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका। इस कायद के कार्य में विधिव का क्या निष्पत्ति प्रतीय सादिता से मिलता।

### सादिका १६

#### कालिजों की संख्या, सन् १८५७

प्रान्त	प्रकार	साधारण कालिज	स.स.क. कालिज	इन्जिनियरिंग कालिज
बङ्गाल	सहायक	७	१	—
	निवासी	७	—	—
बम्बई	सहायक	२	१	—
	निवासी	—	—	—
मद्रास एल्फिन्स्टन	सहायक	४	—	१
मद्रास	निवासी	—	—	—
मद्रास	सहायक	१	१	—
	निवासी	२	—	—
कुल मूल		२३	३	१



पर इस विस्तार के साथ साथ, अनेक दोष भी दृष्टि आने लगे। प्रथमतः, विश्वविद्यालय इतने अधिक कालिजों का भार वहन नहीं कर सकते थे, तथा उन्हें कालिजों की कार्यवाही को निरन्वित करने का कुछ भी अधिकार न था। इसी कारण शिक्षा के स्तर में पतन हो गया था। द्वितीयतः, सदस्यों की संख्या की वृद्धि के कारण, सिनेट का रूप अस्पष्ट हो गया था। ये अपना काम-काज ठीक रूप में संभाल न पा रही थीं। इनके अनिश्चित लोग यह अनुभव करने लग गये थे कि परीक्षा सञ्चालन के लिये, विश्वविद्यालयों को अनुमन्धान तथा अध्यापन-कार्य करना चाहिए।

इतने में लार्ड बंजन भारत के वाइसराय होकर आये। उन्होंने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। बंजीमान की रीति का विवरण दिया गया — “ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की दशा तथा उनके भविष्य की रीति करना और उनके विधान एवं कार्य प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।” अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, लार्ड कर्जन ने सन् १९०४ में एक कानून निराला, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इसके मुख्य नियम निम्न लिखितानुसार हैं :

१. विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिये जायें। इनको अधिकार है कि वे परीक्षा लेने के अनिश्चित अनुमन्धान तथा शिक्षण-कार्य आरम्भ करें। इसके लिये वे प्रोफेसर तथा लेक्चरर नियुक्त करें; पुस्तकालय, अज्ञात घर तथा प्रयोगशालाएँ स्थापित करें, एवं विद्यार्थियों के आवास-गृह बनायें।

२. सिनेट के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाए—यह कम-से-कम ५० और अधिक-से अधिक १०० रहे। उनकी सदस्यता की अवधि आजीवन न होकर पाँच वर्षों के लिये हो। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के निर्धारित सदस्यों की संख्या बीस तथा अन्य विश्वविद्यालयों की निर्धारित सदस्य-संख्या पन्द्रह रखी जावे।

३. सिप्टीकेटों की कानूनी स्वीकृति दी जावे, और उनमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

४. लार्ड कालिजों की सम्पत्ति देने के निम्नी में लाने की जावे, तथा सिप्टीकेट-द्वारा उनके निर्माण की निर्धारित रूप से व्यवस्था हो।

५. सरकार आवश्यकतानुसार सिनेट-ड्राग बनाये गये नियमों की संशोधित एवं परिवर्तित कर सकती है। यदि निर्धारित तिथि तक सिनेट कानून न बनाये, तो सरकार स्वतः कानून बना सकती है।

६. संप्रति गवर्नर जनरल प्रत्येक विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित कर दे।

इतना मय कुछ होते हुए, इस कानून ने न अलीगढ़, बनारस, दाका, पटना, रंगून तथा नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग को स्वीकृति दी, और न सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों की कल्पना ही की। लेकिन कानून ने भारतीय उच्च शिक्षा में कई उल्लेख योग्य परिवर्तन किये। प्रथमतः, सिन्डीकेट एक वैज्ञानिक समिति हो गयी; इस कारण उम्र पर किसीका दबाव न रहा। द्वितीयतः, नए संगठित सिनेट पहले सिनेटों की अपेक्षा अधिक डोल तथा प्रभाव युक्त बनी। तृतीयतः, सम्बद्ध कालिजों के नियंत्रण तथा नियन्त्रण के कारण उच्च शिक्षा की उन्नति हुई। कुछ निकम्मे कालिज तो ग़ुत ही हो गये। चतुर्थतः, विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलने लगा।

लार्ड कर्जन के सुधार के दस वर्ष बाद, उच्च शिक्षा के पुनर्निरीक्षण की फिर से आवश्यकता पड़ी। कालिजों की संख्या-वृद्धि होती जा रही थी तथा विश्वविद्यालयों पर बोझ बढ़ रहा था। इतने पर भी विश्वविद्यालयीय शिक्षा की माँग पूरी न हो रही थी। फलतः, मई १९१३ में सरकारने अपनी शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके अनुसार अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता स्वीकार की गयी। इसने फिर सुझाव दिया कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की अधिकार सीमा इतनी विस्तृत हो गयी है कि उसे घटाकर नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है : (१) प्रत्येक बड़े बड़े प्रान्त में सम्बद्ध विश्वविद्यालय खोले जायें और (२) नये स्थानीय तथा सावसिक विश्वविद्यालय मुख्य उच्च विद्या-केन्द्रों में स्थापित किये जायें। इस प्रस्ताव ने घोषणा की कि सरकार ने पटना एवं नागपुर में प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा दाका, अलीगढ़ और बनारस में स्थानीय विश्वविद्यालय खोलना अवज्ञा कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव ने उचित समझ कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक उन्नति के लिए उपयुक्त वातावरण हो।

इस शिक्षा-नीति की सिफारिशों के कारण, नवीन विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बनारस और मैसूर (१९१६), पटना (१९१७), हैदराबाद (१९१८) तथा एम० एन०

डी० टी० महिला विश्वविद्यालय (१९१७) । इनकी स्थापना में विश्वविद्यालयीय शिक्षा के नये विचार स्पष्ट दृष्टि आने लगे । इनारस सबसे पहला एकात्मक तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है; पटना प्रथम प्रादेशिक एवं सम्बन्धीय विश्वविद्यालय है; मैसूर तथा हैदराबाद तत्कालीन देशी राजवाड़ों के प्रथम विश्वविद्यालय हैं; एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, भारत में उच्च स्त्री-शिक्षा के प्रसार का एक अनूठा दृष्टान्त है । इसके साथ-साथ दाका, पूना तथा अहमदाबाद में क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की चेष्टा होने लगी । सन् १९१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग खोले गये ।

**आधुनिक विश्व-विद्यालयों का उदय-काल.**—इस प्रकार पिछले उपकाल के अन्त में कुछ नये विश्वविद्यालयों का उदय हुआ । किन्तु भी विश्वविद्यालयों की समस्याएँ हल न हुईं । सन् १९१७ में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया । इसकी माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्तावों की चर्चा पहले की गयी है ।<sup>†</sup> विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में आयोग ने ये निष्कारिणें कीं :

१. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विद्यमान विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन—जहाँ तक हो सके, ये एकात्मक, साधारण, वैश्विक गन्धर्व हों ।

२. स्नातक का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो तथा 'पाम बोर्स' के अलावा 'अनर्स बोर्स' आरम्भ हो ।

३. छात्रों की भर्ती के विचार में, हर विश्वविद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा-सचालक नियुक्त किया जाय ।

४. भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए, युनिवर्सिटी प्रोफेसरों की सहायता हो ।

५. अध्यापन, बालन, इन्टीमिजिग, हाकररी, कृषि, एवं आदि की औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालय में किया जावे ।

६. विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचारविमर्श करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिपतियों का सार्वजनिक सम्मेलन किया जावे ।

इस आयोग की रिपोर्ट के बाद, भारत में चढ़ाचढ़ विश्वविद्यालय हुए रहे : दाका और सन् १९२०), अलीगढ़ और सन् १९२१), दिल्ली (१९२२),

गुरु (१९२३), आन्ध्र (१९२६), आगरा (१९२७), अन्नामल्ल (१९२९), बम्बई (१९३७), डकल (१९४३), सागर (१९४७), सिंध तथा राजपूताना (१९४७)। कानिहो तथा उनके छात्रों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। इसका निम्नांकित तालिका में चलेगा।

### तालिका १७

अंग्रेजी भारत में फालिज शिक्षा, १९२१-४७।

विभाग	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४६-४७
कालिज संस्था	२३१	४२७	९३३
छात्र संख्या	७९,७९१	९९,४९३	१,९९,२५३

क्यातन्त्रयोत्तर काल.—देश के विभाजन के बाद, अठारह नवीन विश्व-विद्यालय स्थापित हुए : पंजाब (१९४७), गोवादी, पूना, रद्वी तथा रामू और तिर (१९४८), दहीन (१९४९), बर्नाटक और गुजरात (१९५०), विशाख (१९५२), धीरेंद्रेश्वर (१९५४), जयपुर तथा मगधर परम्पराई विद्यापीठ, जय (१९५५), कुश्नेर (१९५६), सोमनाथ, ब्रह्मपुर, विजय-विश्वविद्यालय, जय (१९५७), मगधराज्य तथा इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलौर (१९५८)। १ अक्टूबर १९५१ में विश्व-विद्यालयी तथा एम० एन० सी० सी० महिला विद्यालय की वैधानिक स्वीकृति दी गयी है।

जबकि, १९४८ में, भारत सरकार ने सी० गणराज्य की अवस्था में, एक विश्व-विद्यालय नियुक्त किया। आयोग की यह निर्देश दिया गया कि यह सर्वत्र विश्वविद्यालय शिक्षा की विधि के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न करें और हमारे न तथा विश्व के विश्व-विद्यालयों से, जो देश की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार हो। अतः १९४९ में, कर्माचार ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित कर दिया। इसके सुझावों की वजहों हम भारत के विश्व-विद्यालयों में वास्तविक।

### वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ

वर्तमान विश्वविद्यालयों को ठीक तरह से समझने के लिए हमारी उच्च शिक्षा के कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक है। इस कारण, इस प्रकरण में इन विषयों के अन्तर्गत की गयी है : (१) कालिजों का वर्गीकरण, (२) विश्वविद्यालयों के प्रकार (३) विश्वविद्यालय प्रशासन और (४) कनिष्ठ प्रशासन-निकाय।

**कालिजों का वर्गीकरण.**—सन् १९५५-५६ में, लगभग देश में, कुल १,२०८ कालिजें थी : ७४६ बन्धु तथा विज्ञान कालिजें, ३४६ विभिन्न व्यवसायीय शिक्षा देनेवाले कालिजें तथा ११६ विविध शिक्षाजाल कालिजें (महानि. शून्य, मध्यम कला, प्रास्ताविका, समान विज्ञान तथा गृह-विज्ञान)। प्रथम की दृष्टि में इन कालिजों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

### तालिका १८

प्रबंधानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९५५-५६।

प्रबंध	कला तथा विज्ञान कालिजें	व्यवसायिक कालिजें	विविध कालिजें	प्रति एक
राजकीय ... ..	१८६	१९४	२८	११९
स्थानीय मण्डल ... ..	६	३	१	०६
व्यवसायिक				
स्थापना प्राप्त ... ..	४५८	१०१	६८	५०३
स्थापित ... ..	९९	४५	१५	१६०
कुल योग	७४६	३४६	११६	१२०८

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है : (१) दो तिहाई कालिजें व्यवसायिक हैं। (२) ५६ प्रतिशत व्यवसायिक कालिजें राजकीय हैं और (३) स्थानीय मण्डलों के कालिजों के अन्तर्गत अल्प संख्या में हैं।



**विश्वविद्यालयों के प्रकार.**—आज भारत में विश्वविद्यालयों की कुल ३८ हैं। ये विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं : (१) सम्प्रदायी, (२) एकात्मक (३) सघात्मक।

**सम्प्रदायी.**—प्रत्येक सम्प्रदायी विश्वविद्यालय का मुख्य कर्तव्य है शहरी कालिजों को न्यता देना। ऐसे विश्वविद्यालय का क्षेत्र विस्तृत रहता है तथा इनके सम्बद्ध दूर-दूर के शहरों तथा गाँवों में फैले हुए रहते हैं। विश्वविद्यालय सम्प्रदायीकरण में तथा शतों ठीक रहता है तथा समय-समय पर वह अपने कालिजों का निरीक्षण करता है। सम्बद्ध कालिजों को विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना पड़ता है, द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाया पड़ता है तथा उसकी सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को घेदना पड़ता है। कालिजों के सफलभूत परीक्षार्थियों को कालिज की डिग्री या डिप्लोमा मिलता है।

विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध कालिजों का पारस्परिक सम्बन्ध भारतीय कालिज कानून, १९०४ के द्वारा नियन्त्रित होता है। कानून के मुख्य मुद्दों का न एक सरकारी रिपोर्ट से उद्धृत निम्न-लिखित अंश से मिलेगा :

एक भारतीय विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ कालिजों का निरीक्षण करता है तथा उससे सम्बन्ध स्थापित करता है, पाठ्यक्रम स्थिर करता है, परीक्षाएँ चलाता है तथा डिग्री प्रदान करता है। .. वह अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी कालिज को, मान्यता प्रदान कर सकता है। ... इन कालिजों को वह स्वतः नहीं चलाता है, पर सम्बद्धीकरण की शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें कालिजों को पालना पड़ता है। निरीक्षण-द्वारा विश्वविद्यालय जाँच करता है कि सम्बद्धकालिज शर्तों का यथोचित पालन कर रहे हैं या नहीं।\*

कानून की २१ वीं, २२ वी तथा २४ वीं धाराओं में सम्बद्धीकरण की शर्तों का पूर्वक वर्णन है। इन प्रतिबंधों की सन्तोषप्रद परिपूर्ति हुए बिना विश्वविद्यालय न कालिज को मान्यता प्रदान नहीं करता है। सक्षेप में, ये धाराएँ कालिजों के अपने के साथ संलग्न हैं : (१) व्यवस्था तथा प्रबंध, (२) कर्मचारियों, (३) सार्वजनिक तथा छात्रावास, (४) शिक्षा-माधन तथा अवसर, (५) विद्यार्थी,

देखिए, दूसरा परिशिष्ट।

*Progress of Education in India, 1927-32, Vol. I p. 54*

*Progress of Education in India, 1902-07, Vol. I p. 13.*

(६) वित्त, (७) पुस्तकालय, (८) प्रयोग-शाला, (९) रजिस्टर और (१०) विविध विवर ।

सुप्रसन्न में ये विश्वविद्यालय केवल सम्बन्धीकरण की व्यवस्था तथा परीक्षा-सम्बन्धन करने में । पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के कारण, इस प्रकार के कार्य सभी विश्वविद्यालय कुछ-न-कुछ अपनापन की व्यवस्था करने लगे हैं । इस देश के सम्बन्धीय विश्वविद्यालय ये हैं : आगरा, आन्ध्र, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, मुंबई, जम्मू और कश्मीर, बनारस, केरल, मद्रास, मगधराष्ट्र, मेरठ, नागपुर, ओम्मानिया, पंजाब, पूना, रायपुर, सागर, एम० एन० टी० टी०, स्वदेश, उत्तर तथा विजय ।

प्रशासनिक.—ऐसा विश्वविद्यालय सामाजिक तथा शैक्षणिक होता है । इसका क्षेत्र किसी भी एक केंद्र में सीमित रहता है, जहाँ पर वह मूलतः सम्पूर्ण अध्यापन कार्य की व्यवस्था करता है । अपने निजी विभागों या अर्थात् कारिगों के द्वारा वह शिक्षण कार्य करता है । यहाँ तक कि सभी अध्यापक विश्वविद्यालय की मानहनी में काम करते हैं । इस प्रकार, ऐसा विश्वविद्यालय अपने प्रमुख, प्रशासन तथा अध्यापन का परिवर्तन करता है । भारत के मुख्य प्रशासनिक विश्वविद्यालय ये हैं : अलीपुर, अमरावती, अजमेर, बनारस, बंगलूर, बम्बई, काशी, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, सागर तथा विश्व-भारती ।

सामाजिक.—सामाजिक विश्वविद्यालय के विचार लक्षण ये हैं : (१) विश्वविद्यालय का क्षेत्र एक केंद्र में ही सीमित रहता है, जहाँ कि उसके समस्त तथा अर्थात् कारिगों का कार्य अवस्थित होते हैं । (२) प्रत्येक कारिग में उच्चतम शिक्षा का प्रवर्धन होता है । (३) विश्वविद्यालय के प्रमुख की उन्नति के लिए प्रत्येक कारिग को उसके प्रशासन में भाग लेना पड़ता है । इस कारण, कारिगों की अपनी स्वतंत्रता होती रहती है । (४) विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कारिग अध्यापन कार्य करते हैं । सामाजिक विश्वविद्यालय विभिन्न कारिगों का एक ऐसा मंच है जहाँ कि शिक्षण कार्य अर्थात् कारिग-समुदाय मिलकर कर करते हैं । सामाजिक विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा प्रशासन के वे समन्वित हैं । इस कारण, उनके अपनी स्वतंत्रता को कुछ-न-कुछ विगड़न करता पड़ता है । अलीपुर तथा बंगलूर के विश्वविद्यालय इस वर्ग में सम्मिलित हैं ।

**विश्वविद्यालय-प्रशासन.**—विश्वविद्यालय का प्रशासन नाना प्रकार के कार्यों-द्वारा सम्पादित होता है। इनमें श्रेष्ठतम है कोर्ट या सिनेट। प्रत्येक शैक्षणिक और दैनिक कार्यों का अन्तिम निर्णय यही करती है। इसके सदस्य पदेन, मनोनीत तथा निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्यों के स्थान, प्रान्तीय शासन तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कालिजों के प्रिन्सिपलों द्वारा भरे जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की लिस्ट प्रान्तीय सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकगण या पंजीयत स्नातक-मण्डल अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्र में कुछ सदस्य चुनते हैं। प्रत्येक प्रकार के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।

सिनेट के बाद आने हैं, एकेडेमिक काउन्सिल तथा सिण्डिकेट। प्रथम निकाय सम्बन्ध रहता है केवल शैक्षणिक प्रश्नों से। सिण्डिकेट या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल विश्वविद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी सभा होती है। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र अभ्यास-समिति संगठित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विविध समितियाँ होती हैं, जैसे : परीक्षा, न्वेग, प्रकाशन, युष्क-कल्याण, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद, छात्रावास, छात्रकाल्य, आदि।

विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, चांसलर या कुलपति। बहुधा स्थानीय राज्यपाल कुलपति होते हैं, पर विश्वविद्यालयों की संख्यावृद्धि के कारण कुछ राज्यों में अब एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इस कारण, कई विश्वविद्यालयों के सविधान में कुलपति-निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है। कुलपति के बाद उपकुलपति का स्थान है। वास्तव में उपकुलपति ही विश्वविद्यालय के मुख्य शासक होते हैं। उपकुलपति की नियुक्ति का सर्वप्रकार एक-सी नहीं है। कहीं ये स्थानीय राज्यपाल-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, कहीं इनका निर्वाचन सिण्डिकेट-द्वारा और कहीं सिनेट-द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति अवधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सविधान के अनुसार तीन से पाँच वर्ष की है। कुछ में उपकुलपति अवैतनिक तथा कोई प्रतिष्ठित मदानुभाव होने से। इस कारण, अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के कार्य में नहीं लगा सकते थे। वर्तमान समय में अन्य शिक्षा की विविधता के कारण पूर्ण समय देनेवाले तथा वेतन-भोगी उपकुलपतियों की माँग है।

**कतिपय प्रशासन निकाय**—विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्रशासन निकाय हैं। इनमें से मुख्य हैं : (१) माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट शिक्षा मण्डल, (२) अन्तरिक्षविद्यालय मण्डल तथा (३) विश्वविद्यालय-अनुदान-मण्डल। इन तीनों निकायों की चर्चा इस प्रकरण में की गयी है।

माध्यमिक पा/और इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल.—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के परामर्श के कारण इन मण्डलों की सृष्टि हुई है। इनकी संख्या वर्तमान काल में पन्द्रह है। पिछले अध्याय में इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है।†

अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल.—ऐसे मण्डल की आवश्यकता का सुझाव सर्व प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। तत्पश्चात् सन् १९२४ में भारतीय विश्व-विद्यालयों की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें ऐसे मण्डल की स्थापना का सकल्प किया गया। एक वर्ष पश्चात् यह विचार कार्यान्वित हुआ, तथा मण्डल का प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

१. अन्तर्विश्वविद्यालय-संगठन एवं सूचना-केन्द्र के रूपमें कार्य करना,
२. अध्यापकों के आशान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना,
३. विश्वविद्यालयों में विचार विनिमय के अभिकरण रूप में काम करना तथा उनके कार्यों में एकरूपता लाना,
४. भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहरी देशों में अपनी उपाधियों की मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना,
५. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजना, और
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों-द्वारा दी जानेवाली उपाधियों की परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना।

प्रत्येक विश्वविद्यालय इन मण्डल में एक प्रतिनिधि भेज सकता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है। शुरू से ही मण्डल उच्च शिक्षा-विषयक मामलों को हल करने में महत्व-पूर्ण भाग लेता रहा है। पर यह स्मरण रहे कि मण्डल केवल एक परामर्श दायी मर्यादा है।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग.—सार्दण्ट योजना के प्रस्ताव के कारण, भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति की नियुक्ति सन् १९४५ में की थी। इसका अध्यक्ष केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से था। पांच वर्ष बाद, यह समिति घट कर दी गयी। इतने में राष्ट्राध्यक्ष-आयोग के सुझाव के अनुसार सन् १९५३ में 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की स्थापना की गयी। आयोग के मुख्य कार्य अगले पन्ने में दिये गये हैं :

**विश्वविद्यालय-प्रशासन.**—विश्वविद्यालय का प्रशासन ज्ञाना प्रकार के निकायों-द्वारा सम्पादित होता है। इनमें भेद्यक्रम है बोर्ड या सिनेट। प्रत्येक देश में या देश के कार्य का अन्तिम निर्णय यही करती है। इसके सदस्य पदेन, मनोनीत तथा निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्यों के ग्यान, प्रान्तीय शासन तथा विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों एवं कालिजों के प्रिन्सिपल्स द्वारा भरे जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की तालिम प्रान्तीय सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यक्षान तथा पंजीयन स्नानक-मण्डल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सदस्य चुनते हैं। प्रत्येक प्रकार के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।

सिनेट के बाद आने हैं, एकेडेमिक काउन्सिल तथा सिण्डिकेट। प्रथम निवार का सम्बन्ध रहता है केवल शैक्षणिक प्रश्नों में। सिण्डिकेट या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल विश्वविद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी मभा होती है। प्रत्येक नियम के पाठनरम का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र अभ्यास-समिति संगठित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विविध समितियाँ होती हैं, जैसे : परीक्षा, अन्वेषण, प्रकाशन, युवक-कल्याण, शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद, छात्रावास, पुस्तकालय, आदि।

विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, चांसलर या कुलपति। बहुधा स्थानीय सरकार कुलपति होते हैं, पर विश्वविद्यालयों की संख्यावृद्धि के कारण कुछ राज्यों में अब एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इस कारण, कई विश्वविद्यालयों के सविधान में कुलपति-निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है। कुलपति के बाद उपकुलपति का स्थान है। बाल्ज में उपकुलपति ही विश्वविद्यालय के मुख्य शासक होते हैं। उपकुलपति की नियुक्ति की प्रथा सर्वत्र एक-सी नहीं है। कहीं ये स्थानीय राज्यपाल-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, कहीं इनका निर्वाचन सिण्डिकेट-द्वारा और कहीं सिनेट-द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति की अवधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सविधान के अनुसार तीन से पाँच वर्ष की है। शुरू शुरू में उपकुलपति अवैतनिक तथा कोई प्रतिष्ठित महानुभाव होते थे। इस कारण, वे अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के कार्य में नहीं लगा सकते थे। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की विविधता के कारण पूर्ण समय देनेवाले तथा वेतन-भोगी उपकुलपतियों की माँग है।

**कतिपय प्रशासन निकाय**—विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्रशासन निकाय हैं। इनमें से मुख्य हैं : (१) माध्यमिक या/और इंटरमीडिएट शिक्षा-मण्डल, (२) अन्तर्विश्वविद्यालय मण्डल तथा (३) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग। इन तीनों निकायों की चर्चा इस प्रकरण में की गयी है।

**माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल.**—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के परामर्श के कारण इन मण्डलों की सृष्टि हुई है। इनकी संख्या वर्तमान काल में पन्द्रह है। पिछले अध्याय में इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है।

**अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल.**—ऐसे मण्डल की आवश्यकता का मुद्दा सर्व प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। तत्पश्चात् सन् १९२४ में भारतीय विश्व-विद्यालयों की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें ऐसे मण्डल की स्थापना का संकल्प लिया गया। एक वर्ष पश्चात् यह विचार कार्यान्वित हुआ, तथा मण्डल का प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

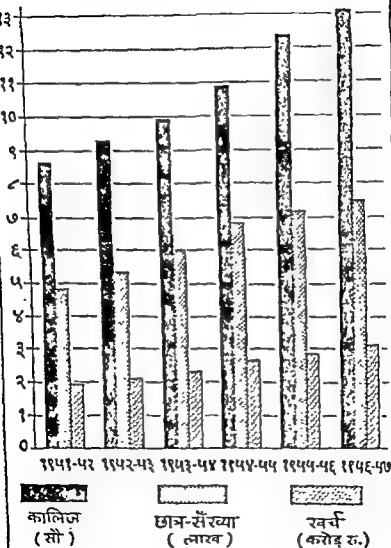
१. अन्तर्विश्वविद्यालय-समूहों एवं सूचना-केन्द्र के रूपमें कार्य करना,
२. अध्यापकों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना,
३. विश्वविद्यालयों में विचार विनिमय के अभिकरण रूप में काम करना तथा उनके कार्यों में एकरूपता लाना,
४. भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहरी देशों में अपनी उपाधियों की मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना,
५. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजना, और
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों-द्वारा दी जानेवाली उपाधियों की परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना।

प्रत्येक विश्वविद्यालय इस मण्डल में एक प्रतिनिधि भेज सकता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है। शुरू में ही मण्डल उच्च शिक्षा विवरक मामलों को हल करने में महत्वपूर्ण भाग लेता रहा है। पर यह स्मरण रहे कि मण्डल केवल एक परामर्श दात्री संस्था है।

**विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग.**—मार्जेंट मोरान के प्रस्ताव के कारण, भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति की नियुक्ति सन् १९४५ में की थी। इसका अध्यक्ष केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में था। पांच वर्ष बाद, यह समिति बन्द कर दी गयी। इतने में राष्ट्राध्यक्ष-आयोग के मुद्दा के अनुसार सन् १९५१ में 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की स्थापना की गयी। आयोग के मुख्य कार्य अगले पृष्ठ में दिये गये हैं :



# उच्च शिक्षा की प्रगति (१९५१ से १९५७)





होते हुए भी, भारत की उच्च शिक्षा अनेक देशों की अपेक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है। जहाँ हम देश में १० लाख में २,००० उच्च शिक्षित हैं, वहीं अमेरिका में २५,०००, गोविण्ड मय में २०,००० तथा आस्ट्रेलिया में ८,००० हैं।†

आइए हमारे देश के लोगों में उच्च शिक्षा पाने की तीव्र आकांक्षा है। कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की छात्र-संख्या इतनी बढ़ रही है कि अनेक विद्यार्थियों को यहाँ प्रविष्ट होना दुष्कर हो रहा है। अतएव नवीन कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पर्याप्त माँग है।

नये विश्वविद्यालय.—कलकत्ता आयोग की सिफारिशों के कारण, देश में एकात्मक विश्वविद्यालयों की सृष्टि हुई है। ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी तथा अध्यापकगण निकट सम्पर्क में आते हैं, अध्यापन सन्तोषप्रद होता है, पढ़ाई और परीक्षा का घना सम्बन्ध रहता है, विद्यार्थियों के खेल-कूद का विशेष प्रबन्ध रहता है, इत्यादि। चूँकि सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों का सम्पर्क अनेक कालिजों से रहता है, इसलिए उन्हें अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में हम देश में केवल एकात्मक विश्वविद्यालय ही खोले जावें। यदि ऐसा हो तो हमारे विद्यमान १,३०० कालिजों को यह रूप देना पड़ेगा और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती ही जावेगी।

इस कारण से स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश में सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की सदैव आवश्यकता पड़ेगी। सार्जेंट योजना का मत है, “आर्थिक दृष्टि की ओर से भारत में सदा सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी। उच्च-शिक्षा अभी भी कुछ चुने हुए केन्द्रों में सीमित नहीं रह सकती है।”‡ ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना सीराष्ट्र, मिथिला तथा तामिल क्षेत्र में अर्थात् त्रिचनापल्ली के आसपास हो सकती है। वर्तमान (पश्चिम बंगाल) में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुलनेवाला है।

एकात्मक विश्वविद्यालय बड़े-बड़े शहरों में खोले जा सकते हैं, जैसे : अमृतसर, अजमेर, बंगलौर, मदुरा, कानपुर, मेरठ, इत्यादि। देखा गया है कि अतीत में कई एकात्मक विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय कुछ प्रसिद्ध कालिजों का बलिदान हुआ था, जैसे : अलाहाबाद इर्विंग क्रिश्चियन कालिज, तथा लखनऊ क्रिश्चियन कालिज।

† *Times of India*, August 23, 1958.

‡ *Sargent Report* p 31.

उच्च-शिक्षा के विस्तार के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। ऐसे पुराने कालिजों के बन्द होने के कारण, स्थानीय जनता के हृदय में धक्का पहुँचता है। इस कारण शुरू-शुरू में जब दिल्ली में एक एकात्मक विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी, तब लोगों ने उसका विरोध किया। यदि वह कल्पना कार्यान्वित होती तो हिन्दू कालिज, सेण्ट स्टीफन्स कालिज तथा गवर्नमेंट कालिज मरीावे तीन प्राचीन स्थानीय संस्थाओं को बन्द करना पड़ता। इस समस्या को हल करने के लिए ही दिल्ली में एक सघीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अतएव कुछ कालिजों में ताला बन्द कर, एक एकात्मक विश्वविद्यालय न खोला जाय। एक विशाल कालिज को बढ़ाकर ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इस पन्थ का अवलम्बन अलीगढ़, बनारस, बटौडा, अन्नामल्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय किया गया था। जिन जगह अनेक कालिज हों, वहाँ एक सघीय विश्वविद्यालय खोलना बेयस्कर है।

भारत में कुछ ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जो कि केवल एक ही विषय में विशेषज्ञ हों। इहकी विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। ऐसे विश्वविद्यालय कई जगह खुल सकते हैं : टाटानगर में धातु विज्ञान, सेवामाम में बुनियादी शिक्षा, अहमदाबाद में दम्भ-विद्या आदि।

हमें की बात है कि संप्रति भारत में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जैसे : कृषि-शोध-संस्था, दिल्ली; कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर (लखनऊ के पास); संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला; संगीत तथा सलिनकला विश्वविद्यालय, तिरागढ़।

उचित व्यवस्था.—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के निमित्त, एक विशेष योजना की आवश्यकता है। ये अत्यन्त समझ-बूझ कर खोले जावें। स्वतन्त्र-काल में सपर नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। इनमें से कुछ के लिए भूमि भवदर तैयार थी, पर अन्य विश्वविद्यालय खींचतान कर खदे किये गये हैं। ये ऐसी जगह स्थापित हुए हैं, जहाँ कि शायद एक भी कालिज न था। वहीं-वहीं, किसी दानवीर ने दान दिया था, पर इस दान में शायद विश्वविद्यालय की एक इमारत भी खड़ी न हो सकी। पर अधिकारियों की स्थापना क्षेत्रीय व्याकाशाओं की तुलना के लिए या राजनैतिक माँगों को पूरा करने के लिए हुए हैं। यह प्रवृत्ति अत्यन्त ही हानिकर है। कोई भी विश्वविद्यालय एकाएक खड़ा नहीं हो सकता है। वह ऐसी जगह स्थापित हो, जहाँ कि अनेक स्कूल हों, विविध विषय के कालिज हों, तबयुक्त प्रयोग शालाएँ तथा पुस्तकालय हों, अनुसन्धान की व्यवस्था हो तथा जहाँ विज्ञार्थियों एवं अध्यापकों की मज्जा पदोज रूप में हो। इन सुविधाओं के अभाव में एक विश्वविद्यालय ठीक नहीं चल सकता है। किन्तु यदि

विश्वविद्यालय का अर्थ एक परीक्षा-कार्यालय ही हो तब तो मुझे इस विषय पर कुछ कहना ही नहीं है।

**ग्रामीण विश्वविद्यालय.**—भारत एक कृषि-प्रधान देश है, और इस देश की ८३ प्रति शत जनता देहात में रहती है। पर इस जनता की शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सम्पूर्ण देश के विज्ञान-व्यय का प्रायः एक-तिहाई गाँवों पर खर्च होता है। प्रचलित स्कूलों तथा कालिजों के पाठ्यक्रम का ढाँचा शहरी है। जैसा कि अमेरिकन विद्वान् मर्गन ने कहा है, “इन पाठ्यक्रमों से ऐसी धारणा होती है कि सम्भवतः भारत में बिस्ले ही गाँव हैं।”†

गाँवों की शिक्षणीय आवश्यकता की ओर सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। आयोग ने प्रस्ताव किया था :

ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना एक केन्द्रीय स्थान में की जावे। इसका सम्बन्ध अनेक छोटे-मोटे सावसिक पूर्व-स्नातक कालिजों से हो, जोकि इसके चारों ओर वृत्ताकार-रूप में स्थित रहें।‡

इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, भारत सरकार ने एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति अक्टूबर, १९५४ में नियुक्त की। इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है। समिति ने कहा कि अभी ग्राम्य विश्वविद्यालय खोलना आवश्यक नहीं है। आरम्भ में कुछ ग्रामीण उच्चतर संस्थाओं की स्थापना हो और क्रमशः ये विश्वविद्यालय के रूप में बढ़ायी जावे। इन संस्थाओं में उत्तर प्रनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के सफलभूत विद्यार्थी भरती किये जावें। इनमें ग्राम्य विपरी से सम्बन्धित सैन-वर्षीय डिप्लोमा, या दो-वर्षीय सर्टीफिकेट कोर्सों का आयोजन हो। हमारे अतिरिक्त उनमें ग्राम्य-शोध, समाज-शिक्षा तथा समाज कल्याण-विस्तार का प्रबन्ध हो।

समिति के मुताबिक पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद्’ स्थापित हो चुकी है। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए ग्यारह संस्थाएँ चुनी हैं, जिनमें अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। ये इन गाँवों या शहरों में स्थित हैं : भीमपेतन, मद्रुवा, जामियानगर, उदयपुर, मुरेन्द्रनगर, बिगडनी (बिहार),

† A E Morgan Higher Education in Relation to Rural India Wardha Hindusthani Talimi Sangh, 1950. p 8

‡ University Commission's Report. p 575.

आगरा, मानासरा (मौगट्ट), गजपुरा (पञ्जाब), कोयम्बर, अमरावती तथा गार्गोटी । परिषद-द्वारा अनुमोदित इन संस्थाओं के लिए चार पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये : (१) ग्राम-सेवाओं का तीन वर्ष का डिप्लोमा-कोर्स — इन डिप्लोमा की विश्वविद्यालय की सर्व प्रथम डिग्री के समान ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है ; (२) दो वर्ष का कृषि-विज्ञान का मैट्रिकुलेट कोर्स ; (३) तीन वर्ष का सिविल तथा ग्राम्य इंजीनियरिंग का कोर्स ; तथा (४) मैट्रिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष का पूर्ण डिप्लोमा कोर्स ।

इन प्रारंभिक संस्थाओं के विषय में, कनिष्ठ विचार मन में उठते हैं : (१) क्या देश की भाग्य की समस्या इन मुद्दामें संस्थाओं से हल हो सकती है, जब कि हमारे देश में प्रायः छः लाख गाँव हैं । (२) क्या हमें इस प्रकार उच्च शिक्षा पर सर्व कर्माचार्य, जब कि ग्रामों में प्रारम्भिक शिक्षा का टीका प्रबन्ध नहीं है । इसके सिवा कभी कभी हमें गहरी सौम भरनी पड़ती है जब हम देखते हैं कि अधिकांश ग्राम्यादि गाँवों में नहीं, बल्कि शहरों में खोली गयी है । यह भी जान नहीं कि ये स्थान किस आधार पर चुने गये हैं ।

आशा की गयी थी कि ये संस्थाएँ ऐसे प्रारंभिक नेता तैयार करेंगी, जो कि हमारे देश की देशतो के समस्याओं को मुद्दामें का प्रयत्न करेंगे । पर देखा जाता है कि इन संस्थाओं के अधिकांश स्नातक गाँव छोड़कर शहर की ओर दौड़ रहे हैं, तथा यहाँ की बेकारी की समस्या को बढ़ा रहे हैं ।

ये सब नहीं धुने सोच विचार कर आरम्भ की जायें । इन नवीन संस्थाओं की ऐसी कुछ विशेष आवश्यकता न थी । हम प्रत्येक के कोर्स हमारे कृषि-कारिगों में अप्रगती में थोड़े ही सर्व में खोले जा सकते थे । हमारे देशों का अल्प कृषि-कारिगों पर निर्भर है, न कि इन टिमटिमाती हुई दस पीढ़ी प्रारंभिक संस्थाओं पर । जब तक हमारे कृषि-कारिग तथा सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम बन्धे से बन्धा लम्बर बन न करेंगे, जब तक हमारे देशता की उन्नति नहीं हो सकती । इन्हीं कृषि कारिगों को ही प्रारंभिक विश्वविद्यालयों के रूप में धीरे-धीरे बदलना पड़ेगा ।

**सरकार तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा :** संविधान तथा विश्व-विद्यालय.—भारतीय संविधान के अनुसार, विश्वविद्यालयीय शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय है, पर उच्च शिक्षा तथा प्रविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं संस्थानों के रूप को उच्च शिक्षा रखने तथा उनमें एकसूत्रता स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कनिष्ठ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत

प्राविधिक संग्माओं का मरोफार केन्द्रीय सरकार में है। इन विषयों के लिए सम्पूर्ण देश में एकस्यता का प्रयोजन है। वाग्य, इनका सम्बन्ध गुरे देश में है। केन्द्रीय सरकार ही यह गमानता सुलिर रग सकती है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार.—उच्च शिक्षा-विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यीय सरकारों को आर्थिक सहायता देती है। पर यह देखा गया कि अनेक राज्य सरकारें उच्च शिक्षा पर यथेष्ट अर्थ खर्च नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा-खर्च ही इतना ऊँचा होता है कि उनके पास अनुरूप अनुदान के लिए भी पर्याप्त अर्थ नहीं रहता। अतएव ये केन्द्रीय उच्च-शिक्षा योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इस आर्थिक समस्या पर विचार करते हुए, कई शिक्षा-विश्वों का मत है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार ले ले।

गवामृणन आयोग इस विचार में सहमत नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे। केन्द्रीय शासन का सबसे बड़ा खर्च रहता है अपरिवर्तनीय एकरूपता। केन्द्रीय सरकार सदा शिक्षा को एक ढाँचे में ढालने की चेष्टा करती है। शिक्षा की प्रगति के लिए यह रवैया अहितकर है। हमें सदा स्थानिक जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह नहीं चाहा कि उच्च शिक्षा शासन हस्तान्तरित होने के कारण भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में अनबन हो। इन अहचनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाय। आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार वित्त, विविष्ट विषयों की सुविधाओं का सयोजन, राष्ट्रीय नीति प्रचलन, प्रशासन के मान-दण्ड का निर्धारण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सम्पर्क-स्थापन तक ही सीमित रहे।<sup>†</sup> आयोग की सिफारिशों के कारण, विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग की सृष्टि हुई है, और इसीके जरिये विश्वविद्यालयों को भारतीय सरकार से प्राण्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालयों के बीच मनोमालिन्य होने की सम्भावना दूर हुई।

विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार.—केन्द्रीय सरकार के मातहत चार विश्व-विद्यालय हैं : अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती। अन्य विश्वविद्यालयों का सम्पर्क राज्य सरकारों से है। पर हमारे देश के विश्वविद्यालय न ब्रिटिश विश्वविद्यालयों

<sup>†</sup> Ibid., pp. 406-7.

के समान सम्पूर्ण स्वाधीन हैं, और न यूरोपीय युनिवर्सिटियों की भाँति पूर्णतः राज्य-शासित हैं। इनकी स्थिति इन दोनों विपरीत दिशाओं के बीच में है। हमारे विश्व-विद्यालय सरकार पर दो विषयों के लिए निर्भर रहते हैं : (१) इनकी सृष्टि राष्ट्रीय विधान-सभा-द्वारा होनी है, अतएव इनके सविधान तथा अधिकार का निर्णय राज्य-सरकार करती है; एवं (२) राज्य सरकार उन्हें अनुदान देती है। प्राण्ट की एकम विधान-सभा निर्धारित करती है। इन दोनों प्रतिक्रियों के सिवा, हमारे विश्वविद्यालय पूर्णतः स्वाधीन हैं।

**विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तता.**—यत्नमान समय में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की विशेष आलोचना हो रही है। कारण, लोगों की धारणा है कि सरकार आनकम विश्वविद्यालय-प्रशासन में निर्बंध हस्तक्षेप कर रही है। कुछ उदाहरणों की आलोचना यहाँ की जा रही है। प्रथम उदाहरण है बर्नार्ड विश्वविद्यालय का। कुछ वर्ष पूर्व, स्वर्गीय डॉ० जॉन मर्फी हम विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ नियुक्तियों की माँग उन्हें राज्यपाल तथा राज्य मंत्रियों के बीच भटकना पड़ा। उन्होंने भारत में प्रचलित इस प्रथा का विरोध किया कि विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्य के राज्यपाल पदेन रहें। बहुतों अब राज्यपाल पदेन कुलपति होता है, जब वास्तविक तान्त्रिक प्रांतीय सरकार के हाथ में पहुँच जाती है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का वैधानिक दायित्व है। राज्य की सरकारें स्वभावतः सभी प्रश्नों की राजनैतिक व्यवस्था की दृष्टि में देखती हैं। किन्तु हमसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में बाधा पड़ती है, और यदि उनमें विचारों का स्वातन्त्र्य न रहे तो वे न तो स्वस्थ शिक्षा ही दे सकते हैं और न मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। मन्त्रिमण्डल की मनोवृत्ति में सार्वजनिक नीति की अभिवृत्ति का प्रभाव हमारे पास प्रतीत होता है। वह शिक्षा के मुक्त वातावरण में सदैव निषिद्ध होती है। उसके प्रभाव तथा में विश्वविद्यालय का सर्वत्र दोषा हुआ है। निम्नो, नज़रों, अप्रतिष्ठ शिक्षकों के शिक्षण में यह इतना उभर आया है कि उसकी गंभीर दृष्टि अंग्रेज़ी कुलपति में लग जाती है, और विश्वविद्यालय के वे अधिकांश शिक्षक कार्य मुक्त विज्ञान, प्रकृत, अर्थशास्त्र और शिक्षण के निरंतर कार्य में आकर उनको प्रेरणा देना और उनका मार्ग दर्शन है, राजनीति और निम्नो की दृष्टि दृष्टि में केवल अपने अन्तर्गत कार्य की ओर ध्यान

नहीं दे पाते। डा० जान मथाई ने इस संवेध में अपने बचड़े के अनुभवों की चर्चा की और अन्त में उन्होंने यह निष्कर्ष-युक्त बात कही, “राज्यपालों के पदेन कुलरति होने की प्रथा बन्द कर दी जाय। कारण, उनके द्वारा विश्वविद्यालयों पर गवर्नैतिक प्रभाव पड़ता है।”† इस निष्कर्ष के लिए, भारतीय शिक्षा जगत् स्वर्गीय जान मथाई का आभारी है।

कुछ ही महीने बाद, मद्रास में राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के बीच झगड़ा खड़ा हुआ। झगड़ा तीन विषयों पर था : (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रारम्भ, (२) कालिजों में मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा और (३) सरकार-द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन।

सरकार का कहना था कि तीन-वर्षीय डिग्री-कोर्स का तात्पर्य है इण्टरमीडिएट कोर्स का अन्त, तथा उसके फल-स्वरूप प्रथम वर्ष का माध्यमिक शिक्षा से योग एवं द्वितीय वर्ष का स्नातक कोर्स से सम्मिश्रित होना। विश्वविद्यालय अकेले यह सुधार अमल में नहीं ला सकता है। कारण, उसका माध्यमिक शिक्षा पर कोई भी अधिकार नहीं है। इसके विपरीत विश्वविद्यालय का कथन था : (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की शुरुआत, सिनेट तथा एकडेमिक काउन्सिल में पूर्ण विवेचना के पश्चात् हुई है; (२) कालिजों की शिक्षा का माध्यम शीघ्र बदल जाय; और, (३) सरकार-द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के कारण, शिक्षा में अपरिवर्तनीय एकरूपता की सृष्टि होगी। — वाद-विवाद के फल-स्वरूप विश्वविद्यालय के अकुलरति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार तद्ग आ गये। सरकारी इस्तेमाल का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने कहा :

जैसी स्वायत्तता खली आ रही है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ... .. हरगिज यह स्वायत्तता नहीं है। शिक्षा-मन्त्रालय ने उपदेशों का तौता लगा ही रहता है। एक सचिव के बाद दूसरा सचिव यह निर्देश देता ही रहता है कि यह शुरू करो और बंद करो।‡

वर्तमान समय की सबसे ज़ेददायक घटना है भारतीय सभ प्रेसीडेंट की चौदहवीं जूल, १९५८ की प्रिंसेप आज्ञा, जिसके द्वारा जनार्ण हिन्दू विश्वविद्यालय एक्ट का मुनार हुआ। इसके अनुसार, सिनेट को केवल परामर्श देने का अधिकार रह गया, तथा सदस्यों का चुनाव बन्द हो गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की कार्यवाही

† *Times of India*, February 28, 1957

‡ *Ibid.*, November 20, 1957

की शीघ्र के लिए एक समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति के प्रतिवेदन पर कांशी समीक्षात्मक चर्चा भी हुई। वह मंत्र को विदित हो गई। इस मंत्र की चर्चा करने हुए, सम्प्रदायी के सम्पादक लिखते हैं :

इस प्रकार विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता मनाम इस हो गयी है। सरकार के मनोनीत लोगों से परिचालित और शिक्षा मंत्रालय के अधीन गवर्नेटोरी मन्त्रालय से स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता नकारिक उपाय नहीं हो सकते। ऐसी समस्या 'जी ह्यूमन और गेन्टिल का ही निदान कर सकेगी।।

ये हुए विश्वविद्यालयीय स्वातन्त्रता सम्बन्धी कुछ रचनात्मक प्रयास थे। उद्योग है कि क्या सरकार को विश्वविद्यालयीय स्वातन्त्रता पर हस्तक्षेप करना उचित है। मान सभी एकमत हो स्वीकार करते हैं कि विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए स्वातन्त्रता निम्न आवश्यक है, पर सम्पूर्ण स्वातन्त्रता दितकर नहीं है। श्री विस्तारित देश-व्यापक बात ही है :

कभी कभी संश्लेष स्वातन्त्रता के कारण विश्वविद्यालयों में सुदृढता और पुनर्गठन देखा गया है। उचित निश्चयनों के अन्तर्गत कारण, कई विश्वविद्यालयों में आन्तरिक झगड़े तथा दृष्टिकोण लगे हुए। ईश्वर का विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय के आन्तरिक शासन विभाग नहीं लिये जा सकते; पर इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरों पर भी दृष्टि है कि विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखें ताकि उनका स्तर निम्नोक्त स्तरों पर न गिरावटी अन्तर्गत का संश्लेष उपाय करें।

विषय : वर्तमान स्थिति.—सन् १९५५-५६ में, विश्वविद्यालयों पर चर्चा करने तथा मान्यता प्राप्त कारणों की कुछ आध १७-८२ करोड़ रुपये थे। १९५६-५७ में, पर १९५६-५७ में २८-५२ करोड़ रुपये तथा १९५७-५८ में ३०-८३ करोड़ रुपये थे। सन् १९५५-५६ की आरम्भ होकर देश-व्यापी स्तरों पर ३० के लिए दृष्टि है :



## तालिका १२\*

वृत्त निष्ठा की आय का भौतिक बेटवार, १९५५-५६  
( करोड़ रुपये )

	रकम	प्रति शत	प्रति शत
<b>भाषा</b>			
केन्द्रीय सरकार	...	१.११	८.२
राज्य सरकार	...	१०.५३	२३.८
स्थानीय मण्डल	...	०.२८	०.२
फीस	...	१३.२५	१५.०
दान	...	०.०६	१.५
अन्य स्रोत	...	२.६१	६.१
<b>अनायता</b>			
केन्द्रीय सरकार	...	२.४८	६.६
राज्य सरकार	...	२.५२	६.७
अन्य स्रोत	...	२.६८	७.१
कुल योग...		३७.८२	१००.००

उपर के अङ्कों से स्पष्ट होता है : (१) ४७.६ प्रति शत खर्च सरकार ने उठाया, (२) दूसरा उल्लेख योग्य स्रोत फीस है एवं (३) स्थानीय मण्डलों का भंडा नहीं के बराबर है। अब यह विचार किया जाय कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न स्रोतवार खर्च का अधिकतम उपयोग किस तरह किया जा सकता है।

सरकारी अनुदान.—यह पहले ही स्पष्ट किया जाय कि विश्वविद्यालय का सर्वकारी अनुदान, फीस, दान एवं हमारे स्रोतों में खल्ला है, पर मान्यता-प्राप्त कालिजों में विश्वविद्यालयों से कुछ भी ग्राण्ट नहीं मिलता है। इन्हें राज्य-सरकार अनुदान नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। कहीं तो कालिजों को कुछ खर्च १५० प्रति शत ग्राण्ट मिल जाता है, और कहीं अनि अन्य। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संघट्ट सरकारी ग्राण्ट के बिना गैरसरकारी कालिज अरथा कार्य ठीक-ठीक नहीं चला सकते। गणकृष्णन-आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी अनुदान न मद्रों के लिए दी जावे : (१) इमागत, (२) असबाब तथा शिक्षा-साधन, (३) पुस्तकालय, (४) छात्रावास, (५) अप्पापकों का वेतन, पेसन तथा प्रार्थीदेण्ट फण्ड, (६) श्रम-कृति एवं परिश्रम-कृति, (७) अप्पदन-अपकाश और (८) गवर्णरा तथा स्नानकोत्तर कार्य, दिनेशन : प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में ।†

अधिकतर राज्य-सरकारें खण्ड-अनुदान नीति का अनुसरण करती हैं। यह गृहम पिछले कई वर्षों की कुछ स्थिर मद्रों के व्यय का हिमात्र लगाकर निर्धारित होती है। इस कारण उनके आय-व्यय में मद्रा घटा घना ही रहता है। अनुदान निर्धारण करते समय मद्रा स्वाभाविक तथा अन्य विचारपूर्ण खर्चों का ध्यान रहे। सरकारी अनुदान का पता वर्ष के प्रारम्भ में चला जाना चाहिए। इसमें शिक्षा-संस्थाओं को अपने आय-व्यय निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलनी है।

केन्द्रीय ग्राण्ट विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के द्वारा प्राप्त होता है। इस अनुदान का आवण्टन विगत कई वर्षों में इस प्रकार हुआ है :

### तालिका २०१

विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग-द्वारा अनुदान-आवण्टन

वर्ष	रकम
१९५४-५५	१,७८,४६,५४६
१९५५-५६	२,६६,१५,२२०
१९५६-५७	३,४१,८९,६३५

† University Education Commission's Report, p. 419

‡ Ten Years of Freedom, p. 13



५. राज्य-सरकार के प्रतिनिधि (यदि कालेज को सरकारी अनुदान मिलता हो), एवं

६. कुछ नामश्रु शिक्षा-शास्त्री (अधि-निर्वाचित सदस्य) ।†

अध्यापकों तथा सञ्चालक-गण के बीच प्रायः सदा झगड़ा चलता रहता है। इसे निबटाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक गैरसरकारी न्याय-सभा की आवश्यकता है, पर इसके फैसले को मान्यता दी जानी चाहिए। इसके बिना सम्पूर्ण कार्यवाही हास्यास्पद हो जाती है। उदाहरण-स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसी संस्था के भूतपूर्व रसायनशास्त्र के अध्यापक भी० एस० दत्त के मुकदमे का बयान नीचे दिया जाता है :

सन् १९४९-५१ के बीच, विश्वविद्यालय के साथ मेरी काफी अनदम हुई। मानला विश्वविद्यालय-न्याय-सभा को सीपा गया। सत्रहवीं जून, सन् १९५३ को सभा ने अपनी राय मेरे पक्ष में दी, पर विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके फलस्वरूप सरकारी अदालत में मुकदमा दायर करने के सिवा मेरे पास कोई धारा न रहा।

मुकदमा छः वर्षों तक मर्योन्व न्यायालय में चला। तथा न्यायालय ने राय दी कि यद्यपि विश्वविद्यालय-न्याय-सभा की झगड़ा निबटाने का पूर्ण अधिकार है, तां भी न्यायालय उस फैसले को पंच-निर्णय-स्वरूप प्रयुक्त करने में असमर्थ है।

यदि मर्योन्व न्यायालय का यह अनुभव है तब तो दूसरों का कदना ही क्या है। कानून में इस प्रकार छिद्र रहने के कारण, निस्संशय अध्यापकों का यह दुर्दशा होती है। विद्यते वर्ष लोक-सभा में शिक्षा-मन्त्री डाक्टर भीमाली ने ऐसी न्याय-सभाओं की ठरयोनिता की खर्चा दी थी। इस विषय में तर्क-वितर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल इन्हीं मसल बनाने की आवश्यकता है, जिसने इनकी रायों का आदर हो।

स्वाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय

भूमिका

इस प्रकार हमारे देश में उच्च शिक्षा की परम्परा प्राचीन काल में चली आ रही है। किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों का शिक्षण। हमने कुछ दृष्टा है अनुसन्धान, क्योंकि विश्वविद्यालय का कार्य सदा उच्चतम शिक्षा देना है। उद्योगवीं शताब्दी में हमारे देश में, सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की सृष्टि

† University Education Commission's Report, p. 419

हुई। इस प्रकार इनके विधिविधानों का एक नवीन समन्वित रूप —  
माध्वीकरण था।

राष्ट्रीयता-प्रेम के कारण हमारे विधिविधानों की विभिन्नता और भी बढ़ गयी है। विधिविधि की शिक्षा हम तथा अनुगन्धान व माध्वीकरण, इनकी विभिन्नता प्रत्यक्ष नहीं हो जाती है। इन्हें माध्वीकरण, अनुगन्धान तथा माध्वीकरण कहा जाता है। इस प्रकार एक आधुनिक विधिविधान व कार्य-विधान की सीमा प्रकीर्ण हुई। आधुनिकता की सीमाएँ तब ही सीमित नहीं रह पाती। इनके माध्वीकरण के विभिन्न रूपों के अन्तर्गत की अन्तर्गतता की ओर ध्यान रखना पड़ता है, यथा: उच्च शिक्षा और अधीक्षण, मुख्य और ग्राह्य, धनी और गरीब, विमान एवं वाहन। उपर्युक्त प्रमाणों का अध्ययन मात्र ही इनकी समझ में आती है। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में विधिविधान का कार्य मुख्य रूप से है: (१) शिक्षा, (२) अनुगन्धान, (३) माध्वीकरण और (४) प्रमाण।

शिक्षण

प्रायः सभी नाबिड़ों तथा विधिविधानों का मुख्य उद्देश्य है अपने-अपने विचारों का शिक्षण। शिक्षण के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न सुटे हुए है। कुछ प्रश्नों की चर्चा इस प्रकरण में की जा रही है।

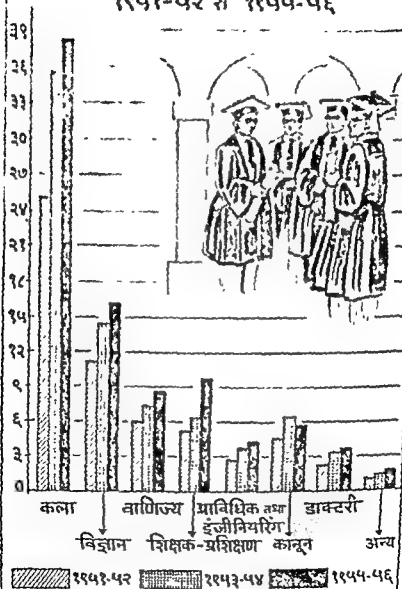
विधिविद्यालयों में प्रवेश.—कुछ वर्षों में विधिविद्यालयों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सन् १९४७ में इनकी छात्र संख्या अर्द्धांश मात्र थी। आज (१९५७) यह आठ लाख है। शिक्षण योजना के अन्तर्गत इस समय के दस लाख तक पहुँचने में सम्भावना है। प्रायः प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्था की छात्र संख्या गत दस वर्षों में दुगुनी हो गयी है। पर इस छात्र-वृद्धि के अनुपात में न उनमें स्थान-विस्तार ही हुआ और न उनके अगमन या शिक्षा-साधन ही बढ़ाये गये। इतना होते हुए भी विद्यार्थियों ने तो नाबिड़ों में भरती होना मुश्किल है। कई एक की तो 'एडमीशन बन्द' की खली ही टाँग देनी पड़ती है। इस सूचना-पट की देखकर विद्यार्थियों को पैसा ही अनस्ताव होता है, जैसा कि एक दर्शनाभिचार्य व्यक्ति की सिनेमा-गृह या नाटक-पर में 'हाऊस फुल' का पाटिस देखाकर, या, नौकरी के उम्मेदवार को किसी कार्यालय में नौकरी खाली नहीं' की सूचना सुनकर मार्मिक पीड़ा होती है।

इतना होते हुए भी सभी शिक्षाएँ करते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता ही जा रहा है। अगले पन्ने के तालिका में विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं का परिणाम दिया जाता है:



# उत्तीर्ण ग्रेजुएट संख्या (हजार)

१९५१-५२ से १९५५-५६







(कला), वाणिज्य व अतिरिक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय को गृह-विज्ञान तथा मन्त्रिक-कला की शिक्षा का अंगीकार करना चाहिए। इनके अतिरिक्त इन प्रत्येक शाखाओं में विविध विषयों के समावेश की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधार में अनेक उपायों की सम्भावना है। प्रथमतः, प्रत्येक कालिज की अपनी-अपनी विशिष्टता रहेगी। ये कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध कर सकेंगे। द्वितीयतः, विविध विषयों के समावेश के कारण, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकेगा। यह निश्चय नहीं उद्घाटन बाधना। तृतीयतः, कालिज की कक्षाओं की छात्र-संख्या घटेगी क्योंकि कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध होगा। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक विषय में तथा व्यावसायिक कालिजों में चुनिन्दा विद्यार्थी शिक्षापरत करेंगे।

ज्ञान-वर्षीय डिग्री कोर्स.—ज्ञान-वर्षीय डिग्री कोर्स की आवश्यकता की सर्वां पहले की जा चुकी है। प्रहरी, कर्नाटक, केरल, मद्रास, ओरिस्सा तथा सागर विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम का आरम्भ १९५७-५८ या उनके पहले ही किया था। अलीगढ़, आन्ध्र, अजामन्य, मैसूर, नागपुर, आनन्द तथा ब्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय इस योजना को १९५८-५९ में एच पुना, राजस्थान, उत्तर, बिन्तम तथा महिला विश्वविद्यालय इसे १९५९-६० में शुरू करनेवाले थे। बचे हुए विश्वविद्यालय इस योजना के विषय में सोच-विचार कर रहे हैं। द्वितीय योजनाकाल में इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए पन्द्रह करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। यह अर्थ १८० इण्टरमीडिएट कालिजों को डिग्री कालिजों में बदलने के लिए तथा ३६० डिग्री कालिजों के पुनर्गठन के हेतु खर्च किया जायगा।†

सामान्य शिक्षा.—देखा गया है कि कालिजों में चार वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात् भी हजारों स्नातकों की शिक्षा का सर्वाङ्गीर विकसम नहीं होता है। उन्हें सत्तर के अनेक विषयों का ज्ञान नहीं रहता है, जिनकी आवश्यकता एक शिक्ष मनुष्य के लिए है। जैसा कि श्री सैयदैन ने कहा है :

विश्वविद्यालयीय शिक्षा-द्वारा हम सकीर्ण, कल्पना-हीन विशेषर प्रस्तुत करते हैं। हमारे विज्ञान के स्नातकों को कला तथा कविता, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इसी प्रकार कला के

† Evaluation Committee Report of the Three Year Degree Course Delhi, Ministry of Education, 1958, p 12

विद्यार्थी ठीक तरह समझ नहीं पाते कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक पद्धति ने किस प्रकार उस विश्व को बदल दिया है, जिस पर वे काम करते हैं ।

शिक्षा की इस कमी को अनुभव करने हुए, गणराज्यन आयोग ने सुझाव दिये कि इण्टरमीडिएट तथा विश्वविद्यालय के विनोदीकृत शिक्षा के ढोरा को दूर करने के लिए कलर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जावे । इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नर एवं नारी को बड़ ज्ञान देना है जो उनको उनके विनोदीकृत अध्ययन के कारण नहीं मिल पाता है । इस प्रकार सामान्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विनोदीकृत शिक्षा के ढोरों को दूर करना है, जिनमें प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगपूर्ण विकास हो सके । साथही उन्हें उनके विशिष्ट क्षेत्र में पूरा प्रशिक्षण मिले, और यह एक उपयुक्त नागरिक बन सकें ।

गत पच्चीस बरों में शिक्षा की इस समस्या पर गुरु बहम हो रही है । अमेरिका तथा यूरोपीय अनेक देशों में सामान्य शिक्षा का सम्परीक्षण चल रहा है । साधारणत एव शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित किछी भी तीन तरीके में होता है ।

१. पाठ्यक्रम का कुछ मुख्य भागों में विभाजन.—विद्यार्थी को प्रत्येक भाग से कुछ-न-कुछ बोझ लेना पड़ता है,

२. उन सर्वेक्षण बोंमें का आयोजन, जिन्हें विद्यार्थी अपने विनोदीकृत अध्ययन के कारण नहीं ल पाते; एवं

३. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम.—जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, मानसिक विज्ञान तथा भाषा-शास्त्र का समावेश रहता है ।

उपर्युक्त तीन पद्धतियों पर, विश्वविद्यालयीय एक समिति ने विचार किया (१९५५) । समिति ने निर्णय किया कि हमारे देश के लिए तीसरी पद्धति अनुकूल होगी । अन्त में सन् १९५६ में एक अध्ययन-मण्डली इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में गई । इस मण्डली ने अपना प्रतिवेदन जूनवरी, १९५७ में सरकार को दिया । मण्डल ने सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तैयार की हैं । इसकी मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, मानसिक विज्ञान आदि में स्पष्टरूप से कुछ विषयों के अध्ययन की सामान्य शिक्षा सभी छात्रक पूर्व और-छात्रमासिक संकायों के लिए अनिवार्य रखी जानी है । वैज्ञानिक योजना में शिक्षा पाठ्यक्रम के अध्ययन तथा निर्माण वर्ग में सामान्य शिक्षा

के लिए गारा में छः पीरियड के अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू करना स्वीकार किया है और अधिकांश में इस माध्यम में कार्य आगम्य भी कर दिया है।

**निर्देश तथा परामर्श.**—विभिन्न विषयों तथा सामान्य शिक्षा के समावेश के साथ साथ आयरस है छात्रों को निर्देश तथा परामर्श। इनके अभाव में प्रत्येक विद्यार्थी के अनुकूल उपयुक्त विषयों का चुनाव अनुभव होगा। इस कारण प्रत्येक कानिष्ठ तथा विश्वविद्यालय में एक निर्देश तथा परामर्श कार्यालय की आवश्यकता है। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य हो, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता एवं रुचि की जाँच करना तथा उमर की पिछड़ी शिक्षा एवं भाष्य की ओर ध्यान ग्राह्य हुए सरथा के प्रचलित पाठ्यक्रम में उसके उपयुक्त विषय स्थिर करना, ताकि उनके अध्ययन से उसे अधिकतम सफलता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी के उद्यम-विरक्त रैकाई की भी आवश्यकता है। कार्यालय इन रैकाई की छानबीन करे तथा विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार परामर्श दे।

**शिक्षण का मान-दण्ड.**—बहुतों का कहना है कि हमारे विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक मान-दण्ड विशेष ऊँचा नहीं है, तथा अध्यापन का स्तर धीरे-धीरे नीचे की गिरता ही जा रहा है। यह आरोप बहुत कुछ सत्य है। शिक्षा की इस अमन्तोपजनक स्थिति के मुख्य कारण ये हैं :—अध्यापकों की नियुक्ति, उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का अभाव, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच निरुद्ध सम्पर्क का अभाव।

एक विश्वविद्यालय अध्यापकों का केन्द्र-स्थल है। वे ही उसे बढ़ा सकते हैं या गड़बड़े में डकेल सकते हैं। इस कारण उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए उपयुक्त अध्यापकों की आवश्यकता है। पर गत-दस वर्षों से कालिजों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि योग्य शिक्षकों का मिलना कठिन हो गया है। किसी-किसी कालिज में तो कोई भी एम० ए० पकड़कर अध्यापक बना दिया जाता है। अनेक होनहार नवयुवक कालिज या विश्वविद्यालय में आचार्य होकर अवश्य प्रविष्ट हो जाते हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य रहता है अधिकतर वेतनवाले पदों के लिए प्रस्तुत होना। आचकल अनेक अध्यापक आई० ए० एस० परीक्षाओं में बैठते हैं। यदि वे यहाँ सफलतापूर्वक न हुए तो वे शिक्षा-कार्य छोड़कर अन्य पदों पर चले जाते हैं। कोई-कोई तो न्यूनतम वेतनवाले पदों को स्वीकार करते हैं; कारण, यहाँ अतिरिक्त अर्थोपार्जन की संभावना रहती है।

इस विवेचन का निष्कर्ष यह निकला कि कालिज एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सन्तोषजनक वेतन मिलना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रावीडेण्ट फण्ड, छुट्टी

आज्ञावाद के पाठों का यथोचित प्रत्यक्ष ज्ञान। इसके सिवा, अध्यापकों के भारी होने की प्रथा में विराम सुधार की जरूरत है। अनेक अध्यापक नये रंगभट्ट होते हैं, उनके अध्यापन-कार्य का कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्तव्य सफलता पूर्वक धारण सकते हैं? आर्य यद्वा प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे शालिक तथा विश्वविद्यालय में कुछ शोध शिक्षक-वृत्ति के पद हों, जिनमें कुछ ज्ञान-उत्तम-प्रेतुर विद्यार्थी कम-से-कम दो वर्षों के लिए नियुक्त हों। इनमें से कुछ चुनकर विद्यार्थी मंडल में अध्यापक नियुक्त किये जायें।

इसके साथ-साथ नये अध्यापकों की शिक्षण-पद्धति का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान प्रदान करना चाहिए। हम ज्ञान में पढ़ाना मरल हो जाता है, तथा शिक्षा विधि रोचक न होती है। अनेक विश्वविद्यालय के उपपुस्तकालियों के एक सम्मेलन में इस विषय की विगत रूप से आलोचना हुई थी, तथा सम्मेलन ने कागजियों के अध्यापकों के लिए एक संश्लिष्ट पूर्व-अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक समझा गया।<sup>१</sup> इस कोष्ठ में उच्च शिक्षा अध्यापन की आवश्यकताओं का ध्यान रहना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि कागज-अध्यापकों को एक से अधिक विषय तथा क्षेत्र में इच्छीन पोरिपट्ट प्रति सप्ताह लेना पड़ता है। इस अतिरिक्त बोझ के दबाव के कारण, वे हॉफले लगते हैं। उनमें नवीन ज्ञान-प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती है और वे अपने व्याख्यान के लिए जो प्रमाला एकत्र कर लेते हैं, उसे ही पढ़ते हैं। या किसी प्रमाला नोट में कुछ अंश पढ़कर विद्यार्थियों को सुना देते हैं। बावजूद अध्यापकों का अध्यापन-कार्य कम न किया जायगा, तब तक यह परिस्थिति ठीक नहीं सकती है। न किसी आचार्य को एकाधिक विषय ही पढ़ाना पड़े, और न उसे सप्ताह में सौन्दर्य से अधिक पोरिपट्ट ही लेना पड़े। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह के अध्यापकों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि भी एम० एन० रोस ने कहा है :

प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनेक तरह के अध्यापकों की अमुविधाओं का सामना करना पड़ता है — न उन्हें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान ही मिलता है, न अनुसन्धान के लिए साधन तथा उपयोगी पुस्तकें, और न अन्य मदकारियों के साथ विचार-विमर्श करने की सुविधा।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> देखिए नवीं अध्याय।

<sup>२</sup> Ministry of Education, Indian University Administration  
१९५१, p. 97

शिक्षा-स्तर के पतन का एक और प्रधान कारण है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच निष्ठ मयोग का अभाव । दस वर्ष पूर्व, किसी भी काॅलिज-वर्ग की छात्र-संख्या ५०-६० से अधिक नहीं रहती थी । इन काॅग विद्यार्थीगण तथा शिक्षकगण परस्पर अपरिचित नहीं रहते थे, तथा शिक्षकगण विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता की ओर ध्यान रख सकते थे । पर आज तो अनेक कालिज की छात्र-संख्या दो-तीन हजार से अधिक है तथा प्रत्येक कक्षा में १५०-२०० विद्यार्थी बैठते हैं । इस अत्यधिक छात्र-संख्या का विषम परिणाम पड़े बिना नहीं रहता । हाल ही में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी कालिज तथा कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या क्रमशः १,५०० तथा ८० से अधिक न हो । इसके अतिरिक्त आयोग ने उपरक्षा-माली पर विशेष जोर दिया है ।

**पाठ्य-अवधि की हदता.**—उच्च शिक्षा में व्ययता का एक प्रधान कारण है पाठ्य अवधि की हदता । हमारे देश की प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा लेने की अवधि निर्धारित रही है, जैसे: बी० ए० या एम० ए० कोर्स दो-दो वर्ष, डाक्टरी कोर्स पाँच वर्ष, इंजीनियरिंग कोर्स चार वर्ष, इत्यादि । यह अवधि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार घटायी या बढ़ायी नहीं जा सकती है । इसके दो प्रमुख दोष हैं । प्रथमतः, इस पद्धति के अनुसार एक कमजोर विद्यार्थी को भी अपनी शिक्षा निर्धारित समय में समाप्त करनी पड़ती है । उसे सभी परखों में एक साथ बैठना पड़ता है, एवं वह दो-तीन बार ब्राह्म परीक्षाओं में छुटकता है और सम्भवतः वह सभी पास भी नहीं होता है । यदि उसे यही पाठ्यक्रम कुछ अधिक समय में समाप्त करने को दिया जाय, तो उसके असफलभूत होने की सम्भावना कम रहती है । द्वितीयतः, वर्तमान शिक्षा-पद्धति विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर कम देती है । यदि पाठ्यक्रम कुछ निर्धारित समय के बदले अमेरिकी पद्धति के अनुसार पाठ्यों में बाँट दिया जाय, तो विद्यार्थियों की यह कठिनाई दूर होगी । कारण, काम करते हुए भी, वे अपने अध्ययन के समय में कालिज में विद्याध्ययन कर सकेंगे । उन्हें एक पूरा काम करनेवाले विद्यार्थी की अपेक्षा समय अवश्य अधिक लगेगा, पर अन्त में उन्हें पूर्ण शिक्षा का लाभ तो मिलेगा । हमारी उच्च शिक्षा में इस सुधार की बहुत ही ज़रूरत है ।

† भीषणाथ मुकर्जी: अमेरिका में शिक्षण—यूनाइटेड स्टेट्स इनकांमिशन सर्विस, १५४, पृष्ठ २३ ।

अंग्रेजी का स्थान —आजकल उच्च शिक्षा के माध्यम एवं पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान देने या न देने के सम्बन्ध में घोर वाद-विवाद चल रहा है। यह मस्य है कि हमारे विद्यार्थी यह भाषा खूबी के साथ सीखते हैं तथा अनेक विद्यार्थियों ने इस भाषा में पर्याप्त दक्षता दिग्गम्य है, पर अंग्रेजी घोटते-घोटते अनेक विद्यार्थियों का दम निकल जाता है। इतने पर भी उनका सम्पूर्ण वैयक्तिक विकास नहीं हो पाता है। हमें मता याद रखना चाहिए कि किसी राष्ट्र की प्रगति निजी भाषाओं द्वारा ही होनी है, न कि एक विदेशी भाषा के द्वारा।

संघाटनन आयोग ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। इस प्रस्ताव पर घोर वाद-विवाद हुआ। उच्च शिक्षा का माध्यम कोई अंग्रेजी रखना चाहते हैं, कोई हिन्दी अर्थात् राष्ट्र-भाषा, एवं कोई क्षेत्रीय भाषा। अपने मत की पुष्टि के लिए प्रत्येक पक्ष कुछ-न-कुछ न्यायगत मुक्ति प्रस्तुत करने हैं। इसी कारण यह विवाद बढ़ता ही जाता है।

मानवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होना चाहिए। जिस प्रकार एक नवजात शिशु के लिए मातृ-दुग्ध हितकर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र तथा व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए मातृभाषा-द्वारा शिक्षा आवश्यक है। पर इस शिक्षा-माध्यम का एक बड़ा खतरा यह है कि हमारे विश्वविद्यालय सर्वांग क्षेत्रीय सरूपाएँ न बन जायें। क्षेत्रीय भावनाएँ हमारे देश के लिए हितकारी नहीं हैं। भारत का उत्तरोत्तर विकास तभी सम्भव है जब कि समूचे देश में एकता कायम रहे। इसी कारण, दूसरा दल राष्ट्र-भाषा के माध्यम का समर्थक है।

तीसरा दल अंग्रेजी के पक्ष में है। उनका कथन है कि चूँकि यह भाषा विदेशी है, इस कारण इसमें उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी ने इस देश में एकता की सृष्टि की है, इसे इसी भाषा के द्वारा शिक्षा का सन्देश प्राप्त होता है तथा उसीके द्वारा हम समस्त समाज पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अतएव हमारे द्वारा अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा किया जाना एक अन्याय है।

इस समस्या को सुलझाने के निमित्त विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने सन् १९५५ में एक समिति नियुक्त की। इसके अध्यक्ष थे श्री हृदयनाथ कुंजरू। समिति की जाँच के निम्न दो थे : (१) विश्वविद्यालयीय शिक्षा के माध्यम पर विचार करना, तथा (२) अंग्रेजी भाषा के स्तर को ऊँचा रखने के लिए उपाय सुझाना। प्रथम प्रश्न पर पूर्णतः विचार करने के पश्चात्, समिति ने प्रस्ताव किया है कि पूर्ण

तैयारी के पश्चात् विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी भी भारतीय भाषा में बदला जावे। इस परिवर्तन के बाद भी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय रहे। इनके अतिरिक्त समिति ने प्रस्ताव किया :

१. जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाना चाहते हों, उनकी शिक्षा में अंग्रेजी के प्रति-विशेष जोर दिया जाय;

२. चूँकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स अपनाया है, इस कारण पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है; और

३. नवीन अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का अध्ययन आवश्यक है, और यह ज्ञान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को दिया जावे।

इस रिपोर्ट पर राज्य सभा में बहस हुई (२६ फ़रवरी, १९५९)। सरकार ने अनुमोदन किया कि उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा दी जावे। पर उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के अभाव तथा अन्य कठिनाइयों के कारण यह निर्णय हुआ कि यह कार्य कुछ समय तक स्थगित रखा जाय। इस अवधि में अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम रहे, अतएव इस भाषा का स्तर गिरने न पावे।

**वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्दः—**जहाँ तक हो सके, प्रत्येक भारतीय भाषा के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत शब्द हो। उच्चतर शिक्षा के लिए यह ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। हमारी भाषाओं में पारिभाषिक शब्द-कोष निर्माण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने इस विषय पर कहा ही है, "अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का उपयोग भारतीय भाषाओं में किया जाय, पर उनके हिज्जे तथा उच्चारण प्रत्येक भाषा के स्वयं के अनुसार अमनाये जायें।"<sup>†</sup> यह मानना ही पड़ेगा कि पारिभाषिक शब्द रीखातानी पर अनुयाति होने हैं। अनेक अनुयाति शब्दों का ठीक अर्थ ही नहीं निकला। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान का सम्बन्ध किसी प्रदेश या देश में नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है। इस कारण, अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हिज्ज तथा आवश्यक है।

<sup>†</sup> University Education Commission's Report p 326.

**परीक्षा.**— भारतीय शिक्षा का एक बड़ा दोष 'उसकी परीक्षा-पद्धति' है। इसके विरुद्ध गत पचास वर्षों से आवाज उठायी जा रही है। सन् १९०२ के विश्वविद्यालय आयोग ने गौर किया कि "विश्वविद्यालयीय शिक्षा का ध्येय है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिये तैयार करना। इस कारण, परीक्षा की विनियम छाप अध्यापन तथा अध्ययन पर पड़ती है।" और, सन् १९४९ में गधाकृष्णन-आयोग ने परीक्षा का विश्लेषण करते हुए कहा, "यदि विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर हमें केवल एक ही सुझाव देना हो तो हम कहेंगे कि वह परीक्षा-सुधार है।"† पर परीक्षाओं के उन्मूलन का समर्थन न कर कमीशन ने उनमें सुधार बाछनीय बनलाया है। आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये :

१. शिक्षा-मन्त्रालय शिक्षण-योगता-ऑन-विषयक विविध परीक्षाओं का मर्दभूग करे।

२. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्थायी, पूर्ण कालिक परीक्षा मण्डल संगठित हो। यह मण्डल अध्यापकों को वस्तुगत प्रश्न के निर्माण तथा प्रयोग के संबंध में पगमरी दे।

३. वर्ष में किये गये कक्षा-कार्य को भी परीक्षा की गणनात्मक असफलता में मगिमग्न किया जावे। प्रत्येक परीक्षा में जो अङ्क निर्दिष्ट रहें, उन अङ्कों का एक-तृतीयांश इस कार्य के लिये सुरक्षित रखा जावे।

४. कालिक की तीन वर्ष की पढ़ाई में, एक अन्तिम परीक्षा के बदले विभिन्न कालिक परीक्षाएँ ली जावें।

५. परीक्षकों का चुनाव काफी मायधानी से किया जाय। कोई भी ऐसा व्यक्ति उम विषय में परीक्षक न बना दिया जाय, जिने उसने कम से कम पाँच वर्ष तक न पढ़ाया हो।‡

उपर्युक्त सुझाव अति दिलचस्पी हैं। बावजूद परीक्षा-पद्धति निर्गमर करने समर आन्तरिक परीक्षाओं, कक्षा तथा उपकक्षा रेबार्ड पर विचार करना अन्वयरपदक है। परीक्षाओं में निरर्थक रूप प्रश्नों के अतिरिक्त, वस्तुगत प्रश्नों का समावेश किया शर। परीक्षा-सुधार पर समग्रतः अनेक कोशिशें हुई हैं। समी ने परीक्षा सुधार का प्रयत्न एक मात्र हंकर रनीकार किया है। प्रश्न केरत दरी दे कि यह सुधार किस प्रकार किया जाय !



**विद्यार्थियों की आर्थिक समस्या.**—उच्च शिक्षा दिनों-दिन अधिकतर खर्चीली होती जा रही है। इस कारण अनेक निर्धन, किन्तु योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। सम्प्रति कालिजों में ५ से १५ प्रति शत विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा अवसर मिलनी है, तथा सरकार ने अनेक छात्र वृत्तियों का प्रबन्ध भी किया है। सन् १९५६-५७ में छात्रवृत्ति पर कुल सरकारों व्यय प्रायः तीन करोड़ रुपये था।

पर यह ध्येय खोष्ट नहीं है। इंग्लैण्ड में ७२.८ प्रति शत विश्वविद्यालयीय विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति या मुफ्त शिक्षा मिलनी है। अनेक पाश्चात्य देशों में सरकारी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में स्थानिक विद्यार्थियों की फीस बहुत ही कम रहती है। पर अर्थाभाव के कारण यह योजना हमारे देश में अभी स्वप्नातीत है। अमेरिका में उच्च शिक्षा के विस्तार का एक प्रधान कारण यह है कि उस देश के अधिकांश विद्यार्थी कमाई भी किया करते हैं और पढ़ते भी हैं। साथ ही कालिज का 'नियुक्त-कार्यालय' विद्यार्थियों को नौकरों दिलाने में उनकी पूर्ण सहायता करता है। हमारे देश में भी ऐसी ही शिक्षा-व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है।

### अनुमन्थान

राधाकृष्णन-आयोग ने कहा है कि 'अनुमन्थान के बिना अध्ययन मृत हो जायगा' — यह अतीव सत्य है। पर हमारे विश्वविद्यालयों ने अनुमन्थान की ओर हाल ही में ध्यान दिया है। यह अनुमन्थान पर्याप्त रूप में नहीं हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं :

१. अर्थाभाव।

२. अध्ययनों पर अधिक दायित्व-भार, जिससे उनका अधिकांश समय क्ल्याक टैक्निक में व्यतीत हो जाता है। इसीसे अनुमन्थान कार्य के लिए उन्हें धनराश ही नहीं मिल पाता है।

३. उपयुक्त पुस्तकालय, आवासभवन तथा प्रयोगशालाओं का अभाव।

४. शोध शिष्य-वृत्ति की अन्यायिता।

५. पी० एच० डी० के प्रशिक्षण में अनुमन्थान रीतियों की अनुपस्थिति।

६. विश्वविद्यालयों का अन्य निवासों के साथ सहभागिता का अभाव, जैसे : आवास, कृति, वाणिज्य, खेल, इत्यादि।

इन कमियों के दूर हुए बिना अनुसंधान की उन्नति नहीं हो सकती है। सम्प्रति सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। अब सरकार संशोधन की वृद्धि के लिए पर्याप्त चेष्टा कर रही है। सन् १९५५-५६ में ५२७ छात्रों को सरकारी शोध-वृत्ति मिली। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने तो अनुसंधान में एक नया जीवन ही डाल दिया है। विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं की उन्नति के लिए पर्याप्त द्रव्य मिलने लगा है, अत्याचारों का संशोधन के निमित्त अधिक सहानुभूति दी जा रही है तथा अनुसंधान के लिये नियुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयीय शिक्षा में संशोधन का एक प्रमुख स्थान मिल रहा है। पर यह शोध केवल औद्योगिक न हो। मानव की उन्नति के लिए सांस्कृतिक अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है।

उपयुक्त अनुसंधान तभी सम्भव है, जब आधारभूत रूप इस कार्य में स्थिरता हो तथा उन्हें संपोषित अवकाश मिले। इस कारण प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे प्राध्यापक हों, जो अपना अधिकांश समय शोध के निमित्त बितायें, तथा उनके लिये कतिपय रिक्त-पैयों का काम करें। हांगकण विश्वविद्यालय का एक आचार्य बयन है: "या तो संशोधनात्मक रूप प्रकाशित करें, या रिजट हो जाओ, या तो रिजल्ट एवं ज्ञान अक्षिप्त करके उत्तर उठा, या विश्वविद्यालय में निवृत्त जाओ।" इस प्रकार अध्यापन क्षेत्र में उन्हीं लोगों की जरूरत है, जो दालबूत या रिजल्ट प्रेमी हैं और जो ज्ञान की बलिबेदी पर मृत्यु-मुविधाओं को खड़ा सकते हैं।

### संरक्षणीकरण

हमारे देश के आदि में अधिक विश्वविद्यालय संरक्षणीय हैं। इनके कार्य-कलाप की खर्चा हम पर चुके हैं। इन पद्धति के अनुसार मरदम कार्य-शे के वास्तविक, पाठ्य पुस्तकें तथा परीक्षाएँ एक ही होती हैं। इनके परिणाम-स्वरूप मरदम अधीनस्थानीयता से घटती है, तथा उनकी स्वायत्त आवश्यकताओं की ओर ध्यान भी पड़ने नहीं दिया जाता है।

विश्व में एक मात्र एक ब्रह्मण्ड शक्ति के लिए, उन्नत पद्धति प्रदर्शन का लक्ष्य है; पर प्रदेव कार्य-शे की निम्न मरदमों तथा स्थानिक आवश्यकताएं रहती हैं। इस कारण उनके वास्तविक में कुछ ही पर प्रदेवनीय होना है। संरक्षणीय विश्वविद्यालयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रदेव कार्य-शे अधीन निम्न मरदमों के अपने निर्देशित शक्ति के मरदम के द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य-प्रकार करें। विश्वविद्यालय की स्वायत्त निम्न-मरदमों इस पर विचार करें तथा विद्यमान निम्न के

करे। समिति के निर्णय के अनुसार, कालिज को अपने कार्य-कलाप में कुछ नई स्वाधीनता मिले। इस प्रकार सर्वद्वीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कुछ की आवश्यकता है। इन्हें सदा लकीर के फकीर रहकर काम न करना चाहिए।

**मेका.**—हमारे कालिज तथा विश्वविद्यालय सामान्य जनता के सम्पर्क में न आते हैं। यह नीति ठीक नहीं है। चूँकि जनता के अर्थ से वे अपित होती हैं, अतएव इन्हें जनता की आवश्यकता की ओर ध्यान देना। इस सम्बन्ध में कालिज तथा विश्वविद्यालय दो प्रकार के काम कर सकते हैं : शिक्षा तथा (२) समाज-सेवा।

**शिक्षा.**—ग्रीड शिक्षा के प्रोग्राम तीन प्रकार के हैं : (१) सातत्य शिक्षा प्रक्रम उन व्यक्तियों के लिए है, जो कालिज के साधारण विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहते हैं। नवीन विद्या पाने की आकांक्षा के कारण, अनेक ग्रीड में भाग लेना चाहते हैं। (२) पुनर्जीवन कोर्स — अनेक व्यक्तियों की में अर्जित विद्या में जग लग जाता है, पर वे आधुनिकतम विद्या का लाभ नहीं लेते हैं। ऐसे वयस्क व्यक्तियों के लिए सक्षिप्त कोर्स लाभदायक होते हैं। कार्यक्रम — इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, हमारे गाँवों तथा शहरों के उत्सार के विविध क्षेत्रों की प्रगति से परिचय कराना।

**समाज-सेवा.**—वर्तमान समय में हमारे विश्वविद्यालय जनता में शान-लेख कुछ वक्तृताओं का आयोजन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक में एक मनोरञ्जन तथा वक्तृता कार्य-पीठ की आवश्यकता है। ऐसी : प्रत्येक अमेरिकी सरकारी विश्वविद्यालय में रहती है। नीचे अमेरिका के विश्वविद्यालय कार्य-पीठ के कार्यक्रम का वर्णन दिया जाता है :

कार्य-पीठ अपने राज्य के विभिन्न सामाजिक समूहों से सम्बन्ध रखती हैं। उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी माँगों को पूरा करने के लिए, वह अपने कालिजों तथा विभिन्न शिक्षा-विभागों से उपयुक्त वक्ता भेजती रहती है। यही मनोरञ्जक कार्यक्रम, नाट्याभिनय, प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी करती है।†

सेवा की ओर हमारे कुछ विश्वविद्यालयों का ध्यान अभी-अभी गया है। १ डाक्टरों की डिग्री मिलने के पहले अनेक विद्यार्थियों को कुछ समय तक

गोवों में काम करना पड़ता है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसके अनुसार प्रत्येक स्नातक के लिए राष्ट्र-सेवा अनिवार्य होगी। शिक्षा-मन्त्रालय इस योजना को तृतीय पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ होने ही चलाना सोच रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के अनुकूल छः महीने से दो वर्ष उन क्षेत्रों की उन्नति में भाग लेना पड़ेगा, जो रिछड़े हुए हैं। आशा की जाती है कि प्रथम वर्ष अर्थात् १९६१-६२ में ९०,००० विद्यार्थी इस कार्य में जुट जायेंगे। इसीके आधार पर अन्दाज लगाया जाता है कि योजना का वार्षिक खर्च पाँच करोड़ रुपया पड़ेगा।†

### उपसंहार

ये हमारे विश्वविद्यालयों की प्रमुख समस्याएँ हुईं। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राजकीय कामकाज के लिए कर्मचारी जुटाना था। इनका ध्येय अध्यापन या अनुसन्धान एकदम नहीं था। ये तो छोटे मोटे दफ्तर थे, जिनका उद्देश्य था परीक्षा चलाना और प्रमाण-पत्र वितरण करना। ये विश्वविद्यालय न हमारे देश के तत्त्वज्ञान या मान्यता से मिलते जुटते थे और न आक्सफोर्ड या पेरिस से। फिर हम उन्हें उनके कार्यक्रमों के लिए बेमने दोषी ठहरा सकते हैं।

कल्पना विश्वविद्यालय आयोग ने हमारे विश्वविद्यालयों को नवीन जीवन प्रदान किया है, और उनके सामने नया उद्देश्य रखा है। यथार्थ में हमारी विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल शारीरिक वर्ष पुरानी है। हम अगले में हमारे विश्वविद्यालयों ने जो कुछ किया है, वह सराहनीय है। हमोंने सम्पूर्ण देश में एकता की सृष्टि की, और यहाँ से निकले हुए स्नातकों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मोर्चा लिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय कभी मृत्यु से न दिगें, तथा महा उच्च आदर्श सामने रखें। जैसा कि महापुरुषान-आयोग ने कहा है :

उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्य ज्ञान के संचयन, नवीन ज्ञान के अन्वेषण, जीवन के प्रयोजन की निरन्तर खोज, तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा के आयोजन हैं। आदर्श कल्पना स्वप्न होते हैं, किन्तु इनकी ओर निरन्तर प्रयत्न करना प्रत्येक नागरिक तथा गवर्नमेंट का कर्तव्य है।‡

† *Times of India*, July 25, 1959

‡ *University Education Commission's Report*, p. 65

## सातवाँ अध्याय

### स्त्री-शिक्षा

#### प्रस्तावना

वर्तमान युग की सबसे उल्लेखयोग्य घटना है, नारी-प्रगति । यदि एक शताब्दी पूर्व का कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीवित होकर भारत में लैंड आवे, तो वह हमारे देश के महिला-जीवन में आमूल परिवर्तन देखकर निश्चय ही दम्भ रह जाएगा । यहाँ पर एक शताब्दी पूर्व अनेक व्यक्ति स्त्री-शिक्षा के घोर विरोधी थे, पर आज सभी स्वीकार करते हैं कि इस शिक्षा के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है । स्त्री-शिक्षा को अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा : पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-शिक्षा के प्रति माता-पिताओं की उदासीनता, पाश्चात्य शिक्षा पर अविश्वास, मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्या, लड़कियों के उपयुक्त पाठ्यक्रम का अभाव, शिक्षिकाओं की अपर्याप्तता, इत्यादि । धीरे-धीरे ये कठिनाइयाँ हल होनी आ रही हैं । आज देश में कन्या-शिक्षा की चाह बढ़ रही है । राष्ट्रीय संगठन में स्त्रियों का विशेष स्थान है ।

#### स्त्री-शिक्षा का विस्तार

**भूमिका.**—सब कुछ होते हुए भी, आज केवल १२ प्रति शत भारतीय स्त्रियाँ शिक्षिता गिनी जाती हैं । गत सौ वर्ष में स्त्री-शिक्षा बहुत ही धीरे-धीरे फैली । सरकार तथा जनता की उदासीनता के कारण, इसका विस्तार आशानुरूप न हुआ । इसका पता निम्न-लिखित विवरण से मिलेगा ।

**ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में.**—स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता के प्रति, कम्पनी का ध्यान कभी नहीं गया । शायद उसे नारी क्लर्क एवं अफसरों की आवश्यकता न थी । इसके अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा के विषय में लोगों में एक भ्रम-भूलक धारणा थी, जो कि परम्परा से चली आ रही थी । स्त्री शिक्षा के विषय में, एडम्स साहब अपनी रिपोर्ट (१८३८) में लिखते हैं, “देश के सभी विद्यालय पुरुषों

के लिए है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो अन्धकार में डूबी हुई हैं।”

इस प्रकार कम्पनी के राजत्व-काल में लड़कियों के लिए एक भी सरकारी स्कूल न था। एनी-मिनी कुछ बालिकाएँ लड़कों के स्कूलों में शिक्षा पाती थीं। इस काल में कतिपय निजी तथा मिशनरी बालिका-विद्यालय अवश्य खोले गये थे। उदाहरण-स्वरूप सन् १८५१ में, प्रोटेस्टेण्ट मिशनरी सब ८६ साक्षर स्कूल तथा २८५ साधारण स्कूल खोले थे। इनकी छात्र-संख्या क्रमशः २,२७४ और ८,९१९ थी। रोमन कैथलिक सघों भी कुछ स्कूल खोले थे, पर इनकी संख्या का कुछ ठीक पता नहीं है। कई उदार इनों तथा सरकारी अफसरों ने भी कुछ बाल्या-शालाएँ खोलीं। इनमें मुख्य है बेथून न, जिसकी स्थापना ईरिशमार् बेथून माह्व ने सन् १८४९ में की थी। ये भारत-भार के कानून-विषयक तत्कालीन महत्त्व थे। अपने जीवन की सारी कमाई इन्होंने स्कूल में लगा दी थी। इस समस्या ने लोगों में बाल्या-शिक्षा के प्रति एक नवीन भावना दी, और उसीके आदर्श पर बालिका-विद्यालय खुलने लगे।

सन् १८५७ से सन् १९०२ तक.—सन् १८८२ के शिक्षा-आयोग ने कहा : “स्त्री शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसे विस्तार करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं।” बर्मीटान ने प्रस्ताव किया कि सरकार स्त्री-शिक्षा पर अधिकतर अर्थ खर्च करे। इस कारण सरकार ने स्वनः कई बालिका-विद्यालय खोले, तथा निजी स्कूलों की अनुमति देना स्वीकार किया। अतएव स्त्री-शिक्षा भी यथेष्ट प्रगति हुई। सन् १९०१-१९०२ में बालिका गणनाओं की संख्या इस प्रकार थी : १२ बालिका, ४६७ माध्यमिक स्तर तथा ५,६२८ प्राथमिक स्तर। इनमें ४,४७,४७० लड़कियाँ शिक्षा का रही थीं।

सन् १९१२ से सन् १९१७ तक.—शूनैः शूनैः स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का उदासीनता दूर होने लगी, तथा जनता स्त्री शिक्षा में रुचि लेने लगी। इसके कई कारण थे। अनेक गांधी पिता अनुभव करने लगे कि उनकी लड़कियों की शिक्षा उनकी ही आवश्यक है, जितनी उनके लड़कों की; अब लोगों में शिक्षिता स्त्री की दार बनी। शिक्षा विन्यास भी स्त्री शिक्षा विस्तार के लिए प्रयत्न करने लगा : स्वतन्त्र तथा सरकारी बालिका-विद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों में बालिकाओं के आवागमन के लिए दान का प्रणय, हस्तकर्मों तथा शिक्षिकाओं की नियुक्ति, लड़कियों के लिए रुचि तथा मन

पीठ की व्यवस्था, बन्वाशास्त्रियों के लिए उन्नत सरकारी अनुदान-नीति, प्रांतीय महिला-शिक्षा-समितियों की नियुक्ति, इत्यादि।

उपयुक्त चेष्टाओं के कारण, स्त्री-शिक्षा फैलने लगी। सन् १९०४ में, धीमती एनी बर्मिस्ट ने बनारस में 'सेन्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय' की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं में हिन्दू-धर्म के आधार पर पाश्चात्य विद्या का प्रसार। सन् १९१६ में लेडी हाइविज मेडिकल कॉलेज, दिल्ली स्थापित हुआ। इस देश में विज्ञान-शास्त्र का यही सर्व प्रथम नारी महाविद्यालय है। इसी वर्ष महिला विद्याविद्यालय भी स्थापित हो गया। सन् १९१७ में बालिकाओं के लिए १२ आर्ट्स कॉलेज, बार ब्यादमादिक कॉलेज, ६८९ माध्यमिक स्कूल तथा १८,१२२ प्राथमिक स्कूल थे। इन समस्त शास्त्रों में इसी वर्ष १२,३०,४१९ लड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं।

सन् १९१७ से १९४७.—इस अवधि में स्त्री-शिक्षा का गन्तव्यप्रद दिशा हुआ, लोगों के अनेक भाग गन्तव्य दूर हुए तथा स्त्री शिक्षा की ग्राह बढ़ी। इसका पता निम्न विभिन्न तालिका में मिलेगा :

## तालिका २२

स्कूल तथा कॉलेजों में लड़कियों की संख्या,

१९२१-२२ से १९४६-४७

वर्ग	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४१-४२	१९४६-४७
प्राथमिक स्कूल	१०,५७,१३७	१९,४६,०७०	३१,२३,६४३	२७,१५,२३०
माध्यमिक स्कूल	७,२६,९५६	७,९६,१७०	४,१०,९३३	४,६२,५०३
आर्ट्स तथा आर्ट्स कॉलेज	१,३०७	२,६८५	११,७३८	१६,७८६
साइन्स तथा कॉलेज ...	७६६	५७१	७,७७५	२,६९८
कुल ...	१९,५७०	२७,५९८	४०,८३६	३६,३१०

नोट : सन् १९३१-३२ से १९४७ तक के बीच सन् १९३९ तक के बीच शिक्षा का ... द्वारा शिक्षित ... से ... है।

यह अवधि भारतीय इतिहास में विरस्मरणीय रहेगी : इसमें दो विश्व युद्ध हुए, सामाजिक क्रान्ति आयी, आर्थिक स्थिति में घोर परिवर्तन हुआ, समूचे देश में राष्ट्रीय जागृति हुई तथा अन्त में १५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ। इसी समय अमेरिका तथा अनेक युरोपीय देशों में नारी-स्वाधीनता का आन्दोलन पूरे दम पर चला। इसकी आँख भारत में भी पहुँची। हमारे देश की लड़नाएँ भी संगठित होने लगीं। सन् १९१७ में डा० एनी बीसेण्ट तथा थीमती मार्गेट कसिन्स के प्रयत्नों के कारण अखिल भारत-महिला-संघ का सूत्रपात हुआ। इसके आठ वर्ष पश्चात्, स्त्री-भारतीय-परिषद् स्थापित हुई। वर्तमान काल में, भारत में इस परिषद् की चौदह राष्ट्रीय शाखाएँ हैं, तथा परिषद् विश्व-स्त्री-परिषद् से सम्बन्धित है। सन् १९२७ में सर्व प्रथम अखिल भारत-स्त्री-परिषद् से सम्मेलन का आदि अधिवेशन हुआ। तबसे यह सम्मेलन वार्षिक हुआ करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही नारी-प्रगति है। इसके साथ ही सामाजिक दोषों का उन्मूलन तथा स्त्री-शिक्षा का विस्तार इस सम्मेलन के लक्ष्य हैं।

इसी समय गान्धीजी का नेतृत्व अस्तित्व में आया। उन्होंने भारतीय नारी जीवन में एक नवीन प्राग का सन्चार किया। स्वातन्त्र्य-युद्ध के लिए उन्होंने भारतीय लड़नाओं को आह्वान किया। राष्ट्रीय भावनाओं में उनका हृदय परिपूर्ण हुआ। वे परदे से निकल कर स्वाधीनता-संग्राम में कूट पड़ीं, और पुरुषों की भाँई उन्होंने सभी यातनाओं को सहन किया। उन पर लाठियों-चलायी गयी, उन्हें कैद भुगतना पड़ा, उन्होंने अपने स्वामियों तथा सन्तानों का रक्तपात देखा, पर वे न टिगीं। इस प्रकार नवीन जागृति हुई। समाज-मुधार तथा स्त्री-शिक्षा-विस्तार की आकांक्षाएँ बढ़ीं। क्या पुरुष, क्या स्त्री सभी यह अनुभव करने लगे कि बालिका-शिक्षा के द्वारा ही माता तथा कुटुम्ब की शिक्षा हो सकती है। शिक्षिता बालिकाएँ ही मुराहिणी बन सकती हैं, तथा समाज का अधिपति मुधार भी उन्हीं पर निर्भर है।

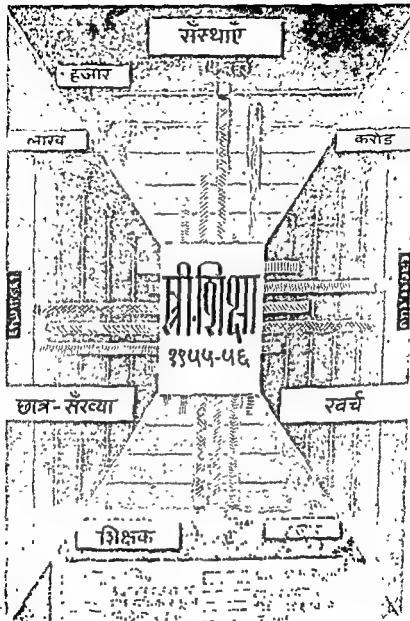
### वर्तमान स्थिति

**भूमिका** — स्वातन्त्र्योत्तर-काल में स्त्री शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। सन् १९४७-४८ में सम्पूर्ण देश में कुल १६,९५१ बालिका-विद्यालय थे, तथा इनकी छात्र-संख्या १५,५०,५०३ थी।<sup>†</sup> सन् १९५६-५७ में विद्यालयों की संख्या २६,४२५ पहुँची, तथा इनकी छात्र-संख्या ९९,९७३३९ हुई।<sup>‡</sup> छात्र-संख्या की सम्मति अधि

† *Seven Years of Freedom*, ■ २९

‡ *Education in the States, 1955-57*, 15 3-4.





वृद्धि कालिज-स्तर में व्यावसायिक और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हुई। इसके बाद विश्व-विद्यालय और कालिज की सामान्य शिक्षा का स्तर आता है। इसके सिवा, माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की संख्या दुगुनी तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह बढ गुनी हुई।<sup>†</sup>

**प्रशासन.**—कहा जाता है कि उपयुक्त प्रशासन के अभाव के कारण, स्त्री-शिक्षा का प्रगन्थ ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी राज्य में अब डिप्टी हाइस्कूल ऑफ़ एजुकेशन अर्थात् शिक्षा-उप सचालिका का पद नहीं है, एवं सम्पूर्ण देश में निरीक्षिकाओं की संख्या ६९ है।<sup>‡</sup> अतएव स्त्री-शिक्षा का प्रशासन अधिकतर पुरुषों के हाथ में है। इन्हें बालिकाओं की विशेष जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए।

स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए मई, १९५८ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नारी शिक्षा-समिति नियुक्त की थी। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य-सरकार में एक प्रशासन-मण्डल की आवश्यकता है जो कि स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की देख-भाल करे। समिति के सुझाव के कारण, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के मानदृत राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद की स्थापना सन् १९५९ में हुई। परिषद में एक अध्यक्ष, चौदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, दो सदन सदस्य तथा योजना आयोग, सामुदायिक विकास तथा सरकार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भ्रम मन्त्रालय, तथा केन्द्र-शासित प्रदेशों का एक एक प्रतिनिधि और शिक्षा मन्त्रालय के दो प्रतिनिधि होंगे। गैर-सरकारी व्यक्तियों का कार्य-काल दो वर्ष रहेगा।<sup>\*</sup>

परिषद की पहली बैठक १६ अक्टूबर, १९५९ में भरी। इसमें यह स्थिर हुआ कि स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों की देखरेख के लिए केन्द्रीय सरकार में एक समुक्त शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए तथा शिक्षा मन्त्रालय में स्त्री-शिक्षा का एक अलग युनिट बना देना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सलाहकार परिषदों के अनिश्चित एक समुक्त निदेशक भी नियुक्त किया जाय, जो शिक्षा तथा स्त्रुत्वियों की शिक्षा के काम की देखरेख करे।<sup>‡</sup>

† शिक्षा-मन्त्रालय: भारत में शिक्षा-लेख चित्रों में। दिल्ली, डेनजर ऑफ़ पब्लिकेशन, १९५०, पृष्ठ २०।

‡ *Education in India*, 1955-56, Vol. I p. 123.

\* भारतीय समाचार, १ अगस्त १९५९, पृष्ठ ४००।

‡ सदेश, १६ अक्टूबर, १९५९, पृष्ठ ६५९।

उत्तुंग अधिकांशों के अधिगम, प्रदेश मान में एक शिक्षा दर मनायिका तथा प्रदेश शिक्षा में एक निरीक्षण की आवश्यकता है। मगनीय मगरनी को मगनीय निरीक्षण शिक्षा की देखरेख के लिए कुछ यंत्रणाएँ नियुक्त करें। मगर अर्थ पर है कि मनी-शिक्षा की धर्म के लिए उत्तुंग मगनीय, प्रत्यक्ष तथा निरीक्षण की आवश्यकता है।

**प्राथमिक शिक्षा.**—मगनीय शिक्षा को मगरनीय शिक्षा के लक्षण तक पहुँचने के लिए अभी एक लक्षण मार्ग तय करना है। मात्र लगभग एक-तिहाई लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। सन १९५०-५१ में ६-११ वर्षीयों के पढ़नेवाले बालक तथा बालिकाओं की सख्या क्रमशः ५९ तथा २५ प्रति शत थी। १९५५-५६ में यह संख्या ६९ लड़कों के लिए तथा ३३ लड़कियों के लिए हो गयी। द्वितीय आयोजना के अंत तक समयतः ८६ प्रति शत बालक तथा ४० प्रति शत बालिकाएँ शिक्षा पागे लगेंगी। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के दौरान में ११-१४ वर्षीयों के छात्रों तथा छात्राओं की संख्या २२ तथा ५ प्रति शत में बढ़कर क्रमशः ३० और ८ हुई, एवं दूसरी आयोजना में ३६ और १० प्रति शत लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा की सुविधाएँ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सांगत यह है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसके सिवाय लड़कियों स्कूलों में ज्यादा दिन नहीं ठहरती। स्कूलों की पहली कक्षा में भरती किये हुए प्रति १०० बच्चों में से प्रायः ४३ चौथी कक्षा में पढ़ना छोड़ देते हैं, पर १०० में से केवल ३० लड़कियाँ चौथी कक्षा में पहुँचती हैं। इस प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, प्राथमिक अवस्था में स्पर्धता अधिकतर है। लड़कियों में अनिवार्य शिक्षा भी अधिक नहीं फैली। सन १९५५-५६ में अनिवार्य शिक्षा की स्थिति इस प्रकार थी : २८४ शहर (केवल लड़कों के लिए) तथा ७९९ शहर (बालक-बालिकाओं के लिए), एवं ८,९५९ गाँव (केवल लड़कों के लिए) तथा ३०,३१७ (बालक-बालिकाओं के लिए)।†

**माध्यमिक शिक्षा.**—लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई है। अनेक बालिका-विद्यालय खुले, छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई, बालकों के स्कूलों में पढ़नेवाली बालिकाओं की संख्या बढ़ी तथा शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाली बालिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। बालिका वेईस से इस प्रगति का स्पष्टीकरण होता है :

† Education in India, 1955-56, Vol II, p 90

## तालिका २३

तालिका माध्यमिक शिक्षा में प्रगति



वर्ष	स्कूल	छात्रा संख्या	बालक विद्यालयों में पढ़नेवाली बालिकाओं का कुल प्रति शत	शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या
१९५१-५२	२,८६३	९,०८,७७५	२९-६	३६,२९५
१९५२-५३	३,००७	९,८७,६४५	२९-७	४५,५०८
१९५३-५४	३,२६८	१०,९२,६२१	३०-७	५८,८८८
१९५४-५५	३,४०२	११,९७,७००	३२-७	६५,४८१
१९५५-५६	३,९२०	१३,४०,०७१	४०-२	७२,३२८

संख्या-वृद्धि के साथ ही, स्त्री-शिक्षा में गुणात्मक उन्नति भी हुई है। लड़कियाँ अब स्कूलों में पहले की अपेक्षा अधिक टहरने लगी हैं। शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या प्रायः दुगुनी हो गयी है। तथापि अभी भी स्थिति सतोषदायक नहीं बनी जा सकती है। आज देश में १४-१७ वयस्वर्ग की लड़कियों की संख्या १२० लाख है। इस संख्या के ३ प्रति शत की शिक्षा मिल रही है। वर्तमान वास्तविकता भी दुःख है। इसमें लड़कियों की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों भी प्रायः उन्हीं विषयों का अध्ययन करनी है, जिन्हें बालक पढ़ते हैं।

उच्च शिक्षा.—उच्च शिक्षा की माँग भी जगहों में बढ़ रही है। वर्ष १९५६-५७ में लड़कियों के लिए ११५ कला तथा विज्ञान के कॉलेज, १४ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देनेवाले कॉलेज तथा १६ विदेशी शिक्षादाते कॉलेज थे। इस वर्ष ८५,८१० छात्राएँ उच्च शिक्षा पा रही थीं। विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या तालिका चौदह में देखिए :

## तालिका २४

विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा-संख्या

परीक्षा	१९८९-९०	१९५५-५६
इण्टरमीडिएट .. .. .	८,२५२	१९,९२१
बी. ए. तथा बी. एससी. .. .. .	४,६९४	८,९४८
एम. ए. तथा एम. एससी .. .. .	६४०	२,१६६
व्यावसायिक विषय (केवल डिग्री) ....	१,१६८	३,८२१

इस प्रकार गत पाँच वर्षों में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी है। इतना होते हुए भी, सम्पूर्ण देश में १७-२३ वयवर्ग की स्त्रियों में से केवल एक प्रति शत ही को शिक्षा मिल रही है। पाठ्यक्रम भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों का पाठ्यक्रम एक सा ही है। हाँ, कहीं-कहीं संगीत तथा नृत्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। सम्प्रति कुछ यह विशाल महाविद्यालय खोले गये हैं, जैसे : लेडी हरविन कालिज, दिल्ली; होम साईन्स फेकल्टी, बड़ौदा; मोहनलाल हरगोविन्ददास महिला गृह-विज्ञान कालिज, जयपुर, इत्यादि। इनके सिवा कुछ सरथाएँ केवल महिलाओं के लिए ही हैं, जैसे : एस० एन० डी० टी० महिला महाविद्यालय, बम्बई; प्रयाग महिला विद्यापीठ, अलाहाबाद; आर्यकन्या महाविद्यालय, बड़ौदा, इत्यादि।

**व्यावसायिक और विशेष शिक्षा.**—इस क्षेत्र के कालिज स्तर में विशेष उन्नति हुई है। सन् १९५६-५७ में १२,७७३ लड़कियाँ यह शिक्षा पा रही थीं। इनमें से सर्वाधिक छात्रा-संख्या ४,६६१ और शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालयों की थी। इसके पश्चात् डाक्टरी कालिजों की छात्रा-संख्या ४,५७७ और ललित कला महाविद्यालयों की छात्रा-संख्या २,११० थी। स्कूल-स्तर में छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ती ही रही। आज लगभग तीस हजार महिलाएँ शिक्षिका-प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षित हो रही हैं। स्वाधीन भारत में, स्त्रियोचित एक नवीन शिक्षण-संस्था अर्थात् 'ग्राम-सेविका-

प्रशिक्षण केन्द्र' का आविर्भाव हुआ है। आज भारत में ऐसे ४३ केन्द्र हैं। इनमें मैट्रिक पास छात्राएँ प्रविष्ट होती हैं। पाठ्यक्रम डेट वर्क का होता है। प्रथम वर्ष में कृषि तथा गृह-विज्ञान मिश्रितया जाता है, और अन्तिम वर्षार्द्ध में प्रमाण पद्धति का साधारण ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षित ग्राम-सेविकाएँ सामुदायिक विकास खण्डों में सेवार्थ नियुक्त होती हैं।

**प्रांठ शिक्षा**—सन् १९४७-५७ में स्त्री-प्रीट-शिक्षा की सच्चे अर्थ पर उल्लेख उपनिर्णय है। सन् १९५७ में एकत्र १,४५,१३९ महिलाएँ ४,७१६ शिक्षा-केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। एक सरकारी रिपोर्ट का कथन इस प्रकार है :

देखा गया है कि क्या गाँव और क्या गाँव—गर्भव—विकाशिता मितियों में समाज शिक्षा पाने की उत्तम आधार है। जहाँ वहाँ उन्हें ऐसी शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ, उसका लाभ उन्होंने पूरा लिया। †

**गृह-शिक्षा**—पालिका विद्यालयों की संख्या अत्यधिक होने के कारण, हमारे देश में गृह शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। सन् १९५५-५६ में विभिन्न शिक्षा-स्तरों में गृह शिक्षा पानेवाली छात्राओं की संख्या का कुल छात्राओं की संख्या का इस प्रकार प्रति हान था : प्राथमिक—७९.२, माध्यमिक—४०.२, उच्च तथा विज्ञान कालिब—५३.१, एवं व्यावसायिक तथा विशेष शिक्षाशाला कालिब—६४.३। प्राथमिक तथा कालिब स्तरों में, गृह-शिक्षा का विशेष विरोध नहीं है। कारण प्राथमिक पालिकाओं में कालिकाएँ निरी बच्चियाँ रहती हैं, तथा कालिकाओं में पहुँची हुई लड़कियाँ अपने आपको बहुत कुछ नियमित बनना सीख जाती हैं। पर माध्यमिक स्तर में गृह शिक्षा वांछनीय नहीं है। विशेष अवस्था के कारण कृषि पालिका-कालिकाएँ इस स्तर में अनेक नैतिक दुर्घटियों पर देखती हैं। पर जब तक लड़कियों के लिए स्वयंसेवक एवं कालिब पद्धति नहीं हो जाती है, तब तक गृह शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए।

### आलोचना

**एक सर्वानुमति-बोध**—यह पढ़ते ही बनकर या चुका है कि भारतीय नारी प्रगति राष्ट्रीय कल्याण के चक्र-स्वरूप हुई है। देश-देश का हीरा लेकर भारत के अनेक शुद्ध तथा शुद्धियों एवं गुरु में रंग मिली। उन्होंने इस देश की रमणियों के समस्त एक नवीन आधार प्रदान किए, तथा पश्चिम समाज को बहिनमुख किया। यद्यपि यह प्रगति सामाजिक अन्तर्गत से संचालित था, तथापि यह हीनता एवं अन्तिमता का। हमने वह पक्ष तथा अनेक नई, जो पश्चिम नारी-अन्तर्गत में पाई जाती है।

आज इस देश में नारी और पुरुष का समान अधिकार है। भारतीय संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे, और अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे। गत दो विश्व युद्धों ने स्पष्ट कर दिया है कि नारी अब अबला नहीं है, वह 'बहुबल धारिणी' है। वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर अब जीविकोपार्जन करने लगी है। आज वह पिछड़ी नहीं, बल्कि अग्रगामीनी है। कार्यालयों में नारी-बाहिनी देखकर लोगों को दङ्ग रह जाता पड़ता है। निम्न लिखित तालिका में कुछ क्षेत्रों में कार्य-रत महिला-कर्मचारियों की (सन् १९५७ की) संख्या दी जाती है :

तालिका २५  
कतिपय क्षेत्रों में नारी†

क्षेत्र	संख्या
राष्ट्रीय प्रशासन ... ..	२,७२,४८१
शहरी तथा स्वास्थ्य ... ..	७९,६२५
शिक्षा तथा अनुसन्धान ... ..	१,१८,४९१
बाल विभाग ... ..	१,०४७
टेलीफोन विभाग ... ..	२,६२१
पुलिस ... ..	४,१२९
बन्दूक तथा फनिंग ... ..	८,९५९

**स्त्री-शिक्षा का आदर्श.**—उपर्युक्त विवरण इस बात का सूचक है कि महिलाएँ पुरुषों के साथ जीवन-यापन के लिए मुकामला कर रही हैं। वे पुरुषों से किसी भी अङ्ग में हीनतर नहीं हैं। गणधारणन आयोग ने कहा ही है, “वे कोई भी माहिरिक कार्य उसी प्रकार सर्वाङ्गपूर्ण सम्पन्न कर सकती हैं, जिस प्रकार पुरुष करते हैं। नर और नारी की योग्यता में विशेष कुछ प्रभेद नहीं है।”† पर इसके साथ-ही प्रश्न उठता है कि स्त्रियों की शिक्षा का आदर्श क्या होना चाहिए। इस विषय में दो विरुद्ध मत हैं। प्रथम पक्ष का मत है कि नारी का स्थान घर में है। इस कारण उनका शिक्षा पुरुषों से भिन्न हो। द्वितीय पक्ष का मत है कि मनुष्य जीवन एक गाड़ी के समान है, जिसके नर और नारी दो पहिये हैं, अतएव दोनों की शिक्षा समान हो।

दोनों पक्षों का कथन बहुत कुछ सत्य है। परम्परा से भारत में गृहणी सद्गृहिणी बन कर बाया और बननी के रूप में इस देश की उन्नति करती रही है, अतएव यह ही उसका प्रधान रंग मन्त्र है। ऐसी स्थिति में स्त्री-शिक्षा के पाठ्य-क्रम का ध्येय यह एवं परिवार की उन्नति होना चाहिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि ये गृह-रूपी कबूतरगाने में बन्द रहा करें, उन्हें मुक्त-वायु सेवन करने न दिया जाय, एव पारिवारिक आर्थिक अवस्था खोचनीय होने पर भी, उन्हें बसाने का अवसर न दिया जाय। जहाँ स्त्रियों पुरुषों के साथ-साथ एक ही पाठ्यक्रम का अभ्यास कर जीवन-यात्रा में उनसे प्रतियोगिता करना चाहती हैं, उनके लिए भी कोई क्वापट न हो। वर्तमान शिक्षा में अनेक दोषों के रहने हुए भी इस शिक्षा ने सरोजिनी नायडू, विद्यालक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकुमार सरोजिनी देविसो को समुद्भूत किया है। परन्तु इसका यह अर्थ कहाँ नही है कि ऐसी शिक्षित नारियाँ अपने घर के प्रति उदासीन हो। नारी घर की अभिजाती देवी है। नारी ही पत्नी-रूप में पति की सहयोगिनी और पगमर्दानात्री बनकर उसे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर करती है, तथा गृह-रथ का सुमन्दायन करती हुई राष्ट्र-निर्माण का मार्ग परिष्कृत करती है।

इस यह कहाँ नही चाहते हैं कि आज शिक्षित नारी बेकारी के दण्ड में फँस जावे। बंगाल की एक शिक्षा रिपोर्ट ने बीन करे पूर्व चेतावनी दी थी : “हमें शिक्षित पुरुषों की बेकारी में शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि स्त्री शिक्षा का भी यही परिणाम न निकले। हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली के दोषों को हमें दूर करना चाहिए।”





शिक्षाजनक करना चाहें, और उसके द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति तथा अपना मानसिक विकास करने का विचार रखती हों। ऐसी महिलाओं को माध्यमिक स्कूलों में भरती करने की राशियों को एकदम इतना चाहिए तथा उन्हें शालान्त परीक्षा में प्राइवेट बैठने देना चाहिए। अनेकों को आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत हो सकती है, अतएव उनके लिए उचित वृत्ति एवं मुफ्त शिक्षा वाञ्छनीय है। राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् की पहली बैठक में यह तय हुआ कि प्रोटेक्स्ट्रियों को मिडिल तथा मैट्रिक शिक्षा देने के लिए छोटे पाठ्यक्रम तैयार करके ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे १०० गांवों के एक सत्र में इस प्रकार के दो पाठ्यक्रम पूरे किये जा सकें।

**उच्च शिक्षा.**—उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष सुधार की आवश्यकता है। कई विश्वविद्यालयों में यह-विज्ञान का अध्ययन आरम्भ हुआ है, पर इस विषय के हेलिने कालिब्र ही हैं। इसके सिवा, पाठ्यक्रम में विविध ललित-कलाओं का समावेश की आवश्यकता है, जैसे : चित्रकारी, संगीत, नृत्य, नाट्य-कला, इत्यादि। ऐसे विषयों के अध्ययन से नारीत्व प्रस्फुटित होने की विशेष सम्भावना है।

मृदाय योजना-काल के दौरान में गाटे आठ लाख स्त्री-कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इन कार्य के लिए ऐसी यशस्वी नारियों की आवश्यकता होगी, जिनकी माध्यमिक शिक्षा समाप्त हो चुकी हो। इनके लिए अल्प-कालिक टोच कोर्सों का आयोजन किया जावे। स्त्रियों के उन्मुख नौकरियों के अनेक मार्ग खुलने जा रहे हैं, जैसे : प्रसू-शिक्षिका, चाची, घाय, प्राग-मोक्षिका, स्टेशनमाफर, आदि। इस ओर महिलाओं को अधिकतर लीकना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस ओर महिलाओं का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है।

**निम्न शिक्षा प्रशिक्षण.**—नारियों स्वभावतः अध्यापन-कार्य सुचारुतापूर्वक कर सकती हैं, परन्तु देश में स्त्रियों का अल्पतरु प्रति शत शिक्षिकाओं का है : प्राथमिक स्तर १६.८ प्रति शत, मिडिल स्तर १७.७ प्रति शत, एवं हाईस्कूल स्तर १९ प्रति शत। इनमें से अनेक शिक्षिकाएँ तो स्कूलों के विद्यालयों में काम कर रही हैं, अतएव स्त्रियों के अधिकतर शिक्षक पुराने हैं। वे स्कूलियों की आवश्यकताओं को पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं।

नारी का हृदय कल्पलव में ओत-प्रोत रहता है। प्राथमिक तथा पूर्व-प्राथमिक स्तरों का अध्यापन-कार्य स्त्रियों को ही सौमना चाहिए। अतएव स्कूलों में यह स्तरों के दौरान में फरह लाल शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, यदि पूर्व-प्राथमिक

तथा प्राथमिक स्कूलों में केवल महिलाएँ ही नियुक्त हैं। परन्तु शिक्षित महिलाएँ शिक्षिका बनना पसन्द नहीं करतीं। इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, शिक्षकों का वेतन आकर्षक नहीं है। द्वितीयतः, महिलाएँ घर छोड़कर बाहर, विशेषकर देहात में, नहीं जाना चाहती हैं। तृतीयतः, शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का पर्याप्त रूप में प्रयत्न नहीं है। इन अमुविधाओं को दृष्टिगत हुए यह आवश्यक है कि शिक्षिकाओं को ठीक वेतन दिया जाय, ताकि शिक्षित लड़नाएँ इस ओर आकर्षित हों। यदि वे पूर्ण समय तक कार्य न करना चाहें, तो वे आशिक काल के लिए ही नियुक्त की जावें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की पढ़ी-लिखी स्त्रियों को भी इस कार्य के लिए रोज़रखा दितकर है। यह भी देखा गया है कि अभ्यापिकाएँ बहुधा अकेली रहने के लिए दिक्कतवादी हैं। यह ठीक ही है। इस कारण स्थान स्थान पर संयुक्त-गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ कुछ शिक्षिकाएँ एक साथ रह सकें।

**प्रौढ़ शिक्षा.**— इस विषय की विवेचना दसवें अध्याय में की जावेगी। यहाँ यह बतलाना उचित है कि प्रौढ़ाओं की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण, पुरुष की शिक्षा एक व्यक्तिमात्र की ही शिक्षा है, किन्तु नारी की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। स्त्रियों को चाहिए बच्चों के पालन-पोषण, सुचि-कर्म तथा परिवारिक कार्य का ज्ञान। उन्हें घर संभालना तथा सुधारना है। वह गृहिणी है, जननी है। राष्ट्र के निर्माण में उसका बहुत बड़ा हाथ है।

### वपसंहार

इस देश में नारी-जागरण पूर्ण रूप से हो चुका है। सैकड़ों बपों की सुपुता नारी ने पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर शुभ जागरण को प्राप्त किया है। इस सभ्यता से वह इतनी प्रभावित हुई है कि वह घर की चहार दीवारी से निकलकर सामाजिक राजनैतिक और साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करने लगी है। वह पुरुष की सहयोगिनी बनकर प्रति पल कदम बढ़ाती हुई, उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँची रही है।

पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमारे देश की स्त्री-शिक्षा पद्धति पर लग रही है। भारतीय रमणियों स्कूलों तथा कालिजों की ओर दौड़ रही हैं, जहाँ उन्हें पुरुषोचित पाठ्यक्रम सिखाया जा रहा है। पाश्चात्य देश भी शिक्षा के इस दौप को अनुसर कर रहे हैं। इंग्लैण्ड की एक सचकारी रिपोर्ट का कथन है, “यद्यपि इस शिक्षा के द्वारा नारी में एक नवीन जीवन का संचार हुआ है, पर वह अपनी सुदृम्भा, सुकोमल

प्रवृत्ति धीरे धीरे खो गयी है।”<sup>१</sup> हमें इस चेतावनी का लाभ उठाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि स्त्री अपनी नारी-सुन्दर लज्जा को खो बैठे। पतजी ने कहा ही है,  
 “आधुनिक ! तुम नहीं कुछ अगर नहीं मिर्फ तुम नारी।”

और न हम यही चाहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के परिणाम-स्वरूप नारी अब स्वच्छन्द-विहारिणी तितली-का-सा रूप धारण कर यहाँ-वहाँ विहार करने लगे। भारतीय नायियों का मश आदर्श रहा है मद्गृहिणी बनकर माता एवं स्त्री के रूप में राष्ट्र की सेवा करना। साम्प्रदायिक भारतीय लज्जा गार्हस्थ्याश्रम को कैसे भूल सकती है ! हमें पाश्चात्य देशों के दृष्टान्त से लाभ उठाना चाहिए। इन देशों में तो जैसे पारिवारिक जीवन ह्रास हो रहा है, और उसके बदले क्लब तथा होटल जीवन का प्रसार हो रहा है। हमें नीर-क्षीर-विवेकी बनकर कर्तव्य-पथ का अनुकरण करते हुए, पश्चिम से ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी मद्भाव को ग्रहण करना है।

परम्परा से हमारे देश में नारी के जीवन-ग्रन्थ के चार अध्याय रहें हैं : पुत्री, भगिनी, भार्या तथा माता। वर्तमान काल तक नारी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप में अपना सुयोग्य मन्तवि-सुमनों-द्वारा राष्ट्र-निर्माण के हेतु न जाने कितना कीर्ति-मकरन्द विकीर्ण किया है। आज वर्तमान की शाकी भी समुग्ग्वल दृष्टिगोचर हो रही है। नारी स्वातन्त्र्य मोक्ष पर आरोहण कर राष्ट्रोन्नति की ओर शनैः शनैः अग्रसर हो रही है। अपनी भटान्त्रलि हम नारी को सादर अर्पित करते हैं। कविवर ‘प्रसाद’ की अमृतमयी उक्ति हमारे कर्ण-कुरुर में ध्वनित हो उठती है :

नारी, तुम केवल धृष्ट हो,  
 विश्वास-वस्तु-जन्म-मद-तल में;  
 पीयूष श्रोत ही बना करो,  
 जीवन के समस्त हृद-तल में।

<sup>१</sup> H. M. S. O. *Differentiation of Curricula, etc* London,  
 H. M. S. O. 1923, p. 13.

## आठवाँ अध्याय

### प्राविधिक शिक्षा

#### प्रस्तावना

क्रिस्ती सप्तम भागत अपने शिल्प एवं विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। महेंद्रगोदार ध्वंसावशेषों के अवलोकन से पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को शहर निर्माण, सिविल इंजीनियरिंग तथा मकान-निर्माण का विशेष ज्ञान था। मग्नेट स्टोन तथा नहर का उद्भव है। अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व हमारे देश का इत्यात सारे विश्व में विख्यात था। स्वदेश लौटते समय सिकन्दर यहाँ से इत्यात लाद कर यूनान ले गया था। तत्पश्चात् इस देश के प्राविधिक ज्ञान का धीरे धीरे क्षय होता गया।

जहाँ एक ओर भारत की प्रगति अवनति होती गयी, वहाँ दूसरी ओर अन्य देशों की प्रगति हुई। दो सौ वर्ष पूर्व अमेरिका एक नव देश गिना जाता था। आज वही देश विश्व का सिमरौ है। वहाँ पर खाद्य-सामग्री के उत्पादन की इतनी प्रचुरता है कि ऊँची कीमत कायम रखने के लिए ज्वार और भुझ जला दिये जाते हैं तथा दूध नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। पचास वर्ष पूर्व जापान भी हमारे देश से बहुत पिछड़ा हुआ था। इस स्वल्पावधि में ही जापान ने अपनी कृषि-उद्योग विषयक अनीघ उन्नति की और हम सोते ही रहे। देखते-ही-देखते सोवियट रशिया का रूप बदल गया। एक पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश ने अपनी उन्नति करके सारे ससार को चन्द्रमा तक पहुँचाने का मार्ग दिखा दिया है।

हमारी अवनति के अनेक कारण हैं। प्रथमतः, यहाँ औद्योगिक ज्ञान वश या परिवारगत ही हुआ करता था। द्वितीयतः, वर्तमान युग में प्राविधिक शिक्षा की पर्याप्त उपेक्षा की गयी थी। इस ओर सरकार का ध्यान अभी-अभी गया है। सन् १९४७ तक इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था। तृतीयतः, अभी अभी तक प्राविधिक शिक्षा अल्प-मति बालकों के लिए ही उपयुक्त समझी जाती थी। विश्वविद्यालयीय शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती

थी, फिर माध्यमिक शिक्षा का, और उसके बाद प्राविधिक शिक्षा का नम्बर आता था। युगोप में भी यही स्थिति थी। आरम्भ में तरुनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं जाता था। कार्टिगल न्यूमैन का कथन है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष स्थान न हो।

आज समय ने पलटा स्वाया है। फलतः हमारे देश में इस समय प्राविधिक शिक्षा की सर्वाधिक माँग है। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए माता-पिता अपनी सन्तान को यही—प्राविधिक—शिक्षा देना चाहते हैं। कारण, दिल्ली तथा प्राविधिकों की मासिक आय पर्याप्त उच्च होती है। आधुनिक सम्पत्ता मशीन, शक्ति तथा ऊर्जा पर निर्भर है। यह जमाना एटम बम का है। एक दार्शनिकाली राष्ट्र भी इसका सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार दारोमिक बल का मान घट रहा है तथा वैज्ञानिक ज्ञान का आडर बढ़ रहा है।

भारत में आज उठकर खड़े होने का प्रयत्न कर रहा है। हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। आज यह सभी अनुभव कर रहे हैं कि देश की गरीबी दूर करने के लिए तथा बेकारी की समस्या के निराकरण के लिए हम शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके बिना न हम कृषि की उन्नति कर सकते हैं, न उद्योग बढ़ा सकते हैं और न अन्य गण्यों का मुकाबला ही कर सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार की अनेक योजनाएँ, देश के सामने हैं। इस अध्याप में इन सब बातों पर विचार किया जायगा।

### ब्रिटिश शासन काल में प्राविधिक शिक्षा

**भूमिका.**—प्राविधिक शिक्षा के कई रूप हैं—औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा शिल्प विज्ञान। यह शिक्षा दो स्तरों में दी जाती है : बालेज तथा विश्वविद्यालय, और स्कूल। अमेरिका के शासन-काल में, हम शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। यह काल मुख्य तीन समयों में विभक्त किया जा सकता है : (१) १८००-१८५७, (२) १८५७-१९०२ और (३) १९०२-१९४७।

**प्रथम उपकाल (१८००-१८५०).**—ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कुछ हनी गिनी सम्पादों स्थापित हुई। इनके खोलने का मुख्य उद्देश्य सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र था। अनेक शासन-काल में कंपनी को टारगटों, इंजीनियरों तथा परिदृष्टिक बमेकारियों की आवश्यकता थी। इसी प्रेरणा के कारण इन संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, न कि उन दिनों के लिए। इस अवधि में पहली, कलकत्ता तथा मद्रास में इंजीनियरिंग

कायित्व समारोह: १८४७, १८५७ तथा १८५८ में म्पायित हुए। पुने में एक इंजीनियरिंग हाग सन् १८५४ में गोन्य गया।

**द्वितीय उपकाल (१८५०-१९०२).—**प्राविधिक शिक्षा का प्रमगद विद्यम सन् १८५७ के बाद हुआ। सन् १८६६ में, पुना इंजीनियरिंग हाग एक कायित्व के रूप में वदित हुआ। सन् १८५७ में विस्योमिया युवर्णु टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना कायद में हुई। यद संस्था कायद में स्थित पुतग्रीपरो के लिये कुशज कारोगरो के प्रशिक्षण के निमित्त उद्घाटित हुई थी।

इंस्ट इण्डिया कम्पनी औद्योगिक शिक्षा के प्रति भी उन्नमीन थी। हों, ईसाई मिशनरो ने कई औद्योगिक स्कूल अवसर स्थापित किये थे। सन् १९०१-१९०२ में भारत भर में कुल चार इंजीनियरिंग कायित्व तथा अस्सी तकनीकी या औद्योगिक स्कूल थे। स्कूलों में पुरानी परिपाटी के अनुसार कई देशी कारीगरी (यदईगिरी, लुहारी, आदि) सिखायी जाती थी।

**तृतीय उपकाल (१९०२-४७).—**उद्योगवीं शताब्दी के अन्तिम दशान्द में देश में प्राविधिक शिक्षा की माँग आरम्भ हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन (सन् १८८७) में यद प्रस्ताव पारित हुआ कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए सरकार तकनीकी शिक्षा की ओर ध्यान देवे। तब से कई परवर्ती अधिवेशनों में भी प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की माँग बुलन्द की गयी। सरकार हाथ-पर-हाथ रखकर मोन न रह सकी। उसने बजीके देकर कुछ चुनिन्दे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युरोप तथा अमेरिका भेजना आरम्भ किया।

तथापि अनेक प्रगतिशील भारतवासी इस वृत्ति-व्यवस्था मात्र से सन्तुष्ट न हुए। सन् १९०४ में कलकत्ता में 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षा-प्रसार-संघ' नामक एक संस्था की स्थापना हुई। कुछ चुने हुए सुयोग्य भारतीय विद्यार्थियों को शिल्प एवं उद्योग सम्बन्धी उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश भेजना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' ने बादवपुर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजिकल कालिज की स्थापना की। इस संस्था ने मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स सन् १९०५ में शुरू किया, तथा केमीकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स सन् १९२१ में आरम्भ किया। पर डिग्री कोर्स आरम्भ करने का श्रेय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालिज को मिलता है, जिमने सन् १९१७ में मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मेटलर्जी का अध्यापन आरम्भ किया। स्वतन्त्रता-

## प्राविधिक शिक्षा

प्राप्ति के समय भारत में अष्टाईस इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक कानिब्र थे। इसी में कई टेक्नोलौजीकल कॉलेज स्थापित हुए। इनमें से मुख्य हैं : इंडियन स्कूल ऑफ मैनेज, धानबाद; इंग्लिश इंजीनियरिंग टेक्नोलौजीकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर; स्कूल ऑफ टेक्नोलौजी, बम्बई, इत्यादि।

इस प्रकार गरीब तथा जनता-दोनों-के प्रथम स्वरूप प्राविधिक शिक्षा विभाजित हो चला। इस कार्य को दो अन्य घटनाओं के कारण और भी प्रेरणा प्राप्त हुई। शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी-समस्या की गहराई के कारण, लोगों का ध्यान तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। इन शिक्षा के प्रति जो सर्वांगीण विचार थे, वे बदल गये, और लोगों में इस शिक्षा की प्राप्ति की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी घटना द्वितीय विश्व युद्ध की थी, जिसने इस प्राविधिक शिक्षा में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध की तात्कालिक मांगों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक फैक्टरी को तकनीकी प्रशिक्षण-केन्द्र बनाना पड़ा। इस प्रकार इस देश में प्राविधिक शिक्षा की स्थापना हुई।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के कुछ ही वर्ष पूर्व भारत सरकार ने एक देश-व्यापी प्राविधिक शिक्षा योजना बनाना आरम्भ किया। उसकी प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :

- ✓ १. औद्योगिक शोध-कार्य की सहायता के लिए 'वैज्ञानिक औद्योगिक शोध-परिषद्' की स्थापना (सन् १९४०)।
२. दिल्ली पॉलीटेक्नीक का आरम्भ (सन् १९४१)।
३. उच्च तकनीकी शिक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में परामर्श के लिए भी नज़िबुल्लाह सरकार की अध्यक्षता में टेक्नोलौजिकल कौन्सिल का नियुक्ति (सन् १९४५)। यह समिति 'सरकार कमेटी' के नाम से जाना जाता है।
४. ३० नवम्बर, १९४५ में 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्' की स्थापना।
५. समूहों देश की सरकारों को देखते हुए विभिन्न स्तर के शिक्षण, संशोधन तथा प्राविधिकों की एक सूची तैयार करके शिक्षण तथा मानवीय शक्ति समिति' की नियुक्ति (सन् १९४७)।



## स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा

**भूमिका—**स्वाधीनता मिश्रण के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा के विस्तार की पूर्ण दम में चेष्टा हो रही है। वास्तव, यह स्पष्ट है कि देश के विकास क्षेत्र की प्रगति—कृषि, उद्योग, वातावरण, कला विनायक, कला उद्योग, कला व्यापार, कला कलाकार—इसी शिक्षा पर निर्भर है। प्रथम योजना का उद्देश्य था, देश के प्रत्येक भाग में रिपरी मूल पर प्राविधिक शिक्षा बढ़ाना तथा इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजीकल के इन राष्ट्रीय प्रयोगों का आरम्भ करना, गिनती स्वरूपता इस देश में नहीं थी। द्वितीय योजना-काल में औद्योगिक प्रसार विचार दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक के द्वारा पूर्ण योजना में जो कार्य शुरू किये गये, उन्हें विस्तारित, समुन्नत तथा विस्तृत करना है; और दूसरे कार्य-क्रम के अनुसार इस आधार में औद्योगिक शिक्षा के नये कार्य शुरू करना तथा नयी संस्थाएँ स्थापित करना है। द्वितीय योजना-काल में ५२ कंग्रेड करके तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किये गये हैं। प्रथम योजना-काल में इस शिक्षा पर केवल तेईस करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अब तृतीय पंच-वर्षीय योजना की योजना हो रही है। उनमें भी तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा के व्यापक रूप को समझने के लिए, हमें इन विषयों का ज्ञान आवश्यक है : (१) प्रशासन, (२) शिक्षा-व्यवस्था, (३) प्राविधिक शिक्षा का विस्तार और (४) नवीन योजनाएँ।

**प्रशासन—**१० फरवरी, १९५८ तक प्राविधिक शिक्षा का प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय के एक विभाग के मातहत था, पर अब इसका सम्बन्ध केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और सृष्टि मन्त्रालय से है। प्राविधिक शिक्षा समस्याओं पर विचार करने के लिए तथा नवीन योजनाओं को चला देने के निमित्त भारत-सरकार समय-समय पर विशेषज्ञों की समितियाँ नियुक्त करती रहती है।

तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्यीय सरकारों को 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद' (अभाप्रक्षिष) परामर्श देनी है। यह परिषद विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों-द्वारा संगठित होती है : सदस्य, विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालय, राज्य सरकारें, अन्तर्विद्वयविद्यालयीय मण्डल तथा प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न गैरसरकारी संस्थाएँ (उद्योग, वाणिज्य, श्रम, व्यवसाय, इत्यादि)। कुल सदस्यों की संख्या ० है। दैनिक कामकाज एक समन्वय मण्डली चलाती है।

प्राविधिक शिक्षा के प्रवर्धन के लिए, परिषद ने चार विभागीय समितियाँ— उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम—नियुक्त की हैं। ये अपने-अपने विभागों की जरूरतों का अध्ययन करती हैं और उनके अनुसार अपनी योजनाएँ चलाती हैं। इन समितियों के अतिरिक्त परिषद ने मात्र पाठ्यक्रम-मण्डल विविध विषयों के सुधार के लिए स्थापित किये हैं : सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा कैमिकल इंजीनियरिंग, यागिज, केमिकल टेक्नोलॉजी एवं एप्लाइड आर्ट्स। प्रत्येक विवर के राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा मशीनिकल पाठ्यक्रम अब तैयार हैं। परिषद ने एक विनोदक समिति स्थापित कर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की है।

परिषद की बैठक प्रति वर्ष एक बार होती है। लेकिन सम्पूर्ण समिति तथा विभागीय समितियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये अपनी आस-सुआना के अनुसार बिछी भी समय बैठ सकती हैं।

शिक्षण-पद्धतियाँ. प्रत्येक उद्योग में तीन प्रकार के कारियों की जरूरत पड़ती है : (१) मैनेजर (२) पारदर्शक कर्मचारी एवं (३) कार्यगर। इसी प्रकार अनुसार प्राविधिक शिक्षा तीन स्तर में दी जानी है : डिप्ली, डिप्लोमा तथा मशीनिकल।

डिप्ली बोर्स. डिप्ली बोर्स की शिक्षा वाणिज्य तथा विधिविचार में दी जाती है। इस पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट का उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम शामिल होता है। स्नातक बोर्स २२ ४ वर्ष का होता है, पर इस बोर्स में प्रवेश के पूर्व उच्च माध्यमिक शिक्षाओं को एवं वर्ष पूर्व स्नातकवर्ष पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है।

स्नातकोत्तर बोर्स की अवधि दो साल की होती है। कुछ वर्ष दूर हमारे देश में इस पाठ्यक्रम का अभाव था। इस बोर्स को दूर करने के लिए 'अनप्लेन' ने एक विनोदक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों पर 'अनप्लेन' ने खुले हुए दो सालों में तैयार दिवस के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार करना स्वीकार कर लिया है। इस ही में 'अनप्लेन' की सिफारिशों पर आज हमारे देश में स्नातकोत्तर की शिक्षा की पद्धति की प्रगति की मजदूरी करने और स्नातकोत्तर के लिए एक अनुसंधान की स्थापना के बारे में सिफारिश करने के लिए एक उच्च अतिरिक्त

समिति नियुक्त की है। वैज्ञानिक अनुसन्धान और मस्कूनि मंत्रालय के सचिव प्रो० ए०-एस० धैकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति स्नातकोत्तर ट्रेनिंग-केन्द्रों और अनुसन्धान शालाओं का दौरा करेगी तथा वहाँ के प्रधानों एवं अनुभवी प्रोफेसरों से विचार-विमर्श करेगी।†

**डिप्लोमा कोर्स.**—डिप्लोमा कोर्स में विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा के बाद भरती वि-  
जाते हैं। इसका दौरान तीन वर्षों का होता है। यह शिक्षा बहुधा पॉलीटेक्नीक तथा तकनीकी स्कूलों में दी जाती है। सफलभूत विद्यार्थीगण विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में परितोषक कर्मचारी नियुक्त होते हैं।

**सर्टीफिकेट कोर्स**—कारागार दो प्रकार के होते हैं : (१) कुशल कारागार और (२) अर्द्ध-कुशल और सामान्य श्रमिक। पहले प्रकार के व्यक्तियों को तकनीकी हाई स्कूल अथवा तकनीकी स्कूल, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल एवं उत्तर-युनिवर्सिटी स्कूलों में ट्रेनिंग मिलती है। पर अर्द्ध-कुशल अथवा सामान्य श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए, हमारे देश में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आशा है कि प्रवर युनिवर्सिटी स्कूल इस माँग को पूरा करेंगे। किसी-किसी उद्योग संस्था ने अपने श्रमिकों के लिए अंश कालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

**प्राविधिक शिक्षा का विस्तार.**—स्वाधीनता मिशन के पश्चात् भारतीय शिक्षा में सबसे उल्लेखयोग्य विस्तार प्राविधिक शिक्षा का हुआ। सन् १९४७ तक, हमारी तकनीकी संस्थाओं से पर्याप्त रूप में शिक्षार्थी नहीं निकलने थे, तथा शोध एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम निदान नहीं था। उग यह पूरे देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षावाले २८ डिग्री-संस्थान तथा ४१ पॉलीटेक्नीक संस्थान थे। सन् १९५७ में डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थानों की संख्या क्रमशः ७४ तथा १२९ पहुँची।

इसी अवधि में छात्र-संख्या में भी विशेष वृद्धि हुई। सन् १९४७ में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्सों में क्रमशः २,९४० तथा ३,६७० विद्यार्थियों के प्रवेश की स्वीकृति दी जा चुकी थी। सन् १९५७ में यही संख्या त्रिगुनी हो गयी। याने ९,७७८ डिग्री कोर्स के तथा १५,९९५ डिप्लोमा कोर्स के हो गये। यद् अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजना-काल के अन्त में प्राविधिक संस्थाओं में डिग्री-पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष क्रमशः १३,००० तथा २४,००० विद्यार्थियों की प्रवेश

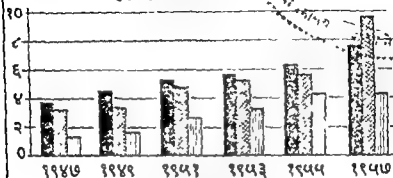
† भारतीय समाचार, १५ नवम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१९।

‡ भारत, १९५९, पृष्ठ ८३।

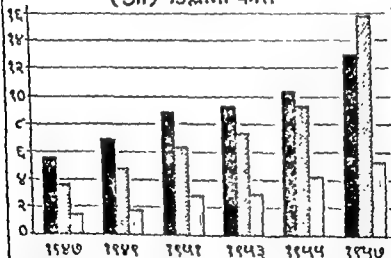
# प्राविधिक शिक्षा की प्रगति

१९४७ से १९५७

(अ) डिग्री कोर्स



(आ) डिप्लोमा कोर्स



संस्थाएँ  
(दस)

स्वीकृत छात्र-संख्या  
(हज़ार)

उत्तीर्ण छात्र-संख्या  
(हज़ार)



**नवीन योजनाएँ.**—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में, प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ चलायी हैं। इनमें से मुख्य ये हैं : (१) भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर की प्रमोदति, (२) उच्चतर प्रौद्योगिकी मर्यादों की स्थापना, (३) नवीन पाठ्यक्रमों का आरम्भ. (४) कृषि की व्यवस्था, (५) विज्ञान मन्दिरों की स्थापना एवं (६) अनुसन्धान।

**भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर**—इस प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना सन् १९११ में हुई, और सभी से यहाँ उच्चतर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। इस संस्था में ३,००० से अधिक स्नातक शास्त्री, भौतिकविद्, इंजीनियर, भूगर्भ-शास्त्री इत्यादि अभी तक निकले हैं। ये भारत की उच्चतम शिक्षा-संस्थाओं, सरकारी ओइशे तथा औद्योगिक केन्द्रों में काम कर रहे हैं। सन् १९४६ में भारत-सरकार इस संस्थान को उन्नत अनुदान दे रही है। मई, १९५८ में, यह संस्था विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत हुई। इस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का समुचित प्रबन्ध है।

**उच्चतर प्रौद्योगिक संस्थाएँ.**—हमारी पञ्चवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों के विस्तार पर ध्यान दिया है। इस कार्य के लिए उच्चतर प्राविधिकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'सरकार-समिति' ने चार उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं — भारत के प्रत्येक विभाग में एक — की स्थापना की निष्कारिणी की थी। 'अभ्यर्था' ने इन मुद्दों का अनुमोदन किया। सन् १९५१ में सर्वे प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बलराने के पास खड़गपुर में स्थापित हुई। बम्बई की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में दिग्दर्शीयता करने पहले सन् १९५८ में प्रवेश हुए। खड़गपुर तथा मद्रास में दो और संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं में कुल मिलाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी।

**नवीन पाठ्यक्रम.**—'अभ्यर्था' की निष्कारिणी के फल-स्वरूप कुछ नवीन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है : मुद्रण-कला, प्रबन्ध-व्यवस्था तथा शास्त्र-ज्ञान-व्यवस्था। देश में इन विषयों के अध्ययन की माँग है, पर इनके प्रशिक्षण का उपोचित प्रबन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्यीय सरकारों के द्वारा समुचित रूप से अग्राहक, बलकता, दमरू तथा मद्रास में स्थापित चार मुद्रण-शालों में ये प्रत्येक में प्रति वर्ष २०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त आठ संस्थाओं में प्रबन्ध-व्यवस्था-शास्त्री पाठ्यक्रम लागू किये जा चुके हैं। इनके

नाम हैं : भारतीय औद्योगिकी संस्था, खड़गपुर; अर्थशास्त्र-स्कूल, दिल्ली; अर्थशास्त्र विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय; अर्थशास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल, बम्बई; भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर; समाज-कल्याण तथा कारोबार-प्रबन्ध-संस्था, कलकत्ता; और पिक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्था, बम्बई । /

दिल्ली में एक 'शहर-ग्राम-कल्पना' विद्यालय (स्कूल आफ टाउन एण्ड कंट्री प्लेनिंग) स्थापित हुआ है । इसमें उत्तर-स्नातक स्तर पर दो प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है : (१) दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा (२) एक गहन कोर्स, उन शिल्पी, इंजीनियर इत्यादि के लिए जिन्हें अपने विषय का कुछ व्यावहारिक अनुभव हो ।

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की ओर से बंगलोर में एक 'औद्योगिक अभ्यासक प्रशिक्षण संस्था' स्थापित होनेवाली है । यहाँ औद्योगिक उत्पादन का उच्चतर ज्ञान दिया जाएगा । संयुक्त राष्ट्र सघ ने इस संस्था को ९,००० डालर अनुदान देना स्वीकार किया है ।

वृत्ति.—तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध की उन्नति के लिए भारत सरकार नेगत दस वर्षों में तीन प्रकार की वृत्तियों का आयोजन किया है : प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टाइपेण्ड, राष्ट्रीय शोध शिष्य-वृत्ति-योजना तथा विश्वविद्यालयीय शोधवृत्ति । प्रथम योजना के अनुसार, खुले हुए स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी शिक्षा समाप्त करने पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए मासिक स्टाइपेण्ड मिलता है—प्रति स्नातक १५० रु. तथा डिप्लोमा प्राप्त-यत्री १०० रु. । इनके ट्रेनिंग का बन्दोबस्त सरकारी तथा विधेय गैरसरकारी केन्द्रों में किया जाता है । अभी तक १,००० स्टाइपेण्ड दिये गये हैं । द्वितीय योजना के अधीन ४०० रु. मासिक की ८० शिष्य-वृत्तियाँ तथा प्रति वर्ष यंत्र तथा अन्य साधनों के लिए एक हजार रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी है । यह योजना सन् १९५५-५६ में शुरू की गयी थी । इनके अतिरिक्त २०० रु. मासिक की ८०० शोध-वृत्तियाँ विश्वविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थाओं को दी गयी हैं ।

विज्ञान-मंदिर.—सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्षेत्रों में 'विज्ञान-मंदिर' नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं । ये केन्द्र ग्रामीण लोगों से वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं, तथा उन्हें इसके उपयोग की साधकता के विषय में समझाते हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय के मन्त्री श्री हुमायूँ कबीर

का ध्येय 'सम्पूर्ण देश में ३२० विज्ञान-मन्दिर—अर्थात् प्रत्येक जिले के लिए एक— स्थापित करना' है। प्रत्येक सरथा का सम्बन्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रहेगा।

**अनुसन्धान.**—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध के लिए भारत सरकार ने, सन् १९४२ में, 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद्' की स्थापना की थी। आज यह परिषद् वैज्ञानिक अनुसन्धान और सश्रुति सम्प्राप्त का भाग है। परिषद् शोध-सम्पन्नो में सगे वैज्ञानिकों को साहाय्य-अनुदान और योग्य व्यक्तियों को छात्र वृत्तियाँ देती तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है। सन् १९५८-५९ में परिषद् का आवसंनक व्यय ३-३१ करोड़ रुपये तथा अनुमानित पूँजीगत व्यय १-७८ करोड़ रुपये हुआ।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद में परिषद् देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित कर चुकी है। इनका विवरण इस प्रकार है : (१) केन्द्रीय ईंधन शोध समिती, जलशोष (विहार), (२) केन्द्रीय बॉच तथा कुम्भकार कार्य शोध-समिती, जादपुर, (३) केन्द्रीय लवन शोध केन्द्र, धानबाद, (४) केन्द्रीय स्वान औद्योगिकी शोध समिती, मैसूर, (५) केन्द्रीय खनिज-शोध समिती, मद्रास, (६) केन्द्रीय नमक शोध समिती, भावनगर, (७) केन्द्रीय भट्टन-शोध-समिती, दहली, (८) केन्द्रीय मीठर शोध समिती, लखनऊ, (९) केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध समिती, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), (१०) केन्द्रीय रिलुन इंजीनियरिंग शोध समिती, दिल्ली, (११) केन्द्रीय रिलुन स्थापन शोध-समिती, बराहकुटी (मद्रास), (१२) केन्द्रीय महुक शोध-समिती नदी दिल्ली, (१३) केन्द्रीय सांकेतिक सम्पत्ति शोध समिती, नागपुर, (१४) प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला, हैदराबाद, (१५) प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला जम्मू-काशी (जम्मू तथा काश्मीर), (१६) विद्युत औद्योगिक तथा औद्योगिकी सम्पत्ति, बल्लार, (१७) भारतीय जीव-समिती तथा परीक्षणक औद्योगिक-समिती, बल्लार, (१८) राष्ट्रीय धातु-कर्म प्रयोगशाला, जलशोष; (१९) राष्ट्रीय औद्योगिक प्रयोगशाला, नदी दिल्ली; (२०) राष्ट्रीय स्थापन प्रयोगशाला, पूना, १६ (२१) राष्ट्रीय दूरदर्शन-विज्ञान केंद्र, लखनऊ।

### बनियवत समितीएँ

**भूमिगत.**—इस प्रकार हमारे देश का प्रादेशिक विज्ञान की स्थापना हम सभी में हुई। इसे स्थापना-कार में हम देश के सभी विभिन्न स्तरों की स्थापना



बोधे जा रहे हैं, बड़े-बड़े कारखानों की सृष्टि हो रही है, आवागमन के साधनों में उन्नति हो रही है, नगर-पुनर्रचना चल रही है, परिवहन का विकास हो रहा है, इत्यादि, इत्यादि ।

पर इन योजनाओं को कौन तैयार कर रहा है ? इन्हें कौन चला रहा है ? खेद के साथ हमें उत्तर देना पड़ता है कि “विदेशी विशेषज्ञ” । हमें उस समय हताश होना पड़ता है, जब हम देखते हैं कि स्वाधीन होते हुए भी, ऐसे कार्यों के लिए हमें विदेशी परामर्श-दाताओं का मुँह ताकना अनिवार्य होता है । विशेषज्ञों की बात जानें दीजिए । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार विकास-कार्य बहुत कुछ हो रहा है ; पर प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में, प्रौद्योगिक प्रशासकों का विशेष अभाव है । वर्तमान जगत में एक औद्योगिक प्रशासक के लिए केवल प्राविधिक ज्ञान ही सफेद नहीं है । भाषा पर उसका ममुचित अधिकार होना चाहिए तथा उसे दकतृत्व-कला-दर्श भी होना चाहिए । उसे देश तथा विश्व की आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि इन सबका घना सम्बन्ध प्रौद्योगिक योजनाओं से है । उसे प्रशासन कार्यक्रम का अनुभव चाहिए, अन्यथा उसे लिपिकों के इशारों पर नर्तन करना पड़ता है । परन्तु उसे सबसे अधिक आवश्यकता ‘मानव-सम्बन्धी ज्ञान’ की है, क्योंकि उसकी अधीनता में कितने ही कर्मचारी कारीगर तथा अभिरु कृषा-रत रहते हैं, जिनके साथ कार्य करना तथा उनसे काम कराना असाधारण कार्य होता है । इन कठिनाइयों का अनुभव करते हुए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने यह विचार किया कि “विकास के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई सख्या में प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।”

‘अभाप्रशिव’ की चेष्टाओं के कारण हमारे देश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हाल ही में शुरू हुए हैं तथा उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं की सृष्टि हुई है । प्रशिक्षण-परिस्था के कालिब भी खुल गये हैं । आशा की जाती है कि इन उच्चतर शिक्षा के मिलने के पश्चात्, हमारे देश में भी पर्याप्त रूप में प्राविधिक प्रशासक निकलने लगेंगे ।

**संकीर्ण पाठ्यक्रम.**—पिछले शीर्षक की चर्चा में यह भी स्पष्ट हुआ होगा कि हमारे देश के प्राविधिक पाठ्यक्रम संकीर्ण हैं । उनमें केवल तकनीकी विषयों का ही प्रेश रहता है । पर एक प्राविधिक के लिए भाषा, अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान ज्ञान जरूरी है । तकनीकी शिक्षा की इन कमी को दूर करने के लिए, अमेरिका ने प्राविधिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा एक अनिवार्य विषय रखा गया है । अमेरिकी उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रेमीडेंट आयोग का कथन है :

सामान्य शिक्षा का मूल तद्देश है, व्यावहारिक योग्यता की वृद्धि इस ज्ञान के द्वारा, मनुष्य की दृष्टि-संकीर्णता दूर होनी है, कार्य कुशल बढ़नी है और यह समाज को स्वतन्त्र समझ सकता है ।।

यह प्रचलित पाठ्यक्रम के सुधार के बिना, सामान्य शिक्षा का समावेश नहीं सकता है । 'अभागाशिव' ने अपने २२ मार्च, १९५७ के अधिवेशन में यह तथ्य निरूपित किया कि एक उचित मान दण्ड नियम रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसीनिर्णय एवं टेक्नोलोजीकल की प्रथम दिग्गज के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रथम पाठ्यक्रमों में आधुनिक विज्ञान का आसक्तिजनित किया जाय । वर्तमान पाठ्यक्रम के गहन के अतिरिक्त परीक्षा का तद्देश है नवीन कौशल में विनिर्णीकृत शिक्षा का विद्या, अतिरिक्त विद्यार्थी का समावेश करना । परीक्षा में यह काम अपने पाठ्यक्रम में गहनता से किया है ।

**आज की दुनिया में साधारण ज्ञान की आवश्यकता** प्रायः भ्रष्ट कुशल सामान्य धर्मिक को भी है । बीगबी शताब्दी मशीन तथा सांख्यिक उत्पादन का विना जाता है । दिन-प्रतिदिन मशीन विज्ञान अधिकतर प्रयोजन होती जा रही है । समाज के लिए, नियम पढ़ने का ज्ञान एक अनिवार्य को भी उत्पन्न है । अत्यन्त के इच्छा-विद्या में एक मजदूर या कारीगर का काम इस समाज में अब भरी भूमि बन गया है । यदि उसे अच्छा, शक्ति तथा समाज-दायक का ज्ञान दिया जाय, तो उच्च वैज्ञानिक विकास के साथ ही उसकी उत्पादन शक्ति भी अत्यन्त उत्कृष्ट हो जिसकी श्रद्धा आवश्यकता है ।

**नये कारिगारों की माँग**—इस ज्ञान की चर्चा करने की ही एक शक्ति कि नवीन श्रद्धा के योग्य में ही नये टेक्नोलोजीकल कारिगर एवं सलारम को वैज्ञानिक स्थापित होय । ये माहुरन संस्थाओं के समाज छोटे-मोटे न होय, और जलमे बहिरंग विद्यार्थी का अध्ययन का कठोरता होय । ये प्रदर्शन होय तथा उच्च शिक्षा विद्यार्थी के प्रदर्शन का अध्ययन होय । इसी पाठ्यक्रम के अनुसार, उनमें समाज को एक प्रयोग-शाला भी स्थापना करनी पड़ेगी ।

**विद्यार्थी की कामों**—समाजों का एकदम दृष्टि के समझने उच्च शिक्षा प्रदर्शन रूप में नहीं मिलने है । किसी किसी कार्यक्रम में विद्यार्थी के लिए

होते हैं। अध्यापकों के अभाव के कारण, प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में बड़ा पहुँचने की सम्भावना है। कर्मरक्ष व्यक्तियों को अध्यापन कार्य में रोकने के लिए उचित वेतन की अवश्य जरूरत है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि तत्कालीन अध्यापकगण शिक्षण-कार्य छोड़कर इधर-उधर न भागने पावें।

कुछ वर्षों से नवीन तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस कार्य के लिए भी काफी अध्यापक नहीं मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए तथा कुछ समय तक तो हमें विदेशियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तथा हमारे कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना पड़ेगा।

**शिक्षा का माध्यम.**—२ सितम्बर, १९५६ को श्री नेहरू ने राष्ट्रीय मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि यह स्पष्ट ही है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए श्री नेहरू का अभिप्राय शायद ठीक ही है; पर भविष्य में सरकारी नीति क्या होगी, यही प्रश्न है। यदि प्राविधिक शिक्षा के माध्यम का निर्णय अनिश्चित काल तक छोड़ दिया जाय तो सभी वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा, और विज्ञान की नीति दूसरे विषयों के लिए भी चलाना पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके, मातृ-भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए।

पर विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक संस्थाओं में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य विषय रहे। इसके सिवा, भारतीय भाषाओं में, प्राविधिक साहित्य लिखने का यत्न किया जावे। यह स्मरण रहे कि चीन तथा जापान सरीखे पूर्वीय देशों में मातृ-भाषा ही प्राविधिक शिक्षा का माध्यम है, पर अंग्रेजी एवं रशियन सीखने पर विशेष जोर दिया जाता है।

**कर्म-शाला-अभ्यास.**—हमारी प्राविधिक संस्थाएँ अपने विद्यार्थियों को सर्वाङ्ग-पूर्ण कर्म-शाला-अभ्यास नहीं दे सक रही हैं। यह याद रहे कि दूसरी विद्याओं का अध्यापन तो मस्था की चहारदीवारी के भीतर हो सकता है, पर प्राविधिक शिक्षा संस्थान के अन्दर सीमित नहीं रह सकती है। मुख्य ज्ञान तो विद्यालय की कर्म-शाला तथा प्रयोग-शाला में अवश्य दिया जायगा, पर यथार्थ व्यावहारिक अभ्यास के लिए बाहरी कर्म-शालाओं, कारखानों तथा खलिहानों की शरण लेनी पड़ती है। तकनीकी शिक्षा की दक्षता बहुत-कुछ भीतरी व्यावहारिक अभ्यास के समन्वय पर निर्भर है। अनेक संस्थानों में उपयुक्त कर्म-शालाओं तथा प्रयोग-शालाओं का अभाव है। इस कारण

हमारे सहायता और भी आवश्यक है। पर यह सहायता हमारे देश में पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही है। सरकार ने सम्प्रति प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की उन्नति के लिए कुछ छात्र-वृत्तियों का बन्दोबस्त किया। पर यह यथेष्ट नहीं है। जहाँ तक बने, सरकार को अपने कल-कारखानों में व्यावहारिक अभ्यास की सुविधा देनी चाहिए। अनेक विना बजीका वाले विद्यार्थी अंश-कालिक नौकरी स्थायी फर्मों में कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कम-से-कम फायदा लाभ है : (१) विद्यार्थियों को प्राविधिक सहायता मिलनी है, (२) उनको स्वाभाविक चानावरण में व्यावहारिक अभ्यास मिलना है (३) उन्हें विभिन्न स्तर के कर्मचारियों तथा श्रमिकों से मिलने का मुअवसर मिलना है, एवं (४) काम करने-काने, उनकी स्थायी नौकरी भी ठीक हो जाती है; और शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्हें नौकरी के लिए यहाँ-वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। यह प्रथा अनेक देशों में प्रचलित है।

**उत्तर-विद्यालय-शिक्षा.**—जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त, मनुष्य को ज्ञानार्जन करने का मुअवसर रहता है। पर बहुधा भाग्यवासियों की शिक्षा स्कूल या कालिज छोड़ने के साथ-साथ समाप्त हो जाती है। विनियमक यह कथ्य एक प्राविधिक के लिए अनिवार्य है। बीसवीं शताब्दी में प्राविधिक ज्ञान की दिन प्रति-दिन उन्नति हो रही है। जो कल था, वह धात्र नहीं है; और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। अतएव एक शिल्पी या यन्त्री अपने पूर्ण ज्ञान के भण्डार निधियत बैठा नहीं रह सकता है। उसे नवीन विद्या के संस्पर्श में रहना पड़ेगा। अतएव उत्तर-विद्यालय-शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। हमारे देश में ३८ विश्वविद्यालय, ७४ डिग्री कॉमर्साली तथा १२९ डिग्रीमा-कॉमर्साली प्राविधिक स्थापण हैं। पर इनका ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। उन्हें प्राविधिकों के लिए पुनर्मौलिक कॉमर्स का आधेकन करना चाहिए, ताकि उन्हें आधुनिकतम विद्या का लाभ मिले और उनके ज्ञान में जेव न लगे।

हमारे कार्यागारों तथा श्रमिकों के लिए अश-कालिज कॉमर्स की अति आवश्यकता है। वे कॉमर्स मायेंकाल में खराबे का सकते हैं, ताकि नौकरी करने हुए भी वे अत्यन्त काम मीमे। उनकी औद्योगिक निपुणता की वृद्धि करने का यह एक अच्छा उपाय है। इसके अतिरिक्त इन लोगों की अवकाश शिक्षा का आधेकन करना पड़ेगा। इन देवर्त है कि हमारे श्रमिकों की पुनर्जाय का समर करने होकरने, बिड़ी चीने या पर निर्यात करने में कीर राया है। वरि तो बर्तमान में हुदे रहने हैं या बर्तमानों की राय में पड़े रहने हैं। परन्तु उनके इस अवकाश काय का सदुपयोग हो सकता है, यदि उनके लिए समार

शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाय। किन्तु हमारी औद्योगिक संस्थाएँ, इस ओर उदासीन हैं। अनेक पाश्चात्य देशों में मजदूरों के लिए नाट्य-शालाएँ, स्नानागार, ग्रीहा-स्थल, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है। ऐसी समुचित सुविधाओं के कारण श्रमिक अपनी थकावट को भूल जाते हैं, उनका पैसा बरबाद नहीं होता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास पूर्णता की ओर उन्मुख होता है। हमारे देश में ऐसी परिकल्पनाएँ इस समय स्वप्नवत् प्रतीत होती हैं।

श्रमिकों के लिए उत्तर-विद्यालय-शिक्षा का आयोजन पाश्चात्य देशों में जरूरी समझा जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियट रूस में किसान तथा मजदूरों के लिए अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा आरम्भ हो गयी है। शिक्षा रात्रि-शालाओं में दी जाती है। पत्र-व्यवहार-द्वारा भी शिक्षा का प्रबन्ध है। ये पाठ्यक्रम लोक-प्रिय हैं। प्रायः २०,००,००० व्यक्ति इस शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं, और १२,००,००० श्रमिक इस आयोजन का लाभ प्रति वर्ष ले रहे हैं। सरकार इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष २०० करोड़ रुबल खर्च करती है।†

**अनुसन्धान.**—स्वाधीन भारत ने अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान दिया है, तथा दस ही वर्ष में अनेक शोध-प्रयोग शालाएँ स्थापित हुई हैं। पर मोड के साथ कहना पड़ता है कि हमें मशीन, कल पुर्जे तथा अग्र-यन्त्र के लिए भी दूसरे देशों की ओर अब भी निर्भरता पड़ता है। हमारे देश की पर्याप्त सम्पत्ति बाहर बिकी जाती है, हम देश की बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सक रहे हैं, तथा उद्युक्त हथियार-औद्योगिक के अभाव के कारण हमारी योजनाओं का ठीक-ठीक विस्तार नहीं हो पा रहा है। अतएव औद्योगिक अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, उत्पादन-शोध हीनिए। इस शोध का लक्ष्य हो : (१) उत्पादनों की गुणवत्तक प्रगति; (२) माल, क्रियाओं तथा बस्तुओं की शक्ति; (३) उत्पादन-क्रिया में विचारित करना; (४) उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की तकनीकी की गैरना; (५) एवं स्वरोपजन स्थापित करना; एवं (६) केला दिक्कतों के मध्य मद्भाग पैदा करना।

इस प्रदेह क्षेत्र में संशोधन का प्रयोजन है। देश की उद्यमों को देशों की मध्य में अग्र औद्योगिक नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता अनुसन्धान की विशेष आवश्यकता है।

कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि का नवीनीकरण इस शोध के बिना नहीं हो सकता है, अतएव हमारे अनुसन्धान कक्षों में इस ओर विशेष ध्यान दें।

**सरकार, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा में सहयोग.**—अन्य शिक्षा क्षेत्र तो अपने पौर पर खड़े रह सकते हैं, पर प्राविधिक शिक्षा एककृत्य नीति का अवलम्बन नहीं कर सकती है। सरकार तथा उद्योग में उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। सरकार कुछ प्राविधिक संस्थाएँ स्थापित करनी है, कुछ को आर्थिक अनुदान देनी है, एव शोध तथा व्यावसायिक अभ्यास का कन्द्रोत्पन्न करती है। उसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा को भी राज्य की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए; जैसा, किस क्षेत्र में तथा कितने प्रविधिजो की आवश्यकता है। इसके लिए उचित सर्वेक्षण होना चाहिए।

इसके अनिर्दिष्ट प्राविधिक शिक्षा तथा उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थाएँ उद्योगों की माँगों को पूरा किया करनी हैं। पर उद्योग तकनीकी विभागियों को व्यवहारिक अभ्यास की सुरक्षा प्रदान करता है, तथा शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त उन्हें नौकरी देता है। किन्तु प्रत्येक उद्योग-मूलक शिक्षा क्षेत्र का ध्येय सब समय स्पष्ट रहना चाहिए। जैसा कि प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् लार्ड यूस्टेन पर्सी का कथन है :

हमें उद्योग को सूचना देनी होगी कि शिक्षा का दाँचा भाव क्या है, इसका साथ क्या है, हम हमसे क्या सुधार करना चाहते हैं, और हमें स्वास्थ्य तथा उद्योग की ज़रूरतों की ओर ध्यान देने हुए उनके उपयुक्त दृष्ट और आशा तैयार करना पड़ेगा। साथ ही उनके अनुसृत नवीन सोचनाएँ खोजनी पड़ेगी।

## उपसंहार

इस अध्याय में भारतीय प्राविधिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की खोज की गयी है, तथा उसमें सम्बन्धित बहुरूप समस्याओं पर विचार किया गया है। बीसवीं शताब्दी शिक्षा का युग है। शिक्षा की प्रगति को न इन रोड सहने है और न रोका जाते है। यदि हम समय राश्ट्रो में अपनी गणना करना चाहते हैं, तो हमें भी उसी स्तर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।

हमारी पर-करीब संस्थाओं का भी ध्येय है, विद्वान् कार्यकर्ताओं को प्रेरणाओं की प्रदाना, उनके उपयुक्त शिक्षा, कौशल तथा प्रविधिजो को तैयार करना तथा देश



## नवाँ अध्याय

### शिक्षक प्रशिक्षण

#### पूर्व-पृष्ठिका

**भूमिका.**—समय में शिक्षा एक प्रधानतम व्यवसाय होत्र है। भारत में आज बाह्य जगत् में अधिक धनिक शिक्षण-कार्य-द्वारा अपनी जीविका चलान हैं। जीवन क्षेत्र में अध्यापन का महत्व सर्वाधिक है। शिक्षकों का सम्बन्ध केवल एक घुड़न छात्र-समूह में ही नहीं रहता, बल्कि विभिन्न आयु के निवासियों में भी रहता है।

प्राचीन एवं मध्य युगीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रशिक्षण का कोई विशिष्ट नियम न था। उर्मीसदी शास्त्री के अन्तर्गत छात्राचारक प्रणाली (मानीटर पद्धति) प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार संपूर्ण स्कूल या कक्षा बतिसर एकत्र टुकड़ियों में बाँट दी जाती थी। प्रत्येक टुकड़ी एक मानीटर या बतिसर शिक्षार्थी के मार्गदर्शन में रहती थी। मानीटर अपनी टुकड़ी को पढ़ाता था। अन्त में टुकड़ी के शिक्षार्थीगत अपना पाठ शिक्षक को सुनाने थे।

डा० एम्. डे. ने, जो कि महान् सैनिक अनायास्य के सुपरिटेण्डेण्ट थे, इस प्रथा को इस नाम से अनायास (सन् १७८७ ई०)। बाद को उन्होंने इसका प्रचार प्रसार में भी किया। सन् १८०१-१८४५ की अवधि में उस देश के प्रचलित स्कूलों में यही पद्धति प्रचलित थी। यह प्रथा कम खर्चीली थी, तथा शिक्षक-सम्पत्ति सम्पत्ति की कमीव कीर्ति थी। इस प्रथा के कई नाम बना हुए : *मानीटर पद्धति*, *महान् प्रथा*, *मैकाल्डेन पद्धति*, *देमोस्ट्रीटि सिस्टि*, *अनायास प्रथा*, *इत्यादि*। समुदाय यह प्रणाली भारतीय प्रचलित देशी पद्धति का अन्तर्भाव थी।

विश्व प्रशिक्षण एक नदीन बना है। भारत में इसका अन्तर्भाव आधुनिक युग में ही हुआ है। इसके शिक्षक का अध्यापन तीन मुख्य कार्य में विभक्त हो गया है : (१) छात्राचारक प्रणाली, (२) विश्व प्रशिक्षण और (३) विश्व प्रशिक्षण।



छात्राध्यापक प्रणाली.—इस बात का विचार सन् १८०१ में सन् १८८२ तक है। इस अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण की विभिन्न मापदण्ड नहीं की गयी थीं। कुछ प्रशिक्षण केन्द्र यहाँ यहाँ अल्पसंख्यक में, पर वे प्राथमिक शिक्षकों के निमित्त होते रहे थे, तथा अधिकतर वे गैरगवर्नरी संस्थान थे।

आरम्भ में इंग्लिश शिक्षणरी पाठशाला में करने स्कूलों के शिक्षकों की प्रशिक्षण करने के लिए कुछ प्रयत्न किये, तथा भीमनगर में डा० बॉरे ने एक नार्मल स्कूल स्थापित किया। तत्पश्चात्, बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की शिक्षा-समिति ने शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की और इसके लिए कुछ केन्द्र खोले। बम्बई देशी शिक्षा मण्डल ने २८ प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की प्रशिक्षण किया तथा उन्हें प्रेसीडेन्सी के विभिन्न भागों में प्राथमिक शिक्षकों के निरीक्षण के लिए भेजा (सन् १८२६)। मद्रास में गव. टाउन मनरो ने शिक्षकों की प्रशिक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय स्कूल खोला (सन् १८२६)। कलकत्ता में स्थानीय स्कूल-समिति ने एक शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया (सन् १८१९)। तत्पश्चात् कलकत्ता महिला शिक्षा समिति ने भी शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के निमित्त एक दूरग केन्द्र खोला।

इन गैरगवर्नरी संस्थाओं के सिवा कुछ सरकारी संस्थान भी स्थापित हुए। उदाहरणार्थ, बम्बई एलफिन्स्टन इंग्लीश स्कूल, पूना मस्जिद स्कूल एवं सेंट अंग्रेजी स्कूल में नार्मल बधाई आरम्भ हुई। सन् १८४९ में कलकत्ते में एक नार्मल स्कूल स्थापित हुआ, और इसके दस वर्षों के भीतर बंगाल में और भी तीन नार्मल स्कूल खोले गये। उत्तर-पश्चिम प्रदेश में आगरा, मेरठ तथा बनारस में क्रमशः १८५२, १८५६ तथा १८५७ में नार्मल स्कूल स्थापित हुए।

बुद्ध के घोषणा-पत्र ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया। इसने आदेश दिया कि प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में नार्मल स्कूल खोले जायें। इस आदेश की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तथा सन् १८५९ के घोषणा-पत्र को कहना ही पड़ा कि “कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के निर्देश के अनुसार, शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र प्रत्येक संस्था में स्थापित नहीं हुए हैं। इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।” सन् १८५९ के पश्चात् निमित्त अनुदान-प्रथा में भी, प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन के लिए अनुदान की

† J. A. Rieise *Selections from Educational Records*, Vol II  
p 38

‡ Stanley's Despatch, para 44

विशेष व्यवस्था रखी गयी। इन विधेयों के फल स्वरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सन् १८८२ में ब्रिटिश भारत में १०६ नार्मल स्कूल थे, शिक्षार्थियों की संख्या ३,८८६ थी तथा प्रशिक्षण पर चार लाख रुपये व्यय किये गये थे।

यह ध्यान रहे कि ये प्रशिक्षण-मस्यौएँ केवल प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए थीं। प्रथम शिक्षार्थी प्राथमिक स्कूल प्राप्त विद्यार्थी हुआ करते थे। पाठ्य-क्रम में स्कूल के दिनों के प्रति विशेष धन दिया जाता था, ताकि शिक्षार्थीगत इसका उपयोग अपनी शिक्षा-समामि के बाद स्कूलों में कर सकें। उस समय शिक्षण-विधि पर विशेष ध्यान न था। शुरू शुरू में शिक्षार्थियों को मानीटर-पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में एक उम्मीदवार-पद्धति शुरू हुई। इसके अनुसार एक पद-विद्यार्थी को कुछ समय तक एक अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में काम करना पड़ना था। उदाहरणार्थ, बम्बई शिक्षा विभाग का तत्कालीन एक आदेश पढ़िए :

प्रत्येक तात्का से कुछ विद्यार्थी चुने जावें। ये तीन वर्षों तक तीन से पाँच रुपये मासिक स्टाइपेंड पर किसी असफल शिक्षक के निरीक्षण में उम्मीदवार की भौति काम करें। तत्पश्चात् वे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल में छः रुपये मासिक स्टाइपेंड पर भर्ती किये जायें।

अब तब माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। केवल दो ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित हुए थे : एक मद्रास में (सन् १८५६) तथा दूसरा, एगोरे में (सन् १८८१)। इनमें स्नातकों और उपस्नातकों को साथ ही प्रशिक्षित किया जाता था। पाठ्यक्रम में स्कूल के शिक्षणपर दिनों के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता था, किन्तु व्यावहारिक विषयों का विशेष ध्यान न था।

**शिक्षक-ट्रेनिंग (१८८२-१९४७)**—इस प्रकार शुरू शुरू में ट्रेनिंग सम्पादकों के पाठ्यक्रम में अध्यापन विधि का विशेष ध्यान न था। सन् १८८२ के भारतीय शिक्षा आयोग तथा सन् १९०४ की शिक्षा-नीति ने प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण की एक नवीन रूप प्रदान किया। प्रथम निष्कर्ष ने सिफारिश की कि नार्मल और ट्रेनिंग सम्पादक देश के भिन्न भिन्न भागों में आवश्यकतानुसार स्थापित की जायें।<sup>†</sup> माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने प्रस्तावित किया।

<sup>†</sup> As quoted by Bhaswati Dayal *The Development of Modern Indian Education* Bombay, Longmans, 1955 p 474.

‘अध्यापन सिद्धान्त एवं प्रयोग’ पर एक परीक्षा आरम्भ की जाय। इस परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षकगण स्थायी रूप से क्या सरकारी और क्या गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त हों।†

कमीशन ने इस बात पर बल दिया कि स्नातकों तथा उपस्नातकों का ‘प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार का हो। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारत में डा. ट्रेनिंग कालिज (मद्रास, लाहोर, राजमहेन्द्री, कुर्सेयांग, अन्नपुर तथा अलाहाबाद) एवं पन्नास ट्रेनिंग स्कूल माध्यमिक शिक्षकों के लिए थे। कुल प्रान्तों ने ‘अध्यापन प्रमाण-पत्र-परीक्षा’ की व्यवस्था भी कर ली थी।

भारत-सरकार की सन् १९०४ की शिक्षा नीति ने शिक्षक-प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर सुचारुरूप से अपना मत व्यक्त किया। शिक्षा-नीति ने प्रस्ताव किया :

१. स्नातक शिक्षकों का कोर्स एक वर्ष का हो तथा प्रशिक्षण समाप्त होने पर सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीय डिग्री या डिप्लोमा मिले। पाठ्यक्रम में औद्योगिक सिद्धान्तों तथा अध्यापन-अभ्यास पर विशेष जोर दिया जाय। उप-स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण कोर्स दो वर्ष का हो। अध्यापन-विधि के अतिरिक्त, इस पाठ्यक्रम में साधारण ज्ञान के प्रति लक्ष्य रहे।

२. शिक्षण-सिद्धान्तों के अध्यापन का अभ्यास के साथ संनिष्ठ सम्बन्ध रहे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्बन्धित एक अभ्यास विद्यालय रहे।

३. ट्रेनिंग महाविद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध रहे, ताकि प्रशिक्षण समाप्त होने पर, प्रत्येक शिक्षार्थी महाविद्यालय में सिखाये हुए सिद्धान्तों का यथोचित अभ्यास करे।‡

इस घोषणा के फल स्वरूप ट्रेनिंग संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई, स्नातकों तथा उपस्नातकों के प्रशिक्षण का स्वतन्त्र-रूप से अलग-अलग आयोजन प्रारम्भ हुआ—स्नातकों के लिए एक-वर्षीय कोर्स तथा उप-स्नातकों के लिए द्वि-वर्षीय कोर्स। इनके साथ-साथ, प्रत्येक ट्रेनिंग संस्था में अभ्यास विद्यालय स्थापित हुए। सन् १९१३ की सरकारी शिक्षा-नीति ने इस कार्य को और भी प्रभावित किया। इस नीति ने स्पष्ट रूप से ही

† Report of the Indian Education Commission, para 2

‡ Government of India's Resolution on Educational Policy, 1904, para 39.

कहा, "प्रशिक्षण के बिना किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की आशा नहीं मिलनी चाहिए ।" कलकत्ता विश्वविद्यालय कमिशन ने शिक्षण में अनुसन्धान, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या वृद्धि की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग खोलने का परामर्श दिया। हाटंग समिति ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जैसे : प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाना, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, पुनर्संजीवन कोर्सों का आयोजन, इत्यादि ।

उपयुक्त सुझावों के कारण, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग स्थापित हुए। प्रशिक्षण-अनुसन्धान-टिप्परी आरम्भ हुई, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हुई तथा पुनर्संजीवन कोर्सों का प्रारम्भ हुआ । देश में तीन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ की गई हुई : (१) स्नातकों के लिए ट्रेनिंग कालिज, (२) उप-स्नातकों या मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल तथा (३) प्राथमरी स्कूलों के लिए ट्रेनिंग नार्मल स्कूल । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रशिक्षण-व्यवस्था इस देश में अब स्थापित नहीं की जा रही है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति (सन् १९४७) तक भारत में १४ शिक्षण महाविद्यालय, ११९ (पुरुषों के लिए) नार्मल स्कूल तथा १८९ (स्त्रियों के लिए) नार्मल स्कूल खुल चुके थे । इनमें शिक्षार्थियों की संख्या क्रमशः २,४९१, २३,७५४ और १०,१९१ थी ।<sup>१</sup>

**शिक्षक-प्रशिक्षण (१९४७-६०).—**इस प्रकार शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्रगति सन् १९४७ के पूर्व हुई । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में नये विचार उत्पन्न हुए। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः, स्वाधीन भारत में अनेक शिक्षा-योजनाएँ चलायी गयी हैं । इनको सफलभूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता है । द्वितीयतः, पूर्ण स्वातन्त्र्योन्मुखता की शिक्षा नीति आज नहीं चलायी जा सकती है । जन-तान्त्रिक राज्य में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकगण लोक-तन्त्र की गुण तथा पद्धति से सम्पूर्ण रूप में परिचित हों । तृतीयतः, सम्पूर्ण विश्व में शिक्षकों की पूर्ण-अभ्यास-क्रिया में आमूल परिवर्तन हो रहा है । हमका सम्बन्ध विद्यार्थियों के सम्पूर्ण जीवन से है । इसकी परिधि अनिश्चित पाठ्य-परिधि तक सीमित नहीं हो सकती है । प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा-शास्त्री विलियम किलपेट्रिक ने कहा है "ज्ञानवर तथा सर्वज्ञ के जट ट्रेण्ड होने हैं, शिक्षकगण प्रशिक्षित होने हैं ।"

<sup>१</sup> Government of India's Resolution on Educational Policy, 1947, para 51.

<sup>२</sup> Progress of Education in India, 1937-47, Vol I, p 31.

अन्ततः, बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव ने भारतीय शिक्षा-जगत में एक क्रांति उत्पन्न की है। यह नवीन शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन, उनके सम्पूर्ण वातावरण तथा सामाजिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देती है। इस विचार-धारा ने हमारे देश की शिक्षक-प्रशिक्षण पद्धति को एक नया जीवन दिया है। इसके साथ साथ गणानुष्ठापन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के कारण यह विचार-धारा और भी प्रभावित हुई है। प्रथम कमीशन ने कहा ही है, "यद्यपि शिक्षा कोरी स्कूली पद्धति तथा मुदन्त विद्या पर निर्भर नहीं रहनी है। इसका सम्बन्ध है दैनिक जीवन तथा आवश्यक कार्य-कलाप से।"† तात्पर्य यह है कि पूर्व-अभ्यास पाठ्यक्रम के सुधार की परांत चेष्टा हो रही है। इसका प्येज है, 'अप्यापक ट्रेनिंग' से 'शिक्षक प्रशिक्षण' की ओर अप्रसर होगा।

### वर्तमान-परिस्थिति

**भूमिका.**—स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्, इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण का दृष्टि विस्तार हुआ है। सन् १९४७-४८ में शिक्षक प्रशिक्षण-संस्थाओं की छान भंगना ४२,१५७ थी; सन् १९५६-५७ में यह मरग्या, १,०५,१९४ तक पहुँची गयी। इसी अवधि में मरग ११६ करोड़ रुपये से २०६३ करोड़ रुपये बढ़ गया।

आज इस देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ साधारणतः छः प्रकार की हैं :

- (१) पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र;
- (२) नार्मल या प्राथमरी ट्रेनिंग स्कूल,
- (३) माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल (उदग्नानक विधियों के लिए);
- (४) ट्रेनिंग कॉलेज (ग्रान्तर विधियों के लिए);
- (५) विन्नेदज ट्रेनिंग केन्द्र, पर
- (६) शिक्षा प्रशिक्षण-संस्थान।

**पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र.**—संमन समर में इस देश की पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण विधियों के संसार में है। मार देश में केवल २६ पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इनमें में सन मरगनी मरगने है, और देव मरगनी है।

† *University Education Commission's Report*, p. 215

‡ *Report of the All-India Child Education Conference*, 1956

इनका कोर्स एक वर्ष का है तथा इनमें बहुत ही मैट्रिक तथा अपर प्राथमरी पास शिक्षार्थी भरती किये जाते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता के अभाव के कारण, प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम में भी समानता नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं, जैसे - नर्सरी स्कूल, किण्डरगार्टन, मोन्टेसरी पद्धति एवं पूर्व-प्राथमिक। तब पर भी पाठ्यक्रम में बहुत कुछ समानता रहती है। मद्रास प्रान्त की 'नर्सरी, माण्टेसरी / किण्डरगार्टन मर्टीफिकेट परीक्षा' के लिए निम्न लिखित विषयों के प्रश्न-पत्र स्वीकृत हैं (१) मनोविज्ञान, (२) आरोग्य-विज्ञान एवं आहार, (३) स्कूल-प्रशासन, (४) शिक्षण-पद्धति (५) संगीत या चित्रकला या सूची कर्म और हेण्ड-क्राफ्ट एवं क्यायड।<sup>†</sup> इसी प्रकार पूर्व-बुनियादी पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विभाग हैं : (१) सामाजिक जीवन की व्यवस्था, (२) समाज प्रशिक्षण, (३) गिनतु अवलोकन, (४) भिक्षु-शिक्षा का इतिहास, (५) पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त एवं ध्येय, (६) पूर्व-बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, (७) कार्यकलाप आयोजन, (८) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (९) मूर्तिप्रतिष्ठा, (१०) नाचा, (११) संगीत तथा ताल, एवं (१२) कला तथा क्राफ्ट।<sup>‡</sup>

गत वर्ष में बड़ौदा विश्वविद्यालय के गृह-विज्ञान कालिदा ने एक छातकोत्तर पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किया है। इसका उद्देश्य है निरीक्षक, प्रधानाध्यापक तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अध्यापक तैयार करना। सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक 'भारतीय गिनतु-शिक्षा-समिति' स्थापित की है। इस समिति का उद्देश्य है : गिनतु शिक्षा के विषय में सलाह देना, तथा देश के विभिन्न भागों में इस शिक्षा में हो रहे कार्यों में एकगुणता स्थापित करना।

**मार्मल तथा प्राथमरी ट्रेनिंग स्कूल :** भूमिका. हमारे देश में दो प्रकार के प्राथमरी स्कूल हैं। बुनियादी एवं गैर बुनियादी : दूसरे के अनुसार प्राथमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ भी दो प्रकार की हैं। सन् १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में, ५८१

<sup>†</sup> Madras Government Press Revised Syllabuses for Nursery, Montessori, Kindergarten Training School Leaving Examinations, 1948 p 1

<sup>‡</sup> Hindustani Talimi Sangh Pre-Basic Education 953 p. 6

बुनियादी तथा ३३५ गैर-बुनियादी शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र थे।† सभी राज्यों में गैरबुनियादी संस्थाओं को बुनियादी रूप देने की चेष्टा की जा रही है।

**सर्टीफिकेट-व्यवस्था.**—दोनों प्रकार के केन्द्रों में दो प्रकार के सर्टीफिकेट की व्यवस्था है : (१) अपर-प्राथमरी पाठ्य शिक्षार्थियों के लिए एवं (२) मैट्रिक शिक्षार्थियों के लिए। प्रथम वर्ग के शिक्षार्थियों को 'अवर शिक्षक सर्टीफिकेट' तथा द्वितीय वर्ग के विद्यार्थियों को 'प्रवर शिक्षक सर्टीफिकेट' मिलता है। दोनों कोर्सों की अवधि दो वर्ष की होती है।

**गैर-बुनियादी पाठ्यक्रम.**—प्रत्येक राज्य के पाठ्य क्रम में कुछ-न-कुछ विशिष्टता रहती है। पंजाब राज्य की 'अवर सर्टीफिकेट परीक्षा' के पाठ्य-क्रम का विवरण नीचे दिया गया है :

(अ) लिखित कार्य : छः पन्ने : (१) एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, हिन्दी या पंजाबी), (२) शिक्षण-पद्धति १ — (भाषा एवं गणित), (३) शिक्षण-पद्धति २ — (सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र तथा दैनिक विज्ञान), (४) कक्षा-प्रबन्ध, (५) शिक्षा-सिद्धान्त एवं शिक्षा-मनोविज्ञान, तथा (६) हिन्दी या पंजाबी (यह भाषा जो पहले प्रश्न-पत्र में न ली गयी हो)।  
(भा) अभ्यापन-अभ्यास तथा मौखिक कार्य : (१) भाषा, भूगोल या इतिहास एवं दैनिक विज्ञान, (२) दो हेण्डी-क्लाफ्ट (प्रत्येक विभाग से एक) — प्रथम विभाग — लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, जिल्द-सजी, बुनाई, कुककूट-पालन, चित्रकारी एवं रेखा-चित्र; तथा द्वितीय विभाग — ईंट बनाना, टोकनी बुनना, दर्पण का काम, साबुन-निर्माण, स्टाही बनाना, छीट की छपाई, कपड़ा, फर्श एवं स्काउटिंग।

प्रवर परीक्षा के पाठ्यक्रम की रूप-रेखा भी इसी प्रकार है, पर स्वाभाविक ही यह कार्य अधिकतर गुरुत्वपूर्ण होता है। अन्तर केवल इन मद्रों पर है : (१) दूसरे पन्ने में बीजगणित तथा रेखागणित शामिल हैं, (२) चौथे पन्ने में कक्षा-प्रबन्ध के अनिर्दिष्ट मूल व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, (३) हेण्डी-क्लाफ्ट-शिष्टा में दो विषय शामिल हैं — कुककूट-पालन, रात्रिगिरी, धर्मकारी, धातु-कार्य, रंगरेखी, फल तथा सब्जी-परिचय, रस्सी बॉन्ना, टाट बनाना, रेसम के बड़े पात्रा, मनुष्य-पत्र, पत्र-पालन।

† Education in the States, 1956-57, pp. 3-5

बुनियादी पाठ्यक्रम.—बुनियादी पाठ्यक्रम में नयी तालीम के निम्नलिखित आदर्शों की ओर लक्ष्य रहता है :

१. सामाजिक जीवन में शिक्षार्थियों को भाग लेना तथा उन्हें मिलनसार बनाना;

२. उन्हें नयी तालीम के सामाजिक आदर्शों का तथा शिक्षा के साथ सत्य एवं अहिंसा के सम्बन्ध का परिचय कराना;

३. शिक्षार्थी के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करना, ताकि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके; एवं

४. उसे अपने व्यावसायिक क्षेत्र के लिए तैयार करना, ताकि वह वर्गों के शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ सके ।†

कुछ समय तो हिन्दुस्तानी तालीम के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खला रहे हैं, और खुले हममें थोड़ा-बहुत हेर-फेर किया है। नीचे बम्बई राज्य के प्राथमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम दिया जाता है :

पहला ग्रूथ (ग्रुप)—१०० गुन : (१) तीन बुनियादी ग्राफ्ट (कतार्ई, कृषि, लकड़ी का काम) एवं (२) चार सहायक ग्राफ्ट (कतार्ई, बागवानी, दफ्तरीगिरी, गृह-कापट) । — प्रत्येक विद्यार्थी को एक बुनियादी ग्राफ्ट और हमे छोड़कर दो और कोई सहायक ग्राफ्ट लेना पड़ता है। महिलाओं के लिए गृह-कापट एक अनिवार्य विषय है।

दूसरा ग्रूथ (शिक्षा)—(अ) लिखित परीक्षा (१५० गुन)—तीन पर्ये : (१) शिक्षण सिद्धान्त, (२) स्कूल व्यवस्था एवं प्रबन्ध, (३) अध्यापन विधि एवं (आ) अध्यापन-अभ्यास (१५० गुन—१०० गुन बन्दूचे काग के काग के लिए एवं ५० गुन अन्तिम पाठ के निमित्त)। परी के काग में शामिल हैं—(१) २० सनकाय पाठ, (२) ५० पाठों का अध्ययन, (३)

† Hindustani Talimi Sangh Revised Syllabus of the Training of Teachers 1952 pp ८-९.



विश्वी पुनिवर्ती शूट में एक गमाह का गमाना अभ्यास प्रमाण, (६) तीन अग्र-पट, (७) दो स्थित गायनी की नैवारी ।

**नामिका प्रप (गामा-पट विद्या) : ३०० गुण—८ : पने—**

(१) दोषीय भासा १ (पाठ्य पुष्पक) (२) दोषीय भासा २ (साधारण)  
(३) विद्या, (४) गमाना अभ्यास, (५) साधारण विद्या एव (६) साधारण  
गाना या एक गायनीय भासा ।

**चौथा प्रप (गामा-पट अनुमति) १०० गुण—१५ दूर की को**  
परोक्षा नहीं है । गुण पूरे वर्ष के कार्य पर दिये जाते हैं । इसमें शामिल है  
गामा-पट अभ्यास तथा कानिज एव अभ्यास विद्या के गामा-पट जीवन में  
भाग-पट ।

अदर एव प्रप परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एकसा है । केवल दूर तीन का  
पाठ्यक्रम प्रप विद्यार्थियों के लिए उच्चतर होता है ।

**माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल.—**निर्दिष्ट शूटों के शिक्षणगत अधिस्त  
मैट्रिक या इण्टरमीडिएट पास होने हैं । ये माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षित होते  
हैं । इनका कोर्स एक या दो वर्ष का होता है, एव सफलभूत शिक्षार्थियों को विश्व  
विद्यालय या शिक्षा-विभाग में टिप्पणियाँ मिलना है । उदाहरण-स्वरूप, बड़ौदा, बम्बई,  
गुजरात, पूना, कर्नाटक, नागपुर, सागर तथा जयपुर विश्वविद्यालयों में उप-स्नातक  
शिक्षकों के लिए टी० डी० (प्रथम पॉन विश्वविद्यालय) या डिप० टी० (अन्तिम तीन  
विश्वविद्यालय) कोर्स की व्यवस्था है । टी० डी० कोर्स की अवधि एक वर्ष की होती  
है । इसमें तीन वर्ष के अनुभव प्राप्ति शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के प्रथम वर्षीय परीक्षा  
में उत्तीर्ण छात्रगण भरती हो सकते हैं । डिप० टी० कोर्स में उप-स्नातक लिये जाते हैं ।  
इसकी अवधि दो वर्षों की है । कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक वर्षीय एल० टी० कोर्स  
चाहू है, जिसमें इण्टरमीडिएट पास शिक्षार्थी भरती होते हैं । इन विश्वविद्यालयों के  
अतिरिक्त, प्रायः सभी राज्यीय शिक्षा-विभाग उप-स्नातक शिक्षकों के लिए स्वतः  
पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा परीक्षाएँ चलाते हैं ।

राज्य-शिक्षा-विभागीय या विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों में समानता नहीं है, पर  
दोषा प्रायः एक-सा है । इसके मुख्य दो भाग हैं : (अ) सैद्धान्तिक कार्य (चार पने)—  
(१) शिक्षा-मनोविज्ञान, (२) शिक्षण-सिद्धान्त, (३) अध्यापन-विधि और (४) स्कूल-  
प्रबंध तथा आरोग्य-शास्त्र; एवं (आ) अध्यापन-अभ्यास ।

**ट्रेनिंग कालिज.—**छात्रक शिक्षकगण ट्रेनिंग कालिजों में प्रशिक्षित होते हैं। ये संस्थाएँ दो प्रकार की हैं : बुनियादी एवं गैरबुनियादी। सन् १९५६-५७ में बुनियादी कालिजों की संख्या ३३ थी तथा गैरबुनियादी कालिजों की १००। इनकी छात्र-संख्या क्रमशः २,४६९ तथा १२,६४७ थी। अधिकतर संस्थाएँ राजकीय हैं। कनिष्ठ संस्थाएँ आर्ट्स एवं साइन्स कालिज चलाते हैं, और कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभाग हैं, जैसे : अलीगढ़, अलाहाबाद, अनामलाय, बड़ोदा, बनारस, गौहाटी, कलकत्ता, कोल्लानिया, लखनऊ, गोरखपुर, नागपुर, लखनऊ एवं पटना।

**गैरबुनियादी संस्थाएँ.—**इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होती है, तथा इनके सफलभूत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीय या राजकीय शिक्षा-विभाग के नियमों के अनुसार बी० टी०, बी० एड०, एल० टी० या डिप० एड० डिग्री मिलती है।

पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित होता है : (अ) सैद्धांतिक (पाँच पवें) : (१) शिक्षा-मनोविज्ञान एवं साहित्यिक, (२) शिक्षा-सिद्धान्त, (३) स्कूल-प्रशासन एवं आरोग्यसाध, (४) अध्यापन विधि, (५) शिक्षा-इतिहास तथा वर्तमान शिक्षा-समस्याएँ; और (आ) अध्यापन-अभ्यास।

**बुनियादी संस्थाएँ.—**बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव के साथ-साथ बुनियादी प्रशिक्षण कालिज स्थापित हुए हैं। इनका उद्देश्य है प्राथमिक स्कुलों के लिए निरीक्षक एवं बुनियादी ट्रेनिंग स्कुलों के लिए अध्यापक तैयार करना। इन संस्थाओं का पाठ्य-क्रम एक-सा नहीं है। प्रत्येक राज्य अपना-अपना पाठ्यक्रम चलाते हैं। इस विद्यमता को दूर करने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग कालिजों के प्रिन्सिपलों की एक समिति ने अधोलिखित पाठ्यक्रम की सिफारिश की है :

**१. प्रथम पवः :** (१) शिक्षण व्यवहार एवं समावसाय ( विशेषकर बुनियादी शिक्षा सम्बन्धि), (२) शिक्षा-मनोविज्ञान, (३) शिक्षण प्रशासन एवं निरीक्षण, या प्रयोगिक शिक्षा एवं शिक्षण-अनुसन्धान विधि, (४) बुनियादी शिक्षा विधि तथा (५) अष्ट-शिक्षा—सिद्धान्त एवं अभ्यास।

**२. द्वितीय पवः :** (अ) मुख्य बुनियादी वास्त ( कोई भी एक )— (१) हार्डि (पशु चालन-सहित), (२) कुनाई एवं बगार, (३) टफ्फरीगिरी, लवरी का काम एवं सार्वजनिक पशु बाड़े, और (आ) सहायक वास्त (कोई

मी एक) — (१) गृह-निर्माण, (२) कनाई (यदि यह मुख्य क्राफ्ट न हो), (३) गन्जी की बाग्यानी (यदि कृषि मुख्य क्राफ्ट न हो), (४) चमड़े का काम, (५) मधु-मक्खी पालन, (६) कुम्हार काम ।

३. अस्थापन-अभ्यास — (१) अभ्यास-योजना रचना, (२) किस्म स्कूल वृत्ता के उपयुक्त निर्वाचित विषयों का योग्यता परीक्षण निर्माण, (३) वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षणों का परिचालन, (४) अपने अभ्यास पाठ के विषयों पर शिक्षा-साधन तैयार करना, (५) बुनियादी स्कूलों से सम्बन्धित समुचित सामग्री-निर्माण । †

यह याद रहे कि इने-गिने दो-चार विश्वविद्यालयों को छोड़कर, बुनियादी उत्तर-स्नातक-डिप्लोमा का परिचालन गजतीय शिक्षा-विभाग ही करते हैं । इस कारण, ऐसे डिप्लोमा धारी व्यक्तियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । बहुधा ये विश्वविद्यालयीय उत्तर-स्नातक कोर्सों में भर्ती नहीं हो सकते हैं । इस कारण, बुनियादी तुमान-निर्धारण-समिति ने प्रस्ताव किया है कि विश्वविद्यालय भी बुनियादी विश्वविद्यालय चलावें तथा उत्तर-स्नातक बुनियादी डिप्लोमा को मान्यता दें । 'केसशिम' भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है

**विशेषज्ञ प्रशिक्षण-केन्द्र.** — विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए आयोजन किया गया है । ये क्षेत्र हैं : शारीरिक शिक्षा, ललित कला, गृह-विज्ञान, पट एवं विविध विषय ।

**शारीरिक शिक्षा** — शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण कालिजों में स्नातकों को तथा लो में उप-स्नातकों को मिलता है । सम्पूर्ण देश में केवल बीस केन्द्र हैं, जो यह शिक्षा देते हैं । इनका कोर्स एक-वर्षीय होता है, तथा डिप्लोमा का सर्टीफिकेट संस्था या राज्यीय शिक्षा-विभाग से मिलता है । अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था नहीं है ।

३० जून १९५७ को केन्द्रीय सरकार ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक महा-विद्यालय की स्थापना की है । भारत में यह सर्व प्रथम संस्था है, जिसने शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स आरम्भ किया है । आशा की जाती है कि विश्व में यह कालिज अनुसन्धान तथा उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा ।

† Ministry of Education. *The Five Year Plan - Schemes of Educational Developments.* pp 4-5

ललित कला.—कतिपय केन्द्रों को छोड़कर, हम महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध हमारे देश में नहीं है। कुछ मुख्य संस्थाएँ ये हैं : (१) विश्व-भारती (संगीत, नृत्य तथा चित्रकला), (२) मज्जे जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट्स, बम्बई (चित्रकारी), (३) ललित कला फेकल्टी, बंगलूर विश्वविद्यालय (चित्रकला और संगीत), (४) कला-क्षेत्र, अहमदाबाद, मद्रास (नृत्य), (५) संगीत शिक्षण मद्रास-विद्यालय, मद्रास (संगीत), (६) राजकीय आर्ट्स स्कूल, लखनऊ (कला), (७) आर्ट प्रशिक्षण-संस्था, जामिया मिलिया, दिल्ली (आर्ट एव क्राफ्ट)।

गृह-विज्ञान.—प्राथमिक स्कूलों के लिए अनेक गृह विज्ञान शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। इन शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध निम्न-लिखित संस्थाओं में है : लेडी हरबिन कॉलेज, दिल्ली; एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय बम्बई; गृह-विज्ञान फेकल्टी, बंगलूर; राजकीय गृह-विज्ञान प्रशिक्षण मद्रासविद्यालय, अन्नासागर; इत्यादि।

क्राफ्ट.—आज्ञा निर्दिष्ट स्कूल-पाठ्यक्रम में क्राफ्ट एक अनिवार्य विषय है। हम कारण, क्राफ्ट शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है। प्रायः सभी राज्यों ने अपने प्राथमिक हाईस्कूलों तथा क्राफ्ट स्कूलों में इन शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रयत्नगत किया है।

विविध विषय.—अनेक राजकीय शिक्षा विभाग तथा प्रशिक्षण मद्रासविद्यालय कतिपय विविध विषयों का बोझ वहलते हैं। मुख्य विषय हैं : अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास, निरंतर तथा पत्राचार। पुरुषों के बोझ एक-वर्षीय होते हैं।

शिक्षिका प्रशिक्षण संस्थाएँ.—शिक्षिकाएँ की अध्यापन संस्थाओं तथा पुष्प मद्रासविद्यालयों में प्रशिक्षित होती हैं। मज्जे १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में ३१ की अध्यापन कॉलेज (एक कुनिपाटी तथा तीन गैर-कुनिपाटी) तथा २५८ स्कूल (१४६ कुनिपाटी एवं ११२ गैरकुनिपाटी) थे। इन वर्ष कॉलेजों की छात्रा-संख्या थी ४,५६१ (कुनिपाटी ४०७ एवं गैरकुनिपाटी ४,१५४), और स्कूलों की छात्रा-संख्या २५,९१४ (कुनिपाटी ११,१६४ एवं गैरकुनिपाटी १४,७५०) थी।<sup>१</sup>

अनुसंधान एवं जनसंज्ञा कार्य

संज्ञा-संज्ञा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य इन देश में हाल ही में आरम्भ हुआ है। यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है : (१) एम० ए० (शिक्षा) एवं एम० ई०



## मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण

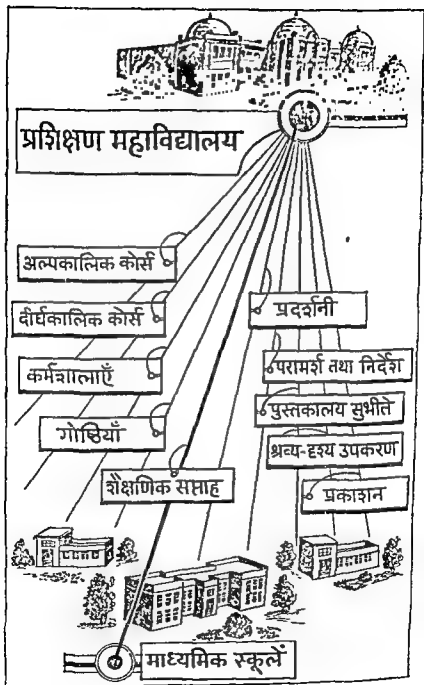
**भूमिका.**—प्रशिक्षण के दो रूप हैं : (१) 'पूर्व-अध्यापन-प्रशिक्षण' अर्थात् किसी प्रशिक्षण-केन्द्र में नियमित रूप से पूर्णकालिक ट्रेनिंग। हम इन दोनों की चर्चा इस अध्याय के द्वितीय शीर्षक के अन्तर्गत कर चुके हैं। अनेक पाश्चात्य देशों में इस ट्रेनिंग का नामकरण 'पूर्व अध्यापन-प्रशिक्षण' किया गया है। कारण, वहाँ पर पूर्ण-कालिक प्रशिक्षण पाये बिना कोई भी व्यक्ति अध्यापन-कार्य आरम्भ नहीं कर सकता है। (२) 'मध्य अध्यापन-प्रशिक्षण'—पूर्व अध्यापन-प्रशिक्षण के पश्चात् एक व्यक्ति शिक्षक बनता है। पर कुछ समय के बाद, उसके पूर्वार्जित ज्ञान में मोरचा ल्या जाता है। अध्यापन कार्य करते हुए, नवीन ज्ञान में सम्पर्क न रखने के कारण ही बहुधा ऐसा होता है। इस असम्पर्क के फल-स्वरूप अध्यापन कार्य ठीक-ठीक नहीं चल सकता है। माध्यमिक आयोग ने कहा ही है :

चाहे कितना ही अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम हो, पर इसमें उत्कृष्ट परिणाम नहीं निकलता है। इसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञान मिलता है, जो एक नौसिखिए को ज़रूरी रहता है। इससे उसका आत्म-विश्वास बढ़ता है। कार्य-क्षमता तभी बढ़ती है जब कि कुछ अनुभव के पश्चात् शिक्षक स्थल-या समुदाय में उन्नति की चेष्टा करे। अतएव शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्रों की मध्य अध्यापन प्रशिक्षण का समुचित आयोजन करना चाहिए।†

**पूर्व चेष्टाएँ.**—यह न सोचना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रशिक्षण की कुछ भी व्यवस्था न थी। समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा विभाग तथा वनियर शिक्षण-प्रशिक्षण समितियाँ कई प्रकार की योजनाएँ चलाती थीं, जिनमें : (१) पुनर्मजीदन बोर्ड, (२) बर्म शाखाएँ, (३) विविध विद्याओं के अन्तःकालिक बोर्ड तथा (४) प्रशिक्षित शिक्षकों की गौहियों एवं सम्मेलन। किन्तु इन कार्य-व्यवस्थाओं की व्यवस्था समुचित न थी।

**ट्रेनिंग कालिज प्रसारण केन्द्र.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग के निर्देशन की ओर केन्द्रीय तथा प्रदेश काउन्सिलों का ध्यान आकर्षित हुआ; और उनकी चेष्टाओं के कारण, हमारे कुछ ट्रेनिंग कालिजों में, प्रयाग-केन्द्र स्थापित हुए — १९५५ में २४ केन्द्र, १९५६ में १७ और भी अतिरिक्त केन्द्र, एवं १९५७ में १२ अतिरिक्त केन्द्र। इस प्रकार की मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण की योजना विश्व के किसी भी देश में

† Secondary Education Commission's Report, p. 175.



चित्र १५ - प्रसारण कार्य

सम्भवतः अभी तक चलीयी नहीं गयी है। फोर्ड फाउण्डेशन हम योजना को आर्थिक साहाय्य—अनुदान—देता है, एवं अमेरिकी टेक्नीकल कोऑपरेशन मिशन शिक्षण-साधन भेंट करती है।

प्रमाण-केन्द्रों के कार्य-कलापों की यह रूप-रेखा है : (१) अल्प-कालिक, दीर्घ कालिक तथा सप्ताहान्त कोर्स, (२) कर्म-शालाएँ, गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन-वर्चा, (३) दैहिक मसाह तथा प्रदर्शनी, (४) परामर्श तथा निदेश गोष्ठियाँ, (५) पुस्तकालयीय मुविधाएँ, (६) अल्प-दृश्य माध्यमों की सहायता एवं (७) प्रकाशन।

**विशिष्ट गोष्ठियाँ.**—प्रमाण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षण-मन्त्रालय समय-समय पर प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षण-प्रशामकों की गोष्ठियाँ आयोजित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों तथा प्रशामकों को एकत्र करना, तथा शिक्षा के उन पंचीदे—उत्पन्न-पूर्व—प्रश्नों की चर्चा करना, जिनसे अध्ययन एवं अध्यापन की उन्नति हो सके। अभी तक ऐसी पन्द्रह गोष्ठियाँ आयोजित हुई हैं। विशेष विषयों की चर्चा के लिए भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। मार्च, १९५७ के अन्त तक ऐसी ग्यारह गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई हैं। इनमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी-अध्यापन, प्रशामन इत्यादि विषय विषयों की चर्चा की गयी है। इनके अतिरिक्त परीक्षा-मुद्धार के लिए सात कर्म-शालाओं की भी व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण एक नवीन जीवन भारत में आरम्भ हुआ है।

### शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ

**भूमिका.**—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में शिक्षक प्रशिक्षण का विशेष स्थान हुआ है, तथापि वर्तमान स्थिति अभी पूर्णतः सन्तोषदायक नहीं है। शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ अध्यापन के नये पंचीदे प्रथम लगे हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत हम प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की जायगी। हमें इस क्षण में टाटुस होता है कि आज शिक्षा अगर् हम मामलों से मुक्तिविग है।

**मर्याद विचार-धारा.**—आश्चर्य हम देश में शिक्षा की विशेष प्रगति हो रही है, और सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि “यह नृपन शिक्षण केवल दृष्टिकोणिक अध्यापन पर ही आधारित न रहे, अतः इसका सम्यक् मानवीय जीवन के दैनिक





# प्रशिक्षण महाविद्यालय

अल्पकालिक कोर्स

दीर्घकालिक कोर्स

कर्मशास्त्राएँ

गोष्ठियाँ

शैक्षणिक सप्ताह

प्रदर्शनी

परामर्श तथा निर्देश

पुस्तकालय सुभीते

श्रव्य-दृश्य उपकरण

प्रकाशन



छपाखाना



माध्यमिक स्कूलें



प्रकाशन

सम्भवतः अभी तक जल्दयी नहीं गयी है। फोर्ड फाउण्डेशन इस योजना को आर्थिक साहाय्य—अनुदान—देता है, एवं अमेरिकी टेक्नीकल कोऑपरेशन मिशन शिक्षण साधन भेंट करता है।

प्रसारण-केन्द्रों के कार्य-कलापों की यह रूप-रेखा है : (१) अल्प-कालिक, दीर्घ-कालिक तथा समाप्तान्त कोर्स, (२) कर्म-शालाएँ, गोष्ठियाँ एवं समूह-वर्चों (३) दैर्घ्यमय तथा प्रदर्शनी, (४) परामर्श तथा निर्देश गोष्ठियाँ, (५) पुस्तकालय सुविधाएँ, (६) अव्य-दृश्य माध्यमों की महामता एवं (७) प्रकाशन ।†

**विशिष्ट गोष्ठियाँ.**—प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षण-मन्त्रालय समय-समय पर प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षण-प्रशासकों की गोष्ठियाँ आयोजित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों तथा प्रशासकों को एकजुट करना, तथा शिक्षा के उन पेंचीदे—उत्पन्न-पूर्ण—प्रश्नों की चर्चा करना, जिनमें अध्ययन एवं अध्यापन की उन्नति हो सके। अभी तक ऐसी पन्द्रह गोष्ठियाँ आयोजित हुई हैं। विदेश विषयों की चर्चा के लिए भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। मार्च, १९५७ के अन्त तक ऐसी ग्यारह गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई हैं। इनमें विशाल समाज शास्त्र, अंग्रेजी-अध्यापन, प्रशासन इत्यादि विषय विषयों की चर्चा की गयी है। इनके अतिरिक्त परीक्षा-सुधार के लिए सात कर्म-शालाओं की भी व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण एक नवीन जीवन भारत में आरम्भ हुआ है।

### शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ

**भूमिका.**—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में शिक्षक-प्रशिक्षण का विशेष दिग्गतर हुआ है तथापि वर्तमान स्थिति अभी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं है। शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ अध्यापन के नये पेंचीदे प्रथम खड़े हो रहे हैं। इस द्वापरक के अन्तर्गत प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की जायगी। हमें इस बात में दाढ़म होता है कि आत्र शिक्षण जगत् इन मामलों से मुररिचित है।

**नवीन विचार-धारा.**—आजकल हम देश में शिक्षा की विशेष प्रगति रही है, और सभी यह अनुमन कर रहे हैं कि "यह नूतन शिक्षण केवल शिक्षाचारि अध्यापन पर ही आधारित न रहे, अरिन्तु इसका मयोग मानवीय जीवन के दैर्घ्य

कार्य-कलाप से हो ।” । अतएव आज अध्यापन-कला में विशेष हेर-फेर की आवश्यकता है, जब कि नूतन शिक्षक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बालकों तथा शिक्षकों के सांसारिक जीवन से रहे ।

इस चुनौती का सामना, बुनियादी-प्रशिक्षण-संस्थाएँ थोड़ा-बहुत कर रही हैं । इस शिक्षा में ज्ञान तथा ज्ञान-स्थितियों से अधिकतर गुरुत्व-पूर्ण है जीवन तथा जीवन-स्थिति । हर्ष की बात है कि थोड़े ही समय में हमारे देश की सभी प्राथमिक अध्यापन संस्थाएँ बुनियादी रूप में परिवर्तित हो जावेंगी ।

यह भावना हमारे बी० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण को भी प्रभावित कर रही है । बी० एड० पाठ्यक्रम-सुधार-समिति को उद्बोधन मागण देते हुए श्री सैयदेन ने सम्पूर्ण देश का ध्यान निर्मालिखित दो मुख्य तत्त्वों की ओर आकर्षित किया है, जिन पर शिक्षक-प्रशिक्षण-सुधार निर्भर रहना चाहिए :

१. शिक्षार्थियों के ज्ञान तथा प्रशिक्षण का स्कूलों के दैनिक कार्य-कलाप से अटूट सम्बन्ध रहे ।

२. ट्रेनिंग कालिज के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है कि उसका सैद्धान्तिक कार्य राष्ट्रीय जीवन के नवीन सामाजिक-आर्थिक विचार-धारा से सश्लिष्ट रहे । इसके अभाव में प्रशिक्षण निस्तेज होगा तथा शिक्षार्थी का ज्ञान अधूरा रहेगा । मनुष्य-जीवन की सम्पूर्ण समस्याओं का चित्र उसके सामने न खिंच सकेगा ।

समिति का विचार-विमर्श उपर्युक्त दो तत्त्वों पर आधारित रहा । समिति-द्वारा स्तुत परिवर्तित बी० एड० पाठ्यक्रम की रूप-रेखा नीचे दी जाती है :

१. सैद्धान्तिक कार्य (चार पन्ने) : (१) शिक्षा-सिद्धान्त तथा तथा स्कूल-प्रबन्ध, (२) शिक्षा-मनोविज्ञान और आरोग्य-शास्त्र, (३) स्कूल-शिक्षण विधि एवं (४) भाग ‘अ’ – भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, और भाग ‘आ’ – किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्यापन : स्कूल पुस्तकालय का प्रबन्ध, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देश, स्कूल-प्रशासन, अशक्त बच्चों की

† University Education Commission's Report. p. 558.

‡ Ministry of Education. Secondary Education. October, 1955.

शिक्षा, साम्य शिक्षा, अल्प-दृश्य-प्रशिक्षण, मानसिक भाव, शारीरिक शिक्षा, मह-पाठ्यक्रमीय कार्य-कलाप, गमात्र-शिक्षा, आदि ।

२. अध्यापन-अभ्यास, जिसमें शामिल रहेंगे, — (१) अध्यापन-पाठ, (२) अद्योक्त-पाठ, (३) समालोचना-पाठ, (४) विभिन्न स्तर और प्रकार के स्कूलों का अवलोकन, (५) मह-पाठ्यक्रमीय कार्य-कलापों में अंश दान तथा उनका प्रवर्ण, (६) स्कूल-विद्यार्थियों के गृह-कार्य तथा स्वाध्याय अभ्यासों का समीक्षण, (७) अल्प-दृश्य ठरकण प्रस्तुत करना ।

मुधार के तीन ध्येय ये : (१) प्रचलित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम को घटाना, (२) प्रत्येक शिक्षार्थी को एक विविष्ट क्षेत्र का ज्ञान देना तथा (३) अध्यापन-अभ्यास का दृढमुक्ती प्रसार । उपर्युक्त रूप-रेखा के आधार पर, सभी विश्वविद्यालयों ने अपने बी० एड० पाठ्यक्रम का सुधार आरम्भ कर दिया है ।

युनियादी तथा गैरयुनियादी पाठ्यक्रम में एकद्वारण की आवश्यकता।—तीसरे अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आज भारतीय शिक्षा में दो विचार-धाराएँ प्रचलित हो रही हैं — युनियादी तथा गैरयुनियादी । हमके अनुरूप शिक्षक-प्रशिक्षण में दो विभिन्न अद्वानिधारे लगी हैं । हम विचार पर कई प्रश्न उठाते हैं : (१) क्या इस देश में प्रतिद्वन्द्वी स्वरूप दो प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण महारिधायकों की आवश्यकता है ? (२) क्या इन दो विभिन्न विचार-धाराओं की आवश्यकता है ? (३) क्या इन दो विपरीत दिशाओं में बढ़ते देना बर्हिद ? (४) क्या यह भव नहीं है कि ये दो निर्झाणियाँ मिलकर एक बृहत् रूप में परिणत हो जायें, जिससे दोनों गुरुक्त हों ?

अब दोनों पद्धतियों पर विचार किया जाये । गैर-युनियादी प्रणाली में सैद्धान्तिक ज्ञान तथा शिक्षण विधियों का व्यापक ज्ञान पूर्ण रूप से दिया जाता है । लेकिन सैद्धान्तिक ज्ञान अभ्यास में दूर रहता है । हमने शरीर ज्ञानात्मक का ध्यान अर्पित रहता है, तथा जीवन की सामाजिक स्थिति में इसका सामर्थ्य नहीं रहता है । हमारे विपरीत युनियादी पद्धति कार्य-कलाप विधि पर निर्भर रहती है, अभ्यास तथा सामाजिक जीवन पर विशेष गौर देती है, एवं साम्य जीवन में साम्य सामर्थ्य अर्पित रहती है । पर इसका सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम दृढमुक्ती नहीं होता है । यह युनियादी शिक्षण विधियों पर आधारित होती है ।

द्वीतर अध्याय अन्तर्गत शिक्षण कार्य-कलापों में दोनों पद्धतियों की तुलना कुछ कुछ लक्ष्य-क्षेत्रों में । अन्त में यह विशिष्ट हुआ कि देश की प्रकृति के विर

एकही प्रकार के उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिनमें दोनों शालियों के विशेष गुणों का समावेश हो। सम्मेलन ने फैसला किया कि यह एकीकरण दो उपायों से हो सकता है :

१. बी० एड० के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के बोझ को कुछ कम करना, तथा उसमें नियमित रूप से सुधार करना; एवं

२. अध्यापन-अभ्यास का प्रसार करना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को क्राफ्ट, सामाजिक जीवन एवं समवाय-शिक्षा का ज्ञान मिले।†

परिवर्तित बी० ए० पाठ्यक्रम में इस ओर अवश्य लक्ष्य रखा गया है, पर पूर्ण रूप से नहीं। दो-एक ट्रेनिंग कालिज इस ओर चेष्टा कर रहे हैं। उदाहरण-स्वरूप, विश्व-भारती के विनय-भवन (ट्रेनिंग-कालिज) में एक पाठ्यक्रम प्रचलित है, जिसकी अवधि पाठ्यक्रम बी० एड० की अवधि से कुछ अधिक है। इस पाठ्यक्रम में बुनियादी और उच्च-बुनियादी सिद्धान्तों का समावेश है। इसी प्रकार का एक प्रयोग विद्या-भवन, उदयपुर भी कर रहा है।

**बी० एड० अध्यापन-अभ्यास में विस्तीर्णता.**—अभी तक बी० टी० बी० एड० अभ्यास के अन्तर्गत, प्रत्येक शिक्षार्थी को कुछ स्थिर पाठ पढ़ाना पड़ता है। आजकल इस पद्धति की काफी नुकता-चीनी हो रही है, क्योंकि इसका दृष्टि-कोण अति सीमित है। आधुनिक शिक्षक का कर्तव्य केवल स्कूल पाठों तक ही मर्यादित नहीं होता है, बल्कि उसे स्कूल के खेल-कूद में भाग लेना पड़ता है, अव्य-दृश्य शिक्षा-धर्मों का विशद रूप में उपयोग करना पड़ता है, आधुनिक वस्तुगत परीक्षाओं को मंजूर करना पड़ता है, विद्यार्थियों की उन्नति-विषयक रिकार्ड रखने पड़ते हैं तथा समाज के साथ मिल-जुल कर रहना पड़ता है। इसके साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि शिक्षार्थियों को देशी स्कूलों का कुछ भी अनुभव नहीं मिलता, जहाँ कि अधिकांश शिक्षार्थियों को अपने ट्रेनिंग के समाप्त होने पर काम करना है। इसी कारण, बुनियादी अध्यापन-अभ्यास (उत्तर-स्नातक डिप्लोमा) का क्षेत्र यथेष्ट विस्तृत रखा गया है, जो समाज एवं देशांतरों से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए 'सघन क्षेत्र' (कॉम्पैक्ट एरिया) में कुछ समय तक लगातार अध्यापन-अभ्यास का क्रोशस्त रखा गया है। बी० एड० पाठ्यक्रम-सुधार-समिति का भी ध्यान प्रचलित अध्यापन-

† *Journal of Education and Psychology* January, 1955 p 231

अभ्यास की संरचना की ओर आवर्तित हुआ था। इसी कारण समिति ने अध्यापन-अभ्यास को सर्वांगीण बनाने की कोशिश की थी। इस ओर चेष्टा भी हो रही है, पर यह काम यथा-रीति नहीं हो सक रहा है। कारण, बी० एड० प्रशिक्षण का कार्य-काल केवल नौ महीने ही है। इस कठिनाई को समझते हुए, समिति ने सैद्धान्तिक कोर्स बहुत कुछ कम कर दिया है।

परन्तु अध्यापन-अभ्यास ठीक तौर से तमो दिया जा सकता है, जब कि ट्रेनिंग कालिब्र का प्रत्येक विद्यार्थी कुछ समय तक किसी स्कूल में पढ़-पढ़ाई के रूप में काम करे, यह स्कूल-कार्य में भाग ले, विद्यार्थियों का यह-कार्य-संशोधन करे, रंजन-कार्य-परिचालन करे, अव्य-दृश्य-उपकरण तैयार करे, स्थानिक समाज के सम्पर्क में आवे, इत्यादि। यह अभ्यास दो से चार सप्ताह तक किसी अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में दिया जाय। सब से अच्छा तो यह है कि इस कार्य के लिए ग्राम्य स्कूल-खुले जायें, ताकि शिक्षार्थी देहात के सम्पर्क में आ सके।

**मान-वर्षीय शिक्षा-स्नातक कोर्स.**—बी० एड० कोर्स अल्प-कालिक होने के कारण, थोड़े समय में शिक्षार्थियों के प्रस्थितिक में बहुत कुछ ठूसना पड़ता है। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने इस कोर्स की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का सुझाव दिया था, किन्तु शिक्षकों की कमी को देखते हुए आयोग को पीछे हटना पड़ा। उसने अंगीकार किया कि 'प्रशिक्षण के लिए हम शिक्षार्थियों को दो वर्ष रोक नहीं सकते हैं।'।

एक और सुझाव दिया जाता है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् एक तीन-वर्षीय शिक्षा स्नातक कोर्स शुरू किया जावे। इसके अन्तर्गत सांस्कृतिक ज्ञान के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण का बी० एड० स्तरीय ज्ञान दिया जावे। जिस प्रकार कृषि या वाणिज्य की व्यवस्था बी० एजी० या बी० काम० कोर्स में की गयी है, उसी प्रकार 'शिक्षा' का अध्यापन प्रस्तावित पाठ्यक्रम में किया जा सकता है। इस मुद्धार से दो मुख्य लाभों की सम्भावना है। प्रथमतः, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक ज्ञान का घना सम्बन्ध रहेगा। द्वितीयतः, शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि दीर्घतर होने के कारण, शिक्षा का ज्ञान एक विस्तृत समय में फैलाया जा सकेगा। इस विषय पर प्रथम अखिल भारतीय-ट्रेनिंग-कालिब्र-सम्मेलन में विषद रूप से चर्चा हुई थी। कतिपय विश्वविद्यालय प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सोच-विचार कर रहे हैं। यह योजना कुछ नवीन

नहीं है। यह अमेरिका में प्रचलित है तथा कुछ अंग्रेजी विश्वविद्यालयों ने भी इसे आरम्भ किया है।

**बहुद्देशीय स्कूलों के ट्रेण्ड शिक्षक.**—हमारे नये बहुद्देशीय स्कूलों के लिए, कई विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है—प्राविधिक, कृषि, ललित कला, वाणिज्य एवं गृह-विज्ञान। प्रथमतः, इन क्षेत्रों के शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। द्वितीयतः, इनके प्रशिक्षण का कुछ भी बन्दोबस्त आब तक इस देश में नहीं है।

ट्रेनिंग की सबसे अधिक कठिनाई यह है कि हमारे प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में इन विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के केवल दो उपाय हैं : (१) इन विशिष्ट क्षेत्रों के कुछ कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हो, या (२) कुछ प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में एक/अधिक विशिष्ट विषय का/के विभाग खोले जायें। दोनों प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा तथा विशिष्ट क्षेत्र के अध्यापनगत कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करेंगे—शिक्षा-शास्त्री अध्यापन-विधि की ओर ध्यान देगा एवं वैशिष्ट्यपूर्ण विशिष्ट विषय ज्ञान पर।

गत वर्ष, राष्ट्रीय शिक्षा-मान्त्रियों के एक सम्मेलन में यह तथ्य हुआ कि चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र इन कार्य के लिए स्थापित हो (२ जुलाई, १९५९)। पर ऐसे केन्द्र जल्दी खोले नहीं जा सकते। हमें उपर्युक्त किसी भी एक तरीके को अग्रगण्य मानेंगे—या, कुछ ट्रेनिंग कालिजों में विशिष्ट क्षेत्रों के विभाग खोले जायें; या, शेषित प्राथमिक कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हो।

**माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल.**—माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों का कोर्स करी एक वर्ष की अवधि का है और कहीं दो वर्ष का है। यह कोर्स सभी राज्यों में दो वर्ष का किया गया, ताकि एक स्तर आये तथा ट्रेनिंग मुक्तक रूप में दिया जा सके—प्रथम वर्ष में प्राथमिक ज्ञान एवं द्वितीय वर्ष में व्यावहारिक शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा के आधिकारिक विवेक शिक्षार्थी कम से कम एक क्षेत्र में शिक्षितता प्राप्त करें : (१) पूर्ण माध्यमिक शिक्षा, (२) मास्टर शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा-आवेश प्राप्त प्रस्तावित एक मास्टर)। (३) शारीरिक शिक्षा एवं (४) कला तथा संगीत।

**उत्तर-ज्ञानक पाठ्यक्रम.**—एन० एड० पाठ्यक्रम के मुख्य की ३१ शिक्षा प्राप्त है। प्रस्ताव देगा जग है कि ये की० एड० कोर्स के शिक्षार्थी अध्ययन है।

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा क्षेत्र के उन्नत उच्च स्तर के शिक्षक, प्रशासक तथा ट्रेनिंग कालिजों के अभ्यारक तैयार करना। इस परीक्षा के तीन मुख्य भाग हैं : (१) अनिवार्य—(अ) शिक्षण तन्त्र ज्ञान, पाठ्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान, विभिन्न देशों के आधुनिक शिक्षण-विधि तथा शिक्षा प्रशासन नियमों का तुलनात्मक ज्ञान, (आ) शैक्षणिक माप-परीक्षा एवं अनुसन्धान विधि; (२) वैकल्पिक—किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान तथा उसीमें सम्बन्धित किसी प्रयोग पर एक निबन्ध; एवं (३) मौखिक परीक्षा।

अनिवार्य विभाग का उद्देश्य हो शिक्षार्थी को शिक्षा के समूचे क्षेत्रों का दिग्दर्शन करना, पर वैकल्पिक विभाग का स्वयं यह है कि उसे एक चुने हुए विषय का विश्लेषण बनाना तथा अनुसन्धान करने के पश्चात् अपने विचारों को विधिवत् निबन्ध रूप में प्रस्तुत करना। मौखिक परीक्षा का अभिप्राय है, शिक्षार्थी की समस्त कीर्ति जाँच करना, जो कि लिखित परीक्षा-भाग कभी नहीं हो सकता है। वैकल्पिक विभाग में कतिपय नये विषयों का समावेश हो, जैसे : पाठ्यक्रम, सुनिपाटी शिक्षा, प्रशासन-कार्य, शिक्षक-प्रशिक्षण, निर्देश एवं प्रगमर्श, किसी विशेष पाठ्य-विषय की शिक्षण विधि, विश्वविद्यालय में सामान्य ज्ञान, इत्यादि।

**कालिज अध्यापकों की तैयारी.**—यह देखा गया है कि शिक्षण-विधि के ज्ञान के अभाव के कारण अनेक कालिज अध्यापकों का अध्यापन सफलीभूत नहीं हो पाता है। इस कारण, उनकी पढ़ाई नीरस हो जाती है। इस विषय की चर्चा, एक आईएन-आन्सेलर के सम्मेलन में की गई थी। सम्मेलन ने अनुभव किया कि कालिज के नये अध्यापकों को शिक्षा-विधि के मूल तत्वों का दिग्दर्शन कराया जावे।† ये विषय हैं : (१) अपने विषय का यथोचित ज्ञान तथा इसे सुव्यवस्थित रूप में समझाना, (२) स्पष्ट भाषण, (३) मुचाकरूप से समझाने की शक्ति, (४) विद्यार्थियों में नवीन विचारों का प्रोत्साहन एवं (५) उनमें ज्ञान-पिपासा की वृद्धि।

इस विषय पर मधुकर-राय अमेरिका में बहुत कुछ चर्चा हुई। अन्त में बहुमत से स्वीकार किया गया कि कालिज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी शिक्षा-पद्धति जानना आवश्यक है। इसके ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा-विधि रोचक बन जाती है। आज अमेरिका के कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में निम्न-लिखित पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है : (१) धनृता-प्रणाली, (२) चर्चा विधि, (३) प्रायोगिक पद्धति, (४) अव्य और हृदय साधनों का उपयोग, एवं



(५) गोठियों तथा कर्मशालाओं का आयोजन । हमारे देश में भी, इस ओर सुधार की जरूरत है ।

**अनुसन्धान-कार्य.**—माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने लिखा है, “ट्रेनिंग कालिब्र केवल शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्था ही नहीं है, बल्कि यह विभिन्न संश्लिष्टीकृत तत्वों का अनुसन्धान-कार्यालय भी है ।”<sup>१</sup> गवेषणा-कार्य प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के आचार्यों के तत्वावधान में हो । हाँ, ये माध्यमिक शिक्षकों से अवश्य सहायता ले सकते हैं । उनके निरीक्षण में कतिपय शोध-शिष्य भी काम कर सकते हैं । आज हमारे देश में निम्न लिखित शिक्षा-क्षेत्रों पर गवेषणा की अत्यधिक जरूरत है :

१. पाठ्य-क्रम निर्माण के लिए प्रायोगिक कार्य,
२. शिक्षा-प्रबन्ध तथा प्रशासन,
३. शिक्षकों का कार्य-बोझ,
४. शिक्षण-पद्धति की उन्नति,
५. भारतीय शिशु का मनोविज्ञान,
६. निर्देश एवं पगदर्श,
७. परीक्षा,
८. बुद्धि-परीक्षण, एवं
९. शिक्षण सभा-शास्त्र ।

**समन्वयता का अभाव.**—अन्त में हम शिक्षक-प्रशिक्षण प्रणाली में समन्वय का अभाव देखते हैं । उदाहरण स्वरूप द्वितीय-दिव्योमाओं का नामकरण ही लीजिए — एम० ईडी०, एम० ए० (निष्ठा), एम० टी०, पी० टी०, पी० एड०, एल० टी०, सी० टी०, टी० टी० सी०, डि० टी०, टी० टी० इत्यादि । फिर ट्रेनिंग की आरंभ टीटिए । कहीं एम० ईडी० का कोर्स दो वर्ष है, और कहीं एक वर्ष । यही बात स्नातक पाठ्य क्रम का भी है । इसी प्रकार ‘कालिब्र’ शब्द का उपयोग शिक्षण स्तर की संस्थाओं के लिए आता है । यही तब कि किसी किसी राज्य में माध्यमिक शिक्षण केन्द्रों के लिए भी यह शब्द प्रचलित है । इतना ही नहीं, कहीं ये केन्द्रों ‘नानेत स्कूल’ कही जाते हैं, और कहीं ‘ट्रेनिंग कालिब्र’ । हम अन्तर्निहित रूप से दो बातें भी उल्लिखित कर देना चाहते हैं ।

हमारे शोध-कार्य में भी एक सुशृंगला की आवश्यकता है। कभी-कभी एक ही प्रसंग पर कतिपय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान चलता रहता है, तथा प्रयोगात्मक कार्य होता रहता है। हमारे देश के लिए यह हितकर नहीं है। कारण, हमारा शोध-कार्य पिछड़ा हुआ है। इसी कारण राधाकृष्णन्-आयोग ने मिफारिश की थी कि अनुसन्धान-कार्य की व्यवस्था अखिल भारतीय आधार पर हो।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रशासन में हम गड़बड़ी देखते हैं। किसी-किसी राज्य में तो उत्तर-स्नातक, स्नातक तथा उप-स्नातक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशासन दो विभिन्न निकाय करते हैं; अर्थात्, विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग। हम अव्यवस्था को दूर करने के लिए, माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने यह प्रस्ताव किया था :

स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को स्वीकृति तथा मान्यता विश्वविद्यालय देये और वे ही डिग्रियाँ प्रदान करें। उपस्नातक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की मुख्यवस्था तथा समुन्नति के लिए एक विशिष्ट मण्डल प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाय।†

## शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ

**शिक्षकों का स्थान.**—किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षक का। शिक्षा की उन्नति के लिए, अवश्य उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, शिक्षा-साधन, शाला-गृह की जरूरत है। पर उनमें क्यात्र जरूरत है पर्याप्त रूप में उपयुक्त शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की। वे ही शिक्षा-पद्धति को चलाते हैं, वे ही पुस्तक, नक्शों, भण्ड-दण्ड उपकरणों का उपयोग करते हैं और उन्हें छात्रों को समझाते हैं, वे ही शाला-गृह में एक नवीन जीवन डाल देते हैं। देश के भावी नागरिकों का निर्माण वे ही करते हैं। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है।

असु, अष्टे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा-पद्धति निर्दोश और निम्नेत्र हो जाती है। यही समस्त घर, प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षकों का एक विशिष्ट स्थान था। राजा और रंक, नर और नारी, पिदान् और निम्नार-मृदावार — सभी गुरु को मान देने थे। समय ने आज पन्थ मारा है। आज, शिक्षक भारतीय समाज का दलित प्राणी है।

**शिक्षकों की संख्या.**—आज, भारत में ११ लाख से अधिक शिक्षक तथा शिक्षिकाएँ विन्यस्त हैं। इनके विभिन्न स्तरों की संख्या का पता तालिका ३० में मिलेगा :

† University Education Commission's Report, p. 216

**तालिका २६**  
**भारत में शिक्षकों की संख्या, १९५६-५७ †**

वर्ग	पुरुष	स्त्री	कुल
विश्वविद्यालय तथा कॉलेज	१३,५५४	४,६१६	४२,१७०
प्राथमिक स्तर :			
प्रशिक्षित ... ..	१,७५,७९७	५०,१३५	२,२५,८१२
अप्रशिक्षित... ..	१,२६,१४१	२०,१६७	२,६७,३०८
प्राथमिक स्तर :			
प्रशिक्षित ... ..	३,५१,०२८	९१,११९	४,४२,१४७
अप्रशिक्षित ... ..	२,१७,८५०	२०,१४२	२,३७,९९२
पूर्व प्राथमिक स्तर :			
प्रशिक्षित ... ..	२२४	१,०३५	१,२५९
अप्रशिक्षित... ..	१०२	७५०	८५२
व्यावसायिक तथा तकनीकी स्तर :	१४,४४२	२,०४९	१६,४९१
विशेष शिक्षानाले स्तर :	२४,२०३	२,२०७	२६,४१०
योग... ..	९,६७,४६१	२,०३,१६०	११,७०,६२१

पन्द्रह प्रति शत शिक्षक महिलाएँ हैं, तथा पूर्व-प्राथमिक स्तरों में अधिकतर शिक्षक महिलाएँ हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या है — माध्यमिक स्तर में ५९.२ प्रति शत (पुरुष ५८.६ तथा स्त्री ७१.१) तथा प्राथमिक स्तर में ५६.६ (पुरुष ५६.६ तथा स्त्री ७१.१) इस प्रकार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षिकाएँ अधिक प्रशिक्षित हैं।

शिक्षकों का वेतन-प्रश्न.—शिक्षकों का वेतनप्रश्न सन्तोषजनक नहीं है, तथा विभिन्न राज्यों की पृथक् नीति है। हम वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए देखते

† Education in the States, 1956-57, pp. 5-6.

हैं तो किसी-किसी राज्य के शिक्षकों को न्यूनतम वेतन-भोगी पाते हैं, जो अत्यन्त हास्यास्पद जान पड़ता है — प्राथमिक शिक्षक ३०], मैट्रिक-पास शिक्षक ४५], स्नातक शिक्षक ७०] एवं हाई स्कूल के हेडमास्टर २००]। अनेक राज्यों में २५ वर्ष नीकरी के पश्चात् एक व्यक्ति १००] मासिक वेतन पर प्राथमिक स्कूल का तथा २००] माहवार पर हाई स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त होता है। इस प्रकार उनके जीवन की उच्चतम आकांक्षा पूर्ण होती है। अवश्य, सभी राज्यों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है।

कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों की स्थिति भी गिरी हुई है। इन अध्यापकों को हम पाँच स्तरों में बाँट सकते हैं — डीन या प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, ट्यूटर ■ डिमोन्स्ट्रेटर। विश्वविद्यालयों में तो यह वर्गीकरण निश्चित रूप से रहता है, पर सम्बद्ध कालिजों में इसका कोई ठीक हिसाब नहीं रहता है। बहुधा 'प्रोफेसर' नामक एक अविशेष रूप से व्यवहृत होता है। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों के वेतन-क्रम भी विभिन्न हैं — किसी विश्वविद्यालय में कुछ, और किसी में कुछ; किसी राज्य में कुछ, तो किसी में कुछ, सरकारी कालिज में कुछ, सौ गैर-सरकारी कालिज में कुछ; साधारण कालिजों में कुछ, तो व्यावसायिक कालिजों में कुछ। इस समस्या की आलोचना करते हुए 'राधाकृष्णन आयोग' ने कहा ही है, "इस प्रकार समान कार्य करते हुए भी, वेतन असमान है।"† चित्र १६ से कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों के विभिन्न वेतन-स्तर के अनुरूप विमापन का पता चलेगा।

इस प्रकार २५ प्रति शत अध्यापकों को १५५] से कम मासिक वेतन मिलता है, ५० प्रति शत को २२०] से कम तथा ७५ प्रति शत को ३१५] से कम। केवल १० प्रति शत अध्यापकों को ४७२] से अधिक मासिक वेतन मिलता है एवं पाँच प्रति शत को ६१५] से ज्यादा।‡

इस ओर शासकों की दृष्टि थोड़ी-बहुत आकर्षित हुई है। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग कालिज तथा विश्वविद्यालय के वेतन-स्तर की उन्नति तथा उसमें श्रृंखला स्थापना की चेष्टा कर रहा है। शिक्षकों की वेतन-वृद्धि के लिए, भारत सरकार राज्यीय सरकारों को अनुदान भी दे रही है—सन् १९५७-५८ में, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम बढ़ाने के लिए ४१,७२,२५० रु० अनुदान देना स्वीकार किया। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के वेतन-

† University Education Commission's Report, ¶ 73.

‡ Ministry of Education Education in Universities in India, 1954-56, Delhi, Manager of Publication, 1959. p. 29.

वेतन-वर्गों के अनुसार  
कालिज-अध्यापकों का वर्गीकरण  
(१९५५-५६)

मासिक वेतन	(प्रत्येक पूर्ण प्रतीक = १००)	संख्या	
१०० रु. से कम		२,१५४	९.८
१०१-१५० रु.		४,०७५	१३.५
१५१-२०० रु.		५,७१२	१८.९
२०१-२५० रु.		५,६२८	१८.६
२५१-३०० रु.		३,५९९	११.९
३०१-३५० रु.		२,२२२	७.४
३५१-४०० रु.		१,६२३	५.४
४०१-४५० रु.		९८०	३.२
४५१-५०० रु.		८७८	२.९
५०१-५५० रु.		४५६	१.५
५५१-६०० रु.		४४३	१.५
६०१-६५० रु.		३२४	१.१
६५१-७०० रु.		२०४	०.७
७०१-७५० रु.		१६९	०.५
७५१-८०० रु.		२०८	०.७
८०० रु. से अधिक		७१९	१२.४

वृद्धि के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सन् १९५६-५७ में ७६,९५,५०० रु. और १९५७-५८ में १,८५,४६,००० रु. दिया था ।†

**अन्य सुभीते.**—वेतन के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य सुभीतों की भी जरूरत है ताकि वे अपना अध्यापन-कार्य ठीक रीति से कर सकें। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित सुभीतों के आयोजन की सिफारिश की है : (१) उचित प्रावर्हीडेण्ट फण्ड तथा बीमा, (२) मुक्त चिकित्सा (३) बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एव (४) मजबूती प्रथा पर मकान । ‡ हर्ष की बात है कि प्रायः सभी राज्यों में गैर-सरकारी शिक्षकों के लिए प्रावर्हीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की गई है—शिक्षक अपने वेतन का ६६ प्रति सत अपने वेतन से देते हैं और उतना ही पैसा परिचालनमग अंशदान करते हैं।

**शिक्षकों के प्रति व्यवहार.**—जीवन में केवल पैसा या वेतन ही सब कुछ नहीं है। संस्था के प्रति शिक्षकों के स्नेह की उत्पत्ति तथा वृद्धि परिचालनमग के व्यवहार पर निर्भर रहती है। पर गैर-सरकारी शिक्षकों के प्रति दुर्गवहार के अनेक दृष्टान्त सुने जाते हैं—कहीं कृथा शिक्षकियों सुननी पड़ती हैं, कहीं अकागम ही पडप्युन होना पड़ता है, कहीं वेतन बाट लिया जाता है, तथा कहीं सिर पर कोई भी चढ़ा दिये जाते हैं। अवदर कभी कभी, शिक्षकमग भी निर्दोष नहीं रहते। पर अपिदाश 'जिनकी लट्टी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ होती है। परिचालनमग की अपाधुग्धी बल्की है।

शिक्षकों के ह्वाव के लिए, प्रत्येक राज्यीय शिक्षा विभाग ने बावदे कानून अववय बनाये हैं। पर उनका दयोचित पालन नहीं होता। शिक्षक तथा परिचालनमग के हाकके के निराने के लिए न्याय-समिति (ट्रिब्युनल) की कहीं-कहीं स्थापना हुई है। पर हर तक इसे कानूनी स्वीकृति न मिले, सब तक दूर बटपुतली के समान है। हमका एक दृष्टान्त निछले पक्षों में लिया गया है ।\*

### अपसंहार

हम हर्ष के रसाधीनता-दिदस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान-द्वारा विभूषित किया। पर दिदस दर्शनन शिक्षा-

† भारतीय समाचार, १५ निम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१८।

‡ Secondary Education Commission's Report pp. 1-1-183

\* द.दि. पृष्ठ १९१।

इतिहास में चिन्तन-स्मरणीय रहेगा । कारण सरकार ने प्रकट रूप में, शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया है ।

पर इने-मिने पत्र-वितरणों से काम न चलेगा । शिक्षकों को अपने पैरों पर खुद टाढ़े होना पड़ेगा, उन्हें मिल-जुलकर काम करना पड़ेगा, कटिबद्ध होकर शिक्षक-संघ स्थापित करने पड़ेंगे । ये संघ विविध स्तर में हों—ग्राम्य, राज्यीय, अखिल-भारतीय । इनका सम्बन्ध विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों के मुताबिक भी हो—प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयीय, प्राविधिक, चिकित्सा, शिक्षक-प्रशिक्षण इत्यादि । 'एकता से लाम' का पाठ केवल कक्षा में ही नहीं, पर उन्हें अपने जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यान्वित करना पड़ेगा । उन्हें खुद को न मगवान् के भरोसे ही छोड़ना चाहिए, न दूसरों के भरोसे । स्वावलम्बी हुए बिना जीवन में कभी सफलता नहीं मिलनी । “ये अपनी समस्याओं पर,” जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, “स्वतः विचार करें तथा उनको हल करने का प्रयत्न करें ।”†

† जाकिर हुसैन : “उद्बोधन-भावण”, बिहार राज्यीय शिक्षण-गोष्ठी, १७ फरवरी, १९५८ ।

# दसवाँ अध्याय

## त्रिविध विषय

### १. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

**भूमिका.**—कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ है। वे दौशवावस्था के गौरव को समझने लगे हैं। यह देखा गया है कि मानव-जीवन के प्रारम्भिक छः वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दौशवावस्था में जो संस्कार बालक में डाल दिये जाते हैं, वे ही कालान्तर में मुदढ़ हो जाते हैं और उसके चरित्र-गठन के आधार बनते हैं। ये संस्कार-मनुष्य के आयु पर्यन्त रहते हैं, क्योंकि प्रथम प्रवाह अन्तिम या स्थिर प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त यदि शिशु के प्रारम्भ से ही सबेग तथा स्थायी भाव मुचाइ रूप से निर्मित हो जावें, तो उनका मनुष्य निश्चित ही उच्चतर बन जाता है। अतएव दौशवावस्था से ही, हमें शिशु के जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए।

**पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का रूप.**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अवधि मनुष्य-जीवन के प्रथम छः वर्ष रहती है, अर्थात् शिशु के भूमिष्ठ होने से लेकर प्राथमिक शिक्षा के आरम्भ होने तक। इसमें शामिल है माता-पिता की शिक्षा, पूर्वजन्म-विषयक तथा उत्तर जन्म-विषयक सतर्कता, एवं दौशवावस्था का प्रशिक्षण। यदि वास्तव में पूछा जाय तो इस प्रशिक्षण की सीमा स्कूल के निश्चित घण्टों की शिक्षा तक ही मर्यादित नहीं रहती है। गान्धीजी ने कहा ही है, “यथार्थ शिक्षा मानव-जीवन के गर्भस्थान से ही आरम्भ होती है, क्योंकि इसी समय से माता बच्चे की जिम्मेवारी लेना आरम्भ करती है।” हमें मर्यादा पढ़ने से मादूम होता है कि अमिन्सु ने अन्न-दिवा का रान मुद्रा के गर्भ में अवस्थित रह कर ही अर्जन किया था।

**पाश्चात्य देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति.**—यह के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आरम्भ करने का भेय मुप्रसिद्ध जर्मन शिक्षा-शास्त्री भी प्रोबेल को निम्ना चादिष्ट। उन्होंने सन् १८१७ में जर्मनी के ‘ब्लेकनबर्ग’ नामक नगर में



प्रथम फ्रिडरगार्टन स्कूल स्थापित किया। श्री फ्रीवेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति शिक्षा-उपकरणों में प्रीक्षा-पद्धति में चरितार्थ करने का प्रयाग किया है। फ्रिडरगार्टन पद्धति बालक की चार वर्ष की आयु से आरम्भ होती है।

फ्रिडरगार्टन के बाट नर्गरी (शिशु) स्कूल शुरू हुए। इनकी योजना उन के लिए की गयी थी, जिनके मरदान तंग मरानों तथा गन्धी गलियों में अग्रगण्य और जिनकी माताओं को जीविकोपार्जन के लिए दिन भर बाहर इतस्ततः काम पड़ता था। ये स्कूल अति ही लोक-प्रिय हैं। कारण, ये सरप्राई छोटे बच्चे रखरदारी रखती हैं। जैसा कि धीमती मार्गेट मेकलिन नामक एक अंग्रेजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा-विद् ने कहा है, “नर्सरी स्कूलों की माँग है; कारण, छोटे-छोटे बच्चों को ही ज़रूरत है।”† नर्सरी स्कूल में दो से चार वर्ष वाले बच्चे भरती किये जाते हैं।

इन सब के पश्चात् प्रचलित हुए ‘मोण्टेसरी स्कूल’। इनकी प्रतिष्ठात्री डा० मोण्टेसरी ने अपनी पद्धति तथा शिक्षा-साधनों का प्रयोग निर्धन एवं अस्वाम्य बच्चों के बीच किया था। उनका पाठन-मुक्ति-ग्रन्थ (डायजेक्टिक एपरेट्स) ऐसी ज्ञान के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा शिशु सीधानि सीध शिक्षा कर लेता है, और अपने ही प्रयास से वह पढ़ना-लिखना तथा गिनना सीख लेता। इस प्रकार, यह पद्धति शिशु को ही अपनी शिक्षा का उत्तर-दायित्व देती है।

**पूर्व-प्राथमिक स्कूल क्या है ?**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ अ बच्चों के गर्भाधान-काल से ही होता है, तथा वह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रा तक चलती रहती है; पर एक पूर्व प्राथमिक स्कूल ही २-६ वयोवर्ग के बच्चों देखरेख का भार उठाते हैं। ऐसे पूर्व-प्राथमिक स्कूल में उपर्युक्त तीन पद्धतियों में कोई भी एक प्रचलित रहती है। इस शिक्षा के मुख्य उद्देश्य अधोलिखित ॥ :

१. बच्चों के शारीरिक वातावरण की ओर ध्यान दिया जाय, ताकि शुक्त वायु, धूप तथा प्रकाश का समुचित सेवन कर सकें;
२. स्वास्थ्यप्रद, आनन्दमय तथा नियमानुसार जीवन-यापन व्यवस्था की जावे;
३. शृंगला-बद्ध हाकरी-निरीक्षण का प्रवन्ध हो;

† Margaret Mc Millan. *The Nursery School* London, Dec 1930. p 5.

४. अच्छी आदतों का निर्माण करना
५. शिशु की कल्पना शक्ति के विकास का प्रारम्भ होना
६. बच्चों के सामाजिक जीवन का संगठन होना
७. यह-जीवन के साथ एकता स्थापित होना

इस प्रकार एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल छोटे बच्चा की शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना है। इस स्कूल एक आदत यावत्तया भी हो, ताकि बच्चों को समझ दिया तथा धूप मिले। उनके स्वास्थ्य का जाल जाला समय पर होनी ही चाहिए, ताकि वे नीरोग बनें, और मरना वे किसी घातक से। सो न बन सके। उनके खाने-पीने, उठाने-बैठने तथा सोने का समय दिया हुआ जाना जाला-सोना चाहिए। उन्हें ठीक तरह मुँह धोना पड़ता है। दात तथा ज़रूर साफ़ करना पड़ता है तथा प्रत्येक घण्टा को यथोचित स्थान पर रखना निर्धारित जाना है। इस प्रकार जलन अच्छी आदतों की नींव डाली जानी है। उनका ठीक उच्चारण के साथ शिक्षण करना तथा अभिनय करना पड़ता है। वे गाते हैं, नाचते हैं, खेलते तथा दृष्टा है। अपने शरीर से शरीर का पहचान बना देने हैं एवं नाली के रूप में नदी बहा देना है, जिन चीजों से या कागज़ काटते हैं। सार अर्थ यह है कि एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल शिशु के शक्ति के विकास की ओर सतर्कता पूर्ण ध्यान देना है। यहाँ शिशु पर कोई दबाव नहीं रहता, वह प्रीति की स्वच्छन्द प्रवृत्ति से जलन उठाना है। इस स्कूल में धार्मिक शिक्षा का नामनिर्देशन नहीं रहता है, बल्कि इसका ध्येय बच्चा में अन्तर्गत धार्मिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त करना होता है, जिसके लिए आवश्यक है— तर्कसंगत, अच्छी आदतें, नियमित जीवन, विमुक्त उच्चारण, एकप्रता तथा समझने की शक्ति। एक सुन्यवरिपत पूर्व प्राथमिक स्कूल यह कार्य बहुत कुछ सम्पादन कर सक्ता है।

**भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा.**—भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा ज़रूरत रूप में है। सन् १९५१-५२ में सम्पूर्ण देश में केवल ३३० पूर्व प्राथमिक स्कूल थे जो १९५६-५७ में ७७३। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग १०० स्कूल खुलते जा रहे हैं। इन स्कूलों में ३-६ बच्चों के बच्चे भरती किये जाते हैं। इनके विभिन्न नाम हैं: नर्सरी, प्रिन्सिपल, मोन्टेसरी, बाल मन्दिर, शिशु-विहार, पूर्व प्राथमिक एवं पूर्व प्रिन्सिपल। इन-मिनी संस्थाओं को छोड़कर प्रायः सभी स्कूलों में प्रिन्सिपल का

बहुधा ये संस्थाएँ कोरी कक्षाएँ होती हैं तथा किसी स्कूल से सलग्न होती हैं। यः सभी संस्थाएँ शहरो में स्थित हैं। राजकीय स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। सरकार अवश्य स्वसञ्चालित स्कूलों को अनुदान देती है। अधिकांश स्कूलों की दशा नीची है। न उनके शाला-गृह ही स्वास्थ्यकर स्थान में अवस्थित हैं, न उनमें यथोचित शिक्षा-उपकरण की व्यवस्था है और न प्रशिक्षित शिक्षकों की। आज पूर्व-प्राथमिक शिक्षा इन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है : शिक्षिकाओं की कमी, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण की अव्यवस्था, इस देश के लिए उपयुक्त शिशु-साहित्य तथा शिक्षण-विधि का अभाव, अनुसन्धान तथा बाल-प्रयोग-शालाओं की अनुपस्थिति।

नये प्रयत्न : प्रारम्भिक चेष्टाएँ.—आज सभी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की योगिता स्वीकार करते हैं। डॉ० मोण्टेसरी इस देश में सन् १९४०-४८ तक रहीं। होने सैकड़ों शिक्षकों को स्वतः प्रशिक्षित किया। इसके फल-स्वरूप हमारे देश की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हमारी कुछ आधुनिक सरकारी स्कूलों ने भी इस शिक्षा की अच्छी कदर की। उदाहरण-स्वरूप 'केसशिम्' की द्वितीय समिति ने मुझाव दिया कि अनिवार्य शिक्षा की सहायता के लिए नर्सरी स्कूल क्लासों की आवश्यकता है। सार्जेंट रिपोर्ट और भी आगे बढ़ी। उसने सिफारिश की कि सरकार को चाहिए कि अपने भावी नागरिकों के लिए स्वास्थ्यप्रद नर्सरी स्कूल प्रारम्भ करे। इनमें शिक्षिकाओं तथा शिक्षा-उपकरणों का यथोचित प्रबन्ध हो। सार्जेंट रिपोर्ट ने मुझाव दिया कि इस देश में दस लाख ३-६ बयोंवर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। हाल ही में अनुमान-समिति की चौथी रिपोर्ट को लोक-सभा में प्रस्तुत करते हुए श्री धन्यन्तराय मेहता ने कहा, "पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विषय में ऐसी अखिल भारतीय नीति नहीं है, जिससे राज्यों तथा व्यवस्थापकों के बीच निर्देश मिल सके।" समिति ने मुझाव दिया कि कुछ शिक्षा-शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों से परामर्श लेकर शिशु-शिक्षा के प्रबन्ध एवं प्रसार के लिए कुछ नियम किये जावें।

**पूर्व-प्राथमिक शिक्षा.**—पूर्व प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में कुछ नये प्रयोग हो रहे हैं। यह शिक्षा गर्भाधान से शुरू होकर सात वर्ष की आयु तक चलती रहती है। इसके मुख्य चार प्रक्रम हैं : (१) गर्भाधान से जन्म तक, (२) जन्म से २½ वर्ष की

† Sargent Report. p 18.

‡ Estimates Committee, Elementary Education, 1957-58

Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. p 6

आयु तक, (३) २३ वर्ष से ४ वर्ष की आयु तक और (४) ४ से छः वर्ष की आयु तक। प्रथम दो प्रक्रमों का सम्बन्ध केवल माता तथा बच्चे के साथ रहता है। इस कारण, पूर्व-बुनियादी स्कूल के साथ एक मातृ-कल्याण सदन का रहना आवश्यक है, ताकि माताओं को अपने तथा बच्चे के सम्बन्ध में यथोचित सलाह मिल सके।

अढ़ाई वर्ष की आयु में, बच्चा एक पूर्व-बुनियादी स्कूल में भरती होता है तथा वहाँ सात वर्ष की आयु तक रहता है। शिशु के प्रशिक्षण में इन बातों की ओर ध्यान दिया जाता है : (१) पाठ्य-प्राप्य, (२) डाक्टरों निरीक्षण (३) आत्म-विकास, (४) सामाजिक प्रशिक्षण, (५) शिष्टाचार स्वरूपात्मक कार्य-कलाप, (६) गीत, कहानी तथा अभिनय द्वारा उच्चारण विकास, (७) अक-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि, (८) वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, (९) समीत एवं लय और (१०) कला। शिक्षा जीवन-स्थिति या शिशु के भ्वाभाविक क्षतायण की परिस्थितियों में सम्बन्धित रहती है।

समन्वय पद्धति.—आज, पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त हमारे देश की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ तो किण्वरगार्थन पद्धति या मोण्टेसरी पद्धति का ही अनुकरण करना चाहते हैं, कुछ पूर्व-बुनियादी शिक्षा को अगना रहे हैं तथा कुछ मोण्टेसरी एवं पूर्व बुनियादी शिक्षा में एक समन्वय स्थापना की चेष्टा कर रहे हैं। तृतीय वर्ग की समस्याओं में नूतन कार्य-शिक्षण-मण, भावनात्मक प्रदान है। हमारे कार्य-कलाप मोण्टेसरी तथा पूर्व बुनियादी पद्धति के अच्छे गुणों के आधार पर एक नवीन प्रयोग लागू रहे हैं। सम्भवतः यह पद्धति हमारे देश के पूर्व प्राथमिक स्तरों के लिए अनुकूल तथा उपयुक्त सिद्ध होगी।

उपसंहार.—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रसार आज सभी चाहते हैं, और हमारा विना अधिक प्रयास होगा, उतना ही यह राष्ट्र के लिए हितकर होगा। पर हमें दो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा : अर्थोन्नति तथा शिक्षकों की कमी। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अर्थोन्नति प्रशिक्षण का है। हम हमें ही हल नहीं कर पा रहे हैं। तब हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा विस्तार का बीड़ा किस पूरे उठा सकेंगे ? लेकिन हमें हल-मार्ग नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश की निजी समस्याएँ हलनीय हैं। हमें भारत की शिक्षा समस्याओं का समाधान निम्न रीति से करना पड़ेगा।

प्रथमतः, हमारे देश में इने-गिने शहर हैं, और समूचे देश में गाँवों का मानो जाल बिछा हुआ है। इन गाँवों में पहुँचने के लिए लम्बे मार्गों को तय करना पड़ता है। मार्गों की यह दूरी पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की स्थापना में बाधा पहुँचानी है। अतएव कुछ समय तक गाँवों को ठहरना पड़ेगा, और हमें अभी शहरों की ओर ही अधिक ध्यान देना उचित है। शहर में भी हमें अमीर, मध्यम वर्ग तथा गरीबों का ख्याल करना पड़ेगा। अमीर तो निस्सन्देह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अध्यापिकाएँ नियुक्त कर सकते हैं, या, सर्वोत्तम पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोल सकते हैं। उन्हें पैसे के लिए पराया मुख ताकना नहीं पड़ता है। परन्तु वस्तुतः ऐसी संस्थाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है उन गरीब बच्चों के लिए, जिनके माँ-बापों को दिन भर काम करना पड़ता है, जिनके पेट में कठिनाई से दाना पड़ता है, और जो गन्दी गलियों में निवास करते हैं। ऐसे ही बालक-बालिकाओं के लिए मुक्त-वायु स्थित नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता है। जब तक इन असहाय बच्चों की ओर हम उचित ध्यान न देंगे, तब तक हम इस राष्ट्र को उन्नत मस्तक न कर सकेंगे।

मध्यम वर्ग के लिए, हमें माता-पिता सम्बन्धी एवं पारिवारिक शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। कारण, शिशु के सब प्रथम शिक्षक हैं उसके माता-पिता। अतएव उन्हें शिशुओं के पालन-पोषण का यथोचित ज्ञान होना चाहिए। यह शिक्षा उन्हें विवाह के पूर्व, स्कूल तथा कालिज में देना उचित है। प्रौढ़ों को भी उत्तर जन्म-विषयक तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हितकर सिद्ध होता है। अपठ प्रौढ़ों के साथ भी परिवार-योजना की चर्चा करनी चाहिए।

इस प्रकार हमें अपने घरों की स्थिति ठीक करनी चाहिए। कारण, देश की समृद्धि यह-यह की उन्नति पर निर्भर रहती है। मनुष्य-जीवन की उन्नति का बीज घर में ही बोया जाता है। उचित वातावरण में वह पल्लवित होकर शाखाएँ प्रशाखाएँ फैलाने लगता है। यदि वातावरण अनुकूल न हुआ तो वह अङ्कुरित होने के पश्चात् ही कुम्हलाने लगता है।

## १. प्रौढ (समाज) शिक्षा

### प्रस्तावना

विशेषता.— सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार देश की कुल जन-संख्या ३५.७ करोड़ थी, अर्थात् पृथ्वी की संपूर्ण जन-संख्या की १५.१ प्रति शत जन-संख्या इस देश में वास करती थी। इस जन-संख्या में १६.६ व्यक्ति माक्षर थे—२४.९ पुरुष एवं ७.९ स्त्री, अथवा ३४.६ प्रति शत शहरी लोग और १२.१ ग्राम-वासी।

अतएव, आज प्रौढ़ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। निरक्षरता देश की उन्नति पग-पग पर बाधा डालती है। चाहे हम कोई भी जीवन-क्षेत्र लें, आर्थिक, राज-नैतिक या सामाजिक। इन सबमें प्रौढ़ जन ही समाज के मुखिया के रूप में हमारे सामने आते हैं। परिवार की उन्नति भी उन्हीं पर निर्भर रहती है। अपढ़ मनुष्य देश का बंधा बन्धु राजु होता है। वास्तव में वह शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाता है, फलतः वह अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देना चाहता। अशिक्षित प्रौढ़ ही बच्चों की शिक्षा में बाधा डालते हैं। अस्तु, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के यथोचित मार्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है।

प्रौढ़ कौन है ?—‘प्रौढ़’ तथा ‘प्रौढ़ शिक्षा’ का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का होता है। इंग्लैण्ड के सन् १९४४ के शिक्षा कानून के अनुसार, अठारह वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का बन्दोबस्त किया गया है, तथा अठारह वर्ष की आयु तक उन्हें आशिक सातव्य शिक्षा मिलनी है। अठारह वर्ष की ऊपर की आयु के व्यक्ति ही इंग्लैण्ड में प्रौढ़ गिने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और स्त्री कम्प्लेक्स (प्रौढ़) कहे जाते हैं। हमारे देश का लक्ष्य ६-१४ वर्षोवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, अतएव १४ वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को हम प्रौढ़ कह सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के रूप.—‘प्रौढ़ शिक्षा क्या है ?’—इस विषय पर भी मतभेद है। प्रसिद्ध अमरीकी विद्वान् हाहमन का कथन है, “इस शिक्षा के अन्तर्गत हम मनुष्य के उन शैक्षणिक कार्य-कलाओं का गिन सकते हैं, जिनका उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में करता है और जिनसे उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है।” इसी प्रकार अंजेल विद्वान् भी अर्नेस्ट बार्कर का मत है, “अपने जीविकोपार्जन के साथ-साथ वह शिक्षा प्रौढ़ों को अंश-कालिक रूप में मिलती है। अतएव इस शिक्षा के अन्तर्गत वे सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक उपदेश आ सकते हैं, जिन्हें हम कक्षाओं को दे सकते हैं।”

हमारे देश में इस शिक्षा के दो रूप हैं : (१) प्रौढ़-साक्षरता, अर्थात् उन बच्चों की शिक्षा, जो निरक्षर हैं, एवं (२) शिक्षित प्रौढ़ों की सातव्य शिक्षा।

प्रौढ़-साक्षरता से समाज शिक्षा

पूर्य-पूर्यवत्.—मागत में बर्मी ऐसा समय नहीं रहा है, जब कि जन-समाज को शिक्षित करके उसके जीवन को उन्नत करने के साधन नहीं अपनाये गये हों। वैदिक काल में प्रत्येक परिवारिक या सन्तानही का बर्तव्य था कि वह नगर-नगर और

ग्राम-ग्राम घूम कर अध्यात्म-नीति तथा सदाचार का प्रचार करे। तत्पश्चात् हमारे सामाजिक जीवन के उन्नयन का प्रेरक एक और साधन था, वह था कथाओं, कीर्तनों, रामलीलाओं, नाटकों आदि की परम्परा। मध्य युग में हमारे माट, चारण, जोगी और ब्रजल द्वार-द्वार पर घूम-घूम कर मित्रता का पाव लिये, सारंगी अथवा अन्य वाद्य की तुमधुर ध्वनि के साथ उपदेशात्मक पद्य सुनाया करते थे। पर आजकल मित्रता वृत्ति एक व्यवसाय-मात्र है।

**ब्रिटिश युग.**—ब्रिटिश युग में हम प्रौढ़ शिक्षा के विकास को दो मुख्य कालों में बाँट सकते हैं। प्रथम काल की अवधि सन् १८५७ से १९१९ ई० तक समझी जाती है, अर्थात् ईस्ट इंडिया कम्पनी के पतन से सन् १९१९ ई० के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया कानून तक। इस अवधि में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ छिट-पुट प्रयत्न अवश्य किये गये। इन सबका उद्देश्य निम्न-श्रेणी के बच्चों तथा बच्चों को साक्षर बनाना था। इसी उद्देश्य से, मिशनरी मण्डलों ने कुछ प्रौढ़ पाठशालाएँ खोलीं तथा औद्योगिक केंद्रों में कतिपय रात्रि शालाएँ सञ्चालित हुईं। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का आरम्भ सन् १९१० में हुआ। इस अवधि के अन्त में कुछ रात्रि पाठशालाएँ मद्रास, बम्बई, बंगाल, मैसूर तथा बड़ौदा में चल रही थीं, पर उनमें उचित व्यवस्था न थी।

प्रौढ़ शिक्षा विकास का द्वितीय युग सन् १९१९ से १९४७ तक माना गया है, अर्थात् गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया कानून, १९१९ से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक। इसी अवधि में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास आरंभ होता है। माण्टफोर्ट सुधार तथा प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों में एक नवीन चेतना आरम्भ कर दी। सुधार के कारण, मत-दान का क्षेत्र विस्तृत हो गया; इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जनता अपने हक को सोचे-समझे। प्रथम विश्व-युद्ध के कारण, अपढ़ सिपाही अन्य देशों के सम्पर्क में आये। ये हमारे देश में नये विचार लाये और उनमें ज्ञान की पिपासा उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त माण्टफोर्ट सुधार के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की बागडोर भारतीय शिक्षा-मान्त्रियों के हाथ में आयी। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया।

इस प्रकार प्रौढ़-साक्षरता का आन्दोलन पूरे देश में आरम्भ हुआ। प्रौढ़ शालाएँ तथा रात्रि पाठशालाएँ खुलीं, कई प्रान्तों में ग्रामीण पुस्तकालय तथा चलते-फिरते पुस्तकालय स्थापित हुए। साक्षरता-प्रचार के उद्देश्य से, अनेक स्थानों में, गैर-सरकारी संस्थाएँ भी खोली गयीं। सरकार ने उन्हें अनुदान अवश्य दिया। सन् १९१८ में भारतीय प्रौढ़-शिक्षा समिति दिल्ली में स्थापित हुई। यह समिति क्रमशः भारत की केन्द्रीय संस्था बनने की ओर अग्रसर होने लगी।

सन् १९४२ ई० के राजनैतिक आन्दोलन और ब्रिटिश दमन नीति का विपरीत प्रभाव साक्षरता आन्दोलन पर भी पड़ा। इस नीति के फल-स्वरूप सन् १९४२ से सन् १९४७ तक सभी प्रान्तों की प्रौढ़ शिक्षा-प्रगति में शिथिलता आ गयी। मिला-मिला कर सरकारों ने अपने आय-व्यय की प्रकृति को घटाकर सीमित क्षेत्र में तय सीमित दम पर साक्षरता प्रसार के कार्य को जीवित करने दिया।

**प्रौढ़ शिक्षा को नया रूप.**—सन् १९४७ तक प्रौढ़ शिक्षा का एक मात्र ध्येय केवल साक्षरता था, पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का अवतरण हुआ। 'केमसिम' के पन्द्रहवें अधिवेशन के समय (जनवरी, १९४४) शिक्षा-मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने घोषणा की कि स्वाधीन भारत में प्रौढ़ शिक्षा का ध्येय केवल साक्षरता नहीं हो सकता है। इस शिक्षा को समाज शिक्षा का व्यापक रूप दिया जाय, जिसमें न केवल साक्षरता का स्वाभाविक हो बल्कि स्वस्थ, सामाजिक चेतना, उन्नत कृषि तथा कला आदि सर्वोद्योग के समर्थकों का समावेश हो।

**समाज-शिक्षा का कार्यक्रम.**—समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पञ्च-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके उद्देश्य ये हैं : (१) साक्षरता प्रसार, (२) स्वस्थ तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना, और (५) समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।<sup>१</sup>

**समाज शिक्षा आन्दोलन**

**भूमिका.**—मौलाना आज़ाद की घोषणा के पश्चात्, प्रौढ़ शिक्षा में एक नया ज्ञान आया। सन् १९४८-४९ के बाद समाज-शिक्षा-प्रसार के लिए स्पष्ट चेष्टाएँ आ गयी हैं। इन सबको हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं : (१) प्रशासन, (२) समाज शिक्षा सरपार, (३) समाज शिक्षा व्यवस्थापक और कार्य-कर्त्ताओं का प्रशिक्षण, (४) गोष्ठियाँ, और (५) उत्तर-साक्षरता का प्रश्न।

**प्रशासन.**—केंद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय अखिल भारतीय स्तर पर समाज शिक्षा को अंगीकृत करता है। यह कार्य योजना-आयोग तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय के सहयोग से चलाया जाता है। अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय-भवन, परिदहन एवं प्रतिगन्ध—खनः कुछ प्रोत्साहन प्रदान करता है।



केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के मुख्य कर्तव्य हैं : संयोजन, निर्देशन एवं धार्मिक सहायता । प्रथमतः, मन्त्रालय उन योजनाओं का विचार करता है, जिन्हें वह स्वतः सुझाता है और जिन्हें विभिन्न राज्य-सरकारें चलाती हैं । द्वितीयः, 'केमशिम' अथवा अन्य परिपदों की बैठकों में भारत के विभिन्न समाज-शिक्षा विषयक कार्य-कलाओं पर विचार विमर्श हुआ करता है । इन सामूहिक बैठकों का निर्णय देश के लिए हितकर सिद्ध होता है ।

समाज शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए कई समितियाँ हैं । प्रथम निकाय है 'केमशिम' की समाज शिक्षा स्थायी समिति, जो सन् १९४८ में स्थापित हुई थी । यह समिति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बयस्कों की शिक्षा समस्याओं पर परामर्श देता है । द्वितीय निकाय है 'केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल' । इस स्वायत्त-शाली संस्था की स्थापना अगस्त, १९५३ में हुई थी । इसके द्वारा समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वेच्छिक समाज सेवा संगठनों को सहायता-अनुदान दिये जाते हैं । समाज शिक्षा इस मण्डल का एक मुख्य काम है । तृतीय निकाय है 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र' । उच्च कर्मचारियों को समाज शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुई समस्याओं पर उपयुक्त शोध-कार्य करने के लिए, इस संस्था की स्थापना हुई है ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है । शोध-कार्य तथा नव-साक्षरों के साहित्य के प्रकाशन के प्रोत्साहन के लिए भी वह आर्थिक सहायता देती है । इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा की कुछ गोट्रियों को या तो वह स्वयं चलाती है, अथवा अन्य संस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान देती है ।

सामाजिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व प्रधानतः राज्य-सरकारों पर ही है, पर इस विषय पर द्वैध शासन है । शिक्षा विभाग, अपना पुराना कार्य चलाते हैं; पर समाज शिक्षा के नवीन अंगों का परिचालन सामुदायिक विकास विभाग करता है । अनेक राज्यों ने इस द्वैध शासन का बहिष्कार किया है । उसका अधिकार एक ही निकाय की अधीनता में रहता है, चाहे सम्पूर्ण प्रशासन न हो ।

सम्पूर्ण राज्य का प्रशासन एक विविष्ट अफसर करते हैं, और उनके नीचे क्षेत्रीय और/या जिला-व्यवस्थापक रहते हैं । विभिन्न स्तर के अधिकारीगण सलाहकारी समितियों की सहायता से काम करते हैं : राज्य, क्षेत्र, जिला या नगर । राज्यीय तथा क्षेत्रीय समितियों का कर्तव्य केवल परामर्श देना ही रहता है, पर जिला या नगर समितियों को

जनता के प्रतिष्ठ सम्पर्क में आना पड़ता है, समाज सेवा के कार्य-कलापों को चलाना पड़ता है, और यदि हेर-फेर की आवश्यकता पड़े तो सरकार को सलाह देना पड़ता है।

**संस्थाएँ**—समाज-सेवा के पंचमुखी उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए विविध प्रकार के संस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक वर्गक अपनी तथा देश की आवश्यकताओं को समझ सके और समाज के निकटतम सम्बन्ध में आ सके। नीचे कनिष्ठ मुख्य समस्याओं का विवरण दिया जाता है।

**माधुरता—बच्चाएँ**—प्राथमिक समस्याओं का उद्देश्य बच्चों की निरक्षरता निवारण करना था। सन १९५३ तक इन संस्थाओं की संख्या ४०,००० थी। इस समय प्रति वर्ष प्रायः चार लाख बच्चे उठाने में। सामुदायिक विकास की कार्यवाही कारण, इन कार्य को विनियमित प्रोत्साहन मिला। इस विकास के आरम्भ होने के प्रारंभ ही ७,००० नयी बच्चाएँ खुलीं, जिनकी छात्र संख्या ९८,००० थी। सन १९५५ के अन्त तक सामुदायिक विकास-खण्ड ७५,००० बच्चाएँ चला रहे थे, जिनमें लाख से अधिक प्रौढ़ समाज-शिक्षा पा रहे थे। निरक्षरता निवारण योजना का प्रचलित दृष्टान्त है।

✓ **समाज-सदन**, कभी-कभी माधुरता-बच्चाएँ विकसित होकर समाज-सदन रूप धारण करती हैं। इन संस्था में गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं। इसमें आमोद-प्रमोद खेल का प्रबन्ध रहता है तथा लोग विविध विषयों की चर्चा भी करते हैं। किसी सदन में तो व्यायाम-घाटा, उद्योग-शिक्षा, ज्ञान-गुरु, आदि की व्यवस्था रहती है।

✓ **तरण संघ**—बेचल-बुद्ध तरणों को ग्रिप्त होते हैं। इन कार्य के लिए, वे स्थापित करते हैं। धीरे-धीरे सच अन्य कार्य भी आरम्भ करते हैं, जैसे : नाट्य-प्रदर्शन, निरक्षरता परिश्रम, स्वायत्तता, सेवा-समिति, सुखा दल, इत्यादि। एक प्रदर्शन गाँवों में कभी-कभी तरण-बुद्ध संघ की स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान विभाग एवं सेवा की उत्पत्ति। अधिकतर ऐसे संघों की स्थापना पंचायत समिति द्वारा है।

**महिला-समिति**—प्रत्येक सामुदायिक विकास-खण्ड में एक महिला-समिति है। उसका काम ही महिला-संस्थाओं की स्थापना करना होता है। इन समितियों के कार्य होते हैं : (१) भवन तथा भोजन के लिए देशीय औद्योगिक सामान, (२) उच्चतम तथा लोचनी का सफाई, (३) घर उत्पत्ति तथा विद्युत-संचय, (४) कृषि एवं सेवा, (५) एक विज्ञान और भोजन स्थान, (६) कुत्तों, भित्तों, दलितों

कोई अन्य इन्सोपोग, (७) पाठों, भाषण, प्रदर्शनी, आदि, (८) मेल-बूट शिबिरों आदि का आयोजन, (९) गाग मन्त्री की कारियों स्थाना, (१०) गाथता, इत्यादि।

विस्तार.—गत कुछ वर्षों में समाज शिक्षा का कार्य विस्तार हो रहा है। विस्तार का अनुमान निम्नलिखित तालिका से दिया जा सकता है।

### तालिका २७

समाज शिक्षा का विस्तार, १९५१-५२ से १९५५-५६

वर्ष	शिक्षा, केन्द्र, स्कूल	छात्र-संख्या	साक्षरता प्रमाण-पत्र वितरण	खर्च (लाख रुपये)
१९५१-५२	४३,४६३	१०,६१,२८०	४,८९,१३५	७१.८३
१९५२-५३	४४,५९५	१०,८८,७८४	४,४२,७००	७३.७७
१९५३-५४	३९,९६५	९,४८,८४७	३,९२,४४०	६२.०५
१९५४-५५	४३,२२३	११,३१,४०५	४,६९,१०१	७७.४६
१९५५-५६	४६,०९१	१२,७८,८२७	५,४५,२२१	९६.८०

सन् १९५५-५६ में कुल संस्थाओं की संख्या ४६,०९१ थी। जिनमें १३,९७४ सरकारी, ४५८ जिला-मंडल की, २८२ नगर-पालिका की एवं ३२,०७७ स्वसंचालित थीं। खर्च का आवण्टन इस प्रकार था : सरकारी ९२.२ प्रति शत, स्थानीय मण्डल १०.० प्रति शत एवं अन्य स्रोत ४.८ प्रति शत।

संस्थाओं के प्रोग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल थे :

१. शैक्षणिक.—साक्षरता-कक्षा, वाचनालय, समाचार-सूचना-पट, पुस्तक-आलोचना, प्रवचन, वाद-विवाद, गोष्ठी, प्रदर्शनी, भाषण, प्रारम्भिक तथा अत्यावश्यक चिकित्सा, इत्यादि।

२. सांस्कृतिक.—अल्प हस्त उपकरणों का उपयोग, नाट्यभिनय, लोक-गीत, लोक-नृत्य, कवि-सम्मेलन, मुद्रापत्र, प्रीति भोज, इत्यादि ।

३. आमोद-प्रमोद.—कथा, भजन, खेल-कूद, प्रीति-यात्रा, तैरना, निरुद्देश्य परिभ्रमण, इत्यादि ।

४. कला और हस्तोद्योग.—बुनाई, सिलाई, दर्जीगिरी, कढ़ीदे का काम, बागदानी बटईगिरी, साबुनसाजी, पाक-क्रिया, कागज बनाना, इत्यादि ।

५. समाज-सेवा.—प्रयात फेरी, नागरिक आन्दोलन, सफाई कार्य-क्रम, गरीब मुहल्लों की सफाई, पागानों आदि का निर्माण, साक्षरता-आन्दोलन, इत्यादि ।

**समाज शिक्षा-कार्य-कर्त्ताओं का प्रशिक्षण.**—समाज शिक्षा एक कला है, और इसकी विशेषज्ञता प्रशिक्षण के बिना सम्भव नहीं है । समाज शिक्षा-कार्य करने-वाले मुख्यतः तीन कोटिओं में विभक्त हो सकते हैं : (१) व्यवस्थापक, (२) कार्य-कर्त्ता शिक्षक तथा बहुमुख्य ग्राम-स्तर कार्य-कर्त्ता (ग्राम-स्तर पर समाज शिक्षा का संगठन करनेवाला, समाज-सेवक, शिविर-व्यवस्थापक, समाज-केन्द्रों का संचालक, ग्रामीण युवक कल्याण व्यवस्थापक) एवं (३) संगठन कर्त्ता । ये धैतनिक और अधैतनिक—दोनों—हो सकते हैं ।

व्यवस्थापक तो उत्तर-रत्नाक्त प्रशिक्षित होते हैं । उन्हें व्यावसायिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा समाज-सेवा महाविद्यालयों में मिलनी है । कार्य-वर्णगा किसी समाज शिक्षा-केन्द्र या जनता-कालिज में प्रशिक्षित होते हैं । भारत में इन केन्द्रों की संख्या प्रायः शून्य है । इन केन्द्रों में तीन से एक वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है । पाठ्यक्रम की रूप-रेखा नीचे दी गयी है :

१. सैद्धान्तिक (सात वर्ष) : (१) समाज-शास्त्र के सिद्धान्त तथा समाज शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय, और समाज-शिक्षा का इतिहास ; (२) शिक्षण मनोविज्ञान और समाज शिक्षा-विधि ; (३) समाज शिक्षा और समाज सेवा का संगठन तथा व्यवस्था एवं व्यापक शिक्षा ; (४) कृषि एवं गृह-उद्योग एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र ; (५) अल्प हस्त शिक्षा और लोक साहित्य तथा लोक कला ; (६) ग्राम-पंचायत, सरदार, सामुदायिक विकास योजना एवं (७) सामान्य जनशरी ।

**२. व्यावहारिक :** गान्ठिक जीवन का अभ्यास, शौर का प्रशिक्षण, भव्य दृश्य कला का प्रशिक्षण, गान्धनिक समस्याओं में भाग, प्रदर्शनी, उत्सव तथा त्योहारों का संगठन, आदि ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण-शिक्षा के अनिवारिक दान-मुषार कार्यक्रमोंओं को सहस्रान्ति तथा कृषि-मुषार की शिक्षा दी जानी है । गाँवों की सर्वतोन्मुखी उन्नति और मुषार के लिए ग्राम-मेरुसंग भी प्रायः इसी दृष्टि से प्रशिक्षित किये जाते हैं ।

**गोष्ठियाँ.**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा-आन्दोलन एक महत्वपूर्ण अभियान है । विभिन्न एशियाई देशों की अन्तरादीय गोष्ठी इस दिशा में एक उत्तेजनायक घटना है । यह गोष्ठी मन् १९४९ में मैसूर में मरी थी । उसमें अनेक एशियाई देशों ने भाग लिया था तथा वयस्क शिक्षा की अनेक समस्याओं पर महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे । तब से हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर गोष्ठियों का आयोजन हुआ ही करता है — अल्पित भारतीय, राज्यीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय । गोष्ठियों में समान शिक्षा के व्यवस्थापकगण, संगठन कार्य-कर्तागण तथा अन्य कार्य-कर्तागण एकत्र होते हैं, और सामूहिक रूप से इस शिक्षा विवरक तथ्यों की आलोचना करने हैं, जैसे : प्रशासन, अनुदान, पाठ्य क्रम, प्रशिक्षण, नवसाक्षर-साहित्य, भव्य-दृश्य-उपकरण, इत्यादि ।

**उत्तर-साक्षरता का प्रवन्ध.**—सामाजिक शिक्षा की जिम्मेवारी साक्षरता प्रमाण-पत्र विनग्न के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है, वरन् यह भी देखना पड़ता है कि नवशिक्षित वयस्क अपनी साक्षरता स्थिर रख सकें । अतएव उत्तर-साक्षरता का प्रवन्ध करना चाहिए, ताकि समान शिक्षा-द्वारा जो कुछ एक प्रौढ़ ने सीखा हो, उसकी घोड़ी बहुत चर्चा प्रौढ़ों में परस्पर हुआ करे । इसके लिए तीन विषयों की व्यवस्था चाहिए : (१) नव साक्षर-साहित्य प्रकाशन, (२) भव्य-दृश्य उपकरणों का निर्माण एवं (३) पुस्तकालयों का प्रवन्ध ।

राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार ने नव-साक्षर साहित्य प्रकाशन की घोड़ी-बहुत व्यवस्था की है । प्रथमतः, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्तम वयस्क-पत्रों की पुस्तकों के लेखक को इनाम दिया जाता है तथा प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन पुस्तकों की अनेक प्रतियाँ सरकार खरीदती है । द्वितीयतः, नव-साक्षरों के उपयोग में हिन्दी पुस्तकें भी सरकार खरीदती है, जिनका आधा खर्च भारत सरकार देती है और आधा राज्यीय सरकार । इसके अतिरिक्त पैकिंग और यातायात का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार स्वयं ही वहन करती है । तृतीयतः, समय-समय पर सरकार विशिष्ट कर्मशालाओं

## विभिन्न विषय

की आयोजना करती है। इनमें लेखकों को इस नवीन साहित्य पर लिखने का प्रोत्साहन दिया जाता है। चतुर्थतः, सरकार स्वयं नव-साधर साहित्य का प्रकाशन करती है। कुछ स्वीकृत संस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान देती है। हाल ही में "राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट" की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आदर्श पुस्तकों का प्रकाशन है।

द्विती में 'केन्द्रीय अथवा राज्य शिक्षा-संस्था' स्थापित हो चुकी है। यह भारत एवं राष्ट्रीय सरकारों को अथवा-राज्य शिक्षा के विषय में परामर्श देती है। चल-चित्र संग्रहालय में शिक्षा तथा सस्कृति-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,९७ चित्र आदि हैं, जो संग्रहालय की 'सदस्य शिक्षा-संस्थाओं' को निःशुल्क दिये जाते हैं। १,००५ शिक्षा-संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'अथवा-राज्य शिक्षा' क्षेत्रिक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। समय-समय पर केन्द्रीय तथा राष्ट्रीय सरकारें अथवा-राज्य कार्य-कर्त्ताओं की प्रशिक्षण गोष्ठियों का आयोजन करती रहती हैं।

पुस्तकालय उत्तर-साक्षरता का प्रधान अङ्ग है पर हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। सम्पूर्ण देश में लगभग ३२,००० पुस्तकालय हैं। ये समाज-शिक्षा-केन्द्रों या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। औसतन एक व्यक्ति पीछे पचास पुस्तकें हैं और प्रति वर्ष शायद ही दस मनुष्य एक से अधिक पुस्तक पढ़ते हैं।

## मातृत्व शिक्षा

**भूमिका.**—खैर की बात है कि हमारे देश में एक शिक्षित व्यक्ति की स्त्री स्कूल या कालिदास की पढ़ाई के साथ समाप्त हो जाती है। स्कूल शिक्षा की समाप्ति पर भी, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को चाहिए कि वह निरा की कुछ न-कुछ व्यवस्थाएँ बनाए, बुद्धिमान इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि यद्यपि मातृत्व शिक्षा सौख्य सकते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र नहीं है—सामाजिक, व्यावसायिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक—सभी जगह कुछ-न-कुछ सीखने की गुंजायिश है। सतत परिवर्तन समाज का नियम है। जो व्यक्ति इस बदलते हुए ज्ञान के अनुरूप नहीं रहेगा, वह जल्द असन्तोषी तथा शिवायनी रहेगा।

शिक्षित व्यक्तियों की ज़म्मेदारी को देखते हुए मातृत्व शिक्षा तीन स्तरों पर चलती है : (१) उच्च शिक्षित, (२) माध्यम शिक्षित और (३) अल्प शिक्षित।

**उच्च शिक्षित.**—उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए कालिज तथा विश्वविद्यालय प्रवेश का बन्दोबस्त करते हैं। भारत में यह आन्दोलन मन् १९१५ में आरम्भ हुआ था। कुछ प्रविश्व महाविद्यालयों के प्रमाण-केन्द्र शिक्षकों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पर यह यथेष्ट नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रमाण-विभाग की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य हो, उच्च शिक्षित व्यक्तियों में मुचाह रूप से प्रमाण-कार्य करना। इनकी चर्चा ऊँचे अध्याय में की गयी है।

**साधारण शिक्षित.**—पैसे के अभाव के कारण, अनेक भारतवासियों की शिक्षा — सांस्कृतिक या औद्योगिक — पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों के हितार्थ कक्षाएँ चढ़ानी चाहिए। यह प्रथा अनेक सम्य देशों में प्रचलित है। अंग्रेजों का उदाहरण लीजिए। यहाँ हजारों नैश-कक्षाएँ चल्ती हैं, जिनका लाभ लाखों लोग उठाते हैं। इन कक्षाओं में अनेक विषयों की अंश-कालिक शिक्षा दी जाती है। अन्तर औद्योगिक क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। पर ये कक्षाएँ निराला-केन्द्र नहीं हैं। यन् इनका वातावरण बहुत कुछ सामाजिक क्लबों के समान होता है, जहाँ कि वयस्क लोग अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होते हैं।

उच्च शिक्षा की माँग को पूरा करने के लिए तथा नौकरी में स्थित व्यक्तियों की प्रगति के लिए, हमारे देश के केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय पत्र-व्यवहार द्वारा कतिपय देशों के कोर्स का प्रवर्धन करनेवाले हैं। मन्त्रालय विश्वविद्यालयों को नैश-कक्षाएँ देने का भी सुझाव देनेवाले हैं, ताकि दिवा-कक्षाओं में भीड़ की कमी हो तथा देश में स्थित व्यक्तियों को अध्ययन का सुअवसर मिले। शिक्षित वयस्कों के सातत्य को यह पहला कदम होगा।

**अल्प शिक्षित.**—माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है :

यद्यपि सविधान यह निर्देश देता है कि चौदह वर्ष के बालक-शालिकाओं के लिए अंश-कालिक शिक्षा का आयोजन किया जाय, तब पर भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निर्देश कार्यान्वित करना, कुछ समय तक असम्भव प्रतीत होता है।

आयोग ने सिफारिश की है कि ११-१४ वर्षीय (वयोवर्ग के) बच्चों के मिडिल तथा हाई स्कूलों में निःशुल्क, अंश-कालिक सातत्य शिक्षा की व्यवस्था की

देखिए पृष्ठ १७६।

↓ Secondary Education Commission's Report p 56.

जाये। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाय तथा चौदह वर्ष की आयु प्राप्त करते-करते विशोर-विशोरी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें।

हमारी मृतीय एवं मृत्युपं पचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य इस मिफारिश को कार्यान्वित करना है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, यह सामान्य शिक्षा दिवस या रात्रि में दी जायगी। इनका ध्येय छात्रों को प्रथम युनिवर्सिटी या मिडिल स्कूल स्तरान्त परीक्षा के लिए तैयार करना है।

हमारे देश में २०-२५ वर्षोर्ग के अनेक बचस्क हैं, जिन्हें २-३ वर्ष की शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था, और जो अब अध्ययन करना चाहते हैं। इनके लिए दो-तीन वर्ष की अवधि के धना-कारिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिये। कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल में इन बच्चों की महिलाओं के लिए कुछ कौमं चलाये थे। जिनमें पढ़कर कुछ शिक्षार्थिनियों बर्नाकुलर फाइनल परीक्षा में बैठी, और कुछ मैट्रिक परीक्षा में। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् जीविफो-पार्जन के अनेक द्वार खुल जाते हैं, जैसे : ग्राम सेविका, धात्री, शिक्षिका, मुर्ररि, इत्यादि। पुरुष तथा स्त्री, दोनों के लिए, ऐसे प्रयानों की आवश्यकता इस देश में इस समय अनुभव की जा रही है।

इस प्रकार हमारे देश में सातत्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है। यह शिक्षा उन बचप्यों की कमियों को दूर करती है, जिनकी शिक्षा अधोमात्र या अन्य कारणों से अधूरी हो रह गयी है। यह शिक्षा न केवल उनके व्यक्तित्व का विज्ञान करती है, बरन् उनके आर्थिक जीवन को उन्नततर करती है। विविध क्षेत्रों के लिए, लोगों को तैयार कर यह देश की जरूरतों को पूर्ण करता है तथा बेकारी-समस्या के उन्मूलन में योग देता है। देखिय, चीन ने क्या कर दिखाया है :

चीन के विश्वविद्यालय उन युवक-युगत्रियों के लिए भी सदा खुले रहते हैं, जो अर्द्ध शिक्षित होते हैं; या, जिनकी शिक्षा मिडिल स्कूल तक ही रहती है। सन् १९५४ की प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थीलन बैठे, उनमें १६ प्रति शत ऐसे ही छात्र-मृन्द थे और उनका कार्य बोर्ड अमन्तोपम न था।

यह सुभवसर अन्य विद्यार्थियों को भी दिया गया। वे ये ३,००० प्रायमरी शिक्षक एवं विविध उद्योगों के ६,००० ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा नहीं मिली थी। इनका प्रवर्गन सरकार ने किया था।



तत्त्वज्ञान में विशेषज्ञता में प्रसिद्ध हुए थे। वे निर्दिष्ट परीक्षा में नहीं बैठे। इनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था।

### ३. मजबूती की शिक्षा

**मजबूती का चरमोत्कर्ष :** भूमिका.—पीगरी का मत है कि हमें एक युवा पिता बनना है। हमें अपने बच्चों की देखभाल के लिए में अपने अन्य गम्भीर देशी में निष्ठा हुआ है, ताकि हम देश में कुछ सामान बन कर रह सकें। पीगरी मजबूत युवा में मानव बलगत तथा बच्चों की मजबूती की ओर ध्यान देना विशेष आवश्यक हो गया है। जो मजबूत में बना ही है :

मजबूती प्रशिक्षण में मजबूत का प्रयोजन स्पष्ट है। मानव विकास की प्रक्रिया विशेषाधिकारों में बाधित होती है। इस कारण, मजबूत की अवस्था शिशु अधिकांश महसूस है।

**मजबूत चरमोत्कर्ष.**—मजबूती दो प्रकार की होती है — बाह्यमूलक तथा आन्तरिक-मजबूती। वैयक्तिक या सामाजिक अरुणोपन के कारण, प्रथम प्रकार की मजबूती आ जाती है। क्योंकि ये शिशु के सामाजिक सामर्थ्य में बाधित निम्न होते हैं। द्वितीय चरमोत्कर्ष का लक्षण होता है कोई अमानव्य या भद्रता आचार व्यवहार। इसी आन्तरिक अरुणोपन के कारण, ये लक्षण प्रकट होते हैं।

**कारणारम्भक चरमोत्कर्ष.**—इस मजबूती की तीन भेदिकाएँ हैं : शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक।

शारीरिक मजबूत या विकसित तीन प्रकार के होते हैं—अल्प, बड़े और मूल्य, तथा लड़के-लड़कियाँ।

मिन लोगों की बुद्धि औसत में कम होती है, ये द्वितीय भेदी में गिने जाते हैं। बुद्धि-परीक्षाओं के आधार पर, ये व्यक्ति दो भागों में बाँटे जा सकते हैं :

१. सीमा-रेखा स्थित अपूर्ण व्यक्ति.. बोध-लक्षि : ७०-८०।

२. मानसिक दुर्बल

(१) मूर्ख ... ... बोध-लक्षि : ५०-७०।

(२) मूढ़ ... ... " : २५-५०।

(३) जड़ ... ... " : २५ से निम्न।

सामाजिक मजदूर अनाथ या निगमित बच्चे होते हैं। ये घर-द्वार-गृहित होते हैं तथा इनके कोई अभिभावक नहीं रहते।

**लक्षण-सम्बन्धी चर्मीकरण.**—जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक बच्चे की अनेक विषयों की जम्हरी रहती है—शारीरिक, वैदिक या सामाजिक। उसे भोजन, शारीरिक आगम, सामाजिक अभिवृद्धि, ध्याय एवं मर्यादा आदि। परन्तु जीवन में ऐसी अनेक बाधाएँ आ जाती हैं, जिनके कारण, इन आकांक्षाओं की तृप्ति के साधन अनुपलब्ध रहते हैं। इन समस्या-असामञ्जस्यों के कारण, मानसिक रोगों की सृष्टि होती है।

बुद्धि व्यापक अवस्था के कारण, मनुष्य अपने प्रवृत्त वातावरण एवं भ्रमों में सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर पाता है—घोड़ी सी कठिनाई पड़ी और उसका अग्रगण्य भाग उड़ा। वातावरण का अभाव भुल्लास नहीं जा सकता है। वातावरण में मुख्य है : अविद्या, निर्धनता, व्यापारिकता में माना-विता का दुर्व्यवहार। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी एहल्ल के बचनानुसार समाज में निम्न स्थान, स्वरंगार में अग्रगण्यता, वैचारिक जीवन में अमान्यता—ये असामञ्जस्य के प्रमुख कारण हैं। परन्तु वह व्यापक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए साम्य नहीं होता, तथापि कुछ इनके लक्षण इन ही रहते हैं। ऐसे घटनस्थिति अपने जीवन को निरपेक्ष गिनते हैं और अचेतना-वश उनमें कुछ-न-कुछ अस्वभाविक आचार पैदा होते हैं। कोई हठीला बन बैठता है, तो कोई रिक्तता हुआ होता है, कोई उदासीन तो कोई अग्रगणी। कई-कई तो अत्यधिक पगलपड़ी का शिकार-श्यामि बन हो जाते हैं।

इन साधारण अवस्थाओं में से तीन मुख्य हैं : (१) अग्रगण्य, (२) रिक्तता-व्यक्ति में होने वाले मानसिक रोग, एवं (३) मूर्खता-व्यक्ति में रिक्तता। बहुत से तीनों अवस्थाएँ आपस में मिली जुली रहती हैं, और तीनों की संश्लिष्ट एक साथ बनता प्रविष्ट है।

**मजदूरों का शैक्षणिक वातावरण :** उल्लेख.—मजदूरों के वातावरण में इनके अपरोधन तथा आकर्षण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात् इनके देखभाल देना कि उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति को यह उम्मीद दिलाने की जरूरत पड़ेगी है। इसके अतिरिक्त उनका वातावरण भी होगा। यह सब होने, होने चाहिए कि वह वातावरण। एहल्ल मजदूर वर्ग की जिंदगी इसमें है और शारीरिक अवस्था उनका वातावरण भी होगा।

**रोग-निर्णय.**—लक्षण-सम्बन्धी अवरोधित व्यक्तियों को समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इनका रोग-निर्णय प्रायः मजबूरी का आविष्कार कहा जा सकता है। इनकी डाक्टरों परीक्षा आवश्यक है। इन्हें निर्देश तथा परामर्श चाहिए। इनके रोग-निर्णय की जिम्मेवारी शिक्षा-निर्देश तथा उपचार-गृहों को सौंप देना उचित है।

**शिक्षण-संस्थाएँ.**—रोग-निर्णय के पश्चात् बच्चों की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है : (१) बच्चों को किसी उपचार-गृह या मानसिक अस्पताल में रखना, (२) बच्चे को एक साधारण स्कूल में भरती करना और उसके अनुरूप किञ्चित् परिवर्तित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, एवं (३) उसे एक विशेष स्कूल या संस्था में दाखिल करना। विशेष संस्थाएँ सात प्रकार की हैं : (१) अन्ध-विद्यालय, (२) मूक-बधिर-विद्यालय, (३) लूले-लैंगरों के शिक्षालय, (४) मानसिक मजबूरी के संस्थान, (५) अनाथालय, (६) बाल-अपराधियों की संस्थाएँ एवं (७) उपचार-गृह तथा निर्देश-केन्द्र।

**भारत में मजबूरी की शिक्षा-व्यवस्था :** मजबूरी की संख्या.—खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की जन-गणना में मजबूर बच्चों का वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया है यहाँ तक कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विरुद्धोक्त की संख्या का ठीक-ठीक पता नहीं मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूरी की संख्या प्रति हजार 'चीम' हैं। इसी गणना के आधार पर, भारत में मजबूरी की संख्या ७० लाख निर्धारित की गयी है। इस आनुमानिक गणना का हम कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं। सार अर्थ यह है कि मजबूरों के लिए कोई भी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करते समय इनकी भिन्न-भिन्न श्रेणियों की संख्या जानना आवश्यक है।

**प्रारम्भिक चेष्टाएँ.**—अमेरिका सरकार मजबूरी की शिक्षा के प्रति निवेष्ट एवं उदासीन रही। प्रारम्भ में इस ओर ईसाई मण्डलियों ने कुछ ध्यान दिया। सन् १८८३ में कुमारी एनी डार्व नामक एक प्रोटेस्टेण्ट महिला ने अमृतसर में एक स्कूल अन्धी लड़कियों के लिए खोला। सन् १९०३ में यह संस्था देहगढ़ में स्थानान्तरित की गयी। सन् १८९० में कुमारी एम्बेविथ ने पाल्म-बोट्याय में एक दूसरा स्कूल अन्धों के लिए खोला। तत्पश्चात् कटकता अन्ध-विद्यालय का नम्बर आता है, जिसे सन् १८८७ में श्री लालविहारी शाह नामक एक मागनीय ईसाई ने स्थापित किया था। सन् १९०० में कुमारी एन्ना मिन्गर्ट ने बम्बई में अन्धों के लिए एक स्कूल खोला, जिसका वर्तमान नाम 'श्री मूल फौज ज्यूरेंट गार्म' है।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में प्रगति.—स्वाधीनता-अर्जन के पश्चात् भी इस क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई। यह अवसर है कि केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय तथा राज्यीय शिक्षा-विभाग मजदूरों की शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं। सन् १९५२ में 'राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्' की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य है, बच्चों के प्रगत्यर्थ कार्य का प्रश्न एवं शोध, आर्थिक सहायता तथा समाचार-प्रदान। सन् १९५५-५६ में एक नया राष्ट्रीय-परिषद् स्थापित की गयी है। यह परिषद् सरकार को विद्वानों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोजन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है।

शिक्षा-संस्थाएँ.—निम्नलिखित तालिका में मजदूरों की भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं तथा उनकी छात्र-संख्या का पता चलेगा :

### तालिका २८

शिक्षा-संस्थाएँ, १९५५-५६ †

संस्था	संस्था-संख्या	छात्र संख्या
विश्वविद्यालय :		
अन्य ... ..	४९	२,२४५
मृदु-शिक्षा ... ..	३४	२,२९०
सुनिश्चित शिक्षा ... ..	८	५५६
मानविक मजदूर ... ..	२	२००
कुल	९३	५,३९१



चित्र १७—बेल-पद्धति द्वारा शिक्षा

अन्ध-विद्यालय.—हमारे देश में बीस लाख से अधिक अन्धे हैं, पर इस समस्या किञ्चित् अंश को ही शिक्षा मिलती है। अधिकांश समस्याएँ स्व-सहाय्य हैं। उन्हें हम अनायास भी कह सकते हैं। उन्हें सरकार में थोड़ा-बहुत अनुदान मिलता है, पर उनकी आर्थिक स्थिति दोचनीय है। ब्रेल-पद्धति पर बच्चों को अपनी मातृ भाषा के बोलने तथा लिखने का ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा एक दम्पकारी भी सीखता है। मुख्य उद्योग है : बेत की बुनाई, टोकरों बनाना, निरार या टाट बुनना, गीमवस्ती का काम, जिल्दमाजी, बटुईंगिरी, बुनाई-कताई, इत्यादि। अन्धे प्रायः मगीत-द्व होते हैं। कई सरथाओं में इन्हें मगीत भी सिखाया जाता है।

अन्धों की शिक्षा की विशेष ज़रूरतों की ओर भारत सरकार ध्यान दे रही है। आज ही मैं 'भारतीय ब्रेल' की सृष्टि हुई है। अक्टूबर, १९५० ई० में, देहरादून में केन्द्रीय ब्रेल-मुद्रणालय स्थापित हुआ है, जिसके द्वारा भारतीय ब्रेल साहित्य प्रकाशन किया जाता है। सन् १९५० में केन्द्रीय सरकार ने देहरादून में 'अन्ध (मौढ़) प्रशिक्षण-केन्द्र' स्थापित किया है। इस समस्या के अन्तर्गत दो वर्ष का पाठ्यक्रम रखा गया है, तथा प्रशिक्षणार्थियों की आधुनिक-लिपि तथा टाइप साहित्य में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समस्या का एक और भी महत्वपूर्ण अङ्ग है 'मगीत-शिक्षा'। सन् १९५८ में इस समस्या के अन्तर्गत एक महिना दिमाग भी घोष्य गया है।

देश में अभी तक नेत्र-हीन बालकों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है। लेकिन सन् १९५१ में अजमेर तथा बांदाय (बन्धु) में इन बालकों के लिए एडवांस्ड स्थापित हो जाने के बाद, यह बड़ी कुछ हद तक दूर हो गयी है। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार नेत्र-हीन बालकों के लिए देहरादून में एक आदर्श एडवांस्ड स्थापित करनेवाली है। आता है कि निकट भविष्य में यह कार्य पूरा हो सकेगा।

नेत्र-हीनों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्य की रीति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने १९४७ ई० में शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत एक विशेष युनिट (एकरी) स्थापित की है, जिसका मन्त्रालय एक उप शिक्षा-मन्त्रालय के अधीन है। भारत सरकार के सहाय प्रशिक्षण नेत्र-हीनों को जीवनी दिलाने की समस्या वर्तमान विद्वत् रूप में विद्यमान थी। इस समस्या को हल करने के लिए १९५५ में सरकार ने मन्त्रालय में एक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य ही निम्नलिखित उद्देश्य ध्येयों में नेत्र-हीनों के लिए समुचित कार्य की तलाश करना तथा उन्हें जीवनी दिलाना है।



‘बाल-अधिनियम’। यह नियम आन्ध्र प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश तथा मैसूर राज्यों और दिल्ली के सचीव क्षेत्र में लागू है। इसके अनुसार बालागमधी न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ इनकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ बालागमधियों का न्याय साधारण अदालतों में होता है। अपराधीमग बालागमधी कैदखानों में निरीक्षण रखे जाते हैं। आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर में ‘किशोर बन्दी’ (बोस्टल स्कूल) अधिनियम लागू है। सन् १८९७ का ‘मुधार-विद्यालय अधिनियम’ सभी बड़े राज्यों तथा कुछ सचीव क्षेत्रों में लागू है।

सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनमें से कुछ मरुथाएँ शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले बाल-अपराधियों को उपकरण तथा धन-सम्बन्धी सहायता भी देती हैं, जिससे वे सीम्मे हुए व्यवसाय में लग सकें। इन संस्थाओं में अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ साथ क्रीडा (खेल-कूद), नाटक, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (वेल-भाल) कार्यक्रम लागू किया है, जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य-प्रदेश, मैसूर तथा त्रिपुरा में मुधार-विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

उपचार-गृह तथा निर्देश-केन्द्र.—इन केन्द्रों में बच्चों तथा यवकों की मानसिक चिकित्सा उच्च स्तर पर होती है। हमारे देश में ऐसे केन्द्र बहुत कम हैं। कुछो के मानसिक अस्पतालों एव बाल-रक्षा-गृहों से चलाने होते हैं। २ मार्च, १९५५ के दिन, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक बाल-निर्देश केन्द्र दिल्ली नर्मिंग महाविद्यालय में स्थापित किया है। भारत में यह सर्व प्रथम सरकारी संस्था है, जिसमें बच्चों की मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है।

प्रशासन.—मजदूरों की शिक्षा के लिए, प्रत्येक राज्य की निजी शासन व्यवस्था है। कहीं पर प्रधान अधिकारी को ‘चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ मर्शालाइट इन्जन’ करने हैं, और कहीं ‘प्रोविजन आफसर’। किसी-किसी राज्य में तो प्रादेशिक आफसर को दोहा हुआ पदम भी नहीं मिलता है। पर उनके सिपुर्द जितने बच्चे भिये रहने हैं, उनकी मरुता के अनुसार उमे मेहनताना मिलता है।

मजदूरों की संस्थाओं के खर्च के लिए चार स्रोतों में आप आती है : (१) सरकार, (२) स्थानीय निधाय, (३) विचारियनों में आप, अर्थात् उनकी की मरुता उनके



द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों से आय एवं (४) दान, चन्दा, आदि। सन् १९५५-५६ में इस शिक्षा पर २३-९६ लाख रुपये व्यय हुए थे।

सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने मद्रास तथा बम्बई में मजदूरों के लिए दो नौकरी-विनिमय केंद्र स्थापित किये हैं। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अन्वे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ दी जाती हैं।

**कतिपय समस्याएँ.**—इस प्रकार मजदूरों की शिक्षा का आयोजन इस देश में किया गया है। मजदूरों की मजदूरियों की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है, पर पैसे की मजदूरी के कारण, सभी मजदूर हैं। कतिपय ऐसी समस्याएँ हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :

१. **मजदूरों की संख्या का निर्णय.**—मजदूर विभिन्न प्रकार के हैं। कोई भी शिक्षा योजना इन विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर रहेगी। पर हमारे देश की जन-गणना रिपोर्टों से इसका पता नहीं चलता है। हमारे देश की भावी जन गणना रिपोर्ट इस ओर ध्यान दें।

२. **उत्तम तथा सुव्यवस्थित संस्थाओं की आवश्यकता**—हमारे देश में मजदूर बच्चों के लिए शिशु शालाएँ, वृद्ध-वृद्धाओं के लिए कल्याण-गृह तथा मजदूरों के लिए पुस्तकालय, दस्तकारी-शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए।

३. **देहाती पाठ्य-क्रम की ओर झुकाव.**—बहु संख्यक मजदूर गाँवों में रहते हैं। इस कारण उनके पाठ्य-क्रम में देहाती एवं कृषि-शिक्षा की ओर अधिक ध्यान रहे, ताकि यह शिक्षा मजदूरों को उपयुक्त ग्राम-वासी बनावे।

४. **यथेष्ट अर्थ की आवश्यकता.**—अधोभार के कारण, मजदूरों की शिक्षा की ओर, उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि हमारा पंचवर्षीय योजनाएँ इस ओर ध्यान देवेंगी। स्वयं-चांश्च संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान-नीति निश्चित होनी चाहिए।

५. **प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत.**—सन् १९५५-५६ में केवल ६७% शिक्षित मजदूर बच्चों के विद्यालयों में काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को द्विती प्रथम का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था।

६ प्रशासन की कमजोरियाँ.—राष्ट्र अधिनियम अभी पूरे देश में क्रियान्वित नहीं हुए हैं; और जहाँ हुए भी हैं, वहाँ भी उनका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। सभी राज्यों में अप्रत्यक्ष की कमी है।

## ४. स्वास्थ्य एवं अनुशासन

भूमिका.—किसी भी देश की शक्ति, जनता के विकास पर निर्भर रहती है, न कि लष्ण शान-शीलता पर। जनता के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा अनुशासन। इतिहास साक्षी है कि जो देश स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहता है तथा अन्य देशों से सहायता की अपेक्षा रखता है, उसकी स्वतन्त्रता बर्बाद स्थानी नहीं रही है।

संघ परिभ्रम के पश्चात् हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है। इस क्षि में पराधीनता की बेड़ियों नहीं पहनना चाहते हैं। पर यदि हममें बीरता की चिनगारी प्रज्वालित न रही, यदि हमारे देशवासी शारीरिक दौर्बल्य के लक्ष्य रहे, यदि हममें उचित अनुशासन न रहा, तो शायद हम फिर से अपनी नवजाति स्वाधीनता को खो बैठें। अतएव हमारा प्रत्येक राष्ट्रीय योजना का एक अनिवार्य अंग होगा स्वास्थ्य एवं अनुशासन। स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा। ये ही हमारे देश के भवी नगरिक हैं। इस विषय के अन्तर्गत आते हैं : (१) शारीरिक शिक्षा तथा खेल, (२) विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा, (३) सुवर्ण-कल्याण तथा (४) राष्ट्रीय अनुशासन योजना।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद : भूमिका:—स्कूल तथा कॉलेजों में बालक तथा खेल-कूद की कुछ न-कुछ व्यवस्था अंग्रेजों के शासन-काल में ही थी। प्रांथि शिक्षकों के अभाव के कारण, कवायद या डिल निहून सैनिकों, अफगानों तथा पारसियों द्वारा सिखलायी जाती थी। पादशाह्य खेलों का प्रचलन अधिक था, एवं देशी खेलों की उपेक्षा की जाती थी।

सर्वान् जागृति.—स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा के दले 'शारीरिक शिक्षा' का उदय हुआ। प्राथमिक स्कूल के प्रथम दर्जे में देश-कला-शिक्षा की समाप्ति पर्यन्त, शारीरिक शिक्षा हमारे स्कूल तथा कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय है। प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान के निम्न पाठ्यक्रम है, पर ये पाठ्यक्रम सुचारु रूप में चलाने नहीं जा रहे हैं। उदात्त प्रदर्शन के लक्ष्य पर ध्यान में नहीं मिलते, ७५ प्रति शत शिक्षा-संस्थानों के खेल कूद के शिक्षक कर्मचारी नहीं हैं, और ६० प्रति शत संस्थानों के स्कूल-गुरु अशक्त हैं।

**केन्द्रीय सरकार की चेष्टाएँ.**—केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान शारीरिक शिक्षा की ओर सम्प्रति आकर्षित हुआ है। मन्त्रालय का एक संविभाग 'व्यायाम तथा मनोरंजन' की देखरेख करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-परामर्श मण्डल' स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में मण्डल ने 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-योजना' तैयार की है। शारीरिक शिक्षावाले संस्थानों तथा कालिजों के विकास के लिए यह योजना तैयार की गयी है। इसका उद्देश्य अलाइव एथं व्यायाम-शालाओं आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

एन मण्डल ने अपनी १० नवम्बर, १९५९ की बैठक में ठहराव किया : (१) केशोरों की शारीरिक उन्नति के लिए एक शारीरिक मान-टण्ड स्थिर किया जाय, जिसमें रहूँचे बिना विद्यार्थियों को शालान्त परीक्षा पास न होने दिया जाय; (२) प्रत्येक शिक्षण-संस्था में प्रति २५० विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक हो; एवं (३) जिन संस्थाओं में छात्र संख्या ७५० से अधिक हो, वहाँ एक उत्तर-स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है। वह संस्था की शारीरिक शिक्षा का मुख्य अधिकारी मिला जाये।

**खेल-कूद का आयोजन.**—खेल-कूद के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत-सरकार ने निम्न-लिखित उपाय किये हैं :

१. अखिल भारतीय खेल-कूद-परिषद् की स्थापना;
२. विभिन्न राज्यों में राज्य खेल-कूद-परिषदों की स्थापना; एवं
३. 'राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेल-कूद विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

**विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा: भूमिका.**—भारत के स्वतन्त्र होने पर हमें अपने सैनिक प्रबन्ध का कार्य अपने कंधों पर उठाना पड़ा है। सैनिक शिक्षा प्रत्येक देश के लिए आवश्यक एवं गौरव की वस्तु है। जहाँ देश के नवयुवकों को पुस्तकीय शिक्षा जाती है, वहाँ इसका होना भी आवश्यक है। इससे नवयुवकों में अनुशासन, आत्म-मर्त्यता, स्वामिमान, स्वदेश-प्रेम और आज्ञाकारिता की भावना का उदय होता है। आज गारे स्कूलों एवं कालिजों में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी टल (एन० सी० सी०) एवं सहायक सैन्य शिक्षार्थी टल (ए० सी० सी०) की ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा-संस्थानों के बाहर एक-सहायक सेना का आयोजन किया जा रहा है।

की स्थापना १५ जुलाई, १९४४ में हुई  
 बयोवर्ग के छात्र और छात्राएँ भरती हो  
 उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों  
 दुकानियों की बल, स्थल तथा वायु-शाखाएँ होती हैं। इन की प्रगति का पता  
 अधो-लिखित तालिका से चलेगा :

**तालिका २८**  
**राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की प्रगति।**

तारीख	घटक		बालिकाएँ		योग
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	
१-१-१९४९	१४,९६०	२०,१६०	—	—	३५,१२०
१-१-१९५०	२२,१८४	३६,१८०	९३	—	५८,४५७
१-१-१९५१	०३,३४९	४०,१०५	२७९	—	४३,७३३
१-१-१९५२	२३,५७०	४०,६६३	२७९	—	६४,५१२
१-१-१९५३	२६,१०३	५३,५१५	५२७	—	८०,१४५
१-१-१९५४	२८,२१७	५४,४००	६२०	—	८३,२३७
१-१-१९५५	३९,०८५	५६,६१७	२,७२८	२,९१४	१,०१,३४४
१-१-१९५६	४६,६८०	६६,३०७	३,२५५	५,१४६	१,११,३८८
१-१-१९५७	५२,१४७	७०,८९९	३,९९९	६,७२७	१,३३,७७२
१-१-१९५८	६४,४०५	७६,५३०	५,७३०	९,२००	१,५६,००५
१-१-१९५९	७३,४०७	९२,२५८	९,२४६	१७,३४२	१,७२,२५३

**सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल.**—स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, जो राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहीं पाते, 'सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल' की स्थापना की गयी है। इसके सैनिक १२-२३ वयवर्ग के होते हैं। प्रशिक्षण में सैनिक की अपेक्षा शैक्षणिक आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्कूलों से चुने जाते हैं, और इन्हें सेना तथा राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के कर्मचारीगण ट्रेनिंग देते हैं। सन् १९५२ में इस दल का आयोजन किया गया था, जब कि शिक्षार्थियों की संख्या ७०,००० थी। सन् १९५८ के अन्त में इनकी संख्या ८,५७,९४७ पहुँची।†

८. लोक-सहायक सेना.—सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में पुनर्संगठित हुई थी, अब 'लोक-सहायक-सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में लगभग पाँच लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देना है। इस सेना में, भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष भरती हो सकते हैं।

नये रंगलटों को तीस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, भोजन तथा वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तथा शिविर की समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको पन्द्रह रुपये दिये जाते हैं।

**युवक-कल्याण**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् युवक-कल्याण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्रायः प्रत्येक स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय में कम से कम एक 'युवक-कल्याण समिति' रहती है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के पाठान्तर कार्यों का आयोजन एवं संयोजन है। संस्थानिक समितियों के अतिरिक्त अनेक जगह क्षेत्रीय समितियाँ भी होती हैं, जो विद्यार्थियों के खेल-कूद, समारोह, रहने की व्यवस्था, आदि की देख-भाल करती हैं।

सन् १९५१ में संयुक्त गण्ट-संघ ने शिमला में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इस गोष्ठी ने युवक-कल्याण के प्रसार के लिए विविध योजनाओं पर विचार किया। नई, १९५५ में केंद्रीय शिक्षा-मंत्रालय में एक युवक कल्याण समिती स्थापित हुआ। युवक-कल्याण के क्षेत्र के मुख्य गति-विधियों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है:

१. सन् १९५४ से अन्तर्विदेशविद्यालय समारोह का आयोजन तथा अन्तर्कालिज समारोहों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया जाना;

२. युवक-नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया जाना;

३. ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक यात्राओं के सम्बन्ध में किराये के सुभीते;

४ युवकों के लिए छात्रावासों का बन्दोबस्त;

५. विश्वविद्यालय तथा राज्य-सरकारों को युवक-बस्त्याग मण्डल स्थापित करने के लिए तथा यथोचित कार्यों के सम्पादन के निमित्त अनुदान;

६. कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन सहन का सर्वेक्षण;

७. छात्रेतर युवक-बस्त्याग मण्डलों की स्थापना;

८. विद्यार्थियों में शरीर-धर्म की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा करने के लिए धर्म-दान तथा समाज-सेवा योजना का लागू किया जाना; तथा

९. अन्तर्कालिज समारोह योजना. प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थानों में व्यायाम-शाला, सन्तान-व्यायय, खुले रंगमंच, आदि की व्यवस्था ।

उपर्युक्त कार्य-कलापों का प्रारम्भ हमारे देश के युवकों में नवीन जगति हुई है । हमारे विश्वविद्यालयों में लज्जित बग़, संगीत, नाट्याभिनय का नवीन रुग्म हो रहा है । स्वाधीनता समाज-सेवा में शिलवर्षी लें रहे हैं, उनका नेतृत्व का प्रशिक्षण मिल रहा है तथा उनमें शरीर-धर्म की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा हो रही है । विभिन्न विद्यार्थियों के धर्म-दान का ध्येय आर्थिक न हो । इसका उद्देश्य सदा वैधानिक रहे ।

**राष्ट्रीय अनुशासन योजना :** पूर्व-वृद्धि.—हल ही में, हम देश में एक नवीन योजना आरम्भ हुई है । इसका उद्देश्य है, विद्यार्थियों की वर्तमान उदात्तता एवं उत्कृष्टता को योजना तथा उन्हें अनुशासित करना । इस योजना की भावना भी अराधना मेरू के एक अति भाव्य से शुरू होती है । सन् १९५४ में उन्होंने दिल्ली के एक राष्ट्रीय मेमिक हल को मुक्त बाट में देश की ग़्वा के लिए प्रेरणा प्रदान किया । इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की पर्चा की । हमें



युवक  
उत्सव



प्रशिक्षण  
शिविर



अन्तर्काभिज  
समारोह



यात्रा के  
सुभीते



श्रमदान तथा  
समाजसेवा

# युवक कल्याण



छात्रावास



छात्रेतर युवक-  
कल्याण मण्डल

छात्रों की रहन-सहन  
का सर्वेक्षण



युवक-कल्याण  
मण्डल

कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी तत्कालीन पुनर्वास उप-मन्त्री श्री० जे० के० भोंगले को सौंपी गयी। जापान तथा अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर, श्री भोंगले ने इस नवीन योजना की एक रूप-रेखा तैयार की।

इसका धीमपेश दिल्ली के 'इन्फ़ोरम निकेतन' में हुआ। मन् १९५४ के अंत में श्री नेहरू ने इस संस्था के शिक्षार्थियों के कार्यकाल का परिदृशन किया। वे इसमें इतने उत्तुष्ट हुए कि उन्होंने इस योजना को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया।

**विस्तार.**— योजना का कार्यक्रम सम्पूर्ण दिल्ली, फरीदाबाद, राजपुरा, उद्दाम-नगर, बल्थार में विस्तारित हुआ। प्रथम वर्ष अर्थात् १९५४-५५ में इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ एक लाख रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष यद् योजना १९ शिक्षा-संस्थानों में लागू हुई, तथा २४,८८१ विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गये। मन् १९५६ के अंत में ६९,००० छात्र-छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए पचास करोड़ रुपये की मांग है।

केंद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का 'व्यायाम और मनोरंजन सविभाग' इस योजना का परिचायन करता है। इस योजना का १९५९-६० में लागू करने के लिए आप-व्ययक्त में दीन लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस साल जिन नयी संस्थाओं में योजना लागू की गयी/या की जायगी, उनकी संख्या इस प्रकार है :

### तालिका २९

राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की व्यवस्था, १९५९-६०†

राज्य	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या
दिल्ली	१६	६,५६१
पन्जाब	८०	४८,२६८
मध्य-प्रदेश	३	१,०००
उत्तर-प्रदेश	८	२,४५०
बम्बई	२५	५,०२०
पश्चिम बंगाल	२६	५,१५०
कुल...	१५८	६८,४४९

† भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, १९५९, १४ ५१९।





# ग्यारहवाँ अध्याय

## कतिपय राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्तावना

गिज़े पत्रों में हमारे देश की मुख्य समस्याओं की आलोचना की गयी है। हमारी सत्ता की आरम्भ में अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध काफी अग्रगण्य था। भारत के अनेक भागों में कुछ समस्याएँ स्थापित हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय चेतना पर प्रभाव डालना। अधिकतर समस्याएँ अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध नहीं न रह सकी, वे विभिन्न हैं। पर कुछ अभी भी अपना सिंग जैसा किए खड़ी हैं। इनमें से मुख्य हैं : लड़कें बर्बादी, एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, विश्व-भारती, त्रिपाठीट, लोरी कामिना मिलिया, एच हिन्दुस्थानी नान्दीभी संघ, सेवाग्राम। इनका सशित विवरण नीचे दिया जाता है।

रिडकुल बौगरी

उत्पीनदी सत्ता की के मध्य में, (हिन्दू-धर्म-सुधार का आन्दोलन आरम्भ हुआ।) लोरी दयानन्द सरस्वती ने घोषणा की, "हमें वेद का पुनरुद्धार करना है।" इसके अनुसार, गुरुकुल प्रणाली का प्रचार भी आवश्यक समझा गया। बीसवीं सताब्दी के आरम्भ में कई गुरुकुल स्थापित हुए। जिनमें गुरुकुल बौगरी मुख्य है। इसकी स्थापना लोरी अज्ञानन्द ने सन् १९०३ में हरिद्वार के पास बौगरी में की।

मध्या की उद्देश्य है सङ्कलित साहित्य के साथ-साथ वैदिक साहित्य का अध्ययन, प्राचीन राष्ट्रीय शिक्षण, भारत के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व का अध्ययन। इसीलिए लोरी सतिनाथ वेद और अंग्रेजी साहित्य के साथ अंग्रेजी, रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, धनार्थन शास्त्र, भू-विज्ञान, कृषि, पशुपालन दर्शन, अर्थशास्त्र तथा आधुनिक चेतना की प्रदर्शना की गई है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी है।

इसके बोधोत्पत्ति से लड़कें प्रकृति देवी की मंदिर में रह सकती स्थित है। लोरी मानव प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थी और शिक्षक साथ-साथ रहते हैं।

११ से आठ वर्ष की उम्र में, यहाँ बालक प्रविष्ट होता है; चौदह वर्ष के अध्ययन के बाद, ह स्नातक तथा दो वर्ष पश्चात् वाचस्पति होता है। गुरुकुल का आयुर्वेदिक विभाग प्रख्यात है। यहाँ विविध प्रकार की दवाइयाँ प्रस्तुत होती हैं। यहाँ का पाठ्य-क्रम च-वर्षीय होता है, और १५-१९ वयोवर्ग के विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं।

गुरुकुल में सहशिक्षा निषिद्ध है। बालकों को चौबीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य-पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। उन्हें निरामिश्र भोजन करना पड़ता है। विद्यार्थियों की दिनचर्या प्राचीन गुरुकुलों की नर्त होती है: प्रातःकाल उठना, शारीरिक श्रम, हवन, इत्यादि। आश्रम को साफ सुथरा उन्हें ही रखना पड़ता है।

### स० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय का विकास पूना के एक सामान्य स्कूल से हुआ, जिसकी स्थापना सन् १८९६ में आचार्य कर्वे ने हिन्दू विधवाओं के लिए की थी। धीरे-धीरे त छोटे से स्कूल में कई संस्थाएँ सलमन हुईं, जैसे : एक छात्रावास, एक प्राथमरी स्कूल तथा एक प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र। संस्था इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक पिता-पिता अपनी कुओंरी कन्याओं को छात्रावास में रखने लगे।

इससे आचार्य कर्वे का उत्साह बढ़ा और उन्होंने भारतीय छात्राओं के लिए एक उच्च शिक्षा योजना आरम्भ की। उनका कथन है कि नर और नारियों का पाठ्य-क्रम भिन्न नहीं हो सकता, कारण दोनों के जीवन-क्षेत्र ही विभिन्न हैं। इसीलिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुकूल उच्च शिक्षा का एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाने चाहिए यह भी तय किया कि यह शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास निज भाषा के द्वारा ही हो सकता है।

सन् १९१६ में आचार्य कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की एक राष्ट्रीय संस्थान है। कारण, यहाँ भारत के कोने-कोने से छात्राएँ अध्ययन आती हैं। विश्वविद्यालय की अधोलिखित विशेषताएँ हैं, जो अन्य विश्वविद्यालय नहीं पायी जाती :

१. विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए है;
२. इसके स्वीकृत कालिज देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं;
३. पाठ्य-क्रम में स्त्रियों के लिए उपयोगी अनेक विषयों का समावेश है, जैसे : संगीत, चित्रकला, नाट्य शास्त्र, यह विज्ञान, आदि;

४. शिक्षा का माध्यम मानुषीय है; एवं

५. परीक्षाओं में साथ छात्राएँ भी बैठ सकती हैं। इसका लाभ अनेक महिलाएँ उठाती हैं, जो कि कालिजे में नियमित रूप से सदा अध्ययन नहीं कर सकती।

सन् १९३० में विश्वविद्यालय का सद्यः मुख्य कक्षों में स्थानान्तरित हुआ। क्योंकि कक्षों के एक करोड़पति ने अपनी माता, श्रीमती नाथीबाई दामोदर टाकरसी, की पुण्य स्मृति में स्थायी रूपसे दान दिये। इसी कारण इस विश्वविद्यालय का वर्तमान नामकरण हुआ। सन् १९५१ में, इसे वैधानिक स्वीकृति दी गयी है। विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेज कक्षों, कड़ीश, पुना, सुन, भावनगर तथा अहमदाबाद में स्थित हैं। गत वार्षिक वर्षों में यह संस्थान हमारे देश की महिलाओं की शक्ति और सामाजिक प्रगति में बड़ा योग दे रहा है।

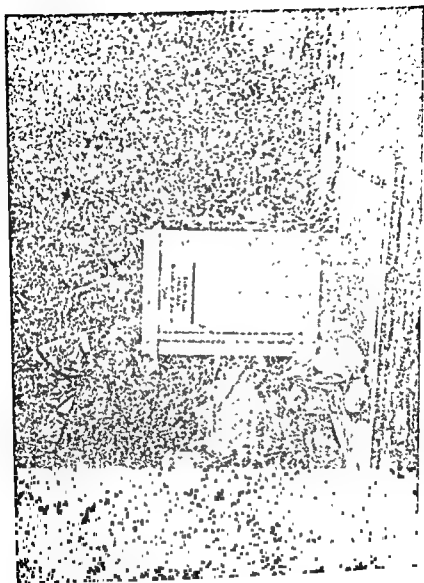
## विश्व-भारती

सन् १८६१ में कवि श्रीरामनाथ टाकुर क रिया, महर्षि देवेन्द्रनाथ टाकुर, ने परमार्थ साधकों के लिए एक आश्रम की स्थापना बलरुते के पास बोलपुर नाम में की थी। इसका नामकरण उन्होंने शान्ति निषेधन किया। जिस स्थान में वे साधना किया करते थे, वही एक सत्यमेव-सिद्धि का बैंगल-भारती में सुना हुआ है :

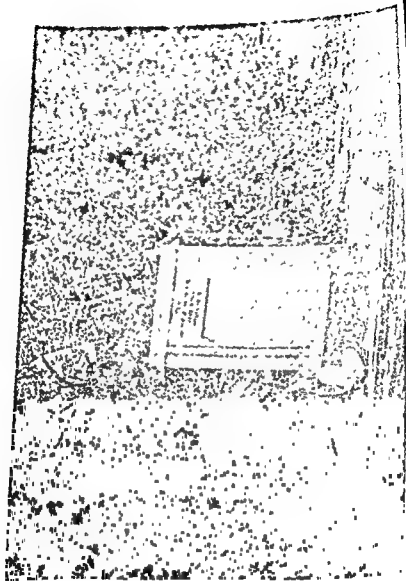
जिन आचार प्राणों आसन, मनो आनन्द, आत्मा शान्ति ।

सन् १९०१ में मुद्रदेव ने इसी स्थान में कक्षाओं के लिए एक प्रादेशिक विद्यालय स्थापित किया, जिसका उद्देश्य देशी शिक्षा देना था जो प्राकृतिक हो जहाँ बच्चे परिवार के दायित्वों का अनुभव करें और वे पारम्परिक शिक्षण और उच्चाई के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन करें। सन् १९२१ में देशी विद्यालय विश्व-भारती के नाम में। अन्तर्जातीय विदेशीकरण के रूप में परिवर्तित हुआ। बलरुते ने संस्था की स्वीकृति की घोषणा की। के. ए. व. जयन्त सरावा की सरकारी कक्षाओं में शामिल होने की शक्ति प्राप्त की। अर्थशास्त्र के कारण उन्हें अध्ययन पढ़ा, या उन्होंने अपने अर्थों का अध्ययन न करना चाहा। स्थायीतः अध्ययन में ही इस विश्वविद्यालय की प्राचीन सफलता सन् १९५१ में वैधानिक स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

१. विश्व के देशों के अन्तर्गत, सब के अन्तर्गत सब का सब का अध्ययन है।







Page 1 of 1

१. विभिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य-जीवन का अध्ययन,
२. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एवं अनुसन्धान;
३. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को उनकी मौलिक एकता के आधार पर पश्चिम के विद्वानों और संस्कृत के निकट पहुँचाना; एवं
४. सहस्रपुत्र का अनुभव करत हुए पूर्व और पश्चिम का समन्वय करना, जिससे विश्व-सन्तुल्य और विश्व-एकता सम्भव हो सके।

विश्व भाषा एक साधारण विश्वविद्यालय है, जहाँ भाषा के विभिन्न भागों से विद्यार्थीगत आते हैं तथा प्राध्यापकगण काम करते हैं। इनके अनिश्चित भ्रम देशों के छात्र तथा दशकगण यहाँ महा आने जाते ही रहते हैं। विदेशी छात्रगण भी यहाँ नियमित या अनियमित विद्यार्थी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अनियमित छात्रों के लिए विशेष उपाय-स्नानक पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जैसे - अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पाली, चीनी और तिब्बती भाषाएँ, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय दर्शन शास्त्र, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इत्यादि। भारतीय कला तथा नृत्य की शिक्षा का भी यहाँ विशेष प्रबंध है। इसके अतिरिक्त हम विश्वविद्यालय में बिना कुछ अनिश्चित की (ग्रुप) दिये कोई भी विद्यार्थी किसी भी देश का अध्ययन नियमित या अनियमित छात्र के रूप में कर सकता है, बसते हैं कि वह उस विषय की और विशेष अभिरुचि दिखलावे।

विश्वविद्यालय के मुख्य निजी कालिब से हैं : विश्व-भवन (उप-ग्राहक एवं उत्तर-भारतक बसाएँ तथा अनुसंधान), शिक्षा-भवन (उच्चतर माध्यमिक स्तर), कला भवन (ललित कला एवं संगीत), संगीत भवन (संगीत एवं नृत्य), विनय भवन (विश्वक प्रसिद्ध महाविद्यालय), शिक्षा-भवन (बुद्धि-शक्ति प्रशिक्षण-केंद्र)। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विस्तृत है जहाँ लगभग दो लाख पाठ्यलिपियों का संग्रह है।

दुनिया के शरीर शास्त्र से हुए, शास्त्र निवेदन में पूर्ण शक्ति निरासरी है। गीत-संगीत के गीत आदर्शशास्त्राचार बसाएँ छात्रों है। शिक्षा में विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्ति-रूप की और विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश है, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा के अनुसार विषय का चुनाव कर सके। विषय-रूप, गीत, संगीत, कठ कला, नृत्य के का कला, माध्यम-कला, इत्यादि विषयों की शिक्षा की यहाँ व्यवस्था है। यह व्यवस्था अनेक विश्वविद्यालयों से नहीं मिली है। विशेष इसका अध्ययन करते हैं।

विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी समस्याएँ समाधान करने शिक्षा-भाषा का एक महान उद्देश्य है। एन्ट्रेंस-परीक्षा, अन्ट्रेंस-परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं की सेवा का सेवा हम विश्व







लक्ष्य ने उठाया है। विद्यार्थियों को आसपास के गाँवों में जाना पड़ता है तथा उन्हें या पतितों की उन्नति की ओर लक्ष्य रखना पड़ता है, ताकि इन गरीबों का जीवन बतु सुखप्रद हो।

शान्ति-निकेतन में एक मील दूरी पर पश्चिम की ओर 'श्रीनिकेतन' है। यह ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था है, और विश्वभारती का एक भाग है। श्रीनिकेतन का स्थापना गुरुदेव ने मन् १९२१ में की थी। तभी से यह ग्राम-सुधार तथा ग्राम-शिक्षा का केंद्र रहा है।

गुरुदेव के देहावसान को आज दस से अधिक वर्ष बीत गये हैं, पर विश्व-भारती पर-रोम में उनके व्यक्तित्व की छाप विद्यमान है। संस्था के वातावरण में कवित्व छूट उठता है — गाँव की सादगी, कोपरई नदी का कल-कल रख, शम-बगीचे की हरीतिमा, शुष्क पत्तों की मर्मर ध्वनि तथा पक्षियों का अजर कर्ण मधुर संगीत ! हम सकते हैं कि शान्ति निकेतन को प्रकृति का घरान है। विश्व-भारती भारतीय ज्ञान का केंद्र है तथा अन्तर्गर्भीय ज्ञान का विद्यापीठ है। इस संस्था के जन-हित समाजसेवा-मन्धवी कार्य मूल्य एवं श्लाघ्य हैं।

विद्यापीठ

मन् १९२० के अमहोपग आन्दोलन के समय, कतिपय राष्ट्रीय विद्यापीठों के मिश्र-मिश्र स्थानों में स्थापित हुए, जैसे : पुना, अहमदाबाद, बनारस, लाहौर, श्रीनगर, (बाद में दिल्ली में स्थानान्तरित)। इनका मुख्य उद्देश्य था हमारे नौजवानों को ऐसी उच्च शिक्षा देना कि उनके हृदय में राष्ट्रीय भाव प्रस्फुटित हो और वे देशोद्धार के मन्मार्ग में चले पड़े। अमेरिकी फाउण्डेशन्स तथा विदेशविद्यालयों की शिक्षा सम्भव न थी।

इस उद्देश्य को मानने लगने हुए विद्यापीठों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। भारतीय ज्ञान और तथा मन्त्रि को प्रमुख स्थान दिया गया, तथा हिन्दी एक प्रमुख विषय बना। इनमें शिक्षा मात्र भारत के माध्यम से दी जाती थी। विदेशी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का प्रश्न करने में। अनेक देश-भक्तों ने अपना स्वीकार कर विद्यापीठों में अध्यापन का कार्य स्वीकार किया, पर अमहोपग आन्दोलन के माध्यम-मध्य दिल्ली की अनेक विद्यापीठों के लिए मन्त्री विद्यापीठ बना। नौजवानों के लिए इन विद्यापीठों के शिक्षा विद्यार्थियों को मान्यता नहीं दी गयी। इन विद्यापीठों के अन्तर्गत क्या मन्त्रों में ? देश-प्रेम की मन्यता औरत में अन्तर्गत मन्त्रों के होते हैं।

कनिष्ठ विद्यापीठ कुछ-न-कुछ कार्य अवसर्गमय चलाते रहे, जैसे : स्नाती-प्रचार, टी शिधा, मान-मुधार आदि । स्वतन्त्रोत्तर साल में इनका पुनरुद्धार हुआ । यह स्वरूप, आज गुजरातविद्यापीठ, अहमदाबाद, निम्न-निम्नित मन्थान या कार्यक्रम रहा है :

१. बुनियादी प्रयोगिक शक्ति-कृत—यह एक उत्तर-बुनियादी शक्ति-कृत है ।

२. महादेव देसाई मन्थान सेवा महाविद्यालय—मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए तीन-साली पाठ्यक्रम ।

३. बुनियादी प्राविधिक विद्यालय—प्राथमिक शिक्षकों के लिए ।

४. राष्ट्र भाषा प्रचार—तीन मुख्य कार्य

(१) बर्भाई चलाया, (२) गुजरात में राष्ट्र-भाषा परीक्षाओं का मन्थान, एवं (३) पुस्तक प्रकाशन ।

५. पुस्तकालय—उद्घाटन करीब एक लाख पुस्तकें हैं ।

६. वरिष्ठ विद्यालय, मानासन सेवा-केन्द्र—अनुसूचित जातियों में काम करने के लिए काम सेवाओं को तैयार करना ।

७. अग्रवर्ती श्रम-केन्द्र—आदिवासी बच्चों के लिए, एक आधुनिक रूप तथा समाज शिक्षा-केन्द्र ।

## मिया मिलिया, दिल्ली

जमिना मिलिया की स्थापना अमरयोग अन्तर्गत के समय सन् १९६० में थी । आरम्भ में ही यह विद्यापीठ अपनी मित्र सेवा किये हुए सेवा करने लगे । इसकी पुरानी आरम्भिक में हुई थी, पर पौंच करीब पचास यह अन्तर्गत दिल्ली में स्थानान्तरित हुई ।

जमिना मिलिया का ध्येय नीचरानों को सरकारी नीचरी के लिए तैयार करना था । इसका उद्देश्य नवयुवकों की आरम्भिक तैयारी है — जैसे तैयारी, तथा आरम्भिक श्रमिक समुदाय के प्रति ध्यान हो, जिसके द्वारा वे देश के लिए सेवा करने के लिए सक्षम बन सकें । यह कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक श्रमिक श्रमिक का अर्थ है, पर उसमें एक-दो श्रमिकों का भी सम्मिलित । यह सभी बौद्धिक विद्यार्थी—कुलमान तथा निम्न-मन्थान—अन्तर्गत करने के । इसकी शिक्षा में उनके दर्शन के विकास का ध्येय पूर्ण अन्तर्गत किया गया है ।

औधी-तूफानों को झेलते हुए भी, जामिया ने अपनी स्वाधीनता कायम रखी। सरकारों मान्यता की परवा न की, और तत्कालीन पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं। इसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसकी डिग्रियाँ भी स्वीकृत हुईं। पर भित्तिारियों को सदा अपनी स्वाधीनता खोनी पड़नी है, इसके कारण या ने सरकारी अनुदान की तनिक भी अपेक्षा नहीं की। उसने सदा अपने आदर्शों कायम रखे। दान और चन्दे पर ही यह सस्था चलती रही। लोगों ने इस सस्था की सहानुभूति भी दिखायी। कागण, उन्होंने जामिया के आदर्शों को समझा।

आज जामिया निम्न-लिखित संस्थाओं को चला रही है :

१. एक सावास कालिज.—इसमें कला, विज्ञान तथा सामाजिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है।

२. एक सावास बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला।

३. एक सावास प्राथमिक स्कूल—यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति-द्वारा शिक्षा दी जाती है।

४. प्रौढ़ शिक्षण-संस्था—जो प्रयोगिक समाज-शिक्षा-केन्द्रों का परिचालन करती है।

५. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय.—इसमें बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। अवर पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा तथा प्रवर पाठ्यक्रम के लिए बी० एड० डिग्री मिलती है।

६. मकतबा.—यहाँ से स्कूली पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होती हैं।

७. पुस्तकालय.—यहाँ बीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं।

८. कला-प्रशिक्षण-केन्द्र.—ग्राफ्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए।

९. ग्राम्य अर्थशास्त्र तथा समाज-शास्त्र केन्द्र—यहाँ उत्तर-स्नातक स्तर पर अनुसन्धान-कार्य होता है।

१०. इतिहास एवं राजनीति शोध-संस्था.—यहाँ इन विषयों की शिक्षण-विवियों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध-कार्य हो रहा है। तथा यहाँ से सहायक शिक्षण-सामग्री तैयार होती है।

११. एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था।

१२. एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल।



औधी-वृक्षानों को डोलने हुए भी, जामिया ने अपनी स्वाधीनता कायम रखने में सरकारों मान्यता की परवा न की, और तत्कालीन पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। इसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसकी डिग्रियाँ भी स्वीकृत नहीं हुई। पर भित्तिारियों को सदा अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ती है, इसके जामिया ने सरकारी अनुदान की तनिक भी अपेक्षा नहीं की। उसने सदा अपने आदर सामने रखा। दान और चन्दे पर ही यह सस्था चली रही। लोगों ने इस संस्था प्रति सहानुभूति भी दिगलायी। काण, उन्होंने जामिया के आदर्शों को समझा।

आज जामिया निम्न-लिखित संस्थाओं को चला रही है।

१. एक सावास कालिज.—इसमें कला, विज्ञान तथा सामाजिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है।
२. एक सावास बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाल।
३. एक सावास प्राथमिक स्कूल.—यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति-द्वारा शिक्षा दी जाती है।
४. प्रौढ़ शिक्षण-संस्था—जो प्रयोगिक समाज-शिक्षा-केन्द्रों का परिचालन करती है।
५. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय.—इसमें बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। अवर पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा तथा प्रवर पाठ्यक्रम के लिए बी० एड० डिग्री मिलती है।
६. मकतबा.—यहाँ से स्कूली पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होती हैं।
७. पुस्तकालय.—यहाँ बीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं।
८. कला-प्रशिक्षण-केन्द्र.—ग्राफ्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए।
९. ग्राम्य अर्थशास्त्र तथा समाज-शास्त्र केन्द्र—यहाँ उत्तर-स्नातक स्तर पर अनुसन्धान-कार्य होता है।
१०. इतिहास एवं राजनीति शोध-संस्था.—यहाँ इन विषयों की शिक्षण-विधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध-कार्य हो रहा है। तथा यहाँ से सहायक शिक्षण-मामूरी तैयार होती है।
११. एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था।
१२. एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल।



१३. समाज-विज्ञान प्रकाशन-केन्द्र.—यहाँ नवविधित नगरों की शिक्षा के विषय में अनुसन्धान किया जाता है, तथा उनके उद्योगी साहित्य का प्रकाशन किया जाता है।

आत्मन्त्याग-मय जेनेरान्ड व्यक्तिओं के द्वारा, इस समस्या का सम्न्धान होता है। ये केवल २००-५०० रु० वार्षिक धन देते हैं तथा समस्या की दीर्घ दूर तक सेवा करना अंगीकार करते हैं। ऐसे ही महानुभाव इस समस्या के सङ्ग हो सकते हैं। यही सङ्ग समस्या की देखभाल करते हैं तथा उसकी प्रवर्धनशीली सेवा का महत्त्व होते हैं।

### हिन्दुस्थानी तालीमी मध्य, सेवामाम

भूमिका.—हुनिवर्दी शिक्षा की दिग्गज नवीन इस पुस्तक के तीसरे अङ्क में भी मिली है। हिन्दुस्थानी तालीमी मध्य, सेवामाम इस नवीन शिक्षा का प्रधान केन्द्र है। इसकी स्थापना सन् १९३६ में हुई थी।

इस कार्य के लिए सेवामाम सर्वोत्तम स्थल मिला जा सकता है। इस केन्द्र के दूर गिरि लगभग तीस मील है। यन्त्र कोई भी गौर यहाँ से अधिक दूर नहीं है। यहाँ केवल स्टेशन यहाँ से केवल चौबीस मील की दूरी पर स्थित है। सेवामाम धर्म मुद्रा, नवीन प्रकाश तथा पशुपालन का एक प्रधान केन्द्र है।

मुक्त-मुक्त में मध्य में एक पूर्ण हुनिवर्दी मूल कार्यक्रम किया। इनमें आटवर्दी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। नयी तालीम के विस्तार के साथ-साथ सत्र की भी अरसे काईलार बढ़ाने पड़े। कारण, नयी तालीम के अन्तर्गत अब शामिल हैं: (१) प्रीट शिक्षा, (२) पूर्ण हुनिवर्दी शिक्षा। (३) हुनिवर्दी शिक्षा एवं, (४) उच्च हुनिवर्दी शिक्षा

विभिन्न विभाग.—आठ गढ़ सत्र अधो-विभिन्न विभागों का सम्बन्ध का गता है—

१. पूर्ण प्राथमिक मूल का 'हनिवर्दी'।

२. हुनिवर्दी मूल (७-१४ बच्चे के बच्चे के लिए)। यह सत्र 'आनन्द शिक्षण' नामक एक मूल चलाता है, और आनन्द के होते में शिक्षण का मत हीन होते के हुनिवर्दी मूल के लिए चलाता है।

३. उच्च हुनिवर्दी मूल—

विश्वविद्यालय के १४  
का सम्बन्ध

सम्बन्ध विदे  
के इन विदे  
, (४) १४



उपादान, ५) बापू एवं भाव्य कार्य, (६) ज्ञान इंजीनियरिंग एवं विमान, (७) युवावे, (८) इकोमिनी, (९) एड रिजिन (नर्सिंग के लिए)। नदी नालीम व. विद्यालया व अनुसंधान विद्यार्थियों को आनन्ददायी बनाए जाता है।

८. विश्वविद्यालयीय शिक्षा—हरि, वस्तु-गणन, ज्ञान इंजीनियरिंग, आगएए एव शिक्षा का दाता प्रत्यक्ष शिक्षा को प्राप्त है या शिक्षा प्रदान करता है।

९. प्रसार कार्य—एक कार्य विश्वविद्यालय कार्य में समाविष्ट है। मुख्य कारणाकार इस प्रकार है। (१) सेवाप्राम में ३ मील के अर्धवृत्त में स्थित सर्वत्र क्षेत्रों में प्रसार कार्य, ताकि लोग सर्वोत्तम समाज के हेतु को समझ सकें। (२) १९ वर्षों के ऊपर के गुरुक एवं युवावर्गों को नदी नालीम की प्राम स्थापना पद्धति में प्रशिक्षित करना, ताकि वे भूदान आन्दोलन में भाग ले सकें। (३) नदी नालीम शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण-कार्य।

उत्तर धूमिदात्री, विश्वविद्यालयीय तथा प्रसार कार्य शिक्षा के लिए भाग के विभिन्न भागों में विद्यार्थीयग्न यहाँ आते हैं। थोड़े-बहुत अनिवार्य विदेशों में भी आते



चित्र २०—सेवाप्राम में गान्धीजी की कुटिया

हैं। इनके लिए अल्प-कालिक (दो सप्ताह से लेकर कई महीने) प्रशिक्षण ■ विशेष प्रयत्न किया जाता है।

**उपसंहार—**यह सब बीस वर्ष से भी अधिक काल से अपना कार्य सतत कर रहा है। इसे अनेक विषय-बाधाओं का सामना करना पड़ा, पर इसने अपना कार्य प्रत्येक स्थिति में जारी रखा। उस ने भारत के शिक्षा जगत में एक नयी क्रांति उत्पन्न की है। सब का उद्देश्य एक ऐसे समाज की सृष्टि करना है, जिसके जन-समुदाय स्वावलम्बी हों, जो अपने हाथ से स्वयं धन कर स्व-भित हों, और उन्हें दूसरों की सहायता कदापि न लेनी पड़े। अपने दृढ़ संकल्प को कार्यान्वित करने में सब को बहुत कुछ सफलता भी मिली है। आरम्भ में स्थित गान्धीजी की कुटिया उसे ज्योति दिखानी रही है, और आगे दिखानी ही रहेगी।

यागद्वयं अध्याय

[illegible]

राष्ट्रीय शिक्षा को अनेक समस्याओं का सामना करना है। इनकी चर्चा रिपोर्ट में की गयी है। फिर भी हम तीन समस्याओं के सम्बन्ध में, इस अध्यान में, बत कदना चाहेंगे। ये समस्याएँ ये हैं : (१) प्रशासन, (२) शिक्षा का गिरता-उड़ता एवं (३) विद्यार्थीवर्ग की अनुशासन-हीनता।

प्रशासन की कमजोरियों के कारण, शिक्षा के दोष दूर नहीं हो रहे हैं। सरकार को किसी भी समय परामर्श का अभाव नहीं रहा। समय-समय पर अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। उन्होंने विभिन्न रूप से शिक्षा-ममस्याओं का अध्ययन किया तथा उचित प्रस्ताव भी किये। वर्तमान काल में शिक्षा के प्रायः प्रत्येक अङ्ग पर पूर्णतः विचार किये तथा सम्यक् सुझाव देने के लिए स्थायी समितियों एवं परिषदों की नियुक्तियाँ की गयी हैं। प्रति वर्ष कतिपय कर्मशालाएँ एवं गोष्ठियाँ भरती हैं। इन सबका परिणाम क्या निकला? कहना नहीं होगा कि निराशा और हाथ मलने के बिना कोई सुफल हमोचर नहीं हुआ। कोई भी क्षेत्र हम लेते हैं तो हमें वहाँ सर्वत्र मृगतृष्णा की सृष्टि माकार दिलायी पड़ती है, चाहे हम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा में बहुद्वितीय पाठ्यक्रम की योजना की ही लें, अथवा अनुसन्धान या विश्वविद्यालयीय शिक्षा का सुधार लें। बड़ी-बड़ी योजनाओं में सब दूरदर्शिता के अभाव का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। उनके अनुसार व्यय की व्यवस्था नहीं हो पाती, और हममें उनकी कार्यान्वित करने की क्षमता भी नहीं रहती है। कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डॉ० बाबूलाल भीमाजी, को लोक-सभा में स्पेड के साथ यह स्वीकार करना पड़ा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भारत मविधान के निर्देशानुसार नियत समय में कार्यान्वित नहीं की जा सकी है।।

दुसरे के दोष दर्शन एवं तुलनाचीनी में हमें आनन्द मिलता है, पर हम यह बभी भी विचार नहीं करते हैं कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं! उदाहरण-रूप, मॉडर्न योजना का उद्देश्य कम-से कम ४० वर्षों में शिक्षा के उस स्तर की प्राप्ति करना रहा गया जो सत्वाधीन इंग्लैंड में पहुँच चुका था। इसकी त्वर दीक्षा-दिप्ति हुई, और स्वर्गीय मोराना आजाद ने कहा कि स्वाधीन भारत चालीस वर्ष दूर नहीं सकता। मन् १९४८ की स्वर-समिति ने सुझाव दिया कि सर्वव्यापी अनिवार्य बेसिक शिक्षा देश में सोल्ड वर्षों के भीतर ही लागू की जा सकती है। पर 'जो की जा सकती है', यह की नहीं गयी। हम लोग प्रसिद्धतम प्रतिवेदन लिख सकते हैं, पर उसे कार्यान्वित करने का हममें कोई दम-लम नहीं। हम मजे में स्वर्गति लेते रहे। अब तो सोल्ड पक्ष अल्प दीर्घ ही समाप्त होने वाली है, और हम खराबी दुस्तर ही पक्षों वाले जा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का ध्येय अब सन् १९७५ में हम लक्ष्य तक पहुँचने

† Inaugural Address at the All-India Council for Elementary Education, March 10, 1954

है। पर हम इतने धक्के खा चुके हैं कि हमारा विश्वास किसी भी योजना पर नहीं है। भगवान् कम-से-कम इस योजना को तो सफल बनावें !

यह मानना ही पड़ेगा कि सरकार शिक्षा के लिए पर्याप्त अर्थ की व्यवस्था नहीं कर रही है। तिस पर भी गत दस वर्षों में हमारे देश का शिक्षा-विभागीय व्यय तिगुना हो गया है। पर यह शिक्षा-व्यय यथोचित नहीं हो रहा है। इस समय तो केन्द्रीय मन्त्रालय की हालत उम गयेवाले बूढ़े के समान है, जो कि सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टाओं में असफल हुआ। मन्त्रालय आज इधर हाथ मार रहा है तो कल उधर। — आज 'जनता कालिज', तो कुछ 'संस्कृत-विश्वविद्यालय', तो परसों 'ग्रामीण उच्चतर शिक्षा'। हाल ही, उक्त मन्त्रालय एक नवीन योजना की परिकल्पना कर रहा है, जिसके अनुसार स्नातक होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष ग्राम-सेवा करनी पड़ेगी। इस अनिवार्य भरती पर वार्षिक व्यय पांच करोड़ रुपये होगा, अर्थात् प्रति व्यक्ति पर एक हजार रुपये। न कभी बलान् कोई कार्य सफल हो सकता है, और न उण्डे की मार में समाज-सेवा का भाव ही उदित हो सकता है। यह तो 'घर-बाप सती करना' रहा। मैं पैसे की बरबादी को भी रोकना चाहिए। कभी-कभी हम अन्धा-धुन्ध अर्थ नाश करते हैं। फरवरी या मार्च में थड़ाथड़ नवीन योजनाओं की स्वीकृति दी जाती है; अविचार-विचार किये बिना ही, अल्प काल में द्रव्य का व्यय कर दिया जाता है और यह व्यय भी नहीं किया जाता कि पैसे का उचित उपयोग हुआ भी है या नहीं। इस समय में हम हार्दिक समिति की अधो लिखित चेतावनी कभी विस्मृत नहीं कर सकें :

लोगों का ख्याल है कि शिक्षा-विस्तार केवल पैसे का सवाल है। यह ठीक नहीं है। हम यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि सर्वदा पैसों की आवश्यकता होती है; पर हमसे भी अधिक आवश्यकता एक हृद् एव मित्र सफल की होती है, जिसके अनुसार शिक्षा-नीति को कार्यान्वित करने का निरन्तर प्रयत्न किया जाय और उसीके अनुरूप अर्थव्यय हो। †

आज हमारे देश की सबसे अधिक आवश्यकता है जन-शिक्षा, और उसी ओर मैं अपने प्रयत्नों को केन्द्राभूत करने की भी आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण से ज्ञात जाता है कि भारत की ५ प्रति शत जनता, याने, दो करोड़ व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकता है, १० प्रति शत याने ३८ करोड़ जनता की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है तथा १० प्रति शत अर्थात् दस करोड़ लोगों की आमदनी १४-६ रुपये है। भारत की एक चतुर्थांश जनता को स्वार आने के पक्ष पर दैनिक जीवन गुज़ारना पड़ता है।

† *Harkness Report*, p. 220

हमारी शिक्षा-योजनाओं को लोगों की आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देना होगा। शिक्षा के द्वारा ही जनता का गरीबी दूर हो सकती है; जैसा कि श्री सेयमन ने कहा है, "उचित शिक्षा के अभाव में यह निर्धनता निरस्थायी रहेगी।"

आज हम ऐसे गण-तांत्रिक समाज के सूत्र में मग्न हैं जो कि न्याय, स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुत्व पर आधारित हैं। पर हम मानना का अभाव हम अपनी शिक्षा-योजनाओं में अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अर्याभार के कारण, हमारे कितने ही नवयुवकों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि पिता या अभिभावक के पास सम्पत्ति हुई तो बच्चे को शिक्षा मिल सके, अन्यथा योग्यता एवं पिपामा रहते हुए भी उसे सरस्वती देवी में नमस्कार कर लेना पड़ता है। हम यह अवश्य मानते हैं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कृति शान तथा मुफ्त शिक्षा का बड़ा बहुत बन्दोबस्त अवसरमेष किया है, पर यह संप्रष्ट नहीं है। हम और बरगै राज्य का प्रयास मराहनीय है। गत वर्ष से हम राज्य में, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय नव सौ रुपये से अधिक नहीं है। शिक्षा को लोक-मन्द्रीय बनाने का हम देश में यह सर्वप्रथम प्रयास है। आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी हम आदर्श का अनुसरण कर शिक्षा को लोक-तन्त्रीयता प्रदान करने में सहायक होंगे।

किसी भी शिक्षा-पुनर्योजना में सबसे अधिक आवश्यकता रहती है सशक्त शासकीय प्रबन्ध की। वेद के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का वाद 'केन्द्रीय शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय' दो भागों में विभक्त हुआ। मौलाना माहव की मृत्यु पर्यन्त, शिक्षा-मन्त्रालय की बागदोर एक मन्त्री मण्डल के सदस्य के हाथ में थी। पर हम विभाजन के कारण, दो राज्य मन्त्री दो भिन्न विभागों के लिए नियुक्त हुए। यदि काम बढ़ जाने के कारण, इन दो पृथक् मन्त्रालयों की सृष्टि हुई हो तो हमें कुछ पड़ना नहीं है; पर यदि इस विभाजन का कोई वैयक्तिक कारण हो, तो यह निस्सन्देह वेद का विषय है। हम नीति का प्रत्यक्ष पट्ट होता है, कतिपय वारंशियों का दोहवा, अर्थ तथा श्रम की कुछ-कुछ बरबादी।

शिक्षा प्रशासन में अभी संप्रष्ट अत्याव है।<sup>†</sup> राज्यीय शिक्षा-विभाग पर शिक्षा की अधिकतर जिम्मेवारी रहती है, और शिक्षा मन्त्रालय ही अधिराज शिक्षा-संस्थाओं को चलाता है। पर कुछ विदेश स्कूलों तथा कालिजों को अन्य मन्त्रालय (केन्द्रीय तथा

<sup>†</sup> *Times of India* July 18, 1959

<sup>‡</sup> दार्जिल १९०१।

गर्जनीय) भी जायते हैं, जैसे : कृषि, रेल, धन, परिवहन, स्वास्थ्य, उद्योग, मानुषादि विकास, आदि । ये मन्त्रालय अपनी-अपनी डाफ्टरों, अपना अपना काम अलग करते हैं तथा ये बहुत ही कम एक दूसरे के संस्पर्श में आते हैं । इनके कार्यालयों में समन्वय स्थापित करने की विनीत आवश्यकता है ।

हमारे शिक्षा कार्यालयों की पाइलों की मर्यादित दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है । किसी भी सामान्य विषय पर आदेश निकालने के लिए महीनों लग जाते हैं । इस प्रकार शिक्षा-प्रकार में लकड़ा लग जाता है । इस शोचनीय स्थिति के दो कारण हो सकते हैं : (१) निर्णयक पथ व्यवस्था तथा दफ्तरों परियाटी और (२) अफसरों की शिक्षिता या अकर्मण्यता । शिक्षा-विभागों को प्रथम कारण की तदर्थीज्ञान करनी चाहिए । जो प्रयास अनायश्यक मादूम पड़े, उन्हें तत्काल उठा देना चाहिए । पर शिक्षिता या अकर्मण्यता तो मरती में ही रोसी जा सकती है । इसे दूर करने के लिए पञ्जाब सरकार ने एक विवेक-पूर्ण मार्ग निकाला है । इसके अनुसार सरकारी अफसरों की एक टोली किसी भी दफ्तर की एकाएक तलाशी लेती है और जाँच करती है कि अफसरों का अपना काम कहाँ तक सुचारु रूप में करते हैं । हाल ही में एक ऐसी जाँच शिक्षा-विभाग की हुई थी; और देखा गया है कि २,६०० अनिर्णित कामजात पड़े हुए थे । एक यह दृष्टान्त ही हमारे दफ्तरों की वर्तमान स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश डालता है ।

अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा-नीति शिक्षा-विदों द्वारा निर्धारित हो, न कि राजनीतिज्ञों या अधिकारी-दल द्वारा । खेद के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी-दल के नियमों के आधार पर अनेक राष्ट्रीय मरझारे अपनी शिक्षा-नीति स्थिर करती है । शिक्षा एक अत्यन्त तकनीकी विषय है, जिसका प्रबन्ध सुचारु रूपेण शिक्षा-शास्त्री ही कर सकते हैं । शिक्षा को सबसे अधिक क्षति पहुँचती है 'प्रयास और भूल पद्धति' द्वारा । हम राजनीतिज्ञों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया शिक्षा-क्षेत्र में अपना पैर पसारने की अनाधिकार चेष्टा न किया करें ।

हमारी शिक्षा की दूसरी जटिल समस्या है शिक्षा का गिरता हुआ मान-दण्ड— शिक्षा स्तर का क्रमागत हास । इस विषय पर दो भिन्न मत नहीं हैं । लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए । हमें समझना होगा कि शिक्षा के विस्तार के कारण, अब सभी प्रकार के विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं । पच्चीस या पचास वर्ष पहले ज्यादातर उच्च स्तर के छात्रगण स्कूल या कालिज में प्रविष्ट होते थे । पर अब तो समस्त शिक्षा-मार्ग छात्र-समूह से स्वतन्त्र मर रही है । हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आश्रम के उच्च विद्यार्थीगण, भूतपूर्व अष्टम छात्रों में अच्छा काम कर दिखा रहे हैं ।

अनेक देशों में भी शिक्षा के मान-दण्ड में अबनति दृष्टिगोचर हो रही है । आक्सफोर्ड या केम्ब्रिज सरीखे विश्वविद्यालयों का ही इन्तज़ाम लीजिए । वहाँ छात्र-वृत्ति या शिक्षण-वृत्ति के लिए विशेष योग्य छात्र नहीं मिल रहे हैं । विछोटे वय उपयुक्त विद्यार्थियों के अभाव के कारण, कनिष्ठ विश्वविद्यालयीय-वृत्ति गोक मन्वी पड़ी थी ।

हम सब लोगों का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम अस्मंश बतकर बड़े गढ़ और निश्चेष्टता के नाम पर और बहाल करें । हम शिक्षा स्तर के उन्नयन की भावना जगा करनी चाहिए । हम सम्भव में कुछ सुपायों की चप्ता पट्टे ही खी गयी है, जैसे : शिक्षा सम्स्थाओं की छात्र-वृद्धि रोचना, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात की वृद्धि, निदेशक-पगमरी योजना, प्रहरेखीय पाठ्यक्रम का प्रबंध, शिक्षा-विधि की वृद्धि, उपस्था-प्रणाली का प्रसार, विश्वविद्यालयों में कुनिष्ठ विद्यार्थियों का प्रवेश, इत्यादि । हम यह भी मानना पड़ेगा कि शिक्षा-सम्स्थाओं की वृद्धि के कारण, अब सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा या प्राध्यापक निपुण हो रहे हैं । हम बाग्य भी अन्वयन स्तर भाव देना नहीं है, जैसा हम वर्ष पूर्व था । विद्यार्थीगण भी आदर्श-नैतिक चरित्र ग्रहण कर रहे हैं । अविश्रांत छात्र मन लगाकर विद्याभ्यसन करते ही नहीं हैं । अन्तर्गत बड़े आनन्द नहीं है कि शिक्षा स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है ।

प्रायः भारतीय शिक्षा की सबसे दुःस्मय एवं निःशुभ समस्या है “विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता” होना । यह विरति होखती है माटी की मूर्ति । इन पाँच दिन वृद्धि की चप्ता जा रही है और हमारे बाग्य गारे देश सभी गरीबी में जा रहे हैं । हम शोचनीय स्थिति पर बड़ी-बड़ी बिजाने गिरी जा सकती हैं । तथापि हमारे प्रमुख कारणों का यहाँ उद्देश्य बिजाना है । ये कारण ये हैं : (१) सुन्दर तथा कार्यक्षम प्रशासन में विधिहीनता, (२) सुन्दर या उपयुक्त अन्वयनों का अभाव, (३) शिक्षा सम्स्थाओं में अन्वयन छात्र-वृद्धि, (४) कर्मचारी पदावली का निरा, विद्यार्थियों में, उपस्था-प्रणाली, सांख्यिक शिक्षा तथा आर्थिक कार्यों का अन्वय, (५) विद्यार्थी-समूहों का अन्वयप्रणाली, (६) शिक्षा सम्स्थाओं में धार्मिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा का अन्वय, (७) अर्थ-समस्याएँ, (८) निदेशक तथा पगमरी सुन्दरता, (९) शोचनीय विरति कि प्रभाव का अन्वय, (१०) दुर्दिन शिक्षा-प्रणाली, (११) उपस्था-प्रणाली का शिक्षा पर प्रभाव, (१२) अन्वयन प्रभावकारी अन्वयप्रणाली का विद्यार्थियों पर प्रभाव, (१३) अन्वयन के विरति के कारण एवं (१४) उपस्था-प्रणाली में अन्वयन का अन्वय ।

प्रत्यक्ष हम कारणों का उद्देश्य हम प्रभाव के सुन्दर से से से सुन्दर है हम सभी पर बेहतर एवं अन्वयन कारणों की चप्ता बहल । हमें सम्भव है विरति कि हमारे





अंग्रेजी मन् १९६७-६८ की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता का मुख्य कारण है सामाजिक जीवन में अनुशासन का अभाव एवं छात्री-बागों का प्रभाव। इसे रोकने के मुख्य तीन उपाय हैं। प्रथमतः, कायदे-कानूनों के द्वारा अच्छी एवं विद्यार्थियों का उपयोग चुनाव या किसी भी गणनीतिक प्रचार के लिए बन्द कर दिया जावे। इसके साथ हमारे नेतागण यह घोषणा करें कि वे विद्यार्थियों का उपयोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं करेंगे। हमारे देश में पुरातन काल से धर्म युद्ध का ही मठब था। क्या चुनाव जीतने के लिए यह आवश्यक है कि हम बालकों की एक पूरी पीढ़ी की नैतिकता और शिक्षता का प्रतिदान कर दें? द्वितीयतः, शिक्षा संस्थानों को भी मनक रचना चाहिए कि मर्यादा में विद्यार्थी-सब क्षेत्रीय या गणनीतिक आधार पर समूहित न होंगे। विद्यार्थियों का सामाजिक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना है। उनका यह उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब वे इन चित्त होकर शिक्षा-प्राप्ति में ही मग्न रहें। गणनीति के कारणों में भाग लेने से, जीवन में मर्यादा, शान्ति और विप्रती के बाजों का अङ्गुग होता है, जिससे उनकी प्रभावता नष्ट हो जाती है और शिक्षा के कारणों में एक प्रकार का आन्दोलन मचता है। तृतीयतः, छात्रों को धरने अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाया जाय। विद्यार्थी कल्याण-कार्यों के प्रसार की सख्त ज़रूरत है।

चतुर्थतः छात्रों की अनुशासन-हीनता की मर्यादा जितने बड़े पैमाने पर हम मुना या पढ़ा करते हैं, उतने पैमाने पर यह होती नहीं है। यह तो परवर्तिका का प्रभाव है कि एक छोटी-सी घटना को मर्यादा समालोचना के रूप में दे दिया जाता है। हमें यह भी स्मृत नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों की यह अनुशासन-हीनता केवल हमारे देश की ही सीमारा नहीं है, बल्कि यह एक विश्व-व्यापी व्यापि है। दो विश्व-युद्धों के बाग, समार के अनेक देशों का नैतिक पतन हुआ है, जेगा कि भी हमारे बरीर रहने हैं :

इन युद्धों के समय में, पृथ्वी से 'मर्यादा' का सबसे पुराने लोग हुआ। लड़ाइयों के पत्र स्वरूप एक ऐसे व्यक्तिवाद का उदय हुआ, जिसने अमन उपायों के द्वारा घन जोड़ा था।... नैतिक पतन, बाग-बाजार, उन्कोच, रिश्वत या घूमगोरी का प्रभाव युद्ध-अनुशासन पर पड़े जितना रहा !!

अनुशासन-हीनता एक और बाग है, और यह है मर्यादा जीवन की अवस्था। विद्यार्थियों का हृदय टहन उठता है, जब वे सोचने हैं कि विद्यार्थी जीवन

की समाप्ति के बाद क्या होगा ! बेकारी की समस्या को सोचकर उनका हृदय भगबुल हो जाता है । आज जो पढ़े-लिखे लोग बेकार हो रहे हैं, और उनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है; वह कितनी चिन्ताजनक है !! आज से अस्सी वर्ष पूर्व भारतेन्दु चन्द्र हरिश्चन्द्र ने एक व्यंग्य लिखा था :

तीन बुलावे, तेरह धावे;

निब-निब विपदा रोह सुनावे ।

आँखें फूटी, मरा न पेट;

क्यों सखि साजन ! नहिं 'प्रेमिएट' !!

हमारे देश में प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है । पर कभी-कभी प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या हम आवश्यकता से अधिक प्राविधिकों की संख्या तो नहीं बढ़ा रहे हैं ? माधारण शिक्षित की बेकारी की अपेक्षा उच्च एवं महींगी शिक्षा पाये हुए प्राविधिक व्यक्तियों की बेकारी में अधिक जटिल समस्याएँ, असन्तोष और कुप्रा उत्पन्न होती है ।

पाउन्डल ऑफ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिमर्च की उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी, १९५७ में १,३४८ उच्च शिक्षा-प्राप्त वैज्ञानिक और प्राविधिक बेकार बैठे हुए थे । ये आँकड़े सम्पूर्ण न थे । अभी जब हमारी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा योजनाएँ पूरी तरह से चालू नहीं हो पायी हैं और उनसे अपेक्षित गति में स्नातक नहीं निकल रहे हैं तब उनकी बेकारी की यह स्थिति है !! तो यह स्थिति उस समय द्रिग रूप में होगी जब देश और विदेश में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर देश में स्नातकों का भंडा लगेगा ! निश्चय ही यह एक जटिल समस्या है, जिसके हल न होने में देश की आर्थिक छवि तो होगी ही, साथ ही हम उच्च शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की बेकारी में उत्पन्न मतभेदों का सामना करने को भी बाध्य हो जाएंगे । जब देश में निरोधन का संकल्प है, तब अत्यंत ही यह आशा की जा सकती है कि देश के वर्गगत अर्थ में हम अपने को मोड़ने का प्रयत्न करेंगे ।

पर सबसे ज़रूरी समस्या है दैनिक जीवन में आरंभ की आवश्यकता की । हम जहाँ भी दृष्टि डालें हैं, वहाँ ही आरंभ का पान देखते हैं । घूम गिरान का प्रयत्न हम करते हैं, बड़े-बड़े जहाजों की आवाजें हैं, आवाजें तो दूर गिरानों की बड़ी-बड़ी मशीनों की आवाजें हैं, बड़े-बड़े जहाजों की आवाजें हैं और कोई ध्यान नहीं है । जहाँ शिक्षा है, जहाँ शिक्षा का प्रयत्न है, न ही वैज्ञानिक बर्ण । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की

उपदेश देने हैं — बड़े-बड़े उपदेश — सत्य बोलो, मेहनत करो, काम से जी न चुगओ, आदि। पर जब वह नवयुवक उसी पूज्य उपदेशक को अमलगानी, उच्छृल्ल और काम-ब्योग पाता है तब वह ध्वरा उठता है, उसका मन सत्य से ढिग जाता है और वह आत्म-विश्वास से भर जाता है। हमारे नवयुवकों के सामने केवल आदर्श की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आदर्श पुरुष, आदर्श जीवन और आदर्श समाज की आवश्यकता है। पर आजकल तो भारत का दिनो दिन नैतिक पतन होता जा रहा है।

आज हम पंच-वर्षीय योजनाएँ चला रहे हैं। हम फैक्टरी तथा वैज्ञानिक शोध-महादाएँ खोल रहे हैं, कल-कारखानों की उन्नति करना चाहते हैं, नदियों पर बाँध बांध रहे हैं, कृषि की उन्नति चाहते हैं, सहकारिता की योजनाएँ चला रहे हैं। इन सब कार्य-कलापों का उद्देश्य है देश की समृद्धि, लोगों की आर्थिक उन्नति तथा देश में गरीबी और बेकारी का निष्कासन। पर किसी भी देश की उन्नति उसकी धन राशि के द्वारा मानी नहीं जा सकती है। देश की उन्नति जनता की वैयक्तिक उन्नति पर निर्भर है। जनतन्त्र भारत में हमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। कारण, जन-तन्त्र इनमें द्वारा ही संगठित होता है। इस कारण, स्वाधीन भारत की उन्नति के लिए हमें ऐसे नर-नारी चाहिए, जिनका हृदय देश-प्रेम से भरा हो, एवं जो कर्तव्य-निष्ठ तथा चरित्रवान् हो। क्या ही है :

बने कर्मठ, दृढ़ मती, पवित्र —

कर लके भारत का अभ्युदय;

लक्ष्य हो जिसका दिग्गज चरित्र

मिले हम सबको ऐसा हृदय!!



**परिशिष्ट एक**  
**शिक्षा संस्थाएँ एवं छात्र-संख्या**  
**भारत (१९५६-५७)**

संस्था	संस्था-संख्या	छात्र-संख्या
विश्वविद्यालय ...	३३	
माध्यमिक एवं हाइगामीट्रिगट शिक्षा-मण्डल	१२	
अनुसन्धान संस्थाएँ	४१	
कला एवं विज्ञान कालिज ...	८४९	६,२७,७३४

**व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा-सम्बन्धी कालिज**

कृषि ...	२५	७,०५१
वाणिज्य	२८	६१,३६३
शिक्षक-प्रशिक्षण ...	१३३	१५,१६६
इजीनियरिंग ...	४७	१९,२०४
वन-विद्या ...	३	४२७
कानून ...	२९	२०,८१७
मेडिकल ...	९९	२७,२८९
शारीरिक शिक्षा	१०	४७८
टेकनोलॉजी ...	७	२,७०१
पशु-विद्या	१४	४,६५९
अन्य क्षेत्र ...	४	८७८

**विशेष शिक्षा-सम्बन्धी कालिज**

संगीत, नृत्य, एवं अन्य उल्लिखित कलाएँ	२७	३,७३८
प्राच्य विद्या	७९	५५३
समाज-शास्त्र ...	६	४७६
अन्य क्षेत्र	१०	३,१८२

## शिक्षा के स्कूल

संस्था संख्या

छात्र-संख्या

उच्च/उच्चतर एवं उच्च-बुनियादी ...

मिडिल

११,८१५

२२,५४,९९२

प्राथमिक

...

२४,४८६

५७,५८,६८५

व प्राथमिक

...

२,८७,००८

५,०९,६४,८०८

३६०

९९,३९३

यिक एवं तकनीकी स्कूल

वि

या एच हाफ्ट

९४

६,०४४

मिडिय

१०४

१४३४५

मिडियरिंग

...

८६९

८०,००९

विद्या

..

६८

५०००६

योग

...

४

१३४

काल

..

५३३

३६८००

शिक्षा

...

१०९

३,५६९

प्रशिक्षण

..

३६

३,५००

पैगजी

..

९९६

९५,४३४

बेगना

...

१११

१३,६६६

विशेष

..

७

१,०६६

...

१९

१०००

ता-महाबन्धी स्कूल

के लिए

कार्यकर्ताओं के लिए

...

९८

५,००८

एच एच अन्य लॉजिस्टिक्स

४४

४,०००

माला

१८४

१०,६०३

मालिकों के स्कूल

...

३,३००

१,००३-६

मैट्रिक शिक्षा

..

३३

२,००३

माल

..

४४,०५८

१०,०४,९८०

...

१,३०३

६८,८०८

कुल योग..

३,००,८३०

३,६०,०५३३०

**परिशिष्ट दो**  
**भारत के विश्वविद्यालय, १९५८**

क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिन्न संख्या	छात्र संख्या
१	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (१९२७)	शैक्षणिक एवं संवर्दीय	६०	३७,३१५
२	अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (१९२०)	सावास एवं शैक्षणिक	२	४,३७०
३	अलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलाहाबाद, (१८८७)	सावास एवं शैक्षणिक	४	८,१६९
४	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वास्तेयर (१९२६)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	४९	२९,८४०
५	अन्नामलय विश्वविद्यालय, अन्नामलयनगर (१९२९)	सावास एवं शैक्षणिक	—	२,७६५
६	बनारस विश्वविद्यालय बाराणसी (१९१६)	सावास एवं शैक्षणिक	२१	१०,२१०
७	बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (१९४९)	सावास एवं शैक्षणिक	३	४,८५१
८	बिहार विश्वविद्यालय, पटना (१९५२)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	७६	४८,०३१
९	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (१८५७)	संघात्मक एवं शैक्षणिक	४२	३९,४५६
१०	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१८५७)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	१४८	१,१३,७५१
११	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (१९२२)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	२२	१३,०२८
१२	गोदायी विश्वविद्यालय, गोदायी (१९४८)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	२६	१५,५८१

क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिन्न सख्या	छात्र-सख्या
१३	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (१९५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१२	—
१४	गुडगत विश्वविद्यालय अन्तर्मन्नाद (१९५०)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४५	२१,५७६
१५	जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (१९५७)	संबन्धीय एवं सघात्मक	१७	—
१६	जाधवपुर विश्वविद्यालय, जाधवपुर (१९५४)	सावाम एवं शैक्षणिक	२	१,२१८
१७	जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय, भीनगर (१९४८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२५	६,०९९
१८	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाह (१९४९)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२५	८,२२०
१९	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (१९३७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	६६	३०,७७७
२०	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (१९५७)	सावाम एवं शैक्षणिक	—	—
२१	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (१९२१)	सावाम एवं शैक्षणिक	१३	१०,८११
२२	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास (१८५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१०५	६०,२८९
२३	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (१९५८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	—	—
२४	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (१९१६)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	५३	२६,२२०
२५	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (१९२३)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२८	१३,४७८



क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	सालिक मर्यादा	छात्र-संख्या
२६	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	३४	१७,५१४
२७	पञ्जाब विश्वविद्यालय, लुधियाना (१९४७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	११६	५१,११५
२८	पटना विश्वविद्यालय, पटना (१९१७)	सावास एवं शैक्षणिक	१०	९,४७७
२९	पूना विश्वविद्यालय, पूना (१९४९)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	३९	१९,८४६
३०	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१९४७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४१	१७,७२४
३१	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (१९४८)	सावास एवं शैक्षणिक	—	६७
३२	सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्हभविद्यानगर, आनन्द (१९५५)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४	२,६३१
३३	सागर विश्वविद्यालय, सागर (१९४६)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२३	९,४५८
३४	एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१९५१)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	६	१,९९४
३५	श्री व्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९४८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१७	१०,००२
३६	उत्कल विश्वविद्यालय, कटक (१९४३)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२१	७,१३०
३७	विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शान्ति-निकेतन (१९५१)	सावास एवं शैक्षणिक	६	६५९
३८	विक्रम-विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२६	—

\* —अंक प्राप्त नहीं हुए।

# परिशिष्ट तनि परिभाषिक शब्दावली

**A**  
 Ability-योग्यता  
 Aboriginal-आदिवासी  
 Academic-शालीय  
 Accommodation-वास-स्थान  
 Account-हिमाव, लेखा  
 Achievement-निराति  
 Act-कानून  
 Activity-क्रियाशीलता  
 ——— Method-क्रियात्मक प्रणाली  
 Administrator-प्रशासक  
 Adolescent-विद्यार्थी  
 Adviser-सलाहकार  
 Affirming-समर्थनीय  
 Agenda-कार्यक्रम  
 Aid-सहायता  
 Aided-सहायता प्राप्त  
 All-India Council for  
 Elementary Education  
 -सर्वभारतीय मूलभूत शिक्षण  
 परिषद्  
 All-India Council for  
 Secondary Education-  
 -सर्वभारतीय माध्यमिक शिक्षण  
 परिषद्  
 All-India Council for  
 Technical Education-  
 -सर्वभारतीय प्रौद्योगिक शिक्षण  
 परिषद्

Astronomy-ज्योतिष  
 Audio-visual aids-श्रवण-दृश्य  
 उपकरण  
 Autonomy-स्वायत्तता  
 ACC-महासंघ मध्य शिक्षार्थी दल

**B**  
 Basic Education-मूलभूत  
 शिक्षा  
 Bat-चिखेरा  
 Biology-जीव विज्ञान  
 Boat-जहाज  
 Book-किताब  
 Book-binding-किताबबन्दी  
 Boarded school-विद्यार्थी-कक्ष  
 Botany-वनस्पति शास्त्र  
 Budget-आय व्यय  
 Bureau-कार्यालय

**C**  
 Crime-सर्जित अपराध  
 Camp-शिविर  
 Card-board work-पत्रकारिता  
 Carpentry-सुदृष्टि  
 Census-जनगणना  
 Central Advisory Board  
 of Education-केन्द्रीय मध्य  
 शिक्षण-परिषद्  
 Central Board of Secondary Education-  
 -केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण  
 परिषद्  
 Central Board of Technical Education-  
 -केन्द्रीय प्रौद्योगिक शिक्षण  
 परिषद्  
 Cell-कोठरी

Cancellor-कुलपति	Director of Education-शिक्षा संचालक
Charter-अधिसार-पत्र	Discipline-अनुशासन
Chemistry-रसायन-ज्ञान	Drawing-चित्र-कला
Citizenship-नागरिकता	Dying-रंगरेजी
Classification-वर्गीकरण	E
Club-उत्सव गृह	Education-शिक्षा
Co-curriculum-पाठ्य-विषयान्तर	Education Department-शिक्षा विभाग
College-बालिका, महाविद्यालय	Educationist-शिक्षार्थी, शिक्षक
Commerce-वाणिज्य	Efficiency-क्षमता
Commission-आयोग	Embroidery-करींदे का काम
Committee-गणिति	Engineer-इंजीनियर
Compact-टीका, मध्यम	English-अंग्रेजी
Cumulative Record Card-उत्तमा विवरक पत्रिका	Entertainment-आनन्द प्रदान करने वाला कार्य
Concurrence-समानता-पूर्णा	Examination-परिक्षा
Co education-सहाय शिक्षा	Examination (External)-बाह्य परिक्षा
Continuation Education-प्रत्युत्थापन शिक्षा	(Internal)-आन्तरिक परिक्षा
Constitution-संविधान	(Personal)-व्यक्तिगत
Coordination-सम्बन्ध, एकत्रीकरण	Experiment-प्रयोग
Correlation-संबन्ध, सम्बन्धित	Extension-विस्तार
Courtesy-करिद्वारा	Experimental Method-प्रयोग विधि
Credit-क्रेडिट	Extra-अतिरिक्त
Cultural Education-सांस्कृतिक शिक्षा	Extra-mural & library extension-बाह्य एवं पुस्तकालय विस्तार

## F

Family Planning-परिवार  
नियोजन  
Federal-संघात्मक  
Fee-शुल्क  
Finance-वित्त  
Fund निधि  
Furniture-अवसाध

## G

Gardening-बागवानी  
General Education-सामान्य  
शिक्षा  
Geology-भूगर्भ विज्ञान  
Geometry-रेखा-गणित  
Gift-उपहार  
Graduate स्नातक  
Grant-in-aid-आर्थिक अनुदान  
Guidance-निर्देश

———— Bureau-निर्देश-केन्द्र

## H

Handicapped-मजबूर  
Handicraft-दस्तकारी  
Hostel-छात्रावास  
Humanities-मानवीय विषय

## I

Idiot-उद्भ  
Indirect-परोक्ष, अप्रत्यक्ष  
Individual-वैयक्तिक, व्यक्तिगत  
Industry-उद्योग  
Infancy-शैशव  
Inspection-निरीक्षण

Inspector-निरीक्षक, इन्स्पेक्टर  
Inservice Education-मध्य-  
अध्यापन शिक्षा

Institution-संस्था  
Integration-एकीकरण  
Intelligence-बुद्धि  
Intelligence Quotient-बोध  
लब्धि

———— Test-बुद्धि परीक्षा  
माप

International-अन्तर्राष्ट्रीय

## J

Juvenile-बाल अपराधी  
———— Court-बालापराधी  
न्यायालय

## L

Laboratory-प्रयोगशाला  
Labourer-श्रमिक  
Leather-work-चर्मकार्य  
Life-long-भाजीवन

## M

Maladjusted-असामञ्जस्य  
Management-प्रबन्ध  
Manual-शारीरिक  
Mechanistic-यांत्रिक  
Medium-माध्यम  
Meeting-बैठक, अधिवेशन  
Mental Testing-बुद्धि परीक्षण  
Military Training-सैनिक  
प्रशिक्षण  
Ministry-मन्त्रालय  
Minute-लघु-पत्र

Monitorial System-

छात्राभ्यास प्रणाली

Moron-मूर्ख

Mother tongue-मातृ-भाषा

Multipurpose-बहुद्देशीय

Municipality-नगरपालिका

Ministry of Education-

शिक्षा मन्त्रालय

Ministry of Scientific

Research and Cultural

Affair-वैज्ञानिक अनुसन्धान

और सांस्कृतिक मन्त्रालय

## N

NCC-राष्ट्रीय सेन्य शिक्षार्थीदल

National Council of

Rural Edn - राष्ट्रीय ग्रामीण

उच्चतर शिक्षा परिषद

National Council for

Women's Edn - राष्ट्रीय

स्त्री-शिक्षा परिषद

Needle-work-सुचि-कार्य

Nurse-प्राणी

## O

Objective Test-वस्तुगत परीक्षा

Observation-अवलोकन

Occupation-धन्धा, रोजगार

Optional-वैकल्पिक

Oral-मौखिक

Overseer-कार्य-निरीक्षक

## P

Physically Handicapped

Physiology-शरीर विज्ञान

Planning-योजना

Post-graduate-उत्तर-ग्रेजुएट

Post-war युद्धनंतर

Poultry-पुष्ट-पालन

Practice Teaching-

अभ्यास

Preparatory-प्रारंभिक

Pre-service Educa

पूर्व-अभ्यास शिक्षा

President-अध्यक्ष

Principal-आचार्य

Private-निजी, स्वमालिक

Productive-उत्पादनशील

Psychology-मनोविज्ञान

## Q

Qualification-योग्यता

Qualitative-गुणात्मक

Quantitative-संख्यात्मक

Quarterly-त्रैमासिक

Quinquennial-पंच-वर्षीय

## R

Rambling-परिभ्रमण

Recognition-मान्यता, प्र

Reconstruction-पुनर्रचना

Re-education-पुनः शिक्षा

Reformatory-सुधार विद्या

Refresher-पुनर्संजीवन

Report-प्रतिवेदन

Repression-दमन

Research-शोध, गवेषणा,

संशोधन

Resolution-प्रस्ताव

Rural-ग्राम्य

## S

Salary-वेतन

Scholarship-वृत्ति

Secretary-सचिव

Self activity-आत्मक्रियाशीलता

—— Government-स्वायत्त शासन

—— Supporting-सहायक, स्वाध्यायी

Sewinar-सोही

Sense training-ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा

Social Efficiency-सामाजिक कुशलता

Socialization-समाजीकरण

Specialization-विशिष्टीकरण

Specialist-विशेषज्ञ

Spinning-कताई

Spiritual-आध्यात्मिक

Stagnation-अवरोधन

Standard-स्तर, मान

Stage-प्रसंग

State-राज्य

Statistic-सांख्यिकी

Survey-अन्वेषण

## T

Table-तालिका

Technical Education-

तकनीकी या प्राविधिक शिक्षा

Text-book-तट्ट-पुस्तक

Theoretical-भेदात्मिक

Thesis-महा निबन्ध

Time-table-समय-सारिणी

Training-प्रशिक्षण

Trial-and-error Method

प्रयास और त्रुटि-प्रणाली

Tribunal-न्याय-सभा

## U

Unaided-स्वाश्रित

Undergraduate-उप-स्नातक

Union-संघ

Unit-अन्विष्टि

UNESCO-विज्ञान एवं संस्कृति संगठन

UNO-संयुक्त राष्ट्र संघ

Uniformity-एकस्यता

Universal-सार्वभौमिक

UGC-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

## V

Value-मान्यता, मूल्य

Virtue-गुण

Vocational-व्यावसायिक

## W

Wastage-व्यर्थता

Weaving-बुनाई

Work-कर्म

—— load-बोझ

—— ship-कर्मशास्त्र

## Y

Youth-युवक

—— welfare-युवक-कल्याण

## प्रथम-सूची

### पहला अध्याय : भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति

1. *Primer of Civilisation in Ancient India*. Patana, Faculty of Education and Psychology, 1957. 2-2.
2. *A. N. Education in Modern India*. Calcutta, Orient Black Co., 1947. 1-1-4.
3. *Dr. B. N. Das*. *Development of Modern Indian Education*. Bombay, Orient Longmans, 1955. pp. 33-.
4. *Government of India India, 1957*. India, Ministry of Information & Public Affairs, 1957. 1-1-53.
5. *James, H. R. Education and State-ship in India*. Bombay, Longmans, 1917. pp. 143.
6. *Mayhew, A. The Education of India*. London, Faber & Gwyer, 1925. pp. 30-.
7. *Mookerji, R. K. Ancient Indian Education*. Bombay, Macmillan, 1947. pp. 65-.
8. *Mukerji, S. N. History of Education in India (Modern Period)*. Baroda, Acharya Book Depot, 1957. pp. 341.
9. *Nurullah S., and Nair J. P. A History of Education in India*. Bombay, Macmillan, 1951. pp. 953.
10. *प्रकाश, मुनेश्वर : भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रथम भाग, पटना, अकाला प्रेस, १९५५, पृष्ठ २८८ ।*

### दूसरा अध्याय : शिक्षा-व्यवस्था

1. *भारत सरकार के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित प्रतिवेदन :*
2. *Annual Reviews on Education: Education in India, 1947-48; 1948-49; 1949-50; 1950-51; 1951-52; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56.*
3. *भारत, १९५९, पृष्ठ २८९ ।*
4. *Education—A Graphic Representation in India. 1957. Ch. VI.*
5. *Progress of Education in India, 1947-52. 1953 pp. 279.*

Mukerji, S. N. *An Introduction to Indian Education*. Baroda, Acharya Book Depot. 1958 Ch. II.

—, *Secondary School Administration* Baroda, Acharya Book Depot, 1959. Ch. III.

The Indian Institute of Public Administration *The Organisation of Government of India* Bombay, Asia Publishing House, 1959. Ch. XVI.

### तीसरा अध्याय : दुनियादी शिक्षा

अन्वारी, गिरद एव दामा, मोहनलाल : दुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त, दिल्ली, अतमचन्द्र कपूर एण्ड सन्स, १९५८, पृष्ठ १६० ।

Aryanayakam, E. W. *The Story of Twelve Years* Sevagram, Hindustani Talimi Sangh n. d. pp. 16

Avinashlingam, T. S. *Understanding Basic Education* Delhi, Manager of Publications, 1954 pp. 61

Government of India. *Handbook of Teachers for Basic Schools*. 1956. pp. 325.

Hindustani Talimi Sangh, Sevagram *Basic National Education* n. d. pp. 96.

—, *Educational Reconstruction*. 1950. pp. 153

—, *One Step Forward*. 1940. pp. 292

गमस्र नई तालीम, १९४६, पृष्ठ २२५.

कश्यप, मनोहरा एव गुप्त, अमृतलाल : नई तालीम के सिद्धान्त एवं शिक्षाविधि, पंजाब, विश्वविद्यालय, १९५७, पृष्ठ २८६ ।

Kripalani, J. B. *The Latest Fsd*. Sevagram, Hindustani Talimi Sangh, 1938 pp. 102.

Patel, M. S. *Educational Philosophy of Gandhiji*. Ahmedabad, Navyan Press, 1953. pp. 23.

Sharma, K. L. *The Wardha Scheme*. Udaypur, Vidya Bhawan, 1949. pp. 323.

Solanki, A. B. *Technique of Correlation in Basic Education* Baroda, Faculty of Education & Psychology, 1956. pp. 43



## संदर्भ ग्रन्थ : प्राथमिक शिक्षा

1. A. N. *Primary Education in India*. Calcutta, India: Asiatic Society of India, 1900. pp. 100.

अनन्त, अमृतमः भारतीय शिक्षा का आधुनिक विकास. मुंबई, इंडिया, १९५०, पृष्ठ १००

Deane, D. V. *Universal Compulsory and Free Primary Education in India*. Bombay: Indian Institute of Education, 1952. pp. 100.

Deane, D. V. *Primary Education in India*. Bombay, Secretariat of India Service, 1948. pp. 100.

दुर्गे प्रदीपिका एवं नृ संजीवनी. भारतीय शिक्षा का इतिहास, अन्तर्गत विभाग, १९५७, पृष्ठ ५९८।

Estimates Committee *Elementary Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1955. pp. 80.

Ministry of Education *Report of the First Meeting of the All India Council for Elementary Education*. Delhi, Manager of Publications, 1953. pp. 121.

Parulekar, R. V. *Literacy in India*. Bombay, Macmillan, 1939. pp. 181.

Sanyal, K. G., Nair, J. P., and Husain S. Abid. *Compulsory Education in India*. Paris, UNESCO, 1952. pp. 191.

Sen, J. M. *History of Elementary Education in India*. Calcutta, Book Co., 1943. pp. 313.

सिंह, जेधोपर एवं शास्त्री, भूदेव. भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास. आगरा, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, १९५७. पृष्ठ २२९।

## पाँचवा अध्याय : माध्यमिक शिक्षा

*A Report on Secondary Education Extension Course.* Madras, South India Teacher, Nos. 7 & 8 1951

Estimates Committee. *Secondary Education* New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. pp. 90.

Government of India *Head Masters on Secondary Education* Delhi, Publications Division, 1954 pp. 40.

—, *Report of the Secondary Education Commission* Delhi, Publications Division, 1953. pp. 319

Hampton, H. V. "Secondary Education", *The Educational System* Bombay, O U.P. n. d. pp. 64

Mukerji, S. N., ed. *Secondary Education in Other Lands.* Baroda. Faculty of Education and Psychology 1956 pp. 65

Report of a Study by an International Team *Teachers and Curricula in Secondary Schools.* Delhi, Ford Foundation 1954. pp. 142.

"Report on Baroda Workshop," *Journal of Education & Psychology.* April, 1955

मिर्, रायप्रसाद : भारतवर्ष तथा उत्तरप्रदेश में प्रजातन्त्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका. लखनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार, १९५९. पृष्ठ २०८।

Siqueira T. N. "The Aim of Secondary Education", *South India Teacher.* November, 1954.

## छठा अध्याय : विश्वविद्यालयीय शिक्षा

Basu, A. N. *University Education in India* Calcutta, Book Emporium. 1944. pp. 166.

Dongerkeri, S. R. *Thoughts on University Education.* Bombay Popular Book Depot, 1955. pp. 170.

— *Universities and National Life.* Bombay, Hind Kitabs 1950, pp. 115.

## चौथा अध्याय : प्राथमिक शिक्षा

Basu, A. N. *Primary Education in India*. Calcutta, Indian Associated Publishing Co. 1946. pp 64.

भटनागर, रामप्रसाद. भारतीय शिक्षा का आधुनिक इतिहास मुद्राबद्ध, स्टोर्स, १९५९, पृष्ठ २४० ।

Desai, D. M. *Universal Compulsory and Free Primary Education in India* Bombay, Indian Institute of Education pp 392.

Desai, Dinker. *Primary Education in India*. Bombay of India Society, 1948 pp. 128.

दुबे लक्ष्मीकान्त एवं सूर रामणीकान्त. भारतीय शिक्षा का इतिहास किताबघर, १९५७, पृष्ठ ५९८ ।

Estimates Committee. *Elementary Education*. New Sabha Secretariat, 1958. pp. 89.

Ministry of Education *Report of the First Meeting India Council for Elementary Education*. Delhi Publications, 1958. pp 121.

Parulekar, R. V. *Literacy in India* Day, Me pp. 181.

Satyadran, K. G., Naik, J. P. in S. Abhi *Education in India*. F 1952

Sen, J. M. *History of India* Book Co., 1943. p

सिंह, ब्रह्मधर एवं शास्त्री गयाप्रसाद एण्ड

- Dasgupta, Jyoti Probha. *Girls' Education in India in the Secondary and Collegiate Levels*. Calcutta, University of Calcutta, 1938. pp. 269
- Gandhi, M. K. *Women and Social Injustice*. Ahmedabad, Navjivan Press, 1942. pp. 276
- Government of India. *Report of the National Committee on Women's Education*. Delhi, Manager of Publications, 1959 pp. 335.
- Indra. *Status of Women in Ancient India*. Lahore, Minerva Book Shop, 1949 pp. 324
- Joshi, K. L., and Shukla P. D. 'Women and Education in India,' *Women and Education*, Paris, UNESCO, 1953 pp. 264.
- मिह, गणेशप्रसाद : हमारी शिक्षा. बागमती, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १९५८. पृष्ठ ६०९.

### आठवाँ अध्याय : प्राविधिक शिक्षा

- C. A. B. E. *Report of the Technical Education Committee*, 1943 Delhi, Manager of Publications, 1956 pp. 37
- Chandiramani, G. K. *Technological Education in India*. Delhi, Publications Division, 1956 pp. 20
- Estimates Committee. *Technical Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1955 p. 127.
- Government of India. *Report on Vocational Education in India*. (Abbott Wood Reports) Delhi, Manager of Publications, 1937. pp. 138.
- . *Scientific Research*. Delhi, Manager of Publications, 1957. pp. 88.
- National Planning Committee *General Education and Technical Education, and Developmental Research*. L. Sax, Vera & Co., 1958. pp. 23.
- प्रसाद, सुनेश्वर : आरंभिक शिक्षा का इतिहास. (1875-1947). वल्लभ, श्री अरवि प्रेस, १९५७. पृष्ठ ५१७.

- Universities and Their Problems.* Bombay Hindustani, 1948. pp. 191.
- Education Committee. *Report of the Three-year Degree Course.* Delhi, Ministry of Education, 1957. pp. 23.
- Estimates Committee. *University and Rural Higher Education.* New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1957. p. 112.
- Ghosh, J. *Higher Education in Bengal.* Calcutta, Book Company, 1929. pp. 242.
- Government of India. *Directory of Institutions of Higher Education.* 1957. Delhi, Manager of Publications, 1955. pp. 245.
- Indian University Administration.* Delhi, Manager of Publications, 1958. pp. 149.
- . *Rural Institutes.* Delhi, Manager of Publications, 1955. pp. 77.
- . *The Report of the University Education Commission.* Vol. I. Delhi, Manager of Publications, 1949. pp. 747.
- Iyenger, K. R. S. *A New Deal for Our Universities.* Calcutta, Orient Longmans, 1951. pp. 134.
- शिवराम, यशोवन्त एव शर्मा, वेदगान : हमारे शिक्षा प्रतिपेदन, अलीगढ़, विश्व-प्रकाशन, १९५९. पृष्ठ ५५८.
- Mukerji, S. N. *Higher Education and Rural India.* Baroda, Acharya Book Depot, 1956. pp. 342.
- Sheshadri, P. *The Universities of India.* Bombay, Oxford University Press, pp. 58.

### सातवाँ अध्याय : स्त्री-शिक्षा

- All-India Women's Conference. *Education of Women in Modern India.* Aundh Publishing Trust, 1946. pp. 87.
- Bair, Tara Ah, ed. *Women of India.* Delhi, The Publications Division, 1958. pp. 276.
- Cousins, M. E. *Indian Womanhood Today.* Allahabad, Kitabistan, 1941. pp. 207.

- Dasgupta, Jyoti Probha. *Girls' Education in India in the Secondary and Collegiate Levels*. Calcutta, University of Calcutta, 1938 pp 269.
- Gandhi, M. K. *Women and Social Injustice*. Ahmedabad, Navivan Press, 1942 pp 276.
- Government of India. *Report of the National Committee on Women's Education*. Delhi, Manager of Publications 1949. pp. 335
- Indra. *Status of Women in Ancient India*. Lahore, Minerva Book Shop, 1949 pp 324
- Joshi, K. L., and Shukla P. D. "Women and Education in India," *Women and Education*, Paris, UNESCO, 1953 pp. 264.
- विश्व. गणेशप्रसाद : हमारी शिक्षा, बागमती, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १९५८, पृष्ठ ३०९.

### आठवाँ अध्याय : प्राविधिक शिक्षा

- C. A. B. E. *Report of the Technical Education Committee*, 1943 Delhi, Manager of Publications, 1956 pp 37
- Chandrasekhar, G. K. *Technological Education in India*, Delhi, Publications Division, 1956 pp 20.
- Estimates Committee, *Technical Education* New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958 p 127
- Government of India. *Report on Vocational Education in India* (Albott Wood Report). Delhi, Manager of Publications, 1937 pp. 138
- , *Scientific Research*, Delhi, Manager of Publications, 1957, pp. 88
- National Planning Committee *General Education and Technical Education, and Developmental Research*. New York, Macmillan & Co., 1958 pp 20
- ग्रन्थ सूची : भारतीय शिक्षा का इतिहास, (१९५२ (२-२)) पृष्ठ ६५, ६५-६६, १९५३, पृष्ठ ५९०.

४७७, एनोत्तर १. भारतीय शिक्षा का इतिहास, भाग II, सत्य प्रकाशन, १९५८, पृष्ठ ६०८।

Venkattaman, K. "Technical Education", *The Educational System* London, O. U. P., 1953. pp. 64

### नवीं अध्याय : शिक्षक प्रशिक्षण

N.Y.C.E.L. *School and Community Laboratory Experiences in Teacher Education*. Oleana, N. Y. 1945. pp. 340

Association of Training Colleges in India. *Report of the First, Second and Third Conferences*. Buxa, Faculty of Education and Psychology.

Commission on Teacher Education *The Improvement of Teacher Education*. Washington, American Council on Education. 1946. pp. 263.

Divekar, S. M. "A Ploy for Bridging Gulf Between the Basic and Non-Basic Graduate Teacher Education Programmes", *Journal of Education & Psychology*, October, 1956,

Filho, M. B. L. *et al. The Training of Rural School Teachers* Paris, UNESCO, 1953. pp. 164.

Hindustani Talimi Sangh. *Revised Syllabus for the Training of Teachers*. Sevagram, 1952. pp. 81.

Kaul, G. N and Menon T. K. N *Experiments in Teacher Training*. Delhi, Publications Division, 1954. pp. 73.

Mukerji, S. N. "Practical Work of Teachers' Colleges." *Journal of Education & Psychology*, January, 1955.

National Teachers' Association. *Education for Teaching*. Washington, WCOTP. 1954. pp. 57.

*of the First Seminar on Extension Services in Training Colleges*. Hyderabad, 1954. pp. 55.

C. A. *et. al. The Education of Teachers in England, France and U.S.A.* Paris, UNESCO. 1953. pp. 339.

Theodore, C. R., and Cooper, R. M., eds. *The Preparation of College Teachers*. Washington, American Council on Ed., 1950. pp. 186.

## दसवाँ अध्याय : विविध विषय

### १. पूर्व-प्राथमिक-शिक्षा

All-India Child Education Conference. *Problems of Child Education in India*. Indore, Bal-Niketan Sangh, 1956 pp. 150

Estimates Committee. *Elementary Education* New Delhi Lok Sabha Secretariat, 1956, pp. 89

Hindustani Talimi Sangh. *Pre-Basic Education* Sevagram, 1953. pp. 26.

Narulkar, Shanta. *Plan and Practice* Sevagram, Hindustani Talimi Sangh, 1950. pp. 64.

### २. समाज शिक्षा

Apte, D. G. *Social Education at a Glance* Baroda, Faculty of Education & Psychology, 1956 pp. 15.

Community Projects Administration. *Manual of Social Education* Delhi, Publications Division 1955 pp. 110.

Indian Adult Education Association. *Teachers' Handbook of Social Education* Delhi, Publications Division 1955. pp. 101.

दासजी धर्मोदय प्रसवारी : सामाजिक शिक्षा और समाज सेवा, पटना, मध्य-राष्ट्रवादी प्रकाशन, ई. १६७.

Sohan Singh. *Social Education in India*. Delhi, Ministry of Education, 1956, pp. 14.

### ३. मजदूरी की शिक्षा

Estimates Committee. *Special Education* New Delhi, Lok Sabha Secretariat 1956 pp. 63

Planning Commission. *Social Welfare in India* Delhi, Publications Division 1955 pp. 253



Priestly, K. L., and Wright B. P. *Mental Health and Education*. Hong Kong, University Press, 1956, pp. 97.

Seit, M. "Problems of Handicapped Children in India", *Indian Journal of Child Health*, November 1952, pp. 597-607.

#### ५. व्याख्य एवं अनुशासन

C. A. B. E. *A National Plan of Physical Education*. Delhi, Publications Division, 1959, pp. 61.

Datta, C. B. *History and Progress of Physical Education in India*. Banora, Faculty of Education & Psychology, (Unpublished Dissertation for M. Ed., 1956, pp. 521.

Estimates Committee. *Cultural and International Activities*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat 1955, p. 116.

Planning Commission. *Social Welfare in India*. Delhi, Publications Division 1955, pp. 93-119.

#### व्याख्यो अण्णाय : कविमय मण्णाय

Living, D. J. *Schools With a Message for India*. Madras, G. P., 1945, pp. 196.

Government of India. *Experiments in Primary and Basic Education in India*. Ministry of E. & A., Govt. 1951, pp. 36.

Government of India. *Annual Report, 1954-55* (Education). Government of India, Madras Press, 1955, pp. 21.

Government of India. *Ward's Basic Education at Serdagan*. 1955, pp. 2.

Government of India. *Ward's Basic Education at Serdagan*. 1955, pp. 2.

Government of India. *History and Geography of India*. 1955, pp. 2.

Government of India. *Ward's Basic Education at Serdagan*. 1955, pp. 2.

Shahore C. N. "Some Aspects of the Educational Thought of India", *Educational Studies and Investigations*, Vol I Bombay, Asia Publishing House, 1951. pp 262

Shrivasthaspati Indra. "Gurukulas Contributions to the Present Educational System", *Educational India* December 1955

Shrivastha-Dharati. *Prospectus*. Santiniketan Press n 1 pp 15

## अष्टमोऽध्यायः : उपसंहार

Shrivastha, A. *Thoughts on Indian Education* New Varanasi of Publications, 1958. pp 101

Government of India. *Future of Education in India* Ministry of Information and Broadcasting, 1957

—. *The Field of Education* Delhi, Ministry of Education & Scientific Research, 1957 pp 72

Shrivastha, Humayun. *Education in New India* London Allen & Unwin, 1955. pp 212

—. *Student Indiscipline* Delhi, Ministry of Education pp 23

Shrivastha, G. D. *A Plan for Youth Welfare* New Delhi Education 1956 pp 67

# अनुक्रमणिका

(विषयानुसार)

अ

अग्रहार, ६ ।

अज्ञायवध, १३९ ।

अमरिकी टेक्निकल कोअपरेशन, २३१ ।

अनाथालय, २६४, २६८ ।

अनुदान केन्द्रीय, २८, ३३, ८६, ९३,

१५९; प्राथमिक, ६४, ६९, ७८,

८६, ९३; प्राविधिक, २-४; प्रौढ़

(समाज), २५२, २५४; माध्यमिक,

९२, ९९, १११, १३१, १३२;

विश्वविद्यालय, १४०, १५९, १६०;

शिक्षक, २४१, २४२; शिक्षक-

प्रशिक्षण, १११; स्त्री-शिक्षा १८० ।

अनुगमन, २७१, २७५, २७७, २७८,

२९०, २९५, २९६ ।

अनुसन्धान: अनुदान, १४८, १५९,

१६०, १७५; प्रयोगशालाएँ, ३३,

१७५, २०५; प्रगमन, १३१;

प्राथमिक शिक्षा, ७२, ९५, ९६;

प्राविधिक शिक्षा, ३३, २०४ २०५,

२१२; पुर्नर्र्जी शिक्षा, ५०, ५१;

माध्यमिक-शिक्षा, ११२, १३१;

विश्वविद्यालयीय शिक्षा, १४२,

१५९, १६०, १६९, १७८, १७९;

बाल, १५९, १७८, १७९, २०८,

२०९; विज्ञानिक, ३३; शिक्षक-

प्रशिक्षण, २१९, २२९, २३०, २३८;

समाज शिक्षा, २५४; संस्थाएँ, ३३,  
३६, २२० ।

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिम  
जातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग, ७३,  
८२, ८९, ९०, ९२, ९९ ।

अवरोधन, ७७, ७८, ९६ ।

असचाय, १११, १४४, १५९, १६० ।

अहिंसा, ४०-४२, ४४, ४७ ।

अंग्रेजी, १८-२० ४२, ४५, ९७, ९८,  
१००, १०१, १२०, १२१, १२३,  
१७१, १७२, २१० ।

आ

आयुर्वेद, १२, ३५ ।

आयोग: अमरिकी उच्च शिक्षा, २०८,  
२०९; माध्यमिक शिक्षा, १०५,

११६-२२, १३०, १३२, १३३,

२३६, २३९, २४३; योजना, ८५,

२०६; विश्वविद्यालय (१९०२),

२१, १३९, १७३; विश्वविद्यालय

अनुदान, ४१, ३३, ११२, १४७,

१४८, १५४, १५९, १७१, २४१,

२९७; विश्वविद्यालयीय (गणराज्य)

शिक्षा, १०५, ११८, १३५, १६२,

१५२, १५४, १७२, १७४, १७७,

१८९, २३९, २६१; भारत, २१

१००-०२, १६३, २१९; रूस,

२१, ९८, १७९, २१७ ।

आधन, ३, ५ ।





१२; काय, ४९, ११३, ११४,  
१३४, २८१; मौखिक, २३७; वस्तु-  
गत, १३४, २३८; विश्वविद्यालयीय,  
१३५, १७३; शास्त्रान्त, १०२,  
११४; मुघार, ११२, १३३, १३४,  
१७३, २३१।  
पञ्च-वर्षीय योजनाएँ : २३, २१३;  
तृतीय, २५, ८५, १७७, १९०,  
१९१, २०२, २६१; द्वितीय, २३,  
२४, ८३, १२५, १९०, २००,  
२०७, प्रथम, २३, ८३, १११।  
पाठ्यक्रम : गुरुकुल, २७९, २८०;  
टोच, १५; पूर्व-प्राथमिक, २४७,  
प्राथमिक, ६३, ७२, ७६, ७७,  
८२; प्राविधिक, १९९, २००,  
२०३, २०४, २०८, २०९;  
म्रीढ़ (समाज), २५३; धुनियादी,  
४२, ४५, ४६, ४९; मकनब,  
१३, १४; मजदूर, २६७-२६९;  
मशाला, १४; माध्यमिक, ११३,  
११९-२५, १२८; विश्वविद्यालयीय,  
१५२, १५३, १६५-६८; शिक्षक-  
प्रशिक्षण, २२८-३२, २३५-३७;  
स्त्री शिक्षा, १७८, १८७, १८९,  
१९१।  
पाठ्य पुस्तक, १४, ३५, ६३, २५८,  
२५९, २८७।  
पाठ्यक्रम, १५, ६२।  
पारिभाषिक शब्द, १७२, २८५।  
परिचय, १७, २७।  
परिचय, २००, २०२।  
पुस्तकालय, १२, १४, १६, ३२, १११,

१३९, १४६, १५९, १६९,  
२५८, २५९, २८३, २८५, २८६।  
पूर्व प्राथमिक शिक्षा : कार्यक्रम,  
२४७, २४९; प्रकार, २४८, २४९,  
प्रगति, २४७; प्रयोग, २४८, २४९;  
म्रीढ़ शिक्षा, ४४; धुनियादी शिक्षा,  
४५, २४६; रूप, २४४; शिक्षक,  
२४९, सुधार, २४८।  
पेन्शन, १५९।  
प्रमाणन, २८, ३२, १७५, २३०,  
२३१, २५४, २५९, २८७।  
प्रदर्शनी, १७६, २३०, २३१, २५६।  
प्रशामन : केन्द्रीय सरकार, २२,  
२७-३३, ४८, ५०, ८५, १११,  
११५, १२५, १३०, १५४, १५५,  
२४१, २५४, २६७, २७२, २९३,  
पूर्व-प्राथमिक, २४५, प्राथमिक,  
७०, ७२, ८५, ८६; प्राविधिक,  
३३, १९८; मजदूरों की शिक्षा,  
२६९, २७०; माध्यमिक, १९,  
१०१, १०८, १०९, १११, ११२,  
१२५, १३०; गरीब सरकार, २१,  
२२, ३३, ३४, ६४, ७१, ८६,  
१११, १२५, १५६, १६०, २४१,  
२५४, २९२; विश्वविद्यालयीय, १९,  
१०१, १३८-४०, १४३, १६७,  
१४८, १५३-५७, समाज शिक्षा,  
२५३, २५४; स्थायी निवास, ३६,  
३७, ६८, ८०; स्त्री शिक्षा, १८३,  
१८४।  
प्रमाणन कार्य, ११३, १६०, १६९,  
१७६, १८७, २११, २६०, २८८।

प्राथमिक शिक्षा : अनुसन्धान, १२,  
 १६; अनिवार्य, ६६ ७१, ७६, ८०,  
 ८८, २९१; इतिहास, ६४-७१;  
 देश, १०, ११; पाठ्यक्रम, ७६,  
 ७७, ८२, ९२; प्रमाणन, ७२, ७८,  
 ८०, ८५; विषय, ७३, ७४, ८०,  
 ८१, ८३, छात्रावास, ७३, १. शिक्षा,  
 ७६, १३, गैर-सामान्य, ८३ ।

प्राथमिक शिक्षा : अनुसन्धान, २०३,  
 २०५, २०७, इतिहास, १९०-१९२,  
 प्रमाणन प्रमाणन समिति, २०३  
 २०४, प्रमाणन प्रमाणन, २०७,  
 २०९, प्रमाणन प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९ २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९ ।

प्राथमिक शिक्षा : अनुसन्धान, २०९, २०९, २०९ ।  
 प्रमाणन प्रमाणन, २०९, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, प्रमाणन, २०९, २०९ ।

प्रमाणन

प्रमाणन प्रमाणन, २०९, २०९ ।  
 प्रमाणन प्रमाणन, २०९, २०९ ।

प्रमाणन

प्रमाणन प्रमाणन, २०९, २०९-  
 २०९, २०९, २०९, २०९, २०९,  
 २०९ ।

प्रमाणन प्रमाणन : अनुसन्धान ५१;  
 अनिवार्य : ४१, ४२; आश्रित,  
 ५२ ५४; प्रमाण प्रमाणन, ४६,  
 ४७, ४८, ४९, ५०, ५१; प्रमाणन  
 प्रमाणन, ४२, ४५, ५२-५४;  
 प्रमाण, ५६-५७, ५८, ५९; प्राथमिक  
 शिक्षा, ५४; प्रमाण, ४०, ४३, ४५,  
 ५७, प्रमाण प्रमाणन, ५८, ५९;  
 प्रमाणन, ४२ ४५ ४६, ४९;  
 प्रमाण प्रमाणन ४५; प्रमाणन ४६,  
 ४९, प्रमाणन, ४३ ५७, प्रमाण प्रमाणन  
 ४४ ४५, प्रमाणन, ४३ ४९;  
 प्रमाण प्रमाणन, २०९, २०९,  
 २०९-२०९, प्रमाणन ५३, ५४ ।

प्रमाण प्रमाणन ५३ ५४ ।  
 प्रमाण प्रमाणन, ५४, ५४ ।  
 प्रमाण प्रमाणन ५४ ५४ ।

प्रमाणन

प्रमाणन प्रमाणन, २०९, २०९, २०९,  
 २०९, २०९, २०९, २०९, २०९,  
 २०९ ।  
 प्रमाणन २०९, २०९, २०९, २०९,  
 २०९ २०९-२०९ २०९ २०९,  
 २०९ ।

प्रमाणन २०९ २०९ २०९ ।  
 प्रमाणन, २०९ ।

प्रमाणन

प्रमाणन प्रमाणन २०९ २०९ ।

मण्डल अन्तर्विषयविद्यालय ३१ १४६,  
१४७, १९९; केन्द्रीय समाज  
कल्याण, ३५४ केन्द्रीय समाज सेवा,  
३१; केन्द्रीय मन्त्रालय शिक्षा,  
२८, ३१, ३२, ४९, ११८, १२३,  
१६५।

मण्डलों की शिक्षा : इतिहास, २६४;  
पाठ्यक्रम, २६३; प्रशासन, २६९,  
२७०; वर्गीकरण, २६२, २६३,  
संस्थाएँ, २६४-६९।

महामा, १४, १७, ६२, १३६।

मनोरञ्जन कार्य १०४, १७६, ५७,  
५६९।

मन्त्रालय कृषि, १३०, ५९०,  
परिवहन एवं प्रशिक्षण, २५३,  
२९३; वाणिज्य तथा उद्योग, १३०,  
वित्त, २१४; वैज्ञानिक शोध एवं  
समस्याएँ, २९, ३३, १९८, २००,  
शिक्षा, २९-३२, ७३, ११३,  
११२, १५६, १७७, १८३, २५४,  
२६४, २७०, ५७४, ७७७, २७८,  
२९१, २९३; अन्न, १३०, १८३,  
१५३; सामुदायिक शिक्षा तथा  
सहायता; १३० १८३, २९३,  
सूचना तथा प्रशासन, १९३; स्वास्थ्य  
१८३, ५६९।

सांख्यिक शिक्षा : अनुसंधान, ११३,  
११३; इतिहास ९७-१०५;  
उद्देश्य, ११५, ११६, साधन इत इत  
९८, शिक्षण ११३; परिणाम ९८,  
९९, ११३-११५, ११३; साधन  
बन ९८, ९९, १०३, १०४,

११३-११४, ११९-२४; प्रशासन,  
१०१ १०६, १०८, १३०-३४;  
साध्य, ९७, १०१; वित्त, ११०,  
१११; विज्ञान स्कूल, १२४-२८;  
शाला-ग्रह ११३; शिक्षा मण्डल,  
१०९; शिक्षक, १२५, ७४०,  
२४१।

मैट्रिक परीक्षा, ३८, ४२, ९३, ९८,  
९९, १०१, १०४, १०९, ११४,  
११६, १५३, १८५ २६०।



यशोपवीत, ७, ५, १

युद्ध कल्याण, १४६, २७४, २७५।

यर्थता, ७७, ७८, ९६, १६३।

युद्धमाय निर्देशक, १०८।

व्यापार, ३, ४, २९ ३०, १०६,  
७७२।



सामुदायिक नियम, २६८।

साम (प्रशासन) सहाय, २७, २८, २८,  
२९ ३२ ३४ ६४ ७१, ७५,  
८६-८८, ९३ ११३, ११५, १५४,  
१६०, २६३ २०४, २९२।

सामुदायिक शिक्षा मण्डल २५, ३३, १५४,  
२०५।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।

सामुदायिक शिक्षा, २०० २०५ २९०।



वाणिज्य, ६, ३८, ४६ ।

वित्त : पत्र-वर्षीय योजनाएँ, २३-२५.

८७, १२५, १९८; प्राथमिक शिक्षा  
६४, ७३, ७४, ८७; प्राविधिक  
शिक्षा, १९८; मजदूरों की शिक्षा,  
२७०; माध्यम-अध्यापन शिक्षा  
२२९, २३१; माध्यमिक शिक्षा,  
११०, विश्वविद्यालयीय शिक्षा  
१५७, १६०; शिक्षा, ३८, समाज  
शिक्षा, २५६ ।

विद्यापीठ, २७९, २८४, २८५ ।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा : अध्यापन,  
१६८-७०; अनुदान, १५९;  
अनुसन्धान, १३९, १६९ १७४,  
१७५; अंग्रेजी, १७१; इतिहास,  
१३६-४२; कालिज १४३, १४८-  
५०, १६०, १६१; ग्रामीण,  
१५२, १५३; छात्र, १४८, १७४,  
१७५; परीक्षा, १३८, १६३,  
१७३; पाठ्यक्रम, १६५-६८;  
पुस्तकालय, १३९, १४५; प्रकार,  
१४४, १४५; प्रशासन, १४६,  
१५३-५७, १६०, १६१; माध्यम,  
१७१, १७२; माध्यमिक शिक्षा,  
१००-१०२; वित्त, १४५, १५७,  
१६० ।

विहार, ९, १३६ ।

विशाल मन्दिर, २५, २०४ ।

वृत्ति, १५, ३०, ३१, १११, १५९,  
२०४ ।

घेतन, ४१, १३३, १३५, १९२, २४१-  
४३ ।

श

शहर-ग्राम कल्याण, २०३, २०४ ।

शान्ति मेना, ४८ ।

शारीरिक शिक्षा, २९, १०४, १२०,  
१३४, १४१, १४६, २२६ ।

शाला-गृह, ६३, ८७, ९०, १११,  
११३, १३२, १५९, १६०, २१४ ।

शिक्षा का माध्यम : १४, १८, १९, २५;  
प्राथमिक, ६३; प्राविधिक, २११;

बुनियादी, ४१; माध्यमिक, ९६,  
२००, २०१, १२०; विश्वविद्या-  
लयीय, १७१, १७२ ।

शिक्षा का ढाँचा, ३६-३८, १०६, १९९ ।

शिक्षा छुनाई सिद्धान्त, ६५, ६६, ७९ ।

शिक्षा-नीति : बेटिक (१८३५), ९६;

हाडिज (१८४४), ९६; सरकारी

प्रस्ताव (१९०४), २१, ६४, ८९,

२०१, २१७; सरकारी प्रस्ताव

(१९१३), २१, ६९, १४० २१८,

२१९ ।

शिक्षा परामर्शदाता, २९, ३१, ७३ ।

शिक्षा-मन्त्री, २२, २९, ३२, ३३, ३४,

४८, ७१, ८५, ८७, ९३, १३०,

१५६ ।

शिक्षा-न्याय, १२, १७, २३, ३९, ४०-

४२, ४६, ६४-६६, ७३, ७४,

८१, ८७, ११०, १५७-६०, १६६,

१८२, २९८, १०४, २१७ २२०.

२२८, २६९, २७७, २९२।  
 शिक्षा-साधन, ६३, ८७, १११; १२३,  
 १४४, १५८, १६०, २३३, २५७।  
 शिक्षा-संचालक, २७, २८, ३४, १८४।  
 शिक्षा-सूचना-कार्यालय, २८, ३२।  
 शिक्षक ४८, ६३, ७६, ८१, ८२,  
 ९३, १०६, १०९; २१० २३९-  
 ४४, २७८।  
 शिक्षक-प्रशिक्षण : अनुमान, १११; अनु-  
 साधन, २७७, २७८; अनुसन्धान,  
 १११, २१९, २२७, २२८, २३८,  
 २४१, २४२-२९; उत्तर-स्नातक,  
 २२६, २२६, २३३, २३४; कालिदास  
 अध्यापन, १६९, २३७; पाठ्यक्रम,  
 २३४, २३५; पूर्व-प्राथमिक, २२०,  
 २२१; प्राथमिक, २२१ २८; बुनि-  
 यादी, २२३, २२५, २२६, २३३,  
 २३४; मध्य-अध्यापन, ९४, ११२,  
 २२९, २३०; उच्च, २१७; श्रुति,  
 १११; शिक्षिका, १८६, १८७,  
 १९१, २२०, २२७; सुधार, २३२-  
 २९; स्नातक, २१९, २२०।  
 अर्थ-तन्त्र शिक्षा, ६३, २३०, २३१,  
 २३३, २३७ २३८, २५७, २७८।

अथ

सनातन धर्म, ८९, ९१, २०४।  
 समाज सेवा, १७६, १७७, १७८,  
 १८४।

समाजिक शिक्षा : अनुमान, १११;  
 २२९;

२००; कम्प्यूटर अनुमान, १६८;  
 केन्द्रीय बुनियादी, ४९; कुञ्जः  
 (शास्त्रीय शिक्षा) २७८, (शिक्षा  
 माध्यम) १७१, १७२; खेद, ४८,  
 ४९, २९१, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा,  
 ३१, १५०, बुनियादी अनुमान  
 निर्धारण शिक्षा, ४५, ५०; ताराचन्द्र,  
 १०५; भारतीय शिक्षा शिक्षा, २०१;  
 राष्ट्रीय नारी शिक्षा, १८६, १९०;  
 वैज्ञानिक एवं मानवीय शक्ति, १९७;  
 सरकार, १९७, २०३, हार्दिक, २८,  
 ७१, १०१, १०२, २९१।

सम्यक्त्व : अखिल भारतीय प्रेसिडेंट कौन्सिल,  
 २३३, २३४, अखिल भारतीय  
 राष्ट्रीय शिक्षा, ४०, ४३, ४४;  
 अखिल भारतीय स्त्री परिषद, १८९;  
 माध्यमिक शिक्षा-मण्डल मन्त्रि,  
 १३४; राष्ट्रीय शिक्षा मन्त्री, ८५,  
 २३६; विश्वविद्यालय उपकुलपति,  
 १६९, २३७।

सर्वश्रेष्ठ, ७२, ७७, ८०, ८१, १३१,  
 २२२।

सह शिक्षा, ५, १८७, १९१, २८०।

संघ : अखिल भारत मन्त्रि, १८९;  
 अखिल भारतीय शिक्षा, ११२;  
 शिक्षा-तन्त्र की प्रेरणा शिक्षा प्रणाली,  
 १९६; शिक्षा-तन्त्र की प्रेरणा शिक्षा प्रणाली,  
 २२२, २२९, २८७, २८८; अनुमान  
 २३३, २३४

गणितशास्त्र भाग, २९, ३० ।  
 गणित, १८, १९, ३५ ।  
 गणन व शिक्षा, ८५, १७५, १९२ ।  
 गणनायक शिक्षा, १६६, १६७, २०९ ।  
 गामुसादिक विभाग योजनाएँ १५३ ।  
 गणनाया, २७, ६२, ९६, १७८, २५०,  
 २५५, २९० ।  
 गिनोट, १३८ ४०, १४६, १५६ ।  
 गिनटीकेट, १३५, १३९, १४६ ।  
 गैरिक शिक्षा, २७२ ७५ ।  
 गैर्य शिक्षार्थीजनः गणनीय, ११३, २७४,  
 २७५, २७८; सहायक, २५, २७२,  
 २७४, २७८ ।  
 स्थापित शासन, २९-३४ ।

ग्रीक शिक्षा : आदर्श, १८९, १९०-९२;  
 इतिहास, १७८-१८१; उच्च शिक्षा,  
 १८५, १८६, १९२; पाठ्यक्रम,  
 १७८, १८५, १८६, प्रमाणन,  
 १८३; प्राथमिक शिक्षा, १८४,  
 १९०; मीटिंग-शिक्षा, १८२; माध्यमिक  
 शिक्षा, १८४, १८५, १९५, १९७;  
 स्नातकोत्तर शिक्षा, १८७; वापसी,  
 १७८; विश्वविद्यालयीय, १८५,  
 १८६, १९२; शिक्षा सम्पादन १९०,  
 शिक्षा प्रमाणन, १९१ ।

ह

हावरी निरीक्षण, ८०, ८९, ।  
 हिन्दी, २९, ३०, ४२, ४३, १२०  
 १२१, १२३, १७१ ।  
 हेट माम्बर २६१ ।

# अनुक्रमणिका (नामक्रमानुसार)

अ

इष्ट, १४, १५।  
स्मैर, १०९।  
गिमान तथा निरीधार, ७।  
गिमान, १४२, १४५, १६६, २२५,  
१०६।

अमरावती, १५३।  
अमरावती, ६८।  
अमरावती, १४, १६, १५२, १६०,  
१७६, २०८, २५१, २६४।  
अमरावती, गजकुमारी, १८९, २७२।  
अमरावती, २६४।  
अमरावती, १०९, १६९, १४५,  
२०६, २२५, २२८, ३०६।  
अमरावती, १४०, १४३, १४५, १४४,  
२०५, २२८, २८४, ३०६।  
अमरावती, २६, ४३, २०६।  
अमरावती, १४३, २८९, ३०६।  
अमरावती, १६६।  
अमरावती, १४।

आ

आमरावती, १६६, १००।  
आमरावती, १६६, १४३, १४५, १४०,  
१६६, ३०६।  
आमरावती, १६६, १४३, १४५, १४०,  
१६६, ३०६।

आमरावती, २६, ११०, १४३, १६६,  
२७२, ३०२।  
आमरावती, १४३, १४५, १६६, २०६।  
आमरावती, ४०।  
आमरावती, १४, १४३।  
आमरावती, ५।

इ

इष्ट, ८८, १४।  
इष्ट, १५।  
इष्ट, १५।  
इष्ट, १६, १७, ८१, ८८, १५,  
१६५, १६७, १७४, १०३, २५१,  
२५१।

उ

उष्ट, १६, ४३, १००,  
२०८, २६०, ३०३।  
उष्ट, १६, ४३, १००, २०२,  
२०२, २०३।  
उष्ट, १६६।

ए

एष्ट, १६, ४३, १००,  
२०८, २६०, ३०३।  
एष्ट, १६, ४३, १००, २०२,  
२०२, २०३।  
एष्ट, १६६।

## ओ

ओदन्तपुरी, १०, १२।  
ओस्मानिया, १४५, १६६, २२५,  
२२८, ३०४।

## क

कर्जन, लाई, २१, १००, १३९, १४०।  
काटक, १०९।  
कनौज, ६।  
कबीर, हुँमायुन, २०४, २९७।  
कमतवा, १३।  
कलकत्ता, २१, ३३, ९८, १३७,  
१३९, १४५, १९५, २१६, २२४,  
२२५, २२८, २८१, ३०२।  
कर्वे, डी० के०, २८०।  
कानपुर, ३३, १९७, २०३।  
कोरे, २१६।  
काशी, ६।  
काश्मीर, १०, ४३, १४२, १४५,  
१४६, ३०३।  
काँची, ६।  
किलपेक्किद्रू, विलियम, २१९।  
कुरुक्षेत्र, १४२, १६५, ३०३।  
कुसैयोग, २१८।  
कुँजरू, हृदयनाथ, १७१, २७८।  
केरल, २६, १४५, १६६, २०२,  
२२२, २६९, ३०३।

## ख

खड़गपुर, २०३।  
खारीजाम, १३।  
खिलजी, अलाउद्दीन, १५।

## ग

गर्गी, ५।  
गार्गोदी, १५३।  
गान्धीजी, ३८, ४०, ४१, ४३, ४४,  
४८, १८१, २४६, २९९।  
गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव, ६७।  
ग्वालियर, १०९।  
गुजरात, १०, ६६, १४२, २२४,  
२२८, ३०३।  
गोलले गोपालकृष्ण, २१, ६८-७०,  
८८।  
गोरखपुर, १४२, १४५, २१८, २२४,  
२२८, ३०३।  
गौहाटी, १४२, १४५, १९५, २२४,  
२२८, ३०३।

## घ

घोषा, ५।  
घोष राघविहारी, १००।

## च

चीन, ८८, ९६, २६१।  
चेम्सफोर्ड, लाई, २१, ६९।

## ज

जादल, १०, १२।  
जबलपुर, १४२, १४५, २१८, २२४,  
२२४, २२८, ३०३।  
जमशेदपुर, २०२।  
जमनी १४, ९५, २१४।  
जयपुर, १०९, ३०४।  
जाकिर हुसैन, ४१, ४३, ५२, ५३,  
२४४।

जार्जे, पेंचम, ६९ ।

जादवपुर, १००, १४२, १४५, १९६,  
३०३ ।

जायान, ८८, ९६, २६१ ।

जमियानगर, १५२ ।

ट

टर्की, ९४, ९६ ।

ठ

ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, २८१ ।

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १००, २८१,  
२८२, २८४ ।

ठाकुरसी, भीमनी नाथीसाई दामोदर,  
२८१ ।

ड

डम्बन, जानार्थन, १७ ।

डेनमार्क, ९४ ।

ढ

ढाका, १०९, १४१ ।

न

नक्षत्रिया, ६ ।

नैजीर, ६ ।

ध

धामस, जान, ११६ ।

धेरा, एम० एम०, २०० ।

द

दण्डानन्द मारवती, ३७८ ।

दिग्री, १३, ३७, ६९, १०९, १३६,  
१४१, १४५, १५४, २०२, २२८,  
३६९, ३७७, ३०८ ।

दुर्गापुर, २०२ ।

दुर्वासा, १३६ ।

देशमुख, चिन्तामन, १५७, १६५ ।

देशाई, महादेव, २८५ ।

देशाई, मोरारजी, २१४ ।

देवशानी, ५ ।

देहरादून, २६४, २६७ ।

न

नवद्वीप, १३६ । -

नागपुर, २७, १०९, १४०, १४१,

१४५, १६६, २०२, २२५, ३०३ ।

नायडु, मरोजिनी, १८१ ।

नाल्फ्ट, १२ ।

नागिक, ६ ।

नेहरू, जवाहरलाल, २१०, २६२, २७५ ।

नैरोबी, ३२ ।

न्यूजीलैण्ड, ९४ ।

प

पाण्डित, विद्यालक्ष्मी, १८९ ।

पन्त, सुमित्रानन्द, २९३ ।

पटना, १०९, १४०, १४१, २४५,

२२५, २८४, ३०४ ।

पटेल, बल्लभभाई, २४२, ३०४ ।

पटेल, विह्वलभाई, ७०, ८८, १४३ ।

पसी, दुर्गेस, २१३ ।

पराब, १०, २६, १३८, १४५, १५३,

२०३, २६९, २७७, ३०४ ।

पाटलीपुत्र, ६ ।

पूना, १०९, १३६, १४१, १४२,

१४५, १६६, १९५, २२४, २८०,

२८४, ३०४ ।



